



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]
No. 47]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 1986/अग्राहायण 1, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 1986/AGRAHAYANA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

सूचनाएं

का.झा. 3899 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जी. एल. नंदा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अजमेर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(75)/86-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 7th November, 1986

NOTICES

S.O. 3899.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri G. L. Nanda Advocate for appointment as a Notary to practise in Ajmer.

1086 GI/86—1

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(75)/86-Judl.]

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1986

का.झा. 3900—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एस. सी. सरकार, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे 24-परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(76)/86-न्या.]

New Delhi, the 10th November, 1986

S.O. 3900.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri S. C. Sarkar, Advocate for appointment as a Notary to practise in 24-Pargana.

(4585)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(76)/86-Judl.]

का.प्रा. 3901.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राधेश्याम गुप्ता एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बलीमरान (दिल्ली) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(77)/86 न्या.]

S.O. 3901.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Radhey Shyam Gupta, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ballimarran (Delhi).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(77)/86-Judl.]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1986

का.प्रा. 3902.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशोक मुखर्जी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे साउथ-24-परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(79)/86-न्या.]

New Delhi, the 12th November, 1986

S.O. 3902.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Asoke Mukherjee Advocate, for appointment as a Notary to practise in South-24-Pargana.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(79)/86-Judl.]

का.प्रा. 3903.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री विक्रमजीत सिंह विश्नोई, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बीकानेर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(78)/86-न्या.]

S.O. 3903.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Vikram Jeet Singh Visnoi, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Bikaner.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(78)/86-Judl.]

का.प्रा. 3904.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अनिल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(69)/86-न्या.]

भार. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3904.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Anil Sharma for appointment as a Notary to practise in Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(69)/86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1986

का.प्रा. 3905.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन.ए.आर. इस विभाग की दिनांक 31-1-1978 की अधिसूचना सं. 1 (2)/विशेष सेन/78-एन. एन. II, द्वारा बन्दीवस्त प्रायुक्त के रूप में नियुक्त समाह्वी जिन्ना श्रीगंगानगर, राजस्थान को जिन्ना श्रीगंगानगर में स्थित उनके अधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रतिकर पूल के भाग-उत्पाजित निष्कास्त सम्पत्तियों, कृषि भूमि, दुकानों तथा खाली स्थलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी करने के उद्देश्य से मुख्य बन्दीवस्त प्रायुक्त को निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपता हूँ :-

(1) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रवील सुनने की शक्तियाँ।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन संशोधन सुनने की शक्तियाँ।

2. इसके द्वारा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भूतपूर्व प्रति और पुनर्वास संकलन (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 31-1-1978 की अधिसूचना सं. 1(2)/विशेष सैल/78-एस. एस. II का अधिकरण किया जाता है।

[संख्या 1(16)/विशेष सैल/86-एस. एस. II]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 21st October, 1986.

S.O. 3905.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section (34) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), I hereby delegate to the Collector, Sriganganagar District, Rajasthan, appointed as Settlement Commissioner vide this Department's Notification No. 1(2)/Spl. Cell/78-SS.II, dated 31-1-1978 the following powers of the Chief Settlement Commissioner for the purpose of passing necessary orders under the Sections mentioned below in respect of the acquired evacuee properties/agricultural lands/shops and vacant sites, forming part of the Compensation Pool situated in Distt. Sriganganagar falling under his jurisdiction :—

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

2. This supersedes erstwhile Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Notification No. 1(2)/Spl. Cell/78-SS.II, dated 31-1-1978, issued in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954.

[No. 1(16)/Spl. Cell/86-SS.II]

का. आ. 3906.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत जिला श्रीगंगानगर में सम्पत्ति भूमि को छोड़कर राजस्थान राज्य में प्रतिकर पूल के भाग-उत्पन्न निष्क्रान्त सम्पत्तियों, कृषि भूमि, दुकानों तथा खाली स्थलों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए राजस्व अधीन प्राधिकारी (1) जयपुर, राजस्थान सरकार को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपता हूँ।

(1) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियाँ।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन संशोधन सुनने की शक्तियाँ।

2. तथापि, राजस्थान सरकार के पुनर्वास विभाग में आयुक्त-सह-सचिव को उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन भारत के भूतपूर्व अन्तर्गत पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 7 अप्रैल, 1973 की अधिसूचना संख्या 1(40)/वि. सैल/72-एम. एस. II के तहत जिस उद्देश्य के लिए ये शक्तियाँ सौंपी गई थी, वे उन शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे।

2. इसके द्वारा भूतपूर्व प्रति तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 24-12-1974 की अधिसूचना संख्या 23/1/73 वि. सैल एस. एस. II का अधिकरण किया जाता है।

[संख्या 1(16)/वि. सैल/86-एस. एस. II]

जो. पी. एन. साहू, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 3906.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section (34) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), I hereby delegate to the Revenue Appellate Authority (I), Jaipur, Govt. of Rajasthan, the following powers of the Chief Settlement Commissioner for the purpose of passing necessary orders under the Sections mentioned below in respect of acquired evacuee properties, agricultural lands, shops and vacant sites, forming part of 'Compensation Pool', in the State of Rajasthan except properties/Lands situated in Distt. Sriganganagar.

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

However, the Commissioner-cum-Secretary in the Rehabilitation Department of the Govt. of Rajasthan will continue to exercise powers under Section 28 of the said Act, for the purpose for which these powers were delegated to him vide Notification No. 1(40)/Spl. Cell/72-SS.II, dated the 7th April, 1973 of the Govt. of India, erstwhile Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation).

2. This supersedes erst while Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Notification No. 21/6/73-Spl. Cell/SS.II, dated 24-12-1974.

[No. 1(16)/Spl. Cell/86-SS.II]

G. P. S. SAHI, Chief Settlement Commissioner.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 3907.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए मैं केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले केवल चार करोड़ पैंतीस लाख रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों 9.75 प्रतिशत तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऋण, 1999 (दूसरी श्रृंखला) के स्वरूप के अधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी है।

[सं. 42/86-का.सं. 33/57/86-वि.क.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th November, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 3907.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes 9.75% Tamilnadu Electricity Board loan, 1999 (2nd Series) to the value of rupees four crores and thirty five lakh only to be issued by the Tamilnadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. 42/86-Stamps-F. No. 33/57/86-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 3908.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र तेईस करोड़ सस्ती लाख पैंसठ हजार रुपये के मूल्य के प्रामित्यरी नोटों "9.75 तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्रेण, 1998" के स्वरूप के बंधनों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[सं. 41/86-स्टाम्प-का. स. 33/60/86-न.क.]

बी. आर. मेहता, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 3908.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes "9.75. Tamilnadu Electricity Board loan, 1998" to the value of rupees twenty three crores eighty lakhs and sixty five thousand only to be issued by the Tamilnadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. 41/86/Stamp-F. No. 33/60/86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1986

का. आ. 3909.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून, 1987 तक गुजराती इन्स्ट्रुमेंट्स कोऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि., गुजराती (कनाडा) पर लागू नहीं होंगे।

[एफ. सं. 8-3/86-ए. सी.]

(Deptt of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th November, 1986

S.O. 3909.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Gulbarga District Co-operative Central Bank Ltd., Gulbarga (Karnataka) from the date of publication of this notification in the official Gazette to 30 June, 1987.

[F. No. 8-3/86-AC]

का. आ. 3910.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून, 1988 तक बाबुरघाट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बाबुरघाट (पश्चिमी बंगाल) पर लागू नहीं होंगे।

[एफ. सं. 8-3/86-ए. सी.]

S.O. 3910.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Balurghat Central Cooperative Bank Ltd., Balurghat (West Bengal) from the date of publication of this notification in the official Gazette of 30 June, 1988.

[F. No. 8-3/86-AC]

का. आ. 3911.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिकारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 8 मार्च, 1988 तक देवघर जामतारा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., देवघर (बिहार) पर लागू नहीं होंगे।

[एफ. सं. 8-3/86-ए. सी.]

के. पी. पान्डियन, अवर सचिव

S.O. 3911.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Deoghar-Jamtara Central Co-operative Bank Ltd., Deoghar (Bihar) from the date of publication of this notification in the official Gazette to 8 March, 1988.

[F. No. 8-3/86-AC]

K. P. PANDIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

का. आ. 3912.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1980 के खण्ड 3 के उप खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के कालम (1) में दिये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

1	2	3
1. विजया बैंक	श्री ए. एम. एन. शर्मा संयुक्त मुख्याधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, धर्मपुर-400005	श्री के. के. सक्सेना संयुक्त मुख्याधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, धर्मपुर-400005
2. सिंध बैंक	श्री बी. एन. दिनानाथकर, श्री पी. बी. कुलकर्णी संयुक्त मुख्याधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, धर्मपुर-400005	

[संख्या एफ 9/2/86-बी. ओ. 1(1)]

एम. एम. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1986

S.O. 3912.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (1) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

TABLE

(1)	(2)	(3)
1. Vijaya Bank	Shri A. M. M. Sarma, Joint Chief Officer, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay-400005.	Shri K.K. Saksona
2. Punjab and Sind Bank	Shri B. N. Dingankar, Joint Chief Officer, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay-400005.	Shri P.B. Kulkarni

[No. F. 9/2/86-BO. I (1)]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

का. आ. 3913.—राष्ट्रियकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकरण उपबंध) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री पी. के. पार्थसारथी, मुख्याधिकारी ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को श्री बी. डी. के. के स्थान पर एतद्वारा सिंडिकेट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/2/86-बी. ओ. 1(2)]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

New Delhi, the 11th November, 1986

S.O. 3913.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri P. K. Parthasarathy, Chief Officer, Rural Planning and Credit Department, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay as a Director of Syndicate Bank vice Shri B. Ray.

[No. F. 9/2/86-BO. I(2)]

S. S. HASURKAR, Director

समाह्वानिय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना सं. सी. ई. आर./आर.-5/6/86

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नागपुर, 4 नवम्बर, 1986

का. आ. 3914.—अधिसूचना सं. सी. ई. आर./आर.-5/3/86 दिनांक 25-4-86 द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या सी. ई. आर./आर.-5/1/84 दिनांक 7-1-84 में नीचे लिखे अनुसार आगे संशोधन किया जाता है—

नियत अधिसूचना में क्रम सं. 27(ए) (ब) के स्तर 3 में 'सहायक समाह्वान' शब्दावली के लिए 'रेंज अधीक्षक' पढ़ा जाए।

[प. सं. IV/(16)8/22/तक/भाग]

कश्मीरा सिंह, समाह्वान

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. CER/R-5/6/86

CENTRAL EXCISE

Nagpur, the 4th November, 1986

S.O. 3914.—Notification No. CER/R-5/1/84, dated 7-1-1984 as amended by Notification No. CER/R-5/3/86, dt. 25-4-1986 is further amended as under :—

In the Annexure to the said Notification against Sr. No. 27(A)(b), in column 3 for the words 'Assistant Collector' the words read 'Range Superintendent'.

[C. N. IV(16)8/22/80/CX|PT]

KASHMIRA SINGH, Collector

वाणिज्य संचालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

प्रादेश

का. आ.—3915 मैक्सिमम नैशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि., एल्यूमीनियम हाऊस, जलपय भुवनेश्वर को मुख्य विदेशी मुद्रा विनियम के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए 6,70,000/-रुपए (छह लाख, सत्तर हजार रुपये मात्र) को एक आयात लाइसेंस में, आई/सी. जी./2041364/सी. एफ. एम./96/85/सी. जी. 2/एन. एम. दिनांक 30-7-85 को जारी किया गया था।

कर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति की अनुतिथि प्रति को जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। प्राप्ति यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति को किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था तथा इस प्रकार सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति का मुख्य बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने दिनांक 19-9-86 की नोटरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथपत्र दायित्व किया है। से, तदनुसार समुचित है कि आयात लाइसेंस सं. आई/सी. जी./2041364/सी. एफ. एम./96/एव/85/सी. जी. 2/एन. एम. दिनांक 30-7-85 की मूल सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रति कर्म ने खो गई/अस्थानस्थ हो गई है यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(ग) के अधीन प्रवर्तित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैक्सिमम नैशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि. भुवनेश्वर, को जारी की गई उपयुक्त मूल सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति सं. आई/सी. जी./2041364 दिनांक 30-7-85 एतद्वारा की जाती है।

3. पार्टी को उपयुक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[सं. सी. जी. 2/साइम्स/2/82-83/549]

पाल बैंक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 11th November, 1986

ORDER

S.O. 3915.—Ms. National Aluminium Co. Ltd., JPICOL House, Janpath, Bhubneshwar were granted an Import Licence No. I/CG/2041364/C/XX/96/85/CGII/LS dated 30-7-85 for Rs. 6,70,000 (Rupees six lakhs and seventy thousand only) for import of Capital goods under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Custom purposes Ex. Control copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Purposes Ex. Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes Ex. Control copy of the licence was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs Purposes Ex. Control copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary Public dt. 19-9-86. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes Ex. Control copy of import licence No. I/CG/2041364/C/XX/96/H/85/CGII/LS dated 30-7-85 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated, 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes Ex. Control copy No. ICG/2041364 dt. 30-7-85 issued to M/s. National Aluminium Co. Ltd., Bhubaneshwar is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes Ex. Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/Mines/2/82-83/549]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

का. प्रा. :—3916 केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्रामादित अधि-भोगियों की देखरेख) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिवृत्तनामं. का. प्रा. 2571, तारीख 9 जून, 1983 को, अधिकांश करने द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं, जो अनवी-जानी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रतिष्ठ में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाधत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रकार और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
3	
1. कामिक और प्रशासन का प्रयास करने स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के परिसर जो पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता और हावड़ा जिला में अवस्थित हैं।

- मुख्य प्रबंधक (कामिक और प्रशासन) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के परिसर जो पश्चिमी बंगाल राज्य में बर्दवान जिला के बर्नपुर बर्नपुर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं।
- कामिक प्रबंधक, राजनीय बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के संकर्म, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., परिसर जो पश्चिमी बंगाल राज्य में बर्दवान जिला के राजनीय, हावड़ा राजनीय, जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल दुर्गापुर और ओडिसा में तथा बिहार राज्य में धनबाद जिला के मुनकरवारी हावड़ा ब्रूम, पु. या. चिरकुंडा में अवस्थित हैं।
- उप प्रबंधक (कामिक बर्नपुर बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के संकर्म, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., परिसर जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर और निवार में अवस्थित हैं।
- वाणिज्यिक प्रबंधक, नेतृत्व संकर्म, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., हावड़ा परिसर जो तमिलनाडु राज्य में सुरमंगलम, जिला सेन, के सेन में अवस्थित हैं। तमिलनाडु
- कामिक प्रबंधक, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के कम्पनी लिमिटेड, मधु प्रभाग, परिसर जो पश्चिमी बंगाल में जेनिगम, जिला मिर्जापुर, जेनिगम, पु. या. तन्वीग्राम पश्चिमी बंगाल और हरिद्वार पु. या. हरिद्वार में अवस्थित हैं।

[फा. सं. 3 (19)/84/एच. एन. III]

सी. के. यमर्, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

New Delhi, the 13th November, 1986

S. (1).—396 In exercise of powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Heavy Industry) No. SO/571 dated 9th June, 1983 the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being officers equivalent to the rank of the Gazetted Officer of the Government to be the Estate Officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction, in regard to the public premises specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. Chief of Personnel and Administration, Bura Standard Company Ltd., Calcutta.	Premises belonging to Bura Standard Company Ltd., situated at Calcutta and in the District of Howrah in the State of West Bengal.

1	2	3
2. Chief Manager (Personnel and Administration), Burnpur Works, Burn Standard Company Ltd., P.O. Burnpur, District Burdwan, West Bengal.	Premises belonging to Burn Standard Company Ltd., situated at Burnpur in the District of Burdwan in the State of West Bengal.	
3. Personnel Manager, Raniganj Works, Burn Standard Company Ltd., P.O. Raniganj, District Burdwan, West Bengal.	Premises belonging to Burn Standard Company Ltd., situated at Raniganj, Jurgapur and Ondal in the District of Burdwan in the State of West Bengal and those situated at Gultarbari, P.O. Mugma, P.S. Chirkunda, District Dhanbad in the State of Bihar.	
4. Deputy Manager (Personnel), Jabalpur Works, Burn Standard Company Ltd., Jabalpur, Madhya Pradesh.	Premises belonging to Burn Standard Company Ltd., situated at Jabalpur and those situated at Nivher both in the State of Madhya Pradesh.	
5. Commercial Officer, Salem Works, Burn Standard Company Ltd., P.O. Surmangalam, District Salem, Tamil Nadu.	Premises belonging to Burn Standard Company Ltd., situated at Salem in the State of Tamil Nadu.	
6. Personnel Manager, Burn Standard Company Ltd., Offshore Division, Jellingham, District Midnapore, West Bengal.	Premises belonging to Burn Standard Company Ltd., situated at Jellingham under P.S. Nandigram and at Haldia P.S. Haldia in the District of Midnapore, West Bengal.	

[F. No. 3(19)/84/HM-III]
C.K. SHARMA, Director

निर्माण महानिदेशालय

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1986

परिपत्र सं. 58/1986

का. अ. 3917:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करते हैं। इनको निर्माण महानिदेशालय की दिनांक 8-9-1978 की अधिसूचना संख्या 2/2/77 हिन्दी और दिनांक 9-8-1984 की अधिसूचना संख्या 2/2/84 हिन्दी जिनके अन्तर्गत क्रमशः 73 और 49 कार्यालयों को अधिसूचित किया गया था, के अनुक्रम में जारी किया जाता है :—

उद्यान निदेशालय (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

1. पूर्वी उद्यान मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इन्द्रप्रस्थ भवन

नई दिल्ली-110002

2. केन्द्रीय उद्यान मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली-110002

[सं. 2/2/86-हिन्दी]

हरीश चन्द्र, निर्माण महानिदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संवायन

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

का. आ. 3918—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बहेज से पालेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए साईर लाईन नैव तथा प्राकृतिक गैस आयो। द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पार्सीपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्सीपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक गैस आयो, निर्माण और देखभाल, प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ीदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हुँहुर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है। कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाय को मार्फत।

अनुसूची

बहेज से पालेज तक पार्सी लाई बिछाने के लिए।

राज्य :- गुजरात

जिला :- महेब

तालुका :- बागरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आरे	सेन्टीयर
सायथा	39/1	0	31	00
	39/2	0	31	00
	39/3	0	31	00
	40/ए	0	28	00
	41	0	36	00
	44	0	49	00
	52	0	36	00
	50	0	01	00
	53/ए	0	18,	00
	55	0	26	00
	68	0	20	00
	70/ए	0	39	00
	70/बी	0	08	00
	72	0	38	00
	80	0	89	00
	86	0	22	00
	69	0	22	00

[सं. O-12016/1986/86-बी एन जी-बी 4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 3918.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej to Palej

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Wagra		
Village	Survey No.	Hectare	Acre Centiare	
Sykha	39/1	0	31	00
	39/2	0	31	00
	39/3	0	31	00
	40/A	0	28	00
	41	0	36	00
	44	0	49	00
	52	0	36	00
	50	0	01	00
	53/A	0	18	00
	56	0	26	00
	68	0	20	00
	70/A	0	39	00
	70/B	0	08	00
	72	0	38	00
	80	0	89	00
	86	0	22	00
	69	0	22	00

[No. O-12016/196/86-ONG-D4]

का. आ. 3919.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पार्श्वलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1476 तारीख 19-4-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पार्श्वलाईनों को बिछाने के अर्जित करने का अपना आणव्य घोषित कर दिया था।

और यतः सभ्य शांतिगरी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र शासन सरकार द्वारा घोषित करती है कि

इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पार्श्वलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उतद्धारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस, आयोग में, सभी बाधाओं से, मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे. आर. एफ. से जी. जी. एस. शालोरा II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला मेहसाना

तालुका : कड़ो

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आ रे.	सेण्टीयर
आद्वज	1336/1	0	00	50
	1327	0	21	35
	1335	0	05	75
	1333	0	00	50
	1317	0	07	95
	1318/2	0	02	00
	1318/1	0	06	25
	1324/1	0	22	68
	1323	0	01	00
	फाई ट्रेक	0	06	00
	1162	0	11	55
	1161	0	01	20
	1121	0	04	50
	1121	0	35	70
	1116/2	0	13	50
	1118	0	03	75
	1117	0	11	85

[सं. O-12016/24/84-मोड़]

S.O. 3919.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 1476 dated 19-4-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

1 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JRF to GGS Jhalora II

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Ar	Centiare
Adraj	1338/1	0	09	50
	1337	0	21	38
	1335	0	05	75
	1333	0	09	50
	1317	0	07	25
	1318/2	0	02	00
	1318/1	0	06	28
	1324/1	0	22	68
	1323	0	01	00
Canal track		0	06	00
	1162	0	11	55
	1161	0	01	20
	1121	0	04	50
	1121	0	35	70
	1116/2	0	13	50
	1118	0	03	75
	1117	0	11	85

[No. O-12016/24/84 Prod.]

का. आ. 3920 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी. सी. एस. से रीलायन्स इन्ड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़ादों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपा-बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इन अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी.सी.एस. से रीलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : दमक्रोई
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर आर. सेंटीयर
हाथीजम	635	0 01 50
	636	0 00 25
	637	0 14 40
	599	0 02 80
	600	0 12 00
	601	0 27 30
	598	0 00 75
	597	0 12 75
	596	0 00 75

[सं. O-12016/191/86 भोएन-डीजी-1]

S.O. 3920.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Ind. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Thane

Village	Block No.	Hectare	Ar	Centiare
Hathijan	635	0	01	50
	636	0	00	25
	637	0	14	40
	599	0	02	80
	600	0	12	00
	601	0	27	30
	598	0	00	75
	597	0	12	75
	596	0	00	75

[No. O-12016/191/86-ONG-D-1]

का.आ. 3921 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रामोल जी.एस.एस. से रीलायन्स इन्ड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़ादों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रामोल जी.सी.एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : दामको			
गाँव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीमीटर	
कनभा	437	0	00	90	
	438	0	24	00	
	439	0	15	15	
	441	0	00	60	
	442	0	18	30	
	444	0	10	50	
	459	0	05	25	
	460	0	06	00	
	461	0	04	20	
	463	0	13	50	
	466	0	07	50	

[सं. O-12016/192/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 3921.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ramol G.C.S. to Reliance Ind. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol Gas to Reliance Industries

State : Gujarat	District : Ahmedabad	Taluk : Dhamro			
Village	Block No.	Hectare	Area Centiare		
Kanbha	437	0	00	90	
	438	0	24	00	
	439	0	15	15	
	441	0	00	60	
	442	0	18	30	
	444	0	10	50	
	459	0	05	25	
	460	0	06	00	
	461	0	04	20	
	463	0	13	50	
	466	0	07	50	

[No. O-12016/192/86-ONG-D4]

का.धा.3922.—यतः केन्द्राय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से पालेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन.ए.आर. अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्ररत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपने आशय एन.ए.आर. घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मरेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति नितिनिष्ठः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

दहेज से पालेज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : अहमदाबाद	तालुका : दामको			
गाँव	सर्वेक्षण नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीमीटर	
खोजबल	227	0	06	00	
	228	0	20	00	
	226	0	10	00	
	225	0	15	00	
	224	0	11	00	
	223	0	53	00	
	165	0	07	00	
	330	0	28	00	
	166	0	07	00	
	162	0	36	00	
	168	0	07	00	
	169	0	23	00	
	161	0	32	00	
	121/ग/1	0	38	00	
	121/ए	0	09	00	
	120	0	17	00	

[सं. O-12016/193/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 3922.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej to Palej

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Wagra		
Village	Survey No.	Hacter	Area	Centiare
Khojbal	227	0	00	00
	228	0	20	00
	226	0	10	00
	225	0	15	00
	224	0	11	00
	223	0	53	00
	165	0	07	00
	330	0	28	00
	166	0	07	00
	162	0	36	00
	168	0	07	00
	169	0	23	00
	161	0	32	00
	121/A/1	0	38	00
	121/A	0	09	00
120	0	17	00	

[No. O-12016/193/86-ONGD-4]

का. अ. 3923 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से पालेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तैय्य तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़ादतों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अर्थना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में द्विपक्ष कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहित प्राधिकारी तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिनियम की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह बह आहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी निधि व्यवसायी को मार्फत।

अनुसूची

दहेज से पालेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : वागडा		
गाव	ब्लॉक नं.	है.	घार	भे.
भटाली	209	0	14	00
	212/ए	0	43	00
	213	0	12	00
	214	0	0	32
	216	0	10	00
	217	0	30	00
	218	0	02	00
	219	0	25	00
	227	0	03	00
	281	0	07	00

[न. O-12016/194/86-ऑ. एन. जी. डी-4]

S.O. 3923.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej to Palej Line

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Wagra		
Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Atali	209	0	14	00
	212/A	0	43	00
	213	0	12	00
	214	0	0	32
	216	0	10	00
	217	0	30	00
	218	0	02	00
	219	0	25	00
	227	0	03	00
	281	0	07	00

[No. O-12016/194/86-ONG-D-4]

का. अ. 3924 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से पालेज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तैय्य तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यहाँ यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एहदाबद्ध अनुसूची में उचित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और नैचुरल गैस पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उपधारा के अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एहदाबद्धा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में बिछाई कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे के पाइपलाइन बिछाने के लिए आशेष गैस प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रमाण, मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उस क गुप्तवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

वहेज से पलेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात; जिला : भारुच तालुका : वाग्रा

गांव	खाना सं.	हेक्टेयर	आर	सें.
1	2	3	4	5
वाहियाल	367	0	36	00
	366	0	18	00
	365	0	06	00
	363	0	32	00
	362	0	66	00
	396	0	10	00
	395	0	27	00
	397	0	32	00
	400	0	36	00
	398	0	28	00
	406	0	19	00
	407	0	18	00
	342	0	44	00
	343	0	16	00
	339	0	02	00
	338	0	20	00
	345	0	01	00
	336	0	34	00
	334	0	04	00
	335	0	09	00
	315	0	36	00
	313	0	07	00
	415	0	37	00
	112	0	25	00
	281	0	33	00
	280	0	27	00
	514	0	47	00
	515	0	02	00
	279/अ	0	38	00
	278	0	36	00
	244	0	34	00
	243	0	34	00
	235	0	23	00

1	2	3	4	5
	236	0	26	00
	237/ए	0	15	00
	195	0	41	00
	196	0	16	00
	197	0	20	00
	172	0	34	00
	173	0	18	00
	174	0	43	00
	159	0	55	00
	153/बी	0	14	00

[सं. O-12016/195/86-ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 3924.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dahej to Palej in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej to Palej

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Wagra

Village	Block No.	Hectare	Aro	Centiare
1	2	3	4	5
Vahiyal	367	0	36	00
	366	0	18	00
	365	0	06	00
	363	0	32	00
	362	0	66	00
	396	0	10	00
	395	0	27	00
	397	0	32	00
	400	0	36	00
	398	0	28	00
	406	0	19	00
	407	0	18	00
	342	0	44	00
	343	0	16	00
	339	0	02	00
	338	0	20	00
	345	0	01	00
	336	0	34	00
	334	0	04	00
	335	0	09	00
	315	0	36	00
	313	0	07	00

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	415	0	37	00		236	0	26	00
	312	0	25	00		237/A	0	15	00
	281	0	33	00		195	0	41	00
	280	0	27	00		196	0	16	00
	514	0	47	00		197	0	20	00
	515	0	02	00		172	0	34	00
	279/B	0	38	00		173	0	18	00
	278	0	36	00		174	0	42	00
	244	0	34	00		159	0	55	00
	243	0	34	00		158/B	0	14	00
	235	0	23	00					

[No. O-12016/195/86-ONG-D4]

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

शुद्धि पत्र

का.आ. 3925.—भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 25 दिसम्बर, 1982 पृष्ठ क्रमांक 4425 का.मा. संख्या क्रमांक 0-12016/67/82-प्रोड के अन्तर्गत भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) को अधिसूचना संख्या क्रमांक 4319 दिनांक 25 दिसम्बर, 1982 के अन्तर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन वर्णित गांव बडगांव, तहसील मावल जिला पुणे महाराष्ट्र के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बबले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 3 के उपधारा (1) के अधिसूचना को अनुसूची को कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग I

कालम II पढ़ें

कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
1	2	3	4	1	2	3	4
बडगांव	8	2	00-42-84	बडगांव	8	का भाग	00-55-00
	13	1	00-05-94		13	"	00-23-00
	15	का भाग	00-14-40		15	"	00-20-00
	27	"	00-32-22		27	"	00-40-00
	28	12	00-09-36		28	"	00-36-00
	28	13	00-09-36				
	28	2	00-12-24				
	29	1	00-24-48		29	"	00-32-00
	8	1					
	29	2	00-05-40				
	236	का भाग	00-47-52		236	"	00-36-00
	237	"					
	238	1	00-27-00		237	"	00-20-00
	241	4					
	238	2	00-24-30		238	"	00-28-00
	240	का भाग	00-35-38		240	"	00-36-00
	241	1					
	241	2	00-08-64		241	"	00-08-00
	241	3					
	255	1			255	"	00-65-00
	256	का भाग	00-43-74		256	"	00-32-00

1	2	3	4	1	2	3	4
	255	2	00-30-42				
	268	1	00-14-40		268	का भाग	00-28-00
	269	3 अ	00-02-70				
	269	3 ग	00-19-44		269	"	00-22-00
	269	2	00-22-68				

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
वडगाँव	14	का भाग	00-08-00

[सं. O-12016/67/82-प्रोड]

New Delhi, the 11th November, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 3925.—In the Notification of Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer's (Department of Petroleum) No. 12016/67/82/Prod dated 25th December, 1982, published under S.O. No. 4319 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (II) at page 4425 issued under Section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of

User in Land) Act, 1962 in respect of villages-Vadgaon for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 3 Sub-Section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read (Col-ID)

For (Col-I)

PART-I

Village	S. No.	H. No.	Area	Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.				G. No.		
1	2	3	4	1	2	3	4
Vadgaon	8	2	00-42-84	Vadgaon	8	(pt)	00-55-00
	13	1	00-05-94		13	(pt)	00-23-00
	15	(pt)	00-14-40		15	(pt)	00-20-00
	27	(pt)	00-32-72		27	(pt)	00-40-00
	28	1(2)	00-09-36				
	28	1(3)	00-09-36		28	(pt)	00-36-00
	28	2	00-11-24				
	29	1			29	(pt)	00-32-00
	08	1	00-14-48				
	29	2	00-05-40				
	236	(pt)	00-47-52		36	(pt)	00-36-00
	237	(pt)					
	238	1			237	(pt)	00-20-00
	241	4	00-27-00				
	238	2	00-14-30		238	(pt)	00-28-00
	240	(pt)	00-35-38		240	(pt)	00-36-00
	241	1			241	(pt)	00-08-00
	241	2	00-08-64				
	241	3					
	255	1			255	(pt)	00-65-00
	256	(pt)	00-43-74		256	(pt)	00-32-00
	255	2	00-30-42				
	268	1	00-14-40		268	(pt)	00-28-00
	269	3A	00-02-70				
	269	3B	00-19-44		269	(pt)	00-22-00
	269	2	00-22-68				

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
Vadgaon	14	(pt)	00-08-00

[No. O-12016/67/82-Prod.]

शुद्धि पत्र

का.आ. 3926.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 15 अक्तूबर, 1983 पृष्ठ क्रमांक 4007 का.आ. संख्या क्रमांक 0-12016/67/82-प्रोड के अंतर्गत भारत सरकार कृषि संचालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 3922 दिनांक 15 अक्तूबर 1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 उपधारा (1) के प्रयोजन वर्णित गांव बडगांव, बडगांव मावन, जिना पुणे, महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बड़े अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाइप लाइन बिछाने का प्रयोजन अनाइनमेंट बदलने से अब न रहा है, अब अब निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि धारा 6 उपधारा (1) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग I

कालम 2 पढ़ें

कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
बडगांव.	8	2	00-42-84	बडगांव	8	का भाग	00-55-00
	13	1	00-05-94		13	"	00-23-00
	15	का भाग	00-14-40		15	"	00-20-00
	27	"	00-32-22		27	"	00-40-00
	28	1 2	00-09-36 }		28	"	00-36-00
	28	1 3	00-09-36 }				
	28	2	00-12-24 }				
	29	1 }	00-24-48		29	"	00-32-00
	8	1 }					
	29	2 }	00-05-40				
	236	का भाग }	00-47-52		236	"	00-36-00
	237	" }					
	238	1 }	00-27-00		237	"	00-20-00
	241	4					
	238	2	00-24-30		238	"	00-28-00
	240	का भाग	00-35-38		240	"	00-36-00
	241	1 }					
	241	2 }	00-08-64		241	"	00-08-00
	241	3 }					
	255	1	00-43-74		255	"	00-65-00
	256	का भाग }			256	"	00-32-00
	255	2 }	00-30-42				
	268	1	00-14-40		268	"	00-28-00
	269	3अ }	00-02-70				
	269	3ब }	00-19-44		269	"	00-22-00
	269	2 }	00-22-65				

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
बडगांव	14	का भाग	00-08-00

CORRIGENDUM

S.O. 3926.—In the Notification of Government of India Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/67/82-Prod dated 15th October, 1983 published under S.O. No. 3922 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 4007 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages-Vadgaon, for S. Nos. and areas shown in the

Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub-Section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read (Col-II)

For (Col-I)

PART-I

Village	S. No.	H. No.	Area	Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.				G. No.		
1	2	3	4	1	2	3	4
Vadgaon.	8	2	00-42-84	Vadgaon.	8	(pt)	00-55-00
	13	1	00-05-94		13	(pt)	00-73-00
	15	(pt)	00-14-40		15	(pt)	00-70-00
	27	(pt)	00-32-72		27	(pt)	00-40-00
	28-1	2	00-09-36				
	28-1	3	00-09-36		28	(pt)	00-36-00
	28-2		00-12-24				
	29	1	00-24-48				
	08	1			29	(pt)	00-32-00
	29	2	00-05-40				
	236	(pt)	00-47-52		236	(pt)	00-36-00
	37	(pt)	00-27-00				
	38	1			37	(pt)	00-20-00
	241	4	00-24-30				
	238	2			238	(pt)	00-28-00
	240	(pt)	00-35-38		240	(pt)	00-36-00
	241	1	00-08-64				
	241	2			241	(pt)	00-08-00
	241	3	00-47-74				
	255	1			55	(pt)	00-65-00
	256	(pt)	00-30-42		56	(pt)	00-37-00
	255	2					
	268	1	00-14-40		268	(pt)	00-28-00
	269	3A	00-02-70				
	269	3B	00-19-44		269	(pt)	00-27-00
	269	2	00-22-68				

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
Vadgaon	14	(pt)	00-08-00

[No. O-12016/67/82-Prod. II]

शुद्धि पत्र

का. आ. 3927—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखण्ड (II) दिनांक 18-6-1983 पृष्ठ क्रमांक 2497 और 2498 का. आ. संख्या 0-12016/59/83-प्रो. के अंतर्गत भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 2576 दिनांक 18-6-1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पार्सी लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)—अधिनियम, 1962 की धारा 3 उपधारा (I) के अधीन वर्णित गांव (i) कोलवडी (ii) ठाणकाम्भोर तहसील हवेली जिला पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम I के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

विम्बनिवृत्त अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पार्सी लाईन बिछाने का प्रयोजन अलार्डमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः विम्बनिवृत्त अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग I

कालम II पढ़ें

कालम I के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
कोलवडी	322	का भाग	00-09-00	कोलवडी	322	का भाग	00-09-00
	326	"	00-07-12		326	"	00-06-00
	327	"	00-10-44		327	"	00-02-00
	328	"	00-03-00		328	"	00-04-00
	331	"	00-03-60		331	"	00-04-00
	371	"	00-08-65		371	"	00-08-00
	372	"	00-13-68		372	"	00-07-00
	378	"	00-24-30		378	"	00-38-00
	397	"	00-04-50		397	"	00-07-00
	394	"	00-07-55		394	"	00-11-00
	395	"	00-05-40		395	"	00-05-00
	396	"	00-46-26		396	"	00-21-00
	387	"	00-08-82		387	"	00-12-00
	388	"	00-12-42		388	"	00-17-00
	389	"	00-13-50		389	"	00-13-00
	390	"	00-06-85		390	"	00-02-00
	312	"	00-02-00		312	"	00-04-00
	313	"	00-03-00		313	"	00-05-00

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
कोलवडी	300	का भाग	00-10-00
	301	"	00-22-00
	302	"	00-15-00
	303	"	00-14-00
	304	"	00-10-00
	306	"	00-09-00
	308	"	00-23-00
	307	"	00-07-00
	308	"	00-06-00
	310	"	00-05-00
	311	"	00-11-00
	325	"	00-01-00

अनुसूची

भाग 1

कालम II पढ़े

कालम 1 के लिए

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
लोणी का नोर	116	का भाग	00-09-67	लोणी का नोर	116	का भाग	00-06-00
	117	"	00-01-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-00		118	"	00-10-00
	120	"	00-04-00		120	"	00-11-00
	122	"	00-02-55		122	"	00-05-50

भाग II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
लोणी का नोर	92	का भाग	00-45-00
	93	"	00-18-00
	94	"	00-05-00
	95	"	00-07-00
	96	"	00-07-00
	104	"	00-11-00
	103	"	00-08-00
	112	"	00-14-00
	121	"	00-07-00

[सं. O—12016/59/83—प्रोड.]

CORRIGENDUM

S.O. 3927.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/59/83-prod, dated 18-6-83 published under S.O. No. 2576 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (II) at pages 2497 and 2498 issued under section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of Villages-1 Kolwadi and 2, Loni-Kalbhor Tahsil Haveli, District Pune.

for S. Nos. and areas shown in the column No. 1 of the schedule appended to this Corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 3 Sub-section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read (Col-II)

For- (Col-I)

PART-I

Village	S. No.	H. No.	Area	Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.				G. No.		
1	2	3	4	1	2	3	4
Kolwadi	322	(Pt.)	00-09-00	Kolwadi	322	(Pt.)	00-09-00
	326	"	00-07-92		326	"	00-06-00
	327	"	00-10-44		327	"	00-02-00
	328	"	00-03-00		328	"	00-04-00
	331	"	00-03-60		331	"	00-04-00
	371	"	00-08-65		371	"	00-08-00
	372	"	00-13-68		372	"	00-07-00
	378	"	00-14-36		378	"	00-13-00
	397	"	00-04-50		397	"	00-07-00
	394	"	00-07-55		394	"	00-11-00
	395	"	00-05-40		395	"	00-05-00
	396	"	00-46-26		396	"	00-11-00
	387	"	00-08-82		387	"	00-12-00
	388	"	00-12-42		388	"	00-17-00
	389	"	00-13-50		389	"	00-13-00
	390	"	00-06-85		390	"	00-02-00
	312	"	00-02-00		312	"	00-04-00
	313	"	00-03-00		313	"	00-05-00

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
1	2	3	4
Kolwadi	300	(Pt.)	00-10-00
	301	„	00-22-00
	302	„	00-15-00
	303	„	00-14-00
	304	„	00-10-00
	305	„	00-09-00
	306	„	00-23-00
	307	„	00-07-00
	308	„	00-06-00
	310	„	00-05-00
	311	„	00-11-00
	315	„	00-01-00

SCHEDULE

Read (Col.-II)

(For Co-I)

PART-I

Village	S.No./ G. No.	H. No.	Area	Village	S. No./G.No.	H. No.	Area
1	2	3	4	1	2	3	4
Loni-Kalbhor	116	(pt.)	00-09-67	Loni-Kalbhor	116	(pt.)	00-06-00
	117	„	00-01-00		117	„	00-03-00
	118	„	00-03-00		118	„	00-10-00
	120	„	00-04-00		120	„	00-11-00
	122	„	00-02-55		122	„	00-05-00

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.		
(1)	(2)	(3)	(4)
Loni-Kalbhor	92	(pt.)	00-45-00
	93	„	00-18-00
	94	„	00-05-00
	95	„	00-07-00
	96	„	00-07-00
	104	„	00-11-00
	103	„	00-08-00
	112	„	00-14-00
	121	„	00-07-00

[No. O-12016/59/83-Prod]

शुद्धि पत्र

क्रा. भा. 3928.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) दिनांक 8-9-1984 पृष्ठ क्रमांक 2684 और 2685 क्रा. भा. संख्या O-12016/59/83—प्रोड. के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 2889 दिनांक 8-9-1984 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)—अधिनियम, 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव (i) कोलवडी (ii) खानि किन्नोर तहसील हवेली जिला पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाइमेंट बदलने से अब न रहा है, अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 6 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

भाग 1

कालम II पढ़ें

कालम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
कोलावडी	322	का भाग	00-09-00	कोलावडी	322	का भाग	00-09-00
	326	"	00-07-12		326	"	00-06-00
	327	"	00-10-44		327	"	00-02-00
	328	"	00-03-00		328	"	00-04-00
	331	"	00-03-60		331	"	00-04-00
	371	"	00-08-65		371	"	00-08-00
	372	"	00-13-68		372	"	00-07-00
	378	"	00-24-30		378	"	00-38-00
	397	"	00-04-50		397	"	00-07-00
	394	"	00-07-55		394	"	00-11-00
	395	"	00-05-40		395	"	00-05-00
	396	"	00-46-26		396	"	00-21-00
	387	"	00-08-82		387	"	00-12-00
	388	"	00-12-42		388	"	00-17-00
	389	"	00-13-50		389	"	00-13-00
	390	"	00-05-85		390	"	00-02-00
	312	"	00-02-00		312	"	00-04-00
	313	"	00-03-00		313	"	00-05-00

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
	300	का भाग	00-10-00
	301	"	00-22-00
	302	"	00-15-00
	303	"	00-14-00
	304	"	00-10-00
	305	"	00-08-00
	306	"	00-23-00
	307	"	00-07-00
	308	"	00-06-00
	310	"	00-05-00
	311	"	00-11-00
	325	"	00-01-00

अनुसूची

भाग 1

कालम II पढ़ें

कालम 1 के लिए

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
खोणी कान्तोर	116	का भाग	00-09-67	खोणी कान्तोर	116	का भाग	00-06-00
	117	"	00-01-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-00		118	"	00-10-00
	120	"	00-04-00		120	"	00-11-00
	122	"	00-02-55		122	"	00-05-00

भाग II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणी काडनोर	92	का भाग	00-45-00
	93	"	00-18-00
	94	"	00-05-00
	95	"	00-07-00
	96	"	00-07-00
	104	"	00-11-00
	103	"	00-08-00
	112	"	00-14-00
	121	"	00-07-00

[सं. O—12016/59/83-प्रॉइ-I]

CORRIGENDUM

S.O. 3928.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/59/83-Prod. dated 8-9-84 published under S.O. No. 2889 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (II) at page 2084 & 2685 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1982 in respect of villages-1, Kolwadi and 2, Loni-Kaibhor Tahsil Haveli, Dist-Pune, for S. Nos.

and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub-Section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read (Col-II)				PART-I			For (Col-I)		
Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area		
	G. No.				G.No.				
Kolwadi	322	(pt)	00-09-00	Kolwadi	322	(pt)	00-09-00		
	326	"	00-07-92		326	"	00-06-00		
	327	"	00-10-44		327	"	00-07-00		
	328	"	00-03-00		328	"	00-04-00		
	331	"	00-03-60		331	"	00-04-00		
	371	"	00-08-65		371	"	00-08-00		
	372	"	00-13-68		372	"	00-07-00		
	378	"	00-24-36		378	"	00-38-00		
	397	"	00-04-50		397	"	00-07-00		
	394	"	00-07-55		394	"	00-11-00		
	395	"	00-05-40		395	"	00-05-00		
	396	"	00-46-26		396	"	00-21-00		
	387	"	00-08-82		387	"	00-12-00		
	388	"	00-12-42		388	"	00-17-00		
	389	"	00-13-50		389	"	00-13-00		
	390	"	00-06-85		390	"	00-02-00		
	312	"	00-07-00		312	"	00-04-00		
	313	"	00-03-00		313	"	00-05-00		

PART II

Village	S.No.	H. No.	Area
Kolwadi	300	(pt)	00-10-00
	304		00-22-00
	302		00-15-00
	303		00-14-00
	304		00-10-00
	305		00-09-00
	306		00-23-00
	307		00-07-00
	308		00-05-00
	310		00-05-00
	311		00-11-00
	325	"	00-01-00

SCHEDULE							
PART-I				For (Col-I)			
Read (Col-II)							
Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area
	G.No.				G.No.		
Loni-Kalbhor.	116	(pt)	00-09-67	Loni-Kalbhor	116	(pt)	00-06-00
	117	"	00-01-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-00		118	"	00-10-00
	120	"	00-04-00		120	"	00-11-00
	122	"	00-02-55		122	"	00-05-00
PART-II							
Village	S.No.	H.No.	Area				
	G.No.						
Loni-Kalbhor	92	(pt)	00-45-00				
	93	"	00-18-00				
	94	"	00-05-00				
	95	"	00-07-00				
	96	"	00-07-00				
	104	"	00-11-00				
	103	"	00-08-00				
	112	"	00-14-00				
	121	"	00-07-00				

[No. O.-12016/59/83-Prod. I]

शुद्धि पत्र

का. आ. 3929.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 26-1-85 पृष्ठ क्रमांक 286 का. आ. संख्या 12016/1/85-ONGD 4 के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) को अधिसूचना संख्या 292 दिनांक 26-1-85 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव अर्द्ध तहसिल पन्वेल जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नंबर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कॉलम के बदले अनुसूची में खसरा नंबर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन आलाइमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

कॉलम 11 पढ़ें				भाग I			
				कॉलम 1 के लिए			
गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
अर्द्ध	116	9	00-03-25	अर्द्ध	116	का भाग	00-07-00
	117	1	00-33-00				
	117	2+3+7	00-10-50		117	"	00-62-00
	117	4+8	00-00-25				
	125	1 (1)	00-15-00		125	"	00-09-00
	125	1 (2)	00-00-25				
	126		00-06-00		126	"	00-03-00
	127	"			127	"	00-22-00
	128	"	00-24-50		127	"	00-11-00
	129	"	00-05-50		129	"	00-01-00

भाग II

गाँव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
अदई	6	का भाग	00-01-00
	114	"	00-05-00
	115	"	00-09-00
	131	"	00-16-00

[सं. O-12016/1/85-ओएनजी-डी 4]

CORRIGENDUM

S.O. 3929.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. 12016/1/85-ONGD-4 dated, 26th January, 1985, published under S.N. No. 292 in the Gazette of India, Part II, section 3, Sub-section (ii) at page 286, issued under Section 3 Sub-Section (i) of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, in respect of village Adace, Tahsil Panvel, District Raigad,

State Maharashtra, for S. Nos. and areas shown in the column No. 1 of the schedule appended to this corrigendum, read the S. Nos. and areas as shown in the column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notifications under section 3 Sub-Section (i) referred to above.

SCHCEDULE

Read (Col-II)				PART-I				Read (Col-I)			
Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area
	G.No.				G.No.				G.No.		
Adace	116	9	00-03-25	Adace	116	(pt)	00-07-00				
	117	1-A	00-33-00								
	117	2+3+7	00-10-50		117	"	00-52-00				
	117	4-A+8	00-00-25								
	125	1 (1)	00-15-00		125	"	00-09-00				
	125	1 (1)	00-00-55								
	126	(pt)	00-06-00		126	"	00-03-00				
	127	"			127	"	00-22-00				
	128	"	00-14-50		128	"	00-11-00				
	129	"	00-05-50		129	"	00-01-00				
PART-II											
Village	S.No.	H.No.	Area								
Adace	6	(pt)	00-01-00								
	114	"	00-05-00								
	115	"	00-09-00								
	131	"	00-16-00								

[No. O-12016/1/85-ONG-D4]

शुद्धि-पत्र

का.प्र. 3930.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 11-5-85 पृष्ठ क्रमांक 2373 और 2374 का.प्र.संख्या 12016/1/85-ओ.एन.जी.डी 4 के अंतर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 1979 दिनांक 11-5-1985 के अंतर्गत—पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)—अधिनियम, 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन वर्णित गाँव अदई तहसील पनवेल जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 1 के बगले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कॉलम 2 में दो नई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से अब नहीं रहा है। अब, अतः, निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 6 के उपधारा (i) के अधिसूचना की अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची

कॉलम II पढ़ें

भाग I

कॉलम I के लिये

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
भदई	116	9	00-03-25	भदई	116	का भाग	00-07-00
	117	1	00-33-00				
	117	2+3+4	00-10-50		117	"	00-52-00
	125	1(1)	00-15-00				
	125	1(2)	00-00-25		125	"	00-09-00
	126	का भाग	00-06-00		126	"	00-03-00
	127	"	00-24-50		127	"	00-22-00
	128	"			128	"	00-11-00
	129	"	00-05-50		129	"	00-01-00

भाग II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
भदई	6	का भाग	00-01-00
	114	"	00-05-00
	115	"	00-09-00
	131	"	00-16-00

[सं. O-12016/1/85-ओएनजे-का 4-I]

CORRIGENDUM

S.O. 3930.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. 12016/1/85-ONG-D-4 dated 11th May, 1985 published under S.O. No. 1979 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at pages 2373 & 2374 issued under section 6 Sub-section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Line (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, in respect of village Adace, Tahsil Panvel, District-Raigad, State Mahara-

shtra, for S. Nos. and areas shown in the column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read the S. Nos. and areas as shown in the column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notifications under section 6 Sub-Section (i) referred to above.

SCHEDULE

Road (Col-II)

PART-I

For (Col-I)

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area	Village	S.No. G.No.	H.No.	Area
Adace	116	9	00-03-25	Adace	116	(pt)	00-07-00
	117	1-A	00-33-00				
	117	2+3+7	00-10-50		117	"	00-52-00
	117	4-A+8	00-00-25				
	125	1 (1)	00-15-00		125	"	00-09-00
	125	1 (2)	00-00-25				
	126	(pt)	00-06-00		126	"	00-03-00
	127	"	00-24-50		127	"	00-22-00
	128	"			128	"	00-11-00
	129	"	00-05-50		129	"	00-01-00

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
Adace	6	(pt)	00-01-00
	114	"	00-05-00
	115	"	00-09-00
	131	"	00-16-00

[No. O-12016/1/85-ONG-D-4-II]

गुद्धि पत्र

का. आ. 3931.—भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 8-9-84 पृष्ठ क्रमांक 2685 और 2686 का. आ. संख्या 0-12016/98/84/ओ. एन. जो. डी.-4 के अंतर्गत भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) का अधिसूचना संख्या 2890 दिनांक 8-9-1984 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)—अधिनियम, 1962 की धारा 3 उपधारा (i) के अधिन वर्णित गांव (i) कोलबडी (ii) लोणी कालभोर तहसिल हवेली जिला पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़े,

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पार्श्व लाईन बिछाने का प्रयोजन अलार्डमेंट बदलने से अब न रहा है अब अनः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 3 के उपधारा (i) के अधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है।

अनुसूची				अनुसूची			
भाग I				भाग I			
कालम II पढ़े				कालम I के लिए			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
कोलबडी	312	का भाग	00-08-00	कोलबडी	312	का भाग	00-10-00
	313	"	00-48-00		313	"	00-58-00
	168	"	00-09-00		168	"	00-09-00

भाग II

अनुसूची				अनुसूची			
भाग I				भाग I			
कालम II पढ़े				कालम I के लिए			
गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
लोणी कालभोर	51	का भाग	00-37-30	लोणी कालभोर	51	का भाग	00-31-20
	53	"	00-28-20		53	"	00-27-00
	68	"	00-03-12		68	"	00-03-90
	67	"	00-02-76		67	"	00-03-75
	63	"	00-02-00		63	"	00-04-00
	65	"	00-02-68		65	"	00-06-75
	78	"	00-07-32		78	"	00-04-00
	91	"	00-08-00		91	"	00-02-00
	90	"	00-10-20		90-	"	00-08-25
	116	"	00-01-25		116	"	00-01-25
	117	"	00-02-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-12		118	"	00-09-50
	120	"	00-02-24		120	"	00-07-00
	121	"	00-02-25		121	"	00-02-25
	177	"	00-04-59		177	"	00-06-50

भाग II

गांव	खसरा नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल
लोणी कालभोर	50	का भाग	00-01-25
	64	"	00-03-00
	89	"	00-03-00
	85	"	00-03-00
	119	"	00-02-00
	121	"	00-10-00
	123	"	00-01-00
	178	"	00-01-75
	84	"	00-03-00
	83	"	00-02-50

CORRIGENDUM

S.O. 3931.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. 12016/98-84-ONGD-4 dated 8-9-84 published under S.O. No. 2890 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at pages 2685 & 2686 issued under Section 3 Sub-section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages-1, Kolwadi and 2, Loni-Kalbhor, Tahsil Haveli, District Pune,

for S. Nos. and areas shown in the column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said Schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended Schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the Schedule appended to the Notification under Section 6, Sub-section (i) referred to above.

SCHEDULE

Read Col. (II)				PART-I				For Col. (I)		
Village	S.No.	H. No.	Area	Village	S.No.	H. No.	Area			
Kolwadi	312	(pt)	00-08-00	Kolwadi	312	(pt)	00-10-00			
	313	"	00-48-00		313	"	00-58-00			
	167	"	00-09-00		167	"	00-09-00			

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
olwadi	NIL		

SCHEDULE

Read Col. (II)				PART-I				For Col. (I)		
Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H.No.	Area			
	G.No.				G.No.					
Loni-Kalbhor	51	(pt)	00-37-30	Loni-Kalbhor	51	(pt)	00-31-20			
	53	"	00-28-20		53	"	00-27-00			
	68	"	00-03-12		68	"	00-03-00			
	67	"	00-02-76		67	"	00-03-75			
	63	"	00-02-00		63	"	00-04-00			
	65	"	00-02-68		65	"	00-06-75			
	78	"	00-07-32		78	"	00-04-00			
	91	"	00-08-88		91	"	00-02-00			
	90	"	00-10-20		90	"	00-08-25			
	116	"	00-01-25		116	"	00-01-25			
	117	"	00-02-00		117	"	00-03-00			
	118	"	00-02-12		118	"	00-09-50			
	120	"	00-02-24		120	"	00-07-00			
	121	"	00-02-25		121	"	00-02-25			
	177	"	00-04-59		177	"	00-06-50			

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
Loni-Kalbhor	50	(pt)	00-01-25
	64	"	00-03-00
	89	"	00-03-00
	85	"	00-03-00
	119	"	00-02-00
	121	"	00-10-00
	123	"	00-01-00
	178	"	00-01-75
	84	"	00-03-00
	83	"	00-02-50

[No. O-12016/98/84-ONG-D-4]

शुद्धि-पत्र

का.अ. 3932.—भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 19-1-85 पृष्ठ क्रमांक 158 का.अ. संख्या ओ-12016/98-84-ओएनजी-डी-4 के अन्तर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 170 दिनांक 19-1-85 के अन्तर्गत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन वर्णित गांव (1) कोलवडी (2) लोनी-कालभोर, तहसील हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र के अन्तर्गत अधिसूचना में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दो गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूचा के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन बिछाने का प्रयोजन अलाईमेंट बदलने से अब न रहा है, अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि, धारा 6 के उपधारा (i) का अधिमूचना को अनुसूचा से कम कर दी गई है।

अनुसूची भाग I				कालम I के लिये			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
कोलवडा	312	का भाग	00-08-90	कोलवडा	312	का भाग	00-10-00
	313	"	00-48-00		313	"	00-58-00
	167	"	00-09-00		167	"	00-09-00

भाग--II

कोलवडा	—	कुछ नहीं
--------	---	----------

अनुसूची भाग I				कालम I के लिये			
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणा-कालभोर	51	का भाग	00-37-30	लोणा-कालभोर	51	का भाग	00-31-20
	53	"	00-28-20		53	"	00-27-00
	68	"	00-03-12		68	"	00-03-00
	67	"	00-02-76		67	"	00-03-75
	63	"	00-02-00		63	"	00-04-00
	65	"	00-02-68		75	"	00-06-75
	78	"	00-07-32		78	"	00-04-00
	91	"	00-08-88		91	"	00-02-00
	90	"	00-10-20		90	"	00-08-25
	116	"	00-01-25		116	"	00-01-25
	117	"	00-02-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-12		118	"	00-09-50
	120	"	00-02-24		120	"	00-07-00
	121	"	00-02-25		121	"	00-02-25
	177	"	00-04-59		177	"	00-06-50

भाग-II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
लोणा-कालभोर	50	का भाग	00-01-25
	64	"	00-03-00
	89	"	00-03-00
	85	"	00-03-00
	119	"	00-02-00
	121	"	00-10-00
	123	"	00-01-00
	178	"	00-01-75
	84	"	00-03-00
	83	"	00-02-50

ह ०/- सक्षम प्राधिकारी

[मं. ओ-12016/98/84-ओ एन जो -डो-4-I]

पा. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

S.O. 3932.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/98/84-ONGD-4 dated 19th January, 1985 published under S.O. No. 170 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 158 issued under Section 6 Sub-section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages 1) Kolwadi and (2) Loni-Kalbhor, Tahsil-Haveli,

District-Pune for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6, Sub-section (i) referred to above.

SCHEDULE

PART I

Read (Col. II)

For (Col. -I)

Village	S.No.	H. No.	Area	Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.				G. No.		
Kolwadi	312	(pt)	00-08-00	Kolwadi	312	(pt)	00-10-00
	313	"	00-48-00		313	"	00-58-00
	167	"	00-09-00		167	"	00-09-00

PART-II

NIL

Village	S. No.	Ho. No.	Area	Village	S. No.	H. No.	Area
	G. No.				G. No.		
Loni-Kalbhor	51	(pt)	00-37-30	Loni-Kalbhor	51	(pt)	00-31-20
	53	"	00-28-20		53	"	00-27-00
	68	"	00-03-12		68	"	00-03-00
	67	"	00-02-76		67	"	00-30-75
	63	"	00-02-00		63	"	00-04-00
	65	"	00-02-68		65	"	00-06-75
	78	"	00-07-32		78	"	00-04-00
	91	"	00-08-88		91	"	00-02-00
	90	"	00-10-20		90	"	00-08-25
	116	"	00-01-25		116	"	00-01-25
	117	"	00-02-00		117	"	00-03-00
	118	"	00-03-12		118	"	00-09-50
	120	"	00-02-24		120	"	00-07-00
	121	"	00-02-25		121	"	00-02-25
	177	"	00-04-59		177	"	00-06-50

PART-II

Village	S.No.	H. No.	Area
Loni-Kalbhor	50	(pt)	00-01-25
	64	"	00-03-00
	89	"	00-03-00
	85	"	00-03-00
	119	"	00-02-00
	121	"	00-10-00
	123	"	00-01-00
	178	"	00-01-75
	84	"	00-03-00
	83	"	00-02-50

Sd/- Competent Authority

[No. O-12016/98/84-ONG-D4-I]

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1986

का.आ. 3933.—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा गुजरात सरकार के परामर्श में डा. ओ. पी. गुप्ता निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 16 सितम्बर, 1986 तथा आकस्मिक रिक्ति पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं. का. आ. 138 में आगे निर्म्तलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में “धारा 3(1)(क) के अधीन मनोनीत” शेष के अंतर्गत क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्—

“(4) डा. ओ. पी. गुप्ता,

निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा,

अहमदाबाद।”

[संख्या बी. 11013/6/86-एम. ई. (पी)]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 3933.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and in consultation with the Government of Gujarat have nominated Dr. O. P. Gupta, Director of Health, Medical Services and Medical Education to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification for a period upto 16th September, 1986 in a casual vacancy.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Ministry of Health S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading “Nominated under section 3(1)(a)”, for serial number 14 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“14. Dr. O. P. Gupta,
Director of Health, Medical Services,
and Medical Education,
Ahmedabad”.

[No. V-11013/6/86-ME(P)]

New Delhi, the 27th October, 1986

S.O. 3934.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the medical qualification ‘Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery’ granted by the Sind University, Pakistan, shall be a recognised Medical qualification from the date of issue of this notification in the Official Gazette, for the purposes of the said Act.

[No. V-11016/5/85-ME (P)]

नई दिल्ली 31 अक्तूबर, 1986

का. आ. 3935.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा निदेश देती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बायना, आस्ट्रीया द्वारा प्रदत्त “एम.डी.” चिकित्सा ग्रहण उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी होने की तारीख से मान्यता प्राप्त चिकित्सा ग्रहण होगी।

[संख्या बी. 11016/1/85-एम. ई. (पी)]

शिवदायाल, उप सचिव

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3935.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the medical qualification ‘M.D.’ granted by the University of Vienna, Austria, shall be a recognised medical qualification from the date of issue of this notification in the Official Gazette, for the purposes of the said Act.

[No. V-11016/1/85-ME (P)]

SHIV DAYAL, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

(पुरातत्व)

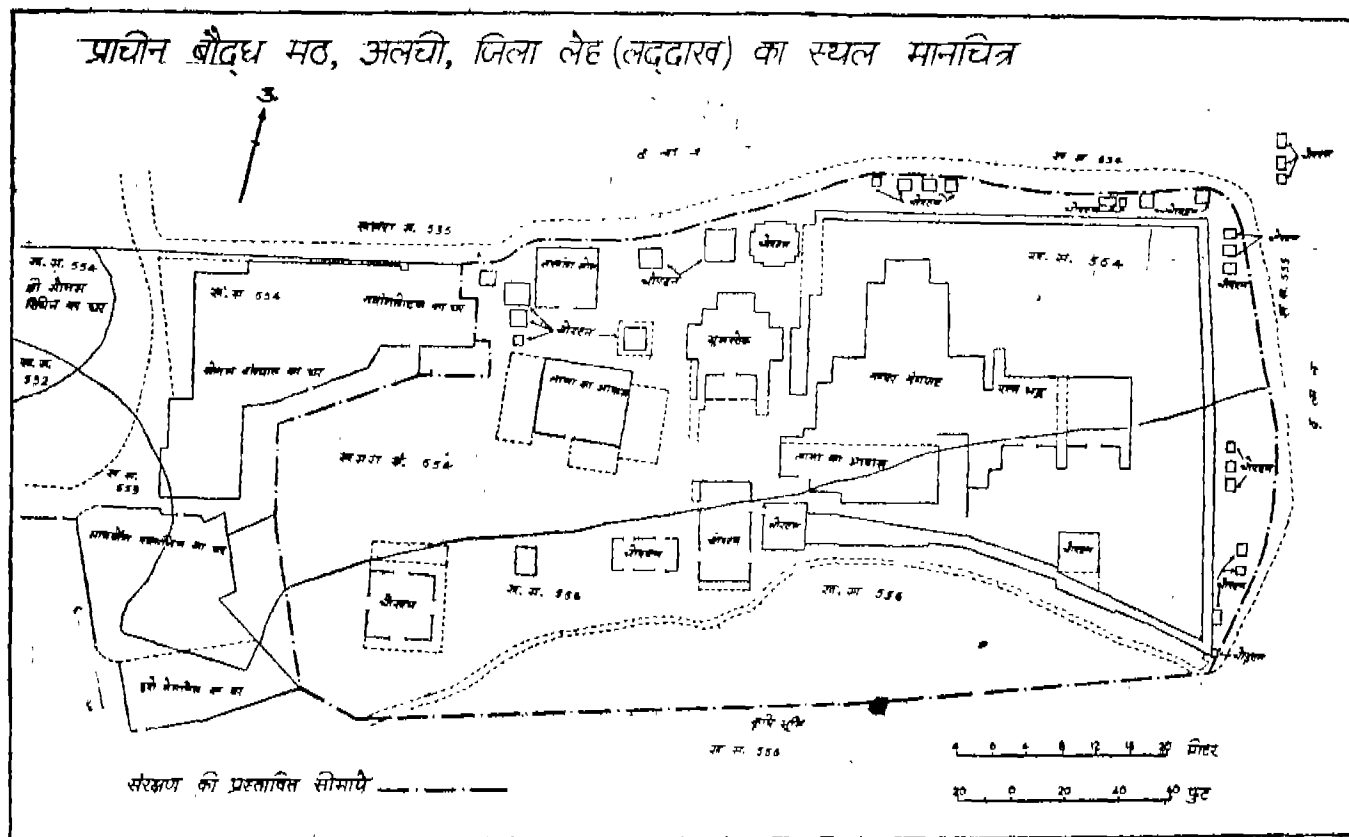
का. आ. 3936.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग, 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 मई, 1985 में प्रकाशित संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का.आ. 2074 तारीख 27 अप्रैल, 1985 को अधिकांश करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किये जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लॉट संख्यांक
1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	लद्दाख	लेह	अलची	नोचे प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 554 और 556 के भागों में समाविष्ट बौद्ध मठ	नोचे प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 554 और 556 के भाग
क्षेत्र	सोमा	स्वामित्व	टिप्पणियाँ		
7	8	9	10		
0.4095 हैक्टेयर	पूर्व : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 555 दक्षिण : सर्वेक्षण प्लॉट संख्यांक 556 का शेष भाग उत्तर : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 534 और 535 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 554 और 556 के शेष भाग	निजी	धार्मिक उपयोग में		



[सं. 2/38/76-एम.]

एम.एस. नागराजाराव, महानिदेशक

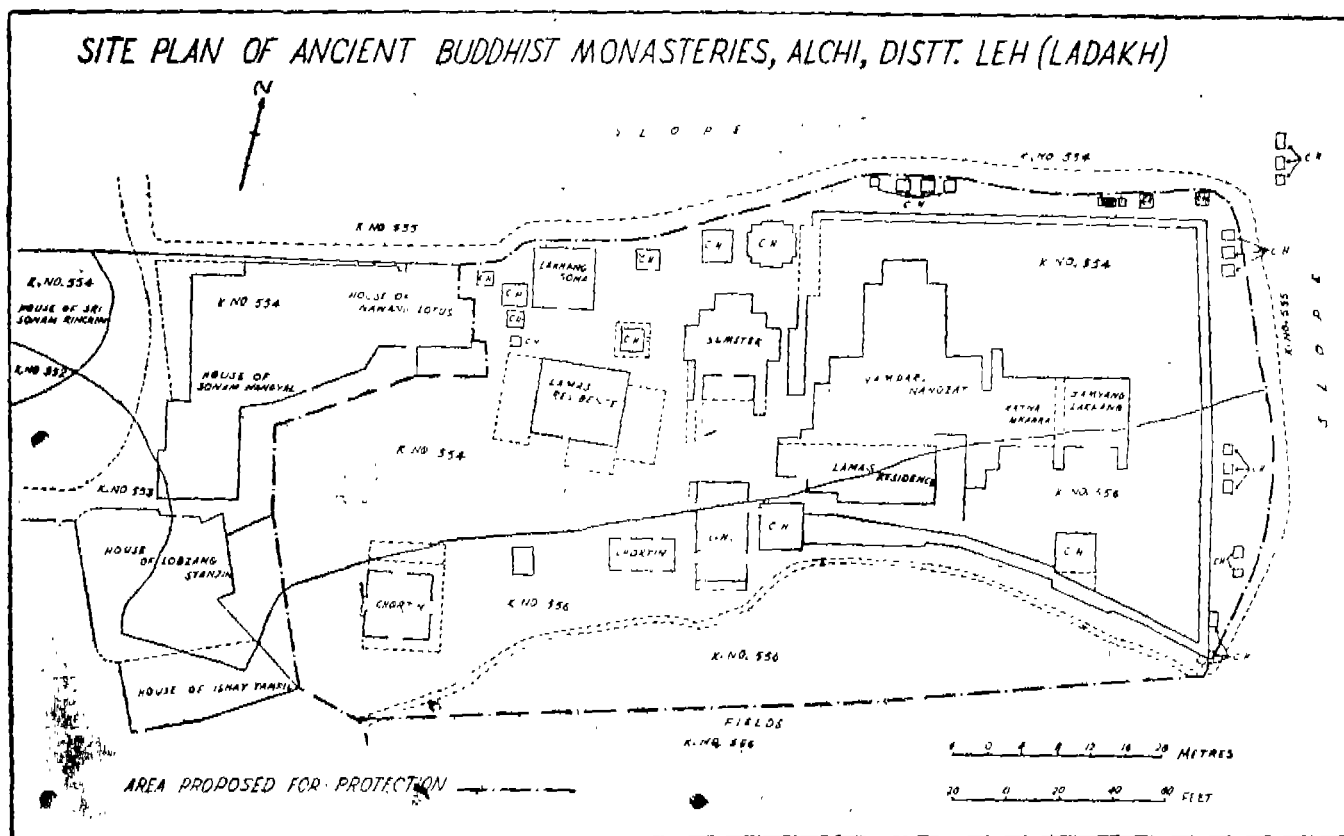
Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and in supersession of the notification of Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 2074 dated the 27th April, 1985 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th May, 1985, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu & Kashmir	Ladakh	Leh	Alchi	Buddhist Monasteries comprised in parts of Survey plot Nos. 554 and 556 as shown in the site plan reproduced below.	Part of Survey plot Nos. 554 and 556 as shown in the site plan reproduced below.	0.4095 Hectares	East.—Survey Plot No. 555 South.—Remaining portion of Survey plot No. 556 North.—Survey plot Nos. 534 and 535 West.—Remaining portions of Survey plot Nos. 554 and 556.	Private	in religious use



संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

का. आ. 3937.—स्वाधीन आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने नन्नियूर पुदूर टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू सर्किल, में निम्नोक्त 26-11-1986 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-26/86-पी. एच. बी.]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 11th November, 1986

S.O. 3937.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 26-11-86 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nanniyur Pudur Telephone Exchange Tamil Nadu Telecom Circle.

[No. 5-26/86-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1986

का.आ.-3938—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिवचना संख्या का.आ. 898, तारीख 16 फरवरी, 1986 के क्रम में नव मंगलौर पत्तन न्यास, मंगलौर के अधीन कर्मशाला और मोटर मरम्मत कर्मशाला तथा सविस केन्द्र को 1 अक्तूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी:—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं;

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधाओं को, जो ऐसी प्रमुविधाएँ हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसम्पाक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/47/85-एस. एस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को

मूलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3938.—In exercise of the powers conferred by section 90 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 898 dated 16th February, 1986, the Central Government hereby exempts the employees of the Workshop and the Auto Repair Shop and Service Station under the New Mangalore Port Trust, Mangalore from the operation of the said Act for a further period with effect from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this Notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/47/85-SS I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 3939—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड, पंचकुला हरियाणा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 मई, 1985 से 30 अप्रैल 1986 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रख गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या

अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उस अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का व्यक्तिगत कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/32/85-एस.एस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 3939.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts M/s. Bharat Electronics Limited, Panchkula, Haryana, from the operation of the said Act for a period of one year from 1st May, 1985 upto and inclusive of the 30th April, 1986.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this Notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/32/85-SS I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली 10 नवम्बर 1986

क्र० आ० 3940—मैसर्स—हिन्दोस्तान मोटर्स, लि०, पोस्ट ऑफिस हिन्दमोटर, जिला-हृगली, पश्चिम बंगाल (इल्यु.बी./370) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का.ग्रा. 4576 तारीख 22-11-1983 के अनुसरण में और

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 17-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 16-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाल जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपने चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदियह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/227/83-पो.एफ/एस एस-2]

New Delhi, the 10th November, 1986

S.O. 3940.—Whereas Messrs. Hindustan Motors Limited, P.O. Hind Motor, District Hooghly, West Bengal (WB/370) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4576 dated the 22-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17-12-1986 upto and inclusive of the 16-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee, legal heirs of the deceased member entitled for it and any case within one month from the receipts of claim complete in all respects.

[No. S-35014/227/83 PF.II-SS-II]

का. प्रा. 3941:—मैमर्स पोलिसैत लिमिटेड, 7 जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-400020 (एन. एच./5207

जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए, आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं व ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभोग हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 4717 तारीख 24-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-बट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाय जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रह सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगन हो जाने दिया जाता है तो छूट रह सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाव को प्राप्त के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/242/83-पी.एफ.-2/एसएस-2]

S.O. 3941.—Whereas Messrs. Polycham Limited, 7, Janshedji Tata Road, Bombay-400020 (MH/5207) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4717 dated the 24-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/242/83-PF.II.SS.II]

का.आ. 3942:--मैसर्स नूतन तागरिक सहकारी बैंक लि. बिकटोरिया जुबली हस्पताल के सामने, डा० मोतीभाई मार्ग, पंचकुबा, अहमदाबाद (जी.जे./4694), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसके इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना हों, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4655 तारीख 24-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-12-1988 से तीन व की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पढ़ने ही सदस्य है, उस के स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में सन्देश्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशितों को प्रति-कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन

के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगन हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के ना - निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों की उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/244/83-पी.एफ.-2/एस एस-2]

S.O. 3942.—Whereas Messrs Nutan Nagrik Sahakari Bank, Limited, Opposite Victoria Jubilee Hospital, Dr. Motibai Marg, Panchkua, Ahmedabad (GJ/4694) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4655 dated the 24-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-

missioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/244/83-PF.II-SS.II]

का. आ. 3943 :—मैसर्स इन्डियन ग्रांसीजन लि., लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर, पश्चिम, बम्बई-400086 (एम.एच./1172) और अपने ग्रांसीजन हाऊस, पी-34,

ताराताल रोड, कलकत्ता-700053 स्थित रजिस्टर्ड प्राक्सि सहित, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 312 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य, निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास के समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संशय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या का भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुख्यालय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाधक आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दाय करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी राशि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम का दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न द गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का

सम्बन्धित तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के मातर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/252/86-एस एस-2]

S.O. 3943.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkoper West Bombay (MH/1172) including its registered office at Oxygen House, P. 34, Tara-tala Road, Calcutta-700053 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 312 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/252/86-SS. II]

का. आ. 3944—मैमर्स सायल मैनिफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन, 876, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना-3 (पी.एन./5043), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी मूल्यक अभिदाय या प्रेमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उभावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के समान उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसे सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के मातर संदाय करेगा जो केन्द्रीय

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने का व्यवस्था करेगा जिसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किस कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उक्त रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रत्येक के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुष्टियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निवृत्त तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यवधत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014/253/86-एसएस-2]

S.O. 3944.—Whereas Messrs Sayal Manufacturing & Trading Corporation, 876, Industrial Area-A, Ludhiana-3. (PN/5043) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submissions of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(253)86-SS. II]

का.आ. 3945.—मैसर्स मोहन बोटलिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड, 186, जी. टी. रोड, धनडारी कलान, लुधियाना (पी. एन./7557) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किम बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग्य हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखागा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसे अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाली सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि किये जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर हा. स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वशा

में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दे से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किय गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंगत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस - 35014 (254) /86-एसएस-2]

S.O. 3945.—Whereas Messrs Mohan Bottling Company Private Limited 186, G. T. Road, Dhandari Kalan, Ludhiana, (PN/7/557) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment

from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under this said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

का. आ. 3946.—मैसर्स राजीव मटल इंडस्ट्रीज, 3-सी, टैक्सटाईल कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया-ए, लुधियाना-3 (पी. एन./3385) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ब्राब्र

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों, में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एम् - 35014 (255)/86 - एम् एम् - 2]

S.O. 3946.—Whereas Messrs Rajeev Metal Industries 3-C, Textile Colony, Industrial Area-A, Ludhiana-3 (PN/3385) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of

Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the

benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/(255)/86-SS-II]

का. आ. 3947.—संसद राजीव इंजीनियरिंग वर्क्स, 2-सी, ट्रेक्सटाईल कालोनी, इन्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना (पी. एन. / 9867) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 को उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसे पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहव्यय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेष हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा 17 को उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के अंतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम का धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारियों भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संभर करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होनी जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यय-गन हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई

होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होती। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

3.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की वसालत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वसालत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस - 35014 (256)/86 - एस एस - 2]

S.O. 3947.—Whereas Messrs Rajeev Engineering Works, 3-C, Textile Colony, Industrial Area-A, Ludhiana-3 (PN) 9867) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation..

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/(256)/86-SS-II]

नई दिल्ली 14 नवम्बर, 1986

का. आ. 3948.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1053 के क्रम में हिन्दुस्तान एण्टोवायटिक्स लि., पिम्परी, पुणे को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि को वापत देने योग्य ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारि,—

(i) धारा 44 की उपधारा (i) के अधीन उक्त अवधि के लिए दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों

को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुद्धि-धाओं को, जो ऐसी प्रसुद्धि-धाएँ हैं जिनके प्रति फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भार-साधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संशय से संबंधित ऐसे लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारि के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या मेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारि के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबह, या अन्य दस्तावेज को नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एम-38014/42/85-एन. एन.-1]

ए. के. मट्टगई, अवर सचिव

संघटक/कार्यक स्थापन

इस मामले में छूट का भूतलज प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाह करने में समय लगा था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलज प्रभाव देने में किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 14th November, 1986

S.O. 3948.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91-A of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the Notification No. S.O. 1053 dated the 21st February, 1985, the Central Government hereby exempts the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Pune, from the operation of the said Act for a further period of one year from 1st July, 1985 upto and inclusive of the 30th June, 1986.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration which exemption is being granted under this notification; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to :—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No S-38104/42/85-SSI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

1086 GI/86--7

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1986

का. अ. 3949.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, न्यू मैंगलोर पोर्ट के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, बंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करत है, जो केन्द्र सरकार को 27-10-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th November, 1986

S.O. 3949.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby published the award of the Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the New Mangalore Port and their workman which was received by the Central Government on the 27th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA BANGALORE

Dated this the 20th day of October, 1986

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer.
Central Reference No. 7 of 1982

I PARTY

The General Secretary,
New Mangalore Port &
Dock Workers' Union,
Room No. 97, Central,
Market Building,
A. S. Pai Cross Road,
Mangalore, 1.

Vs.

II PARTY

The Chief Engineer &
Administrator,
New Mangalore Port,
Panambur, Mangalore-10.
II (a) The Chairman,
New Mangalore Port Trust,
Panambur, Mangalore.

APPEARANCES :

For the I Party.—Shri H. Umanath Nayak, Member, AITUC., D. K. Dist. Mangalore.

For the II Party.—Shri K. S. Bhat, Advocate, Mangalore.

REFERENCE :

(Government Order No. L-45015/2/78-D. IV(A) dt. 7-8-1982).

AWARD

The Central Government after forming an opinion that an industrial dispute exists between the above parties has referred this dispute for adjudication in exercising the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 to adjudicate on the schedule stated herein below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of New Mangalore Port is justified in increasing the working hours from 7 to 8 of the work charged employees transferred on 1-8-1977 to regular establishment on ad-hoc basis? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The II Party management in justification of the action taken by them have contended in their statement that the New Mangalore Harbour Project was started in the year 1962 with the creation of a field division. During the project stage a number of workers had to be engaged temporarily for civil and mechanical engineering works and they were brought on what is called as work-charged establishment. Their service condition are as provided in C.P.W.D. Manual Volume III. The words 'work-charged establishment' was defined as :—

"Broadly speaking work charged establishment means that establishment whose pay, allowances etc., are directly chargeable to 'works'. Work charged staff is employed on the actual execution of a specific work, sub works of a specific work etc. The cost of entertainment of work charged establishment should invariably be shown as a separate sub-head of the estimate for a work. In other respects the work charged staff is quite comparable to the regular categories."

3. The working hours of employees on the regular establishment has always been 8 hours a day. Ever since the inception, the number of working hours of employees in 'work charged establishment' was 8 hours. To fall in line with the regulation under C.P.W.D. Manual Volume III, the II Party thought it desirable to reduce the working hours from 8 hours to 7 hours with effect from 16-6-1976. The port was declared as a Major Port from 4-5-1974. Thereafter the workers of work-charged establishment began demanding that they should be absorbed in the regular establishment so that they can get all the benefits of regular establishment. After some negotiations an industrial dispute was raised and ultimately a settlement was arrived at under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act before the Assistant Labour Commissioner, Bangalore on 28-6-1977, wherein it was agreed by the management to transfer and absorb all the employees who were in the work charged establishment as on 1-1-76 to the regular establishment. Though it was agreed to implement the same by 1-8-77 there were some administrative difficulties, that is, the relevant Recruitment Rules required amendment and the same was to be done by the Central Government. The amendment could not be effected as early as expected and meanwhile the pressure on the part of the workers, as a *via media*, in order to help work charged employees, it was decided to transfer them to the regular establishment on ad hoc basis with effect from 1-8-77 pending approval to the Recruitment Rules. Consequently upon this transfer the said employees began to enjoy almost all the benefits of the regular employees. This arrangement was in compliance with the demand of the employees.

4. They have further contended that after their transfer they started getting benefits as if they are regular employees and therefore their working hours have to fall in line with that of regular employees that is 8 hours per day which is a condition of service. The work charged employees cannot claim only the benefits without the obligations. The management was then advised that the number of working hours of 'workcharged' employees when transferred to regular establishment will automatically be raised from 7 hours to 8 hours a notice under Section 9-A was given on 30-7-1977. This was opposed by the employees and the employees insisted that their working hours should not be changed even though they were transferred to the regular establishment on ad-hoc basis. All the employees transferred to regular establishment on ad-hoc basis has since been regularised with effect from 1-12-1979/21-12-1979.

5. It is further contended that there is no change in conditions of service and increase in working hours from 7 hours to 8 hours per day was only an incident of being transferred to the regular establishment and doing out door work.

6. It is further contended that without prejudice the II Party is justified in effecting the said change and it has not caused any prejudice to the I Party workers. In fact their working hours upto 16-6-76 was 8 hours and the I Party had no grievance about the same. To keep two types of working hours in the regular establishment doing out door work will create anomaly and discrimination which would have lead to new problems. In all major port Trusts it is 8 hours duty for the outside staff. They prayed to reject the reference with costs.

7. The I Party union in their claim statement which they filed after the objection statement of the II Party, have contended that the concerned workers were taken on work charged basis by the Administrator of the II Party in or about 1963. These workers were governed by the C.P.W.D. Rules. Till about 1976 these workers were not given any

benefits not even the over-time wages for the over time work extracted from these workers. These workers were made to work 8 hours a day though C.P.W.D. Manual prescribed only 7 hours work per day.

8. They have denied that the management has reduced the working hours from 8 to 7 of their own accord. On the other hand they had to do it when they were forced to make themselves understand what they were doing was nothing but illegal. Thus the management was doing an illegal act from 1963 upto 16-6-1975. Actually these workers had to raise disputes to get atleast a part of over time wages for the overtime work they had no other than this over time work of one hour every day. They have demanded over time wages for this one hour but it was denied to them.

9. The workers pressed for their regularisation and the II Party reluctantly agreed to regularise them with effect from 1-4-1976. But the same was not done as agreed but they were regularised on ad-hoc basis with effect from 1-8-1977. Since then the workers never demanded for the raising of their working hours. Their services being regularised with effect from 1-12-79/21-12-79, they were entitled to work only for 7 hours a day as they were work-charged workers.

10. It is further contended that there was no proper notice under Section 9-A of the Industrial Disputes Act when the working hours changed from 7 to 8 hours a day and this change involved a change in the service conditions of the workers regarding the working hours and hence Section 9-A notice was imperative. There was no justification to increase the working hours from 7 to 8 hours a day till these work charged workers were regularly regularised. Hence they prayed to grant these workers overtime wages for the one hour extra work they had done since their appointment and more particularly from 1-8-1977 upto 1-12-1979/21-12-1979 with the cost of this proceedings.

11. Since there was no scope to frame any additional issues, the parties have been directed to lead their evidence on the points of dispute. The I Party have examined the Assistant Secretary as MW-1 and the documents Ext. M-1 to M-6 are marked. On behalf of the I Party one Assistant Foreman was examined as WW-1 and closed their evidence. On the basis of both oral and documentary evidence the learned counsels have addressed their arguments.

12. The contentions of the I Party union on the basis of their pleadings, appears to be that these work charged employees having worked 8 hours per day from their appointment and more particularly from 1-8-77 when they have been appointed on ad hoc basis till they have been regularised, should be treated as one hour extra work every day and over time wages should be granted.

13. The contentions of the II Party is to honour the demand of these work-charged employees they have been provided the job of a permanent employees on ad hoc basis from 1-8-77 and after amendment of the rules they have been regularised subsequently hence from the date of their ad-hoc appointment, they are entitled to work 8 hours per day in par with the other permanent workmen working in the Port.

14. MW-1 has deposed that the Harbour project was started in 1962 and it was called as field division. They have appointed temporary employees on work-charged basis according to the Central P.W.D. Manual. These category should work for 7 hours but they were working for 8 hours. After the management came to know the working hours of these workmen it was reduced to 7 hours per day.

15. He has further deposed that on 4-5-74 the Central Government has declared the Mangalore Port as a major port. During June 1977 all these work charged workmen have demanded to regularise their appointment. On this point, the conciliation was taken place and a settlement was arrived as per Ext. M-1. It was agreed that the employees who are on roll as on 1-4-76 will be regularised from 1-8-77. To effect regularisation, the management had a technical problem of amending Recruitment Rules. It should be done by the Central Government, Ministry of Shipping and Trans-

port. The Government has approved the amendment which was received on 19-11-79 as per Ext. M-3. Then they regularised the services of these employees in two batches as per Exts. M-4 and M-5. Pending approval of the amendment the management have regularised these workmen on ad-hoc basis from 1-8-77 extending all the benefits entitled for a regular employee.

16. The working hours for the out door staff is 8 hours per day. As a precautionary measure though it was not required the management have issued a notice under Section 9-A of the Industrial Disputes Act to the concerned authorities and the union as per Ext. M-6. Hence they are not entitled for any extra payment for working 8 hours after 1-8-77.

17. It is elicited in his cross-examination that the existence of C.P.W.D. Manual came to be known when these employees demanded to reduce the working hours from 8 hours to 7 hours as per the Manual. No overtime charges was paid after they came to know the working hours should not exceed 7 hours per day. It is further elicited that all the benefits were given from 1-8-77 and notice under Section 9-A was issued before 1-8-77 directing them to work for 8 hours. It is further elicited for fixing duty hours there was no regulation but it was only a practice observed in the Port.

18. Against this evidence on behalf of the I Party one Assistant Foreman has deposed that he joined as a work-charged employee during October 1966 and according to C.P.W.D. Rules the hours of work was 7 hours per day but they have made to work for 8 hours per day. After they agitated on this matter from 1-4-76 the management have agreed to reduce the working hours to 7 hours per day.

19. He has further deposed that from 4-5-74 the Mangalore Port was declared as a Major Port and they were asking to regularise their services for which the management have agreed to regularise on ad hoc basis from 1-8-77. On 1-9-77 the management gave a notice under Section 9-A of the Act changing the working hours from 7 hours to 8 hours per day. They have protested for the issuance of this notice and also raised a dispute before the Central Assistant Labour Commissioner and this 8 hours per day was made when the matter was pending before the Assistant Labour Commissioner. He has further deposed that the management has not informed under what rules, 8 hours work was insisted and they have been regularised permanently from December 1979. Hence they are entitled to the overtime wages from 1-8-77 to 1-12-79 and 1-8-77 to 29-12-79.

20. In the cross-examination it was elicited that this workman was appointed to work inside the factory and he do not know that 8 hours was prescribed for the workmen working inside the factory and 7 hours for the staff working in the field under C.P.W.D. Rules. Inside the factory, the categories of regular employees and work-charged employees were working and he do not remember the starting and closing time from 1-4-76. It is further elicited that, from 29-12-79 he is working 8 hours per day in accordance with the regular employees. Before 1979 also the working hours for the regular employees was 8 hours per day. They have not made any demand from 1-12-79 to 29-12-79 respectively for working 8 hours per day as their earlier demand was pending before this Tribunal. He has accepted the fact from 1-8-77 the management extended all the benefits applicable to regular employees as shown in the notice Ext. M-6 including the extension of working hours from 7 hours to 8 hours. He has also accepted the fact that pending the Central Rules for regularisation the II Party has made ad-hoc regularisation from 1-8-77.

21. On the basis of the evidence both oral and documentary, the learned counsel for the II Party after referring to the points that has to be decided in this dispute has submitted that in view of the amendment by the Central Government for the Service Rules the management to maintain the industrial peace for regularised this work charged employees with effect from 1-8-77 with all the benefits that is applicable to a permanent employee and their regularisa-

tion was effected after receipt of the amended rules. Hence the workmen cannot make any grievance for 8 hours working day from the date of ad-hoc appointment to the permanent post. There is considerable force in the submission of the learned counsel for the II Party as it is not denied by the witness for the I Party that from 1-8-77 they have been regularised on ad-hoc basis with all the benefits extended to a permanent employee. It is also not denied that the working hours for a permanent employee or a regularised employee was 8 hours at that time. Hence I find no merits in the stand taken by the I Party that even after regularisation they are entitled to work for 7 hours only and additional one hour shall be treated as over time work.

22. The main grievance of the I Party union has made out before me is the validity of the notice issued under Section 9-A of the Act to effect the change in the working hours after regularisation. Since it is an undisputed fact that the working hours for a regular workman is 8 hours per day and when the work-charged employee was changed into regular category, this working hours of 8 hours is automatic, which is not severable to the incident of the employment and however the II Party have issued the notice under Section 9-A in accordance with the Act.

23. However, the learned counsel for the I Party has relied on a decision of the Supreme Court reported in 1972 Lab. I. C. 1128. This decision is not applicable to the facts and circumstances of this case as in this decision the question was whether a notice under Section 9-A was necessary to change in weekly days of rest from Sunday to some other day where the management have omitted to give notice of change to workmen.

24. Though the I Party have prayed for the grant of over time wages for the period they worked as work-charged employees the same cannot be gone into as it is outside the scope of the reference made by the Government. The ad-hoc regularisation made to these work charged employees from 1-8-77 is as good as a regularisation made after the Central Government has amended the rules, hence the workmen are not entitled to claim any relief in this dispute. Hence I make the following award :

AWARD

The action of the management of New Mangalore Port is justified in increasing the working hours from 7 to 8 of the work-charged employees transferred on 1-8-1977 to regular establishment on ad-hoc basis. The parties shall bear their own costs.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by her and corrected by me.)

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer
[No. I-45015/2/78-D-IV (A)]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986

का. आ. 3950.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार, सिंडिकेट बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक, अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रिय सरकार को 23-10-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th November, 1986

S.O. 3950.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 13 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Syndicate Bank, Hyderabad.

AND

The Management of Syndicate Bank, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sarvasri A. K. Jayaprakash Rao and P. Damodhar Reddy, Advocates for the Workmen.

Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal, Kumari G. Sudha, Advocates and H. R. Sudarara, Assistant Personnel Manager, Syndicate Bank, Zonal Office, Hyderabad for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation by its Order No. L-12012/252/83-D.II(A), dated 14-2-1986 referred the following dispute under Section 7-A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Syndicate Bank and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Syndicate Bank, Hyderabad in relation to their Currency Chest, Mukharamjahi Road, Branch, Hyderabad in not entrusting Special Assistant's duties to Shri K. Manjunath Bhat, Clerk during his tenure there for the period from 6-2-81 to 21-1-82 is justified ? If not, to what relief is the workmen concerned entitled ?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 13 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. In the claims statement it is mentioned that K. Manjunath Bhat, Clerk who is presently working in the Central Accounts Office, Hyderabad, during his tenure at Currency Chest at Mukharamjahi Road, Hyderabad from 6-2-1981 to 21-1-1982 was not given for any special allowance. Whenever a permanent special assistant in a Branch or Office goes for sanctioned leave for more than six days, the senior most clerk in the Branch or office should be entrusted with temporary special assistant duties in the absence of the permanent incumbent. Sri K. Manjunath Bhat was not entrusted with temporary special assistant duties on a number of occasion while he was working in the Currency Chest, Mukharamjahi Road, Hyderabad from 6-2-1981 to 21-1-1982 notwithstanding that he was the senior most clerk of the Bank. Sri K. Manjunath Bhat was transferred to Currency Chest Mukharamjahi Road, Hyderabad vide Zonal Office letter dated 3-2-1981. He joined at Mukharamjahi Road, Hyderabad Branch on 6-2-1981 and it was confirmed by the Head Office letter dated 17-2-81. In fact he was asked to work at Nizam Shahi Road Currency Chest with effect from 22-1-1982 and the sanction of the Manager of Central Accounts Office, Hyderabad was dissatisfied by the Regional Office, Hyderabad in their letter dated 25-3-1982 in view of the fact that Sri K. Manjunath Bhat was required to work at Mukharamjahi Road, Branch Hyderabad from 3-2-1981 to 21-1-1982. Any temporary special assistant duties during this period which arose on account of the permanent incumbent absence or administrative should have been entrusted to Sri K. M. Bhat by virtue of seniority in Mukharamjahi Road Branch. The employee was informed by the Manager by his letter dated 19-12-1981 that the Currency Chest of Mukharamjahi Road Branch attached to Central Accounts Office, Hyderabad that the claim for entrustment of special assistant at the Branch could not be entertained and claim for temporary special assistant at the Branch could not be entertained. It is wrongly contended by the Management that K. M. Bhat was attached to Central Office, Hyderabad and not to Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad on account of this erroneous stand. Sri K. M. Bhat incurred monetary loss since he is not entrusted with temporary special duties at Mukharamjahi Road, Hyderabad as and when vacancies arose. Though the Circular

dated 20-7-1981 published showed eligible employees as on 30-3-1981 for entrustment of duties for Special Assistant in Branches situated in Hyderabad Region and though Sri K. M. Bhat stands at S. No. 22. The name of Sri G. Raghaviah another employee of Mukharamjahi Road Branch whose name stand at S. No. 23 and Radha Kumar and Annabath, Clerks of Central Office, Hyderabad are at S. No. 26 and 44 in the said list. Therefore the Central Office is estopped from contending that he belongs to Central Account Office, Hyderabad. In many places the currency chest are attached to the Branches also, and where in India the Currency Chest are operating independently and currency chests are invariably attached to the Branches or Central Accounts Offices depending upon the convenience of the Bank and this is strictly in compliance with the Reserve Bank of India instructions. The contention of the Management that currency chest Mukharamjahi Road is having separate identity and establishment and that the said currency chest is independent of Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad is evidently wrong. There is irrefutable evidence to prove that K. M. Bhat in fact belong to Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad and that temporary entrustment of Special Assistant duties at Mukharamjahi Road, Hyderabad could have been made to K. M. Bhat as and when vacancies arose on account of the absence of the permanent incumbent during the period from 6-2-1981 to 21-1-1982. Therefore the Management be directed to disburse the arrears of special allowance to Sri K. Manjunath Bhat at the rate of Rs. 283.00 per month during his tenure at Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad from the date and period in which seniority was overlooked.

3. In the counter filed by the Management it is mentioned that as per Circular dated 30-11-1977 whenever a permanent special assistant in a Branch or Office goes on sanctioned leave for seven days or over the senior most clerk in the Branch/Office should be entrusted with temporary special assistant duties due to absence of permanent incumbent. It is also admitted that while the Petitioner was working at Clerk at Currency Chest from 6-2-1981 to 21-1-1982 temporary vacancies of special assistance arose on various dates at Mukharamjahi Road Branch. As per the 6 Circular the senior most clerk working in that Branch are entrusted with temporary special assistance duties and there was special allowance proportionately as per the provisions of By-partite settlement. The currency chest at Mukharamjahi Road Branch premises started functioning from 23-11-1979. It was made clear to him by stating that he had to report to Currency Chest, Mukharamjahi Road Branch and it cannot be construed that Currency Chest is part and parcel of Mukharamjahi Road Branch. Sri K. M. Bhat working at Currency Chest, Mukharamjahi Road, Hyderabad from 6-1-1981 to 21-1-1982 if Currency Chest is considered as one of the department of the Branch then there is no need for maintaining two musters one for the Branch and the other for Currency Chest. As per the existing set up the Currency Chest as well as Central Account Office are headed by one Divisional Manager. The Officer Incharge of the Currency Chest will report to the Divisional Manager of the Central Accounts Office who is having administrative Control over the currency chest. The currency chest represents the duties carried out by the Reserve Bank of India and it is a separate identity and it is controlled by Central Accounts Office. Therefore the Manager of Mukharamjahi Road Branch have no control over the employees of the Currency Chest, Mukharamjahi Road, Hyderabad.

4. In the rejoinder filed by the President, Syndicate Bank Staff Association. It is contended that the Petitioner employee was transferred from Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad with a direction to work at Currency Chest and denial of temporary special assistant duties to Sri K. M. Bhat amounts to unfair labour practice and filed certain documents also.

5. The workmen examined W.W. 1 and marked Exs. W1 to 2, 2(a), 2(b), 3 to W.10. On behalf of the Management three witnesses were examined as M.Ws. 1 to 3 and marked Exs. M1 to M26.

6. The evidence of W.W.1 is to the effect that during 6-2-1981 to 21-1-1982 he worked at Mukharamjahi Road Branch and the Bank prepared seniority list of special assistants and his name is found in S. No. 22 in the seniority list of special assistants, as per Ex. 1. It is his case that

there are two sections in Mukharamjahi Road Branch, one is known as Currency Chest section and the other is General Banking Section. Both sections are situated in the same premises. The currency chest section is in underground otherwise known as underground cell and the general banking is done on ground floor. The Branch Manager is in charge of both the sections. Whenever special assistants of branch goes on leave for more than one week the senior most clerk in the Branch will act. There is special allowance to special assistant posts, the person who is acting in that post will be paid special allowance also. According to him for the period from 6-4-1981 to 21-1-1982 there were some other persons who were junior to him, were appointed as special assistants in the Branch on temporary post and when he questioned the Branch Manager told him that he was not staff member of the Mukharamjahi Road Branch and that W.W.1 was working in Currency Chest Section. The Branch Manager further told him that they had nothing to do with the Currency Chest since this Currency Chest is not part and parcel of the Branch for them. He mentioned that Jayaprakash who was in the Currency Chest during his time but he was senior to him. He filed Ex. W2 to show that festival advance is granted to him by the Branch Manager. Ex. W3 is the letter addressed by the Asstt. General Manager to Branch Manager showing him that he was sanctioned increment. Ex. W4 is the consequential pay roll given to him. According to him Ex. W5 did not contain the Branch name, it contained Branch Code. Ex. W6 dated 3-10-1981 is the certificate issued by the Principal Staff Training College at Hyderabad that he underwent Training Course under copy to the Branch Manager. Ex. W7 is the Transfer order showing that he was transferred to Zonal Office to Mukharamjahi Road Branch by the Deputy General Manager. Ex. W8 is the relieving order. He was relieved on 5-3-1981 at Zonal Office. He reported at Mukharamjahi Road Branch on 6-2-1981 as per Ex. W9. Ex. W10 is the confirmed transfer order issued by the head office. Therefore he prayed that he should be paid special allowance for the period was other juniors to him were asked to work as special assistants. According to him he is entitled to Rs. 400.00 approximately. He admitted that Mukharamjahi Road Currency Chest was opened in 1978 or 1979 and that the currency chest which was at Nizam Shahi Road was shifted to Mukharamjahi Road and he also admitted that under Ex. M2 the Reserve Bank of India permitted the Head Office to convert the existing currency chest at N. S. Road Branch into a repository. He also admitted that an additional accommodation for currency more particularly to outgoing and incoming currency the N. S. Chest was shifted to M. J. Road. He admitted that Syndicate Bank is a Schedule Bank and it is controlled by Reserve Bank of India. He admitted in their currency chest 7 other clerks and five officers and 2 sub-staff work with designations as Sub-Manager who are assistant managers and eight cashiers and he is a Cashier in the Currency Chest. It is also admitted that in the Branch the General Custodian Shroff handles the iron safe along with General Custodian Officer. Both the people of Branch Office operate safe with their respective keys simultaneously. He conceded that the duties of cashier handling the cash in the chest are totally different from the cashier handling the cash in the counter and safe of a branch. He admitted that he works under Sub-Manager of the Chest and he applied leave to the Sub-Manager and that he never address the leave to the Branch Manager. Mukharamjahi Road Branch. He admitted that there is separate attendance register for chest staff and separate attendance register for Branch Staff and his name figures in the chest register for the month of July 1981 as per Ex. M11 and similarly for the Currency Chest Attendance Register for the month of February 1981 is marked as Ex. M12. He also admitted that he worked for more than one year in the Currency Chest. Mukharamjahi Road and he was signing in the Currency Chest only during this period and he even'th signed in the Attendance Register of Mukharamjahi Road Branch. According to him when there is short of hands in the Currency Chest of Mukharamjahi Road Branch the staff of Mukharamjahi Road Branch Office are made to work in the Currency Chest situated in the same building and the staff who are deputed to the Currency Chest at such times used to sign the Currency Chest only. He admitted that their Currency Chest never handle the cash or customers at Mukharamjahi Road. After seeing the transfer orders that Jayaprakash under Ex. M13, M14, and M15 he admitted

that Jayaprakash came to the chest situated at Mukharamjahi Road Branch either from R. P. Secunderabad or Hyderabad Branch. He also admitted Ex. M16 is licence given to Mukharamjahi Road Branch and he admitted after seeing Ex. M3 for the chest it is not exhibited in the chest. He saw the Circular Ex. M17 with reference to special assistant allowance. He admitted that the Currency Chest is functioning in the Central Accounts Office and he admitted Ex. M19 showing that he was transferred to N. S. Road, Currency Chest with effect from 22-1-1982. He admitted that as per Ex. M19 the Central Accounts Office Manager is having control over the N.S. Currency Chest Mukharamjahi Road Currency Chest. He denied the suggestion that he was exclusively an employee of the Currency Chest and it is nowhere connected with the Branch and that is why he was not entitled for any special allowance.

7. MW 1 is the Deputy General Manager, Inspection Department, Hyderabad. According to him there was currency chest at N.S. premises and it used to be under the control of the Central Accounts Manager and he was the Central Accounts Manager at that time i.e. from July 1978 to August 1981. He deposed that they obtained permission from the Reserve Bank of India to open a chest at Mukharamjahi Road and it was incidentally located in the same premises as that of Mukharamjahi Road Branch. Ex. M16 is the licence given to the Syndicate Bank authorising to open a Branch at Hyderabad Mukharamjahi Road. The basement floor of the same is the currency chest. Ex. M3 is the Reserve Bank of India permission to open currency chest at Mukharamjahi Road. The Nizam Shahi Road Branch is working as Repository for holding the cash on behalf of the Reserve Bank of India. The currency chest is in charge of the Sub-Manager and he report to him any matters of importance. The Sundry Advances establishment register maintained at Central Accounts Office is marked as Ex. M20 and he said that all the expenditure is borne by the Central Accounts Office and the Clerical Staff working at Currency Chest is entitled to cashier allowance. According to him as per Ex. M21 which is debit advice from Mukharamjahi Road Branch it indicated the Central Accounts Office reimbursement. He asserted as on today the Syndicate Bank has one Currency Chest and it is under control of the Central Accounts Manager and K. M. Bhat was working in Central Accounts Office and all his salaries and allowances are borne by the Central Accounts Office and he relied them that on Ex. M20.

8. MW2 is the Sub-Manager, Syndicate Bank, Mukharamjahi Road Branch for six years. According to him he was Sub-Manager of the Currency Chest and Manjunath Bhat worked as Clerk in Mukharamjahi Road Currency Chest, attending to Accounting of cash, and sorting of cash. He filed Ex. M23 Attendance Register for the Currency Chest showing K. Manjunath Bhat. According to him the Currency Chest is operated by the Syndicate Bank on behalf of the Reserve Bank of India and it had nothing to do with Syndicate Bank Branch Office, Mukharamjahi Road. He asserted that this currency chest is directly under the control of the Central Accounts Office of the Syndicate Bank.

9. MW3 is the Branch Manager of Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad since November, 1980. It is his case that Mukharamjahi Road Branch is under control for administrative purposes and he maintains Attendance Register for the staff of the Branch Ex. M24 and he did not bear the name of K. Manjunath Bhat. The Licence under A. P. Spons and Establishments Act for their Branch is marked as Ex. M25. He asserted that the Currency Chest staff and Currency Chest are not treated as part of the Mukharamjahi Road Branch. He also said that he had no powers to call for the staff working in Currency Chest to come and work in his Branch. He also mentioned that K. Manjunath Bhat who came to join duty did not report to Branch Office. It is his case that whenever vacancies due to leave arose in his Branch he was taking the seniormost of the clerks in his Branch and not from the Currency Chest staff and there are circulars to that effect. He relied upon Ex. M17 Circular. He filed also Ex. M26 to show that K. Manjunath Bhat applied Festival Advance to Sub Manager, Currency Chest.

10. It is now clear that Sri K. Manjunath Bhat was a clerk working in the Syndicate Bank and there is no dispute

that he worked during the period from 6-2-1981 to 21-1-1982 in the Currency Chest which is situated on the ground of Mukharamjahi Road Branch Office. There is no dispute about the Circular Ex. M17 and also about the seniority list maintained for Special Assistants as shown under Ex. W1 would show that Sri K. Manjunath Bhat was at S. No. 22 as per seniority and that there is still circular dated 20-7-1981/30-12-1981 under Ex. W1 showing that the seniority list of the Sub Staff who are promoted to the clerical cadre, were shown the seniority and they published 50 names of eligible employees for entrustment of special assistants duties in each region. It is not in dispute that whenever the special assistants in the branch goes on leave for more than one week the seniormost clerk in the branch is made to act as special assistants and he is paid special allowance for acting as special assistants in the case of clerical staff working in the Currency Chest they are entitled for cashier allowance. Ex. M21 would show that the clerical staff of the Currency Chest being paid such cashier allowance and the same being deputed to the Central Accounts Office for reimbursement of the amount, and Ex. M22 would show also the advice note given by the Central Accounts Office to Mukharamjahi Road Currency Chest with reference to certain particulars of the staff. Ex. M17 is the circular dated 30-11-1977 which is the circular to be followed by the Branches in entrustment of duties of special assistants to seniormost clerk during the leave period of regular special assistant. They have given certain guidelines and instructions. Regarding Ex. M17 circular also there is no dispute. Sri K. Manjunath Bhat case is that he is shown to be working in Mukharamjahi Road Branch Office and if it is proved that he is only a clerk working the Mukharamjahi Road Branch Office and if he is not considered when the vacancies arose in July 1981 and May 1982 to September 1981, August 1981 etc., as deposed by him then it must be certainly held that Ex. M17 circular is violated in the lights of Ex. W1 seniority list showing him to be senior to some of those people who work in the Mukharamjahi Road Branch. But if the Currency Chest is a separate wing and it is only under the control of Central Accounts Office of Regional Office and if it has nothing to do with the Branch Office of the Mukharamjahi Road Branch then Sri K. Manjunath Bhat had no case since as a cashier of the Currency Chest which is the wing of Central Accounts Office he had nothing to do with the Branch Office. The evidence of MWs. 1 to 3 as well as Attendance Registers maintained for the Currency Chest and Mukharamjahi Road Branch would show that the Currency Chest is saving separate Attendance Register Ex. M23 and Sri K. M. Bhat was shown as a cashier in the Currency Chest. Ex. M24 is the Attendance Register separately maintained for Mukharamjahi Road Branch Office and the Management examined both the Branch Managers of Mukharamjahi Road Branch (MW3) as well as Sub-Manager who worked at the Currency Chest as MW2 to show that the Currency Chest kept at Mukharamjahi Road with the permission of the Reserve Bank of India had no connection whatsoever with the Mukharamjahi Road Branch, either in transactions of work or nature of duties. Infact WW1 himself admitted that the duties of cashier handling the cash in the chest are totally different from the cashier handling the cash in the counter of the branch. In case of a Branch Office there will be dual responsibility and Joint Custodian Shroff and as well as Joint Custodian Officer handle the safe with their respective keys simultaneously and these Joint Custodian Shroff who handle the cash otherwise known as Joint shroff is given key allowance. But such things are not given to the cashier in the Currency Chest and Cashier of the Currency Chest is paid only Cashier allowance and not any special allowance. Moreover the Circular Ex. M17 and W1 are meant for entrustment of duties of special assistance to the seniormost clerk during the leave period of regular special assistants in the Branches and it has nothing to do with the persons in the Currency Chest.

11. Therefore the question to be seen is whether the Currency Chest which was originally at Nizam Shahi Road premises when it is shifted to Mukharamjahi Road Branch with the permission of the Reserve Bank of India, whether the said currency chest merged with the Branch Office or whether it had independent existence. The evidence of MWs. 1 to 3 as well as Ex. M20, 26, 26 and 19 would show that the Currency Chest is incharge of a Sub-Manager and acts

under the control of Central Accounts Office and the salaries of the Currency Chest establishment which constitute about five officers, eight cashiers and one Sub-Manager and four Assistant Managers and two Attendants is a separate establishment of its own which is under the direct control of the Central Accounts Office. The Currency Chest Staff seniority is counted in the Central Accounts Office only and with the Branch Offices seniority. Therefore the averments of Sri K. Manjunath Bhat that his seniority should be counted with the Syndicate Branch Office, Mukharamjahi Road is not tenable. When he is not staff member of the Mukharamjahi Road Branch whenever vacancies of Special Assistants arose as per Circular Ex. M17 though he may be senior as shown in Ex. W1 when he is not a clerk working in Mukharamjahi Road Branch, his senioritywise—vis the seniority of other clerks working in Mukharamjahi Road Branch cannot be looked jointly. His seniority will be seen only in the Currency Chest of the Central Accounts Office and it is not his case that special assistants post in the Central Accounts Office fell vacant and that some body junior to him in the Central Accounts Office was given special assistant post during the vacancies. He is demanding for special assistants post in Mukharamjahi Road Branch where he had no footing and the averment that he was transferred to Mukharamjahi Road Branch Office as is tried to shown from Ex. W2 and W9 are all mistaken notions of Sri K. Manjunath Bhat that he is posted to Mukharamjahi Road Branch. Infact he was posted to Currency Chest which is described for the purpose of clarity that the Currency Chest was situated at Mukharamjahi Road Branch but when the Attendance Register are separate as could be seen from Exs. M23 and 24 and when his leave application and Festival Advance are dealt by the Currency Chest authorities and when the controlling authorities is only Central Accounts Office for the Currency Chest it is important to conceive that he was rightly not given the special assistants duties during the leave period of seniormost clerks in the Mukharamjahi Road Branch. It is too much to conceive when the Mukharamjahi Road Branch and Currency Chest situated at Mukharamjahi Road Branch are two separate identities that for the leave vacancies arising in the regular special assistant posts of Mukharamjahi Road Branch that Sri K. Manjunath Bhat who is in the Currency Chest which had no connection whatsoever but for the description of the place of location to contend that Ex. M17 Circular was not implemented towards him. Therefore on a careful consideration of the entire matter and also the admissions of MW1, W1 to MW3 and documents I hold that the action of the Management of Syndicate Bank, Hyderabad in relation to their Currency Chest, Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad in not entrusting Special Assistants duties to Sri K. Manjunath Bhat. Clerk during his tenure there for the period from 6-2-1981 to 21-1-1982 is perfectly valid and the workman is not entitled for any relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 26th day of September, 1986.

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

Witnesses Examined

for the workmen

W.W.1 K. Manjunath Bhat

Witnesses Examined

for the Management

M.W.1 K. Vaman Naik.

M.W.2 Sanjeeva Pai

M.W.3 H. Ravindernath Rao

Documents marked for the Workmen

Ex. W1—Photostat copy of the entrustment of duties of Special Assistant list of eligible employees as on 31-3-81.

- Ex. W2—Photostat copy of the application dt. 11-1-82 for Festival advance of Rs. 500/- applied by K. Manjunath Bhat to the Sub-Manager, Syndicate Bank Currency Chest, Mukharamjahi Road.
- Ex. W2 (a) Remarks of the Manager on Ex. W2.
- Ex. W2(b) Remarks of the Forwarding Officer on Ex. W2.
- Ex. W3 Photostat copy of the letter dt. 15-10-81 addressed by Assistant General Manager, Syndicate Bank, Regional Office, Hyderabad, Staff Department to K. Manjunath Bhat, Clerk, Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad with regard to sanction of annual increment.
- Ex. W4 Photostat copy of the consequential pay roll of K. Manjunath Bhat.
- Ex. W5 Photostat copy of the proforma of Syndicate Bank Employees' Provident Fund, Manipal.
- Ex. W6 Photostat copy of the letter dt. 3-10-81 addressed by principal Staff Training College Syndicate Bank, Chapel Road, Hyderabad to K. Manjunath Bhat with regard to closure of training programme and enable him to join M. J. Road, Hyderabad Branch.
- Ex. W7 Photostat copy of the Transfer Order dt. 3-2-81 issue K. Manjunath Bhat by the Deputy General Manager, Syndicate Bank Zonal Office Anchalik Karyalay) Staff Administration Section.
- Ex. W8 Photostat copy of the relieving Order dt. 5-2-81 issued to K. Manjunath Bhat.
- Ex. W9 Photostat copy of the joining Report dt. 6-2-81 of K. Manjunath Bhat in Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad.
- Ex. W10 Photostat copy of the letter dt. 17-2-84 addressed by Dy. Personnel Manager, Syndicate Bank, Personnel Department to K. Manjunath Bhat Clerk, Zonal Office, Hyderabad with regard to transfer to Mukharamjahi Road Branch, Hyderabad.

Document marked for the Management :

- Ex. M1 Photostat copy of the letter dt. 29-11-79 addressed by Regional Development Manager, Syndicate Bank, Zonal Office, Hyderabad to All the Branches in Andhra Pradesh with regard to New Currency Chest at Mukharamjahi Road Branch premises.
- Ex. M2 Photostat copy of the letter addressed by N. C. Mitra, R. Currency Officer, Reserve Bank of India issue Department 6-1-56 Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad to the Manager, Syndicate Bank, Central Accounts Office, N. S. Road, Hyderabad with regard to currency chest.
- Ex. M3 Photostat copy of the letter dt. 5-4-1978 addressed by Chief Accountant Reserve Bank of India Central Office Department of Accounts and expenditure Bombay to the General Manager, Syndicate Bank, premises and maintenance Department Manipal, Karnataka State with regard to shifting of the existing currency chest at N. S. Road Branch (Hyderabad) to Mukharamjahi Road, Hyderabad.
- Ex. M4 Privilege leave application of K. Manjunath Bhat dt. 30-3-1981 addressed to the Sub-Manager, Syndicate Bank Currency Chest, Hyderabad.
- Ex. M5 Casual Leave application of K. Manjunath Bhat dt. 12-3-81 addressed to the Sub-Manager, Currency Chest, Mukharamjahi Road, Hyderabad.
- Ex. M6 Privilege Leave application of K. Manjunath Bhat dt. 29-11-81 addressed to the Manager, Syndicate Bank Currency Chest Mukharamjahi Road, Hyderabad.
- Ex. M7 Letter dt. 21-9-1981 addressed by K. Manjunath Bhat, Currency Chest, M. J. Road, Hyderabad to the Managing Director, Personnel Department

Head Office, Manipal, through the Principal Staff Training College, Hyderabad with regard to joining the refresher course training programme.

- Ex. M8 Casual Leave application of K. Manjunath Bhat, dt. 3-6-1981 addressed to the Sub-Manager, Currency Chest, Mukharamjahi Road, Hyderabad.
- Ex. M9 Letter dt. 3-8-81 addressed by K. Manjunath Bhat to the Sub-Manager, Syndicate Bank, Currency Chest, M. J. Road, Hyderabad requesting for grant of special Casual Leave from 15-7-81 to 17-7-81.
- Ex. M10 Privilege Leave application of K. Manjunath Bhat dt. 7-5-1981 addressed to the Sub-Manager, Syndicate Bank, Currency Chest, M. J. Road, Hyderabad.
- Ex. M11 Register of Attendance of the Staff of Syndicate Bank, M. J. Road (Currency Chest) for the month of July, 1981 at Page 26.
- Ex. M12 Photostat copy of the Register of Attendance of the Staff of Syndicate Bank for the month of February, 1981.
- Ex. M13 Photostat copy of the transfer Order dt. 20-9-76 issued to M. Jayaprakash Clerk, Secunderabad main Branch by Staff Controller.
- Ex. M14 Photostat copy of the transfer Order dt. 20-9-76 issued to M. Jayaprakash, Clerk, Secunderabad main Branch by Staff Controller.
- Ex. M15 Photostat copy of the Transfer Order dt. 31-3-1981 issued to M. Jayaprakash, Clerk, Mukharamjahi Road, Branch, Hyderabad by the Dy. Personnel Manager.
- Ex. M16 Photostat copy of the letter dt. 19-12-1974 of Dy. Chief Officer, Reserve Bank of India department of Banking operations & Development Bangalore-2 authorising Syndicate Bank to open a Branch at Hyderabad Mukharamjahi Road.
- Ex. M17 Photostat copy of the Circular No. 313/77/BCISTF/38, dt. 30-10-77 with regard to entrustment of duties of Special Assistants to Senior most clerks during the leave periods of regular Special Assistants.
- Ex. M18 Joining Report dt. 6-2-1981 of K. Manjunath Bhat at Mukharamjahi Road, Hyderabad.
- Ex. M19 Letter dt. 20-1-82 addressed to K. Manjunath Bhat Clerk M. J. Road, Currency Chest, Hyderabad by B. R. Madhava Rao Manager, Syndicate Bank, Central Accounts Office, N. S. Road, Hyderabad directing him to work at N. S. Road, Currency Chest with effect from 22-1-82 until further orders.
- Ex. M20 Register of General Account ledger Head of Account Establishment from 1978 to 1981.
- Ex. M21 Letter dt. 28-4-81 addressed to the Manager, Central Accounts Office, Hyderabad by the Manager, Syndicate Bank, Mukharamjahi Road, Hyderabad with regard to reimbursement of amount.
- Ex. M22 Letter dt. 1-4-81 addressed to the Sub-Manager, Currency Chest M. J. Road, Hyderabad by the Manager, Syndicate Bank Branch, Central Accounts Office, Hyderabad with regard to calling for certain particulars of the staff.
- Ex. M23 Attendance Register pertains to M. J. Road, Currency Chest from January 82 to December, 1982.
- Ex. M24 Syndicate Bank's Attendance Register from May 1981 to February 1983.
- Ex. M25 Letter dt. 22-11-82 addressed by Manager Syndicate Bank to the Assistant Inspector of Labour, Government of Andhra Pradesh, Musheera-

bad, Hyderabad with regard to renewal of Certificate No. 1739/CS/78 for the year 1982.

Ex. M26 Letter dt. 11-1-82 addressed by K. Manjunath Bhat, Currency Chest, Mukaramjahi Road, Hyderabad to the Sub-Manager, Syndicate Bank Currency Chest, Mukaramjahi Road with regard to Festival Advance of Rs. 500 (Rupees Five Hundred only).

Dated : 6-10-1986

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. L-12012/252 83-D.II(A)]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 3951.—भारत के राजपत्र में दिनांक 7 जून, 1986 को प्रकाशित श्रम मंत्रालय को दिनांक 29 मई, 1986 को अधिसूचना संख्या-एल.-17011/2/83-डी-4(ए) के उपाबंध में पैरा 48 के अंतिम वाक्य में जहाँ कहीं "कर्मकारों" शब्द विद्यमान है उसे "कर्मकार" पढ़ा जाए।

[सं. एल.-17011/2/83-डी-4(ए)]
के. जे. देव प्रसाद, डेस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

S.O. 3951.—In the annexure to the Ministry of Labour Notification No. L-17011/2/83-D.IV(A) dated 29th May, 1986 which was published in the Gazette of India dated 7th June, 1986, the word 'workmen' wherever it appears in the last sentence of paragraph 48 may be read as 'workman'.

[No. L-17011/2/83-D.IV(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986

का. आ. 3952.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप-खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या का. आ. 2224 तारीख 29 मई, 1986 द्वारा मिश्रूरटो पेपर मिल, होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 मई, 1986 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोग सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 नवम्बर, 1986 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोग सेवा घोषित करती है।

[काइल संख्या एस.-11017/10/81-डी-1(ए)]
नन्द लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 12th November, 1986

S.O. 3952.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 2224 dated the 29th May, 1986 the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 28th May, 1986;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 29th November, 1986.

[F. No. S-11017/10/81-D.I(A)]
NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

का. आ. 3953.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ई. डी. एम. सो. चिकबालापुर सब-डिविजन के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, बैंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-10-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th November, 1986

S.O. 3953.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of E.D.M.C. Chickballapur Sub-Division and their workmen which was received by the Central Government on the 28th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 10th day of October, 1986

PRESNT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer.
Central Reference No. 2 of 1985

I PARTY :

Sri A. S. Nagaraj, S/o A. S. Sambamurthy, No. 534,
Kandavarpet, Chickballapur, Pin-562101.

Vs.

II PARTY :

The Sub-Divisional Inspector, Chickballapur Sub-Division, Chickballapur-562101.

APPEARANCES :

For the I Party—Smt. Shantha Chellappa, Advocate,
Bangalore.

For the II Party—Sri K. V. Viswanatha Murthy, P.M.G.
Office, Karnataka Circle, Bangalore.

REFERENCE :

(Government Order No. L-40012(22)/84-D.II(B) dated
5-2-1985)

AWARD

The Central Government after forming an opinion that an industrial dispute exists between the above parties has referred the said dispute for adjudication under Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on the following Schedule :—

SCHEDULE

"Whether the action of the Sub-Divisional Inspector Sub-Division (Postal) Chickballapur in Kolar Postal Division, Kolar in terminating the service of Shri A. S. Nagaraj, Extra Departmental Mail Carrier at Ajjavara, Chickballapur Sub-Division is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The II Party to justify the termination of the I Party workman, briefly contended in their claim statement that the I Party while working as Extra Departmental Mail Carrier was found to have taken leave in excess of 180 days in a continuous period of 12 months from 9-2-82 to 21-10-82 totalling 248 days. Thereby he violated the provisions of Rule 5 of the E.D. Agents (C & S) Rules, 1964, hereinafter referred to as Rules. As per the directions of the authority immediately superior to the appointing authority, a notice was issued to the I Party stating that it was proposed to remove him from service for availing leave in excess of 180 days. The I Party gave a representation dated 27-4-83 and he has been let off with a warning. Subsequently the authority superior to the appointing authority has called for the explanation of the appointing authority for flouting the rules and thereafter the II Party terminated the services of the I Party under the provisions of Rule 6. Thereafter, the I Party submitted a petition to the Director of Postal Services and since no appeal lies, the same was not forwarded to the authority and thereafter the I Party submitted a petition to the Postmaster General, Karnataka Circle under Rule 16 and the order of termination was upheld by the Postmaster General. Thereafter, the I Party has submitted a petition to the President of India on 22-12-84, which was forwarded to the Director General, Posts & Telegraphs, New Delhi, and the same is pending.

3. In their further statement, the II Party have further contended that the I Party having presented a petition to the President of India cannot seek remedies simultaneously in this Tribunal. This Tribunal cannot give an award in violation of statutory provisions of the termination of services of the I Party is in accordance with Rule 6.

4. The sum and substance of the claim statement made by the II Party is that the I Party workman being appointed temporarily as E.D.M.C. took leave during the year 1982 for 248 days hence he has been issued with a memo and after his explanation he has been let off with a warning and allowed to work. Subsequently the Senior Superintendent of Post Office of Kolar Division after reviewing the order has warned the appointing authority of the I Party for flouting the rules and thereafter the appointing authority terminated the services of the I Party by issuing a memo without assigning any reason. The further contentions taken by the II Party is the order of termination is in accordance with Rules framed exclusively to which the I Party belongs, hence he cannot be governed simultaneously both the Service Rules as well as the Industrial Disputes Act. In view of the fact that separate service rules have been framed by the Government of India, the provisions of the Industrial Disputes Act will not in any manner trench on the field occupied by the Service Rules.

1086 G of I/86—8.

5. The I Party has filed the counter statement which he has subsequently amended by inserting additional grounds which in brief is as follows :

"The I Party who joined as E.D.M.C. on 1-4-1981 was diligent and sincere during his service and after 3-4-82 due to heavy cycling involved into official duties started developing severe back pain and other illness which forced him to take medical leave at different times. In the first year of service he has not availed any leave and after 3-4-82 he has availed medical leave supported by medical certificates. When he was served with a memo on 4-4-83 by the Sub-Divisional Inspector, Chickballapur he sent a suitable reply and after considering the reply the II Party vide their memo dated 27-11-83 have taken a lenient view and he was let off with a warning and also with a direction that he should not take any leave for one year from 27-4-83. Accordingly he did not avail any leave till 2-6-83 on which day to his surprise and shock he was served with a termination order without assigning any reason and without giving an opportunity before his termination".

6. He has further contended that he has filed an appeal on 27-6-83 to Post Master General, Bangalore and also to the Senior Superintendent of Post Office, Kolar Division. Pursuant to the appeal, the Superintendent of Post Office appears to have passed an order on 8-7-83 stating that no appeal lies and also directing the Sub-Divisional Inspector, Chickballapur to inform the same to him. Thereafter he has filed a review petition before the Post Master General and then raised the conciliation at K.G.F.

7. He has further contended that the termination is illegal and arbitrary and against the principles of natural justice and though it looks as a termination simpliciter it is dismissal for misconduct. He has further contended that the order of termination amounts to retrenchment as defined in Section 2(cc) of the Industrial Disputes Act, hereinafter referred to as Act, and prior to passing of termination, no notice was issued nor any notice pay was given which is violative of the mandatory provisions of Section 25-F of the Act. He has further contended that the termination order is not a speaking order as it does not indicate the ground on which he was terminated and also violative of Article 311 of the Constitution of India, as the I Party was not given a chance to meet the case against him. He is not guilty of any offence as his leave has been supported by the medical certificate and sanctioned by the II Party. He has not been served with any memo that his leave has not been sanctioned nor he was called upon to join duty, as his leave has not been sanctioned. Hence he prayed to pass an award setting aside the termination order and directing the II Party to reinstate him to duty with continuity of service with all the benefits and also to order for back wages from the date of termination till his reinstatement.

8. This Tribunal on the basis of the original pleadings has framed only one issue calling upon the II Party to show that he is empowered to terminate the services of the I Party and under the provisions of Rule 6 for violation of Rule 5 of E.D. Agents (C & S) Rules, 1964 without holding a domestic enquiry. The subsequent statement filed by the II Party after amendment of the counter statement of the I Party, a jurisdictional fact has also been taken.

9. Now the issues that arise for determination are :—

- (1) Whether the II Party is empowered to terminate the services of the I Party workman under the provisions of Rule 6 of E.D. Agents (C & S) Rules, 1964 without holding a domestic enquiry?
- (2) Whether the II Party proves that the Industrial Disputes Act is not applicable to the E.D. Agents in the P&T Department under Art. 311(2) of the Constitution of India?

(3) What order?

10. Findings—

- (1) Issue No. 1—Negative.
- (2) Issue No. 2—Negative.
- (3) Issue No. 3—As per order below :

11. REASONS :

Issue No. 1—This issue has been framed on the basis of the contentions raised by the II Party which is also having a hearing on the Schedule referred by the Government. A detailed examination of the evidence led by the witnesses on behalf of the II Party is found unnecessary as the dispute can be brought to a narrow campus on the admitted facts. It is admitted by both the parties that the I Party workman has availed the leave during 1982 for 248 days and after his assumption to duty in the month of November 1982 a memo was issued to him on 4-4-83 as per Ext. W-1. In Ext. W-1 it is stated that as per E.D. Agents Rules the maximum number of days of leave admissible is only 180 days and hence they proposed to remove the workman from service and against that proposal he may give a representation within 7 days from the date of receipt of that proposal order. The workman gave a representation on 9-4-83 as per Ext. W-2 that due to his ill-health on account of continuous riding of bi-cycle he was taking treatment and hence he may be excused and further that he will be regular in future. This explanation was accepted by the Appointing Authority and he has been let off with a warning further directing him not to take leave during the period on one year from 27-4-83. It appears that this order reviewed by the Senior Superintendent of Post Offices and he issued a letter dated 25-5-83 as per Ext. W-4 calling upon him to explain for flouting of rules contained in Rule 8. The latter he has issued a memo terminating the service of the workman which appears to have received by the workman on 2-6-83. Unfortunately this termination memo has not been marked as an exhibit by either of the parties though it was filed before this Tribunal in the list of documents dated 5-11-85. On a perusal of this memo dated 2-6-83 which reads as follows :—

"The services of Sri A. S. Nagaraja, EDMC A'javara are hereby terminated under Rule 6 of E.D. Agents (C & S) Rules, 1964 with immediate effect."

12. When this workman made representation against this order to the Senior Superintendent Post Offices, Kolar Division, the same was not entertained on the ground that no appeal lies on the order issued to the workman. Subsequently, the workman has filed an appeal to the Director of Postal Services, Bangalore as per Ext. W-8 which appears

to have been rejected and the order of rejection was communicated to the Senior Superintendent of Post Offices who intimated to the workman as per Ext. W-10.

13. It is not in dispute that this workman has availed the leave of 248 days by making leave applications which was granted and a substitute workman recommended by the workman was accepted by the II Party to do the work in his place during his leave period.

14. On this material, the learned authorised representative for the II Party has submitted that since this workman has been terminated from service in accordance with Rule 6 it is a termination simpliciter and not as a punishment, hence the workman is not entitled for any relief. Against this submission, the learned counsel for the workman Smt. Shanta Chellappa has submitted that the facts and circumstances which led to the termination of this workman clearly indicate that it is not a termination simpliciter and as a measure of punishment the II Party has resorted to an easy method of invoking Rule 6 to get rid of this workman hence the termination amounts to a punishment and the said termination is liable to be set aside.

15. To appreciate the contentions raised by the parties it is necessary to advert to the Service Rules in this regard. Under E.D.A. (C&S) Rules applicable to this workman, Rule 5 reads as follows :

"5. Leave :

The employees shall be entitled to such leave as may be determined by the Government from time to time :

Provided that—

- (a) where an employee fails to resume duty on the expiry of the maximum period of leave admissible and granted to him, or
- (b) where such an employee who is granted leave for a period less than the maximum period admissible to him under these rules, remains absent from duty for any period which together with the leave granted exceeds the limit up to which he could have been granted such leave,

he shall, unless the Government, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise decides, be removed from service after following the procedure laid down in Rule 8."

16. Under the Director General's instructions to E.D. Agents should be permitted to avail leave of absence for more than 90 days at a strength which may be extended up to 180 days in exceptional circumstances by the Divisional Superintendent of Post Offices. If an E.D. Agent remains on leave for more than 180 days at frequent intervals in a period of one year he shall cease to be an E.D. Agent.

17. Under Rule 6 Termination of Services.—The service of an employee who has not already rendered more than three years continuous service from the date of his appointment shall be liable to termination by the appointing authority at any time without notice.

Under Director-Generals instructions, the termination under this rule will be made generally for an ED Agent if physically or mentally unfit or he is found to be unfit to discharge the responsibilities. If the post is abolished or upgraded he cannot be accommodated in any other suitable post. Any termination under this rule, no appeal lies except a review under Rule 16 by an authority immediately superior to the authority passing the orders.

18. Rules 7 and 8 deal with the nature of penalties and the procedure imposing the penalty which is as under :—

7. Nature of penalties :

The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee by the appointing authority, namely :—

- (i) recovery from allowance of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders;
- (ii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
- (iii) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

8. Procedure for imposing a penalty :

(1) No order imposing a penalty shall be passed except after—

- (a) the employee is informed in writing of the proposal to take action against him and of the allegation on which it is proposed to be taken and given an opportunity to make any representation he may wish to make, and
- (b) such representation, if any, is taken into consideration by the appointing authority;

Provided that the penalty of dismissal or removal from service shall not be imposed except after an enquiry in which he has been informed of the charges against him and has been given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges;

Provided further that where it is proposed after such enquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such enquiry.

(2) The record of proceedings shall include :—

- (i) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him;
- (ii) a copy of the statement of allegations, along with a list of evidence in support thereof, communicated to him;
- (iii) his representation, if any;
- (iv) the records of the enquiry proceedings along with the enquiry report of the appointing authority or enquiry officer, if any, appointed in a case where a formal enquiry is necessary;

(v) findings of the appointing authority in respect of the allegations with reasons therefor; and

(vi) the order imposing the penalty.

19. On a reading of the above provisions it is to be noted that any violation of rule 5 the concerned workman will be removed from service only after following the procedure laid down under Rule 8. Admittedly, this workman was originally issued with a memo of removal from service due to availing the leave of more than 180 days and his explanation being satisfied he was let off with a warning and was asked to continue his work. He has been terminated from service under Rule 6 by the appointing authority only after he has received a letter from his superior officer questioning the action taken by him in letting off a workman with a warning and allowing him to continue his work. A specific mention was also made in Ext. W-4, addressed to the appointing authority, by his superior officer that any violation of Rule 5 the action shall be taken under Rule 8 before taking any action against the workman. So, it looks that the Sub-Divisional Inspector has taken an easy resort to terminate this workman under Rule 6 which found to be very convenient in the circumstances under which Sub-Divisional Inspector was placed at that time.

20. The facts and circumstances of this case clearly reveal that the termination of this workman is not a termination simpliciter as the reason for his termination is for the violation of Rule 6 and since the procedure laid down in the Rule 8 being not followed, I have no hesitation to hold that this termination is null and void. The above finding will find support in a decision of Kerala High Court between Kunhiraman Nair and Superintendent of Post Offices reported in 1984 I L.L.J. 135. In this case the question of termination order of an Extra Departmental Postmaster is challenged on the ground that he did not comply with Rule 6 of 1964 Rules. The petitioner who was functioning as Extra Departmental Branch Post Master was served with a memo informing him that under Rule 6 of the Extra Departmental Agents (C & S) Rules, 1964 the services of the petitioner is terminated with immediate effect. Their Lordships while discussing have held in para 5 of the judgment that a "termination under Rule 6 must be a termination which indicates the reason."

21. Their Lordships further held in para 9 as—

"Even though the termination order is specifically challenged as arbitrary, inasmuch as the administrative ground which is said to have prompted the passing of that order is not disclosed, no attempt is made in the counter affidavit to explain or indicate the administrative reason which weighed with the authority in passing the order of termination. There is only a reiteration that the termination was on administrative ground. That would not satisfy the requirement of Rule 6 and therefore, the plea of discrimination must succeed."

22. On a rerusal of the pleadings of the II Party they are not specific in their stand as in one breath they say that the termination of the workman was due to violation of the provision of Rule 5, which requires an enquiry under Rule

8, and in another breath they say that since the workman has not completed 3 years of service, his services are terminated without assigning any reason under Rule 6. There is glaring inconsistency in the stand taken by the II Party, hence I hold this issue in the negative.

23. Point No. 2.—The learned representative for the II Party by relying on a decision reported in 1984 I LLJ 485 has submitted that since the order of termination is in accordance with the rules framed exclusively for such category of employees the provisions of the Industrial Disputes Act will not apply and hence this Tribunal has no jurisdiction to entertain this reference.

24. Against this submission, the learned counsel for the I Party has submitted that the decision relied by the II Party is distinguishable as Industrial Disputes Act is applicable to the workman in Post and Telegraph Department and to drive home this point, the counsel relied on the decision of Bangalore Water Supply and Sewerage Board reported in 1978 SC 548.

25. Their Lordships of the Kerala High Court, which is a Full Bench decision, in the decision cited by the II Party have held that the Industrial Disputes Act is not applicable to the Central Civil Services (Temporary Service) Rule, 1965 as it is a special rule applicable to temporary Government servants. Their Lordships have taken this view which can be found on the discussion made in para 23 of the Judgment as —

"Industrial Disputes Act therefore is a general law relating to industrial disputes. Rules relating to the Temporary employees in the P & T Department are special provisions applicable to a particular class. These rules take note of the special features of these categories of Government servants and take care of their tenure and termination. Entry 61 in List-I relates to industrial disputes concerning union employees. There was no such entry in the Government of India Act. It seems thus to be clear that the Union is now armed with a specific entry in List-I to embark on a fresh legislation relating to industrial disputes concerning union employees, a special subject, incidentally implying that the field under Entry 22 List-III is of general application. In fact both the centre and the States have enacted several laws where specific provisions for industrial disputes in particular industries have been made, notwithstanding Act 14 of 1947. The special rules relating to the temporary Government servants thus exclude the general provision in the Industrial Disputes Act".

26. As submitted by the learned counsel for the I Party workman this judgment is distinguishable. Their Lordships have stated at para 20 which reads as follows :

"We shall guard ourselves by stating that we have considered only the impact of special rules, the Central Civil Services (Temporary service) Rules, 1965 on the Industrial Disputes Act and nothing further".

27. It is not in dispute that Post and Telegraph Department is an industry as it passed the test laid down in Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa.

In this judgment a question for consideration was whether the rules under Art. 309 of the Constitution expressly or by necessary implication exclude the operation of the Industrial Disputes Act came for consideration and it was held :

"(a) Rule under Art. 309 of the Constitution may expressly or by necessary implication exclude the operation of the Industrial Disputes Act. That is a question of interpretation and statutory exclusion."

(b) Constitutional and competent enacted legislative provisions may well remove from the scope of the Industrial Disputes Act categories which may have covered thereby.

(c) "Only those services which are governed by separate rules and constitutional provisions such as Art. 310 and 311, should, strictly speaking, be excluded from the sphere of industry by necessary implication." (Beg. C. J. concurring)

(d) "If express rules under other enactments govern the relationships between the State as an employer and its servants as employees, it may be contended, on the strength of such provision, that a particular set of employees are outside the scope of the Industrial Disputes Act for that reason. The special excludes the applicability of the general (Beg C. J. concurring)."

28. The Extra-Departmental Agents (Conduct and Service) Rules are the rules governing the service conditions of Extra Departmental staff which deal with the appointment, termination, enquiry, etc., of these category of workman. These rules are not considered as a rule framed by the President of India in exercise of the powers conferred by Art. 309 in the judgment of 1984 I LLJ 484 by Their Lordships of the Kerala High Court. Hence there is no express exclusion of the Industrial Disputes Act to the E.D. staff.

29. Now coming to the case in hand this Tribunal has already given a finding that the procedure adopted by the II Party in terminating the services of the I Party—Workman is violative of the service rules for extra departmental staff. When that being the case, since there is no remedy for the dismissed employee available under the said service rules, there is absolutely no bar for him to invoke the jurisdiction under the Industrial Disputes Act, 1947. Hence I hold this point in the negative and pass the award accordingly.

AWARD

The II Party was not justified in terminating the services of the I Party-workman. The I Party workman is entitled for reinstatement with continuity of service. Since the back wages cannot be computed due to the nature of post held by the I Party workman to compensate his unemployment from the date of his illegal termination to the date of his reinstatement I award cost of Rs. 3,000 payable by the II Party.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by the).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-40012/22/84-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3954--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार जो 30 जून, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

[सं. एक 19/21/86-बी.ओ. 1]

एम. एस. सोतारामन, अवर सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

पहला जुलाई 1985 से 30 जून 1986 तक

भाग I— आर्थिक स्थिति

सातवीं योजना का पहला वर्ष होने की वजह से 1985-86 में अर्थ-व्यवस्था का निष्पादन विशेष महत्व रखता है। छठी योजना (1980—85) के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में 5.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना संभव हो सका था, हालांकि इसे 1979-80 के अपेक्षा न्यून स्तर से प्राप्त किया गया था। इसके बावजूद 1974-75 के दौरान अर्थव्यवस्था की सुधरी हुई स्थिति अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाने में सहायता की है। सातवीं योजना (1985—90) के लिए वृद्धि दर को 5 प्रतिशत पर बनाये रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि के दौरान वृद्धि को मुख्य आधार औद्योगिक क्षेत्र से मिलने की आशा की जाती है और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि का लक्ष्य 8 प्रतिशत वार्षिक रखा गया है, जबकि छठी योजना के दौरान प्राप्त की गयी औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत के आस-पास थी। इसके अलावा, आंतरिक बचत दर में संभावित मामूली सी गिरावट और विदेशी बचतों के अभाव का सोनाचों को दबोड़ने के प्रयासों में बड़ी हुई उत्पादकता और कुशलता पर अधिकारिकता भरोसा करना होगा कि सातवीं योजना में समग्र लक्षित वृद्धि दर प्राप्त की जा सके।

2. 1985-86 के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में अनुमानित वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत थी, जिसका अर्थ हुआ, लगातार दूसरे वर्ष भी दर 5 प्रतिशत से काफी नीचे रही। कृषि क्षेत्र में लगभग एक प्रतिशत की प्रत्याशित वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था सिर्फ वही हासिल कर सकी है जो उसने 1984-85 में खोया था। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि को 6.3 प्रतिशत की अनुमानित दर भी विन्ता की बात है क्योंकि 1981-82 के बाद से लगातार चार वर्षों में से किसी भी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत की वृद्धि दर तक नहीं पहुँचा है, सिर्फ 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन ने 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की थी। उच्च वृद्धि दर के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि बिजली की आपूर्ति मांग की तुलना में लगातार कम रही। अतः, यह मानते हुए कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न

नियमित उपायों और वास्तविक औद्योगिक वृद्धि पर उनके प्रभाव के बीच के समय का अंतराल लगभग दो वर्ष का होता है, 1986-87 में बृहत्तर उत्पादन स्थितियाँ देखने की मिल सकती हैं। सातवीं योजना में लक्षित अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर प्राप्त हो, इसका सारा दायरामदार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर है।

3. मौजूदा अर्थव्यवस्था वातावरण में के शक्ति के कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। उन स्रोतों में ये शामिल है: मुद्रा स्फूर्ति की वृद्धि में कमी, सार्वजनिक प्रणाली में खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार, देशी बचत का ऊँचा स्तर और विदेशी मुद्रा का यथोचित रूप से सुविधाजनक स्तर और विदेशी वित्तीय बाजारों में साख।

4. विन्दुवार आधार पर, थोक मूल्य निरन्तर गिरावट दर्ज करते हुए 1983-84 के 8.9 प्रतिशत से कम होकर 7.6 प्रतिशत रह गये और 1985-86 में ये और गिरकर 3.8 प्रतिशत रह गये। साप्ताहिक औसत आधार पर भी गिरावट देखने में आयी जो 1983-84 में 9.5 प्रतिशत से गिरकर 1984-85 में 7.1 प्रतिशत और 1985-86 में और गिरकर 5.7 प्रतिशत रह गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जून 1986 के अंत में इनके 28.6 मिलियन टन रहने के अनुमान हैं। इन बड़े स्टाकों से केवल कृषि के लिहाज से खराब वर्षों में मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ न केवल सुरक्षा की भावना रहती है बल्कि इससे रोजगार बढ़ाने और पूँजी निर्माण के लिए भी मार्ग खुल जाते हैं।

5. बचत के संबंध में उपलब्ध प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि बाह्य बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध देशी बचत 1985-86 में 16.1 प्रतिशत थी। हालांकि यह प्रतिशत 1983-84 से कमोबेश अपरिवर्तित बना रहा है, किन्तु यह अधिकांश विकासशील देशों की बचत दर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

6. बाहरी मोर्चे पर, विदेशी मुद्रा के भंडारों ने 1985-86 में रुपये के सन्दर्भ में वृद्धि दर्ज की यद्यपि वृद्धि की मात्रा पिछले वर्ष हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। दूसरी ओर विशेष आहरण अधिकारों के सन्दर्भ में 1985-86 में थोड़ी-सी गिरावट आयी। इसके बावजूद मौजूदा प्रारक्षित निधियाँ 4-5 महीने के आयातों के बराबर हैं।

7. ऊपर बताये गये अनुसार अपर्याप्त औद्योगिक उत्पादन के अलावा, अर्थव्यवस्था के चिन्ताजनक लक्षणों में से उपभोक्ता मूल्यों की प्रवृत्ति और विदेशी भूगतान स्थिति पर पड़ते हुए दबाव प्रमुख हैं। ऊपर चर्चित थोक मूल्यों में गिरावट उपभोक्ता मूल्यों में हुई वृद्धि के साथ-साथ चलती है। विन्दुवार आधार पर उपभोक्ता मूल्यों ने 1984-85 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 1985-86 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मासिक औसत आधार पर 1985-86 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि के बराबर ही थी। इसलिए अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों पर सावधानीपूर्वक निगाह रखने की जरूरत होगी।

8. भुगतान संतुलन पर पड़ रहे दबाव, व्यापार घाटे की बड़ी मात्रा में पूरी तरह से उजागर हो रहे हैं। हालांकि तेल मूल्यों में हाल ही में की गयी कमी ने दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया है, परन्तु व्यापार घाटा सातवीं योजना के बाकी वर्षों के लिए चिंता का कारण बना रहेगा। इसी वजह से निर्यात वृद्धि में ऊंची दर प्राप्त करने की जरूरत महत्वपूर्ण हो गयी है।

कृषि उत्पादन

9. 1985-86, जो कि सातवीं योजना का पहला वर्ष था के दौरान कृषि उत्पादन ने केवल 1.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष उत्पादन में 0.9 प्रतिशत की मामूली-सी गिरावट आयी थी। इसका अर्थ यही हुआ कि 1983-84 के उत्पादन का स्तर ही प्राप्त किया गया। इसके विपरीत, 1982-83 और 1983-84 के दो वर्षों के दौरान वृद्धि की औसत दर 5.1 प्रतिशत बैठती है।

10. 1985-86 के दौरान कृषि क्षेत्र की कार्य स्थिति प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से प्रभावित रही। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आयी, जबकि दक्षिण, पश्चिम और मध्यवर्ती भारत के कुछ हिस्से भयंकर सूखे की चपेट में आ गये। 35 मौसमी विभागीय उप-खण्डों में से वर्ष के दौरान 9 उपखण्डों में बर्षा या तो कम या बहुत ही कम रही जबकि पिछले वर्ष ऐसी स्थिति 7 उपखण्डों में रही थी। इससे, और बरसात ठीक समय पर न होने और उसकी मीयाद में फर्क पड़ जाने की वजह से मोटे अनाजों के उत्पादन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा और यह 4.7-5.2 मिलियन टन तक की गिरावट के साथ, हाल के वर्षों के न्यूनतम स्तर, 26-26.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि चावल का उत्पादन 63.0-63.5 मिलियन टन के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाने के बावजूद वर्ष के दौरान कुल मिलाकर खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सा कम रहा।

11. खरीफ के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में मामूली गिरावट को रबी मौसम के दौरान बेहतर उत्पादन से पूरा कर लिया गया। गेहूं का 46.5-47.0 मिलियन टन का उत्पादन न केवल पिछले वर्ष के 44.2 मिलियन टन से अधिक था। बल्कि यह 1983-84 के दौरान प्राप्त किये गये 45.5 मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन से भी अधिक था। अलबत्ता, दालों का उत्पादन पिछले वर्ष के 12.0-12.5 मिलियन टन के स्तर पर स्थिर बना रहा।

12. कुल मिलाकर 1985-86 में खाद्यान्नों का उत्पादन 148.0-149.5 मिलियन टन आसपास आंका गया है। यह 1984-85 के 146.2 मिलियन टन के उत्पादन से लगभग 2-3 मिलियन टन अधिक है। जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सवाल है, जूट और मेस्ता का उत्पादन एक नये स्तर तक जा पहुंचा जबकि कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के ऊंचे स्तर पर ही बना रहा। गन्ने के उत्पादन में

मामूली-सी वृद्धि दर्शायी, लेकिन तिलहनों के उत्पादन काफी नीचे आ गये। कच्चे जूट और मेस्ता के 126 लाख गांठों के उत्पादन ने 1981-82 में प्राप्त किये गये 84 लाख गांठों के पिछले कीर्तिमान की तुलना में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1985-86 में उत्पादन में इस प्रचुर वृद्धि का श्रेय पिछले वर्ष कच्चे जूट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण। और अधिक बड़े क्षेत्र में इसके खेतों को दिया जा सकता है। हमारी उपभोक्ता आवश्यकताओं से कहीं अधिक मात्रा में इस रिकार्ड फसल से मूल्यों पर काफी गम्भीर प्रभाव पड़ा है और भारतीय जूट निगम को मजबूरन काफी बड़ी मात्रा में जूट समर्थन मूल्य पर खरीदना पड़ा है। कपास के 86-87 लाख, गांठों के उत्पादन ने जो पिछले वर्ष के उत्पादन से थोड़ा अधिक है, आपूर्ति स्थिति को सरल बनाये रखा और दाम कुछ नीचे आये। गन्ने का उत्पादन 175 मिलियन टन से सिर्फ मामूली-सा ज्यादा था लेकिन यह 1982-83 के दौरान दर्ज किये गये रिकार्ड उत्पादन से 14.5 मिलियन टन कम था। तिलहनों का 11.6 मिलियन टन का उत्पादन 1984-85 तथा 1983-84 के उत्पादनों से क्रमशः 1.5 मिलियन टन और 1.1 मिलियन टन कम था।

13. गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप हान अनाजों की खरीद भी ऊंचे स्तर पर बनी रही। चावल विपणन वर्ष में अब तक (अक्टूबर 1985- जून से 1986 तक) चावल की खरीद, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गयी खरीद के लगभग बराबर ही अर्थात् 9.6 मिलियन टन रही; इस वर्ष के दौरान कुल खरीद पिछले वर्ष के 9.8 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाने की आशा है। 1986-87 विपणन मौसम के दौरान गेहूं की खरीद एक नये उच्चतम स्तर तक पहुंचने की आशा है, क्योंकि 30 जून 1986 तक 10-41 मिलियन टन गेहूं की खरीद पिछले मौसम (अप्रैल-मार्च) की 10.34 मिलियन टन का रिकार्ड खरीद को पार हो पोछे छोड़ चुकी है।

14. भारत सरकार ने वर्ष के दौरान खाद्यान्नों को, विशेष रूप से गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उठाने में वृद्धि के लिए कई उपाय किये। इन में रोलर घाटा मिलों को गेहूं की 172 रुपये प्रति क्विंटल की घटी हुई दर पर आपूर्ति करना, विक्रेताओं को गेहूं की नीलामी करना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए बड़ी हुई मात्रा आवंटित करना और मात्रा को कोई सीमा बांधे बिना जनता को गेहूं जारी करना आदि शामिल थे। परिणाम यह हुआ कि वितीय वर्ष वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं उठाने में लगभग 3.0 मिलियन टन या 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.8 मिलियन टन अधिक हो गया। गेहूं उठाने में वृद्धि के एक बड़े हिस्से (1.7 मिलियन टन) का श्रेय रोलर घाटा मिलों को जाता है। शेष वृद्धि (1.3 मिलियन टन) में विक्रेताओं को निम्नी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उठाये गये गेहूं का हिस्सा बराबर-बराबर रहा। 1985-86 के दौरान उठाये गये 7.1 मिलियन टन चावल

भी 1984-85 के दौरान उठाये गये चावल (6.6 मिलियन टन) की तुलना में अधिक रहे।

15. इन वर्षों के दौरान अधिक उत्पादन की वजह से खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में खरीद और खरीद मूल्यों में वृद्धि तथा इनके साथ ही खुले बाजार में गेहूं की आसान उपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम मात्रा में गेहूं उठाये जाने की वजह से सरकार के पास खाद्यान्नों के रिकार्ड स्टॉक जमा हो गये हैं और जून 1985 को 29.2 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गये। इनमें 21.0 मिलियन टन गेहूं तथा 8.0 मिलियन टन चावल और 0.2 मिलियन टन मोटे अनाज शामिल थे। जून 1986 के अंत में खाद्यान्नों के स्टॉक 28.6 मिलियन टन के आसपास रहने का अनुमान है। इनमें 19.1 मिलियन टन गेहूं 9.4 मिलियन टन चावल और 0.1 मिलियन टन मोटे अनाज होंगे।

16. पटसन और रुई की खरीद नये रिकार्ड स्तरों तक जा पहुंची। 1985-86 के मौसम के दौरान भारतीय जूट निगम द्वारा पटसन की खरीद पिछले वर्ष 10.1 लाख गांठों की और 1981-82 में 17.6 लाख गांठों के पिछले कीर्तिमान की तुलना में 28 लाख गांठें रही इसी तरह भारतीय रुई निगम (सी.सी.आई.) ने 1985-86 में अब तक (जून 1986 तक) 15.3 लाख गांठें खरीदी हैं। और महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक विभाग महाराष्ट्र (एम.ए.सी.जी.एन.एफ.) ने 27.6 लाख गांठें खरीदी हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उनकी खरीद क्रमशः 6.4 लाख गांठें और 16.5 लाख गांठें थीं। सी.सी.आई. द्वारा पिछली बार, 1980-81 में अधिकतम 11.8 लाख गांठें खरीदी गयी थी जबकि महाराष्ट्र कपास एकाधिकार योजना के तहत अधिकतम खरीद 1982-83 में, 18.2 लाख गांठें रही थी।

17. चूंकि तिलहनों का उत्पादन मांग से बहुत कम हो गया है, अतः तिलहनों के मामले में स्थिति चिंता का कारण बनी रही। 1983-84 और 1984-85 में तिलहनों का उत्पादन बढ़ जाने के बाद यह गुजरात और मध्य प्रदेश के मूंगफली उगाने वाले इलाकों में सूखा पड़ जाने के कारण, 1985-86 में कम होकर 11.6 मिलियन टन रह गया। खद्य तेलों की उपभोक्ता जख्ती वगैरह एन.आई. पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये की औसत वार्षिक लागत पर आयात करके पूरा करता पड़ा। इन आयातों से निर्यात आय का दसवां हिस्सा खर्च हो गया।

18. सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर लगभग 18 मिलियन टन ले आने का है। इस स्तर पर उत्पादन देश की खाद्य तेलों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और लगातार आयात करने की जरूरत पड़ेगी। हाल ही के वर्षों में हालांकि तोरिया/सरसों तथा सोयाबीन के उत्पादन में आभासी वृद्धि हुई है, खाद्य

तेलों की जरूरत का काफी बड़ा भाग अभी भी मूंगफली के तेल से पूरा किया जा रहा है तथा मूंगफली के तेल का उत्पादन अधिकतर मानसून के रुख पर निर्भर होता है। तिलहनों का उत्पादन कम से कम समय में तत्काल बढ़ाये जाने की जरूरत है ताकि भुगतान संतुलन पर पड़ रहे बोझ को कम किया जा सके।

19. वनस्पति निर्माताओं द्वारा नये तेलों जैसे बिनोला तेल, चावल की भुली का तेल तथा कम मात्रा में पैदा होने वाले अन्य तेलों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति के उत्पादन में इस प्रकार के इस्तेमाल के अनुसार उत्पादन शुल्कों में रियायतों की घोषणा की गयी है। सरकार ने भी महंगे रिफाइनड तेलों-मूंगफली तथा तोरिया/सरसों-पर उत्पादन शुल्क लगा दिया है ताकि नये तेलों के लिए प्रतियोगी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। सरकार ने तिलहन उत्पादन के लिए फसल बीमा रक्षा की व्यवस्था भी की है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1986 में तिलहनों और वनस्पति तेलों पर बैंक अप्रिमों के न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत पाइंट की चोतरफा कमी की है और तिलहन उगाने के लिये इस्तेमाल में लाय जाने वाले, और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित अधिक उपज वाले संकर बीजों को अग्रणीकरण के सभी उपबंधों से छूट दे दी है।

20. तिलहनों के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि किये गये उपायों की सफलता पर निर्भर होगी। बहुत कम उपज होने पर, केवल ऊंचे मूल्यों से किसान को लाभप्रद प्रतिफल का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, ऊंचे बाजार मूल्यों का फायदा किसानों तक हर बार पहुंचाता की नहीं है। कुछ मूंगफली उत्पादक प्रदेशों से मूंगफली और मूंगफली का तेल बाहर ले जाने पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाये जाने से इन राज्यों में मूल्य नीचे बन रहे हैं इतना ही नहीं, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने के बावजूद खरीद एजेंसियों हमेशा ही उत्पादों को मजबूरन ओले-पीने दामों पर बिकने से नहीं रोक पाती। यह सुनिश्चित किय जाने की जरूरत है कि इस प्रकार की स्थिति न आए।

21. तिलहन उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए सही मूल्यों का निर्धारण और फसल बीमा की व्यवस्था के अलावा तिलहन टेक्नालॉजी में और विकास आवश्यक प्रतीत होगा। किसानों को उचित निवेश वस्तुएं, जैसे अच्छी किस्म के बीज और कीटनाशकों, ऋण विस्तार सेवाओं तथा सिंचाई सुविधाओं का भी जरूरत पड़ेगी। नष्ट हुई फसलों के फसल बीमा के अंतर्गत समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकारें तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्रों पर खास ध्यान दे सकती हैं और जहां किसानों को वास्तव में आय का लाभ मिलता हो, ऐसे क्षेत्रों में अन्य फसलों अर्थात् गेहूं और चावल की जगह तिलहन उत्पादन की ओर व्यवस्थित रूप से प्रेरित करने के प्रयास कर सकती हैं।

22. कुल मिलाकर, अब देश जहाँ गेहूँ, चावल, कपास और पटसन के क्षेत्र में काफी अच्छी स्थिति में है, वहीं तिलहन, दालों और गन्ने के उत्पादनों में कमी बनी हुई है। इसमें से कुछ कमियाँ वर्षा वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता में पिछड़ेपन के साथ जुड़ी हुई है। इनके अलावा, अलग-अलग किस्मों की दृष्टि से भी असंतुलन देखने में आते हैं; जैसे कपास के मामले में लम्बे और अतिरिक्त लम्बे रेशों वाली कपास का उत्पादन उपभोग के वर्तमान स्तर से काफी अधिक हुआ है। उत्पादन का ये घटना-अकृता चिन्ता का कारण बने हुए हैं। अधिक उत्पादनों से भण्डारण और विपणन और साथ ही बढ़ी हुई आर्थिक सहायता की समस्याएँ सामने आती हैं जबकि उत्पादन कम होने से भुगतान संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

23. कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के फसलवार और क्षेत्रवार असंतुलनों को दूर करने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है जिनके जरिये विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक विशेषताओं

को ध्यान में रखते हुए फसलों के लिए स्रोतों का बेतहर आबंटन किया जा सके। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विपणन को शामिल करते हुए बनायी एक समेकित कृषि नीति बहुत अहम भूमिका अदा कर सकती है।

औद्योगिक उत्पादन और निवेश की प्रवृत्तियाँ

24. सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि की दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की योजना बनायी गयी है। विनिर्माण क्षेत्र में 8.0 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जबकि बिजली उत्पादन में 12.1 प्रतिशत और खनन क्षेत्र में 13 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 1985-86 अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन (समायोजित सूचक) में अंतिम आंकड़ों के आधार पर वृद्धि 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 1)।

सारणी 1—औद्योगिक उत्पाद की प्रवृत्तियाँ*

आधार 1970-100

उद्योग	भार	वित्तीय वर्ष			
		1984-85		1985-86	
		सूचकांक	प्रतिशत वृद्धि दर	सूचकांक	प्रतिशत वृद्धि दर
1. खनन और उत्खनन	9.69	234.8	+ 8.1	245.5	+ 4.6
2. विनिर्माण	81.08	183.0	+ 5.7	194.1	+ 6.1
3. विद्युत	9.23	285.0	+ 12.0	309.4	+ 8.6
4. सामान्य सूचक	100.0	197.4	+ 6.8	209.8	+ 6.3

*औद्योगिक उत्पादन के समायोजित सूचकों पर आधारित

25. इसके विपरीत 1984-85 में वृद्धि दर संशोधित आंकड़ों के आधार पर 6.8 प्रतिशत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1985-86 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट आयी है। यह गिरावट विद्युत के मामले में सबसे अधिक थी जहाँ 1985-86 में वृद्धि दर पिछले वर्ष की 12.0 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 8.6 प्रतिशत कम हुई। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।

क्षेत्रवार प्रवृत्तियाँ

26. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 137 मदों के बारे में आंकड़े उपलब्ध न होने से, 1983-84 से शुरू करते हुए, सूचक में 11.69 प्रतिशत के संयुक्त भार के साथ, समायोजित भार इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक उत्पादन का सूचक तैयार किया है। नीचे दिया गया विश्लेषण उक्त सूचक में दिये गये समायोजित भारों पर आधारित है। खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1984-85 की 8.1 प्रतिशत की तुलना में 1985-86 में 4.6 प्रतिशत की कम वृद्धि दर का कारण कोयले

(लिग्नाइट को छोड़कर) और कच्चा पेट्रोलियम था। कोयले (लिग्नाइट को छोड़कर) के उत्पादन दौरान ने वर्ष के 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह 154.3 मिलियन टन रहा। पिछले वर्ष की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी। कोयले के उत्पादन में गिरावट विशाल पिट-हड्ड स्टाकों को देखते हुए उत्पादन में जानबूझ कर की गयी कमी की वजह से हुई। कच्चे पेट्रोलियम का 30.2 मिलियन टन का उत्पादन 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो कि सातवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप ही है। लेकिन यह पिछले वर्ष की 11.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम है।

27. विद्युत के क्षेत्र में नाभिकीय बिजली सहित ताप बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष हुई 14.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन वर्षा कम होने के कारण जलविद्युत के उत्पादन ने पिछले वर्ष की 7.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शायी। परिणामस्वरूप, कुल बिजली उत्पादन में जलविद्युत का हिस्सा 1984-85 के 34.3 प्रतिशत से कम होकर

1985-86 में 30 प्रतिशत रह गया। मांग के अनुपात के रूप में बिजली आपूर्ति की अखिल-भारतीय कमी, वर्ष के दौरान 7.9 प्रतिशत हो गयी जबकि 1984-85 में यह प्रतिशत 6.7 था। पूर्वी क्षेत्र में कमी सबसे अधिक—13.8 प्रतिशत रही। इसके पश्चात् उत्तरी क्षेत्र (10.7 प्रतिशत) और दक्षिणी क्षेत्र (9.3 प्रतिशत) रहे। मांग की तुलना में बिजली की कम उपलब्धता को देखते हुए कई राज्यों को बिजली में कटौती करना पड़ी/प्रतिबंध लगाने पड़े। पश्चिम बंगाल के मामले में यह कटौती 5-30 प्रतिशत के बीच और हरियाणा के मामले में 60-70 प्रतिशत के बीच में रही। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य थे जहाँ भीषण रूप से बिजली की कटौती की गयी। बिजली

क्षेत्र की वृद्धि दर में कम बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत स्थिति की द्योतक है।

तिमाही प्रवृत्तियाँ

28. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का तिमाही आधार पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि 1985-86 की दूसरी छमाही के दौरान वर्ज की गयी वृद्धि दर पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गयी वृद्धि दर से तज थी। पिछले वर्ष पहली छमाही में वृद्धि की उंची दरें दर्ज की गयी थीं (सारणी 2)।

सारणी 2

औद्योगिक उत्पादन में तिमाही वृद्धि दरें*
(आधार 1970-100)

(प्रतिशत रूप में)

अवधि	सामान्य सूचक		खनन और उत्खनन		विनिर्माण		विद्युत	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
अप्रैल-जून	+ 6.9	+ 5.8	+ 14.1	+ 1.1	+ 4.4	+ 6.1	+ 15.6	+ 7.8
जुलाई-सितम्बर	+ 8.6	+ 5.3	+ 5.4	+ 3.0	+ 8.2	+ 4.9	+ 13.8	+ 9.9
अक्तूबर-दिसम्बर	+ 5.2	+ 7.2	+ 4.3	+ 5.3	+ 4.3	+ 7.3	+ 11.4	+ 7.0
जनवरी-मार्च	+ 6.4	+ 6.6	+ 8.9	+ 7.8	+ 5.8	+ 6.0	+ 7.7	+ 9.5

* औद्योगिक उत्पादन के समायोजित सूचकों पर आधारित

यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष की दूसरी छमाही में, वर्ष की पहली छमाही और साथ ही 1984-85 की दूसरी छमाही के दौरान प्राप्त की गयी वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गयी।

आधारभूत षांचा

29. 6 आधारभूत उद्योगों [अर्थात्, बिजली, कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर), कच्चा पेट्रोल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, बिज्जी योग्य स्टील तथा सीमेंट] के मिले जुले सूचक ने, जिसका औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचक में संशोधित भार 24.25 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की 9.9 प्रतिशत की तुलना में 1985-86 के दौरान 8.2 प्रतिशत की कम वृद्धि दर दर्ज की।

30. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन ने 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि बिज्जी योग्य स्टील के उत्पादन ने 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। बाकी उद्योगों में से जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अल्प वृद्धि दरें दर्ज कीं, बिजली उत्पादन तथा कच्चे पेट्रोलियम ने 1985-86 के लिए निर्धारित क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दरों से थोड़ा सा अधिक उत्पादन किया।

उपयोग-आधारित और निवेश आधारित वर्गीकरण के आधार पर प्रवृत्तियाँ

31. औद्योगिक उत्पादन के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि पूंजीगत माल, माध्यमिक

माल और उपभोगता सामान के उद्योगों ने 1985-86 में ऊँचा वृद्धि दर्ज की, प्रत्यक्षता, मूल उद्योग समूह अपवाद

रहा और उसने पिछले वर्ष की तुलना में नौवें वृद्धि दर दर्ज की: (सारणी-3)।

सारणी 3

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि: उपयोग—प्राधारित वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

उद्योग समूह	वित्तीय वर्ष		
	भार	1984-85	1985-86
मूल उद्योग	33.23	+ 9.5	+ 7.2
पूँजीगत वस्तु उद्योग	14.98	+ 2.6	+ 3.5
माध्यमिक वस्तु उद्योग	21.33	+ 9.5	+ 10.2
उपभोग्य वस्तु उद्योग	30.46	+ 3.2	+ 3.8
(क) टिकाऊ वस्तुएं	3.81	+ 19.1	+ 14.4
(ख) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	26.65	+ 0.4	+ 1.6

32. मूल उद्योग समूह के उल्लेखन्य न्यूनतर वृद्धि दर मुख्यतः कोयला उत्पादन के न्यूनतर वृद्धि दर के कारण थे। इस समूह का कार्य निष्पादन भा.स.में उत्पादन में न्यूनतर वृद्धि दर और एल्युमिनियम के उत्पादन में गिरावट, इन विजन अधि. उद्योगों पर विज्ञान के कम के प्रतिकूल प्रभाव का प्रदर्शित करता है। पूँजीगत वस्तु समूह में, बॉयलर, स.मेंट, मशीन तथा बॉल और रोलर बियरिंग उद्योगों के उत्पादन में वर्ष 1984-85 के तुलना में वर्ष 1985-86 में उच्चतर दर पर वृद्धि हुई, जबकि कागज और लुगद मशीन, कृषि संबंधी ट्रैक्टरों तथा मशीन औजारों जैसे उद्योगों के उत्पादन ने गिरावट का सामना किया। रेल बगनों का उत्पादन वर्ष 1984-85 में प्रायः 25.1 प्रतिशत का तथा गिरावट के विपरीत मामूल रूप से बढ़ा। मध्यवर्ती वस्तु समूह में वर्ष 1985-86 के दौरान सूत धागे, म्यूजप्रिट और नायलॉन धागे के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का तुलना में ऊँचा वृद्धि दर प्राप्त हुई था। इस समूह के कार्यक्षेत्र में आने वाले जूट वस्त्र उद्योग, सियेटिक रबड़ और विस्कोज टायर काँई के उत्पादन में 1985-86 के दौरान गिरावट दर्ज की गई। उपभोग्य उद्योग समूह के टिकाऊ वस्तु खण्ड ने पिछले वर्ष के दौरान हुई 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 14.4 प्रतिशत के उल्लेखन्य वृद्धि दर्ज की। मोटर वाहन, स्कूटर, तिपहिया (थ्रीव्हीलर), स्कूटर और बिजली के पंखे जैसे टिकाऊ वस्तुओं ने अपनी निम्ने दर्ज की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1985-86 में उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की। गैर-टिकाऊ उपभोग्य वस्तु समूह के उत्पादन में 1984-85 के 0.4 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस समूह के अंतर्गत आने वाले चमड़ा, कागज और गन्ना, विद्यासज्जाई, रेजर ब्लेड और रबड़ के जूते जैसे उद्योगों में वर्ष 1985-86 के दौरान सुधार परिलक्षित हुआ और उनमें उच्चतर उत्पादन स्तर दर्ज किये गये जबकि पिछले वर्ष की तुलना में उद्योगों के उत्पादन में गिरावट पायी। कपड़ा (मिल क्षेत्र), वनस्पति, साबुन और सिगरेट जैसे उद्योगों

में वर्ष 1985-86 के दौरान उत्पादन में गिरावट परिलक्षित हुई।

33. निवेश-प्राधारित वर्गीकरण के अनुसार, कृषि-प्राधारित उद्योग समूह ने पिछले वर्ष दर्ज की गई 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 2.9 प्रतिशत का अल्प वृद्धि दर दर्ज की। धातु-प्राधारित उद्योगों ने पिछले वर्ष की 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 5.4 प्रतिशत की ऊँची वृद्धि दर दर्ज की। रसायन-प्राधारित उद्योगों के मामले में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर 1984-85 के स्तर पर हासिल रहा।

क्षमता सृजन और उपभोग

34. औद्योगिक उत्पादन के सूचक में 53.64 प्रतिशत के संशोधित भार वाले चुने हुए उद्योगों में 1985-86 में क्षमता सृजन के प्रांकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि चुने हुए मूल सामान उद्योग (भार 17.31 प्रतिशत) तथा माध्यमिक उद्योग (भार 13.77 प्रतिशत) ने 1984-85 में दर्ज की गयी क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की तुलना में क्षमता में 7.9 प्रतिशत प्रत्येक की ऊँचा दर पर बढ़ोतरी की। चुने हुए उपभोग्य सामान उद्योग (भार 16.53 प्रतिशत) के मामले में 1984-85 में प्राप्त की गयी क्षमता सृजन की ऊँचा दर प्राप्त न की जा सकी। प्रत्यक्षता पूँजीगत माल समूह की क्षमता में वृद्धि के बारे में उतने निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर 1985-86 में स्थापित क्षमता में वृद्धि 9.5 प्रतिशत के आसपास या जबकि पिछले वर्ष चुने हुए उद्योगों के संबंध में यह 7.9 प्रतिशत था।

35. हालांकि चुने हुए उद्योगों में क्षमता वृद्धि के प्रांकड़ों से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश संबंधी गतिविधि का हल्कासा आभास मिलता है लेकिन इन प्रांकड़ों से पूरे औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर उभरकर नहीं आती। इसके अलावा लम्बे अवधि वाली परियोजनाओं में होने वाले विलम्बों को देखते हुए इन

प्रवृत्तियों से पिछले वर्षों में किये गये निवेशों के परिणामों का हवाला पता चल पाता है। सम आधुनिक वर्ष के दौरान निजी निगम क्षेत्र में औद्योगिक निवेश का प्रवृत्तियों का अधिक स्पष्ट जानकारी अखिल भारतीय अर्थशास्त्र संस्थाओं द्वारा किये गये वितरणों तथा बाजार से उगाहा गया। कुल पूँजा के आंकड़ों से मिल सकता है। तब प्रमुख अर्थशास्त्र संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक अर्थ और निवेश निगम) के वितरणों का राशि जो कि लगभग 3,387 करोड़ रुपये था पिछले वर्ष के वितरणों का तुलना में 31.2 प्रतिशत अधिक था। निवेश मापन के मूल्यां में वृद्धि के लिए गुंजाइश रखने के बाद भी ये आंकड़े निजी निगमित क्षेत्र में औद्योगिक निवेश में वृद्धि दर्शाते हैं। और सरकारी कंपनियों द्वारा जुटाया गया पूँजा के अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने बाजार से 1984-85 के 857 करोड़ रुपये का तुलना में इस वर्ष 935 करोड़ रुपये जुटाए।

36. औद्योगिक उत्पादन संसूचक में 61.66 प्रतिशत वार (तथापेक्षा) वाले 51 उद्योगों के संकेत में निकाले गये अमरा-उद्योग-प्रवृत्तियों से 1985-86 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को गिरावट का शोका सा प्रभाव मिला है। 1985-86 में लगभग 22 उद्योगों (वार 19.12 प्रतिशत) व 80 प्रतिशत या अधिक के अमरा-उद्योग-प्रवृत्तियों दर्ज किये। इसमें फॉसफैटिक उर्वरक, बॉल और रोलर बियरिंग, पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद, स्पूजिस्ट, साइकलों के टायर, नाइलॉन फिजमेंट यार्न तथा बिजली के पंख शामिल हैं, जिन्होंने 1984-85 के प्रारंभ उत्पादन स्तरों का तुलना में 1985-86 में ऊँचे अमरा-उद्योग-प्रवृत्तियों दर्ज किए। ट्रैक्टरों, मशीनों के पुर्जों, जूट निमित्तियाँ, ताबुन तथा बिजली के तैनों जैसे उद्योगों में पिछले वर्ष का तुलना में अमरा-उद्योग तथा उत्पादन स्तर, दोनों में ही गिरावट आयी, जहाँ-जहाँ वर्ष इसका अमरा-उद्योग-प्रवृत्तियों 80 प्रतिशत में अधिक रहा था। ऑटोमोबाइल टायर, पॉलिस्टर, रेन, पेंट तथा वाणिज्य तथा दुग्धिया मादिर्यों ने उच्चतर अमरा गुण के कारण ऊँचे उत्पादन स्तरों के बावजूद भी अमरा-उद्योग प्रवृत्तियों दर्ज किये। अन्य उद्योगों में से, समेंट, डबल इजिन, स्टारज बेटरियों, त्रिपेडल डिजेंट, चमड़े के जूतों और काटन स्विचिंग के उत्पादन में दर्ज वृद्धि का दृष्टि से उल्लेखन्य था कि उद्योग 1984-85 का तुलना में प्रारंभ अमरा उत्पादन और अमरा उद्योग के प्रवृत्तियों में वृद्धि दर्ज की।

37. कुछ उद्योगों में स्टॉकों के जमाव की स्थिति का विश्लेषण विशेषतः कुछ क्षेत्रों में व्याप्त इस भय के संदर्भ में कि मान में गिरावट से उद्योग के कुछ क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है आवश्यक प्रतीत होता है। वाणिज्यिक बाहनों के अन्तिम आंकड़े रखने से पता चलता है कि पिछले वर्ष को 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का तुलना में 1985-86 में उत्पादन में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरा और विक्रियों में

1984-85 का 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध 1985-86 में 0.8 प्रतिशत की अन्तर्गत गिरावट आयी। अन्तर्गत और अधिक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस उपतनुह के मत ह मशीने और भार वाहन तथा हल्के वाणिज्यिक वाहनों के विक्रियों के प्रवृत्तियों में अमरा आसमान का अंतर है। मशीने और भार वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन की वृद्धि दर 1984-85 के 2.5 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 0.7 प्रतिशत रह गयी जबकि पिछले वर्ष विक्रियों के वार 1.3 प्रतिशत बढ़ने के बाद 1985-86 में 5.2 प्रतिशत कम हा गयी। दरम्यान, विक्रियों 1982-83 तथा 1983-84 में भी क्रमशः 1.1 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े। इस वजह से उत्पादन और विक्रों के बीच अंतरा रह जाँके कारण स्टॉक इकट्ठे हो गये, जहाँ-जहाँ पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्पादन की वृद्धि दरें काफी ताब थीं। हल्के और भार वाणिज्यिक वाहनों की विक्रों पर शायद हल्के वाणिज्यिक वाहनों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता तथा रेलों का सुधार हुई निष्पादकता का बुरा असर पड़ रहा है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों के विक्रों की वृद्धि दर 1983-84—1985-86 के तनों वर्षों के दौरान 9 प्रतिशत वाणिज्य के हितार्थ से बढ़ती रह रही है। हालाँकि पिछले दो वर्षों से इन क्षेत्रों में भी विक्रों के दर में मामूल से गिरावट नजर आने लग रही है।

38. समेंट उद्योग में बहुत अधिक स्टॉक जमा नहीं हुए, क्योंकि उत्पादन और मापूति में समुलन बना रहा। 1985-86 में बड़े समेंट संयंत्रों में 3.7 मिलियन टन के उत्पादन स्तर के बावजूद वर्ष के अंत में उनके पास 0.6 मिलियन टन के स्टॉक जमा थे। 1985-86 के दौरान माइक्रो-जिनय उर्वरकों के स्टॉक और अधिक बढ़ गये, हालाँकि उनके उत्पादन की वृद्धि दर 1984-85 को 12.2 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 10.5 प्रतिशत रह गई थी। उर्वरकों के विक्रों जो कि 1984-85 में 7.2 प्रतिशत बढ़े थे 1985-86 में इस विक्रों में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि का संभवता है। माइक्रो-जिनय उर्वरकों के बढ़ते हुए स्टॉकों को देखते हुए 1986-87 के लिए आयातों में यथाचित समायोजन की जरूरत है।

औद्योगिक रुग्णता

39. औद्योगिक रुग्णता चिंता का कारण बन रही है। उपभोक्तात्मक उपायों के लिये रुग्णता के विभिन्न कारणों का अंतर समझना आवश्यक है विशेषतः ऐसे कारणों के बीच जो किम एक पूरे उद्योग की रुग्णता के लिये विशेषतः जिम्मेदार है, और अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के लिये विशेषतः उत्तरदाय है रुग्ण इकाइयों का भाव अर्थक्षमता का साधन-पूर्वक मूल्यांकन एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालाँकि सख्त इकाइयों को फिर से चलाने के पूरे प्रयास किये जाने चाहिए। ऐसे इकाइयों के बारे

में भी कठोर निर्णय करने से नहीं कतराना चाहिए जिन्हें फिर से चलाया नहीं जा सकता। किसी इकाई का रूपण इकाई के रूप में पता लगाये जाने के बावजूद उसका अर्थक्षमता का सम्पादन करने के लिए तथा इस उद्देश्य के लिए विस्तृत मानदण्डों के व्यापक ढाँचे के अन्तर्गत उनके लिए उपयुक्त पुनर्वास कार्यक्रम बनाने के लिए बैंकों तथा मालिकों के संस्थाओं के बीच समेकित कार्यनिति सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 1985 में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। रूपण इकाइयों के पुनर्वास के लिए तथा नये इकाइयों में समाविष्ट रूपणता का शास्त्र हाँ पता लगाने को दृष्टि से सरकार ने एक नया अधिनियम अर्थात् रूपण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 पारित किया है जिसमें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित करने का व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को एक सार्वजनिक कनिगम अर्थात् भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में बदल दिया गया है ताकि औद्योगिक पुनरुज्ज्वलन के लिए प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण एजेंसियों के रूप में इन्हें भूमिका को मजबूत किया जा सके और उद्योगों के पुनर्निर्माण में लगा अन्य संस्थाओं की कार्यो का समन्वय किया जा सके। औद्योगिक रूपणता की समस्या को जितना बजह से रोजगार का नुकसान पूंजगत आस्तियों का बरखार उत्पादन का हानि, और खजाने में राजस्व का कम होना है दायरों का पता इस तथ्य से चल जाता है कि कुल बैंक ऋण का लगभग 8 प्रतिशत इन रूपण इकाइयों में फंसा पड़ा है। जून 1983 और 1985 के बीच बढ़े मशीनें और अन्य क्षेत्रों में रूपण इकाइयों के रूप में निर्धारित इकाइयों का संख्या 66,062 से बढ़कर 99,668 हो गया और उनमें अटके पड़े ऋण को राशि 2,793 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,805 करोड़ रुपये हो गया।

1986-87 के दौरान औद्योगिक वृद्धि के लिए परिदृश्य

40. जैसा कि पहले बताया जा चुका है सातवीं योजना को सफलतापूर्वक लागू करना अनिवार्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र की निष्पादनता पर निर्भर है, जिसके लिए अंतिम 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर का कल्पना की गयी है। निवेश की ऊँचा दर प्राप्त करने में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अब तक महसूस की जा रही अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार से कई उपायों का घोषणा की है। अधिक उत्पादन के रूप में इन उपायों का प्रभाव पड़ने में कुछ और समय लग सकता है। उद्योग को आधुनिक बनाने और उत्तम प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक और पूंजगत माल के आयात का सुविधा दी गयी है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि की ऊँचा दर के लाभ नहीं मिले हैं। 1986-87 में कृषि उत्पादन में सुधार से औद्योगिक उत्पादन की बेहतर वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए मदद मिलना चाहिये। वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार उस वर्ष मानसून अनुकूल रहा और इस बात की सम्भावना

है कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा। अच्छे मानसून से अवधिगत शक्ति का भी अधिक उत्पादन होगा। अतः यह उम्मीद करना बिल्कुल उचित होगा कि 1986-87 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1985-86 में दर्ज की गयी 6.3 प्रतिशत की तुलना में ऊँचा रहे।

राष्ट्रीय आय बचत और निवेश

41. वास्तविक रूप में एक राष्ट्रीय आय में 1985-86 के दौरान वृद्धि दर 4 प्रतिशत के आसपास रहने की सम्भावना है जबकि 1984-85 में यह 3.7 प्रतिशत थी। 1985-86 में कृषि उत्पादन के बारे में अनुमान है कि यह पिछले वर्ष के स्तर से लगभग एक प्रतिशत बढ़ा है। 1984-85 में इसमें 0.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन का 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर 1984-85 की वृद्धि दर से थोड़ा-सा कम था। कुल शुद्ध देशांतर 1985-86 में चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 16.1 प्रतिशत पर रहने का अंतिम अनुमान लगाया गया है जोकि पिछले दो वर्षों के लगभग बराबर हो है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत जो 1983-84 के 14.1 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 14.5 प्रतिशत हो गयी थी, 1985-86 में और बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो गयी है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र का बचत जो 1983-84 के 1.8 प्रतिशत से कम होकर 1984-85 में 1.1 प्रतिशत रह गया था 1985-86 में और कम होकर 0.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। बरेलू निजी निगमित क्षेत्र का शुद्ध बचत जो 1983-84 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 0.6 प्रतिशत हो गया था 1985-86 में भी उसी स्तर पर बना रहने का अनुमान है।

42. अंतिम आँकड़ों से पता चलता है कि कुल शुद्ध निवेश में वृद्धि हुई और वह 1984-85 के चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 18.1 प्रतिशत हो गया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुपातित शुद्ध बरेलू बचत और निवेश के आँकड़े सारणी 4 में दिये गये हैं।

43. हाजाकि पहले इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में बरेलू क्षेत्र की कुल बचत में वृद्धि हुई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वित्तीय आस्तियों के रूप में बचत के अनुपात में मामूला सा गिरावट देखने में आयी। दूसरी ओर भौतिक आस्तियों के रूप में बचत जो 1983-84 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 6.2 प्रतिशत से गिरकर 1984-85 में 5.2 प्रतिशत रह गया था 1985-86 में फिर बढ़कर इसके 5.7 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है।

सारण: 4-घरेलू बचत और निवेश के अनुमान
(चालू बाजार)

(प्रतिशत रूप में)

क्षेत्र/मह	राजकीय वर्ष		
	1983-84	1984-85 (अनुमानित)	1985-86 (प्रारम्भिक अनुमान)
1. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में घरेलू क्षेत्र की शुद्ध बचत जिनमें से वित्तीय परिसंपत्तियों में बचत	14.1 7.9	14.5 9.3	14.9 9.2
2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी क्षेत्र की शुद्ध बचत	1.8	1.1	0.6
3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू निजी निगमित क्षेत्र की शुद्ध बचत	0.4	0.6	0.6
4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में (1+2+3) में कुल शुद्ध घरेलू बचत	16.3	16.2	16.1
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद विदेशी संसाधनों का आगम	1.7	1.3	2.0
6. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुल निवेश (4+5)	18.0	17.5	18.1

टिप्पणी: 1983-84 तथा 1984-85 के शुद्ध अनुपात पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाते, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अनुमानों में बाव में त्रुटि और आंकड़ों उपलब्ध होने पर बचत एवं निवेश में काफी संशोधन किये गये।

44. वित्तीय आस्तियों के रूप में घरेलू बचत जो 1983-84 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 9.3 प्रतिशत हो गयी थी, 1985-86 में मामूली-सी कम होकर 9.2 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। अलबत्ता, सामान्य रूप में वित्तीय आस्तियों के रूप में बचत में वृद्धि 1829 करोड़ रुपये के आस-पास रही। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों में बचत के अनुपात में अनुमानित मामूली सी कमी मुख्य रूप से मुद्रा और बैंक जमा राशियों के रूप में अपेक्षाकृत कम बचत की वजह से हुई थी। मुद्रा विस्तार की तेजी से घटी हुई दर से मुद्रा के रूप में बचत में कमी आयी है और यह 1984-85 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 1.0 प्रतिशत रह गया है। हालांकि वाणिज्य बैंकों की कुल बैंक जमा राशियों (विदेशी मुद्रा अनिवार्य तथा अनिवार्य विदेशी जमा राशियों को छोड़कर) में 1985-86 में 11,243 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी और 1984-85 में यह वृद्धि 10,892 करोड़ रुपये की थी। फिर भी वृद्धि दर 1984-85 के 18.8 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 16.4 प्रतिशत रह गयी। तदनुसार, वित्तीय बचतों के अनुपात के रूप में बैंक जमा राशियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत 1984-85 के 42.7 प्रतिशत से गिरकर 1985-86 में 41.4 प्रतिशत रह गयी। यह गैर-बैंकिंग बचत साधन, विशेष रूप से अल्प बचत के प्रति आकर्षण की दृष्टिकोण है। बैंक जमा राशियों के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत 1985-86 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 4.8 प्रतिशत निकलती है, जबकि यह 1984-85 में 5.1 प्रतिशत थी।

45. अलबत्ता, सरकार पर दायों ने 1984-85 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से वृद्धि दर्शायी है

और वे 1985-86 में 1.9 प्रतिशत हो गये हैं। गैर-बैंकिंग कंपनियों की बचत भी 1984-85 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 0.6 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। घरेलू क्षेत्र की देयताएँ जो 1983-84 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 2.9 प्रतिशत घटकर 1984-85 में 2.6 प्रतिशत रह गयी थीं, 1985-86 में और कम होकर 2.4 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

46. सार्वजनिक क्षेत्र की बचत मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा बचत न कर पाने की वजह से 1984-85 के शुद्ध, राष्ट्रीय उत्पाद के 1.1 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 0.6 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। यहाँ यह बताया जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का अनुमान लगाते समय तेल कंपनियों की अतिरिक्त निधियों को तेल समन्वयन समिति को अंतरित किये जाने को पहले की तरह शामिल नहीं किया गया है, अतः सार्वजनिक क्षेत्र की बचत के स्तर में अनुमान कुछ कम लगाया गया है।

47. विदेशी स्रोतों की शुद्ध आवक जो 1983-84 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से घटकर 1984-85 में 1.3 प्रतिशत रह गयी थी, 1985-86 में उसके फिर से बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है। फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल शुद्ध निवेश का 1984-85 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 18.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

ऋण नीति विषयक गतिविधियाँ

नीति की प्रमुख विशेषताएं

48. अर्थव्यवस्था में समग्र नकदी (एम 3) की वृद्धि दर का नियंत्रण ही 1985-86 के दौरान तथा राजकोषीय वर्ष 1986-87 के शुरू के अर्धवर्ष के दौरान ऋण नीति का प्रमुख लक्ष्य बना रहा। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभिक धन की मात्रा तथा समग्र नकदी में बहुत अधिक वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि मुद्रा स्फीति को फिर से बहुत उभरने से रोकने के लिए सतर्क ऋण नीति जारी रखी जाये। अतएव, यह निर्णय लिया गया कि 1985-86 में नकदी की कुल वृद्धि को 1984-85 की तुलना में नीची दर पर रखा जाये। पिछले तीन वर्षों के विपरीत, जहाँ प्रारंभिक आस्तियों को बढ़ाना स्थूल मौद्रिक प्रबंध का मुख्य घटक बना रहा, 1985-86 में प्रारंभिक आस्तियों में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी; सिवाय मार्च, 1985 में घोषित सांविधिक चलनिधि अनुपात के, जिसे जुलाई 1985 तक दो चरणों में पूरा किया गया था। अलक्ष्यता, प्रारंभिक आस्तियाँ नीति निर्धारण की मुख्य घुरी बनी रहीं। लेकिन सांविधिक चलनिधि अनुपात को दैनिक आधार पर कारगर ढंग से बनाये रखने पर जोर दिया गया। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सांविधिक चलनिधि अनुपात में व्यतिक्रम करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी थी। ऋण प्राधिकरण योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गयी थी और इस अवधि के दौरान वित्तीय लेनदेनों की मात्रा और प्रकार में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विनिर्माता/व्यापारी निर्यातक के लिए कार्यशील पूंजीगत सीमाओं के लिए न्यूनतम सीमाओं में तथा तदर्थ सीमाएं मंजूर करने के लिए बैंकों के विवेकाधिकारों में कुछेक परिवर्तन किये गये थे। "तुरंत कार्रवाई" (फास्ट ट्रेक) योजना तथा वित्तीय अनुभासन में ढील दिये बिना योजनाएं लागू करने में अधिक लचीलापन लाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़े उधार खाते अंतरित करने के लिये विनियम में भी परिवर्तन किये गये। इसके अलावा, चपलात्मक ऋण नियंत्रकों को विवेकपूर्ण बनाया गया और विदेशी मुद्रा अनिवासी योजना के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा राशियों पर व्याज दरों को विदेशों में लागू व्याज दरों को विदेशों में लागू व्याज दरों के अनुरूप बनाते हुए कम किया गया। कुल मिलाकर, हाल ही में किये गये नीतिगत परिवर्तन कमोबेश उपायों को विवेकपूर्ण बनाने के रूप में थे और इनमें मौजूदा उपायों को कारगर ढंग से लागू करने पर अधिक जोर दिया गया।

बजट घाटे तथा मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण की संकल्पना में परिवर्तन

49. चक्रवर्ती समिति ने सिफारिश की थी कि बजट घाटे की परिभाषा बदल कर उसे सरकार को रिजर्व बैंक के कुछ ऋण कर दिया जाये ताकि इससे बजटीय घाटे के

मुद्दीकरण को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। समिति की इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है और बजटीय घाटे की संकल्पना में ऋणबद्ध रूप से परिवर्तन के बारे में उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे रिजर्व बैंक के पास अपनी नकदी शेष राशियों में तथा खजाना बिलों में अपनी धारिताओं में बहुत अधिक परिवर्तन करने से बचें क्योंकि इन गतिविधियों से सरकार को रिजर्व बैंक के कुछ ऋणों में अस्थिरता पैदा होती है। बैंकों को सूचित किया गया कि प्रारंभिक चल निधि अनुपात अपेक्षाओं का औसत निकालने की सुविधा उन्हें अपनी नकदी के प्रबंध में कुछ लचीलापन लाने के लिए दी गयी थी, लेकिन इस सुविधा का उपयोग नकदी शेष राशियों में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव लाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा मंजूर की गयी चक्रवर्ती समिति की दूसरी सिफारिश मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण शुरू करने से संबंध रखती है। इससे यह संकेत मिलेगा कि राजकोषीय और मौद्रिक, दोनों ही नीतिगत उपायों को मौद्रिक सकल राशियों के उतार-चढ़ावों से और अधिक निकटता से जोड़ा जायेगा।

नीतिगत उपाय—अप्रैल 1985

50. 1985-86 की पहली छमाही को यह अवधि माना जाना था जब बैंकिंग तंत्र को अपने स्रोतों को बचा कर रखा था और प्रारंभिक अपेक्षाओं को पूरा करने में अनेकालो किसी भी कमी को दूर करना था। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि इस अवधि के दौरान दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात के पर्याप्त रखरखाव के लिए कारगर और सक्षम प्रयास होते चाहिए। समग्र नकदी निधि को वृद्धि को सीमित करने और 1985-86 की पहली छमाही के दौरान ऋण आवश्यकता को पूरा करने को जल्दतः देखते हुए अप्रैल 1985 के दौरान कुछ नीतिगत उपायों को घोषणा की गयी थी। उन न्यूनतम स्तरों में जिनसे ऊपर बैंकों को खाशान्न खरीदने के लिए शत-प्रतिशत पुनर्निवेश उपलब्ध कराया जाता है, वृद्धि करने उन्हें बढ़ाया गया तथा पुनर्निवेश दर में भी, जिनमें कई वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, यथावत रूप से सुधार किया गया। इन वर्षों के दौरान चपलात्मक ऋण नियंत्रण, जो कि बहुत अधिक जटिल होते चले गये थे और जिन्हें बैंक ऋणों को अनिवार्य वस्तुओं की सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी रोकने के मुख्य लक्ष्य से हटे बिना विवेकपूर्ण बनाने को जरूरत थी, सरल बनाया गया। कुछेक वस्तुओं के लिए प्रादेशों में दोहराव से बचते हुए, कई ऐसे नियंत्रण समाप्त कर दिये गये, जिन्हें अब जरूरी नहीं समझा गया।

नीतिगत उपाय—जुलाई 1985

51. 29 मार्च 1985 से बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के लागू हो जाने के बाद सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने में दैनिक कमियों

के लिए दण्ड निर्धारित किये गये थे। दैनिक कमी की राशि पर दण्डात्मक ब्याज, कमी जारी रहने की अवधि के अनुसार, बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक या बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक है।

52. प्रमुख अनुसूचित बैंकों के साथ ऋण बजट पर वर्षाओं के दौरान तथा 1985-86 के गुरु के महीनों में सांविधिक चलनिधि अनुपात को दैनिक रूप से बनाये रखने के कार्य का निरीक्षण करने पर पता चला कि कई बैंकों के नाम पर भारी कमियाँ थीं और वे 30 मार्च 1985 से भारी जुमनि भरा कर रहे थे। उपबंधों का कड़ाई से पालन करने से कुछेक महत्वपूर्ण ऋण कार्यों में अचानक बाधा पड़ सकती थी। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादक जहरतों को पूरा करने के लिए ऋण निरंतर उपलब्ध रहें, बैंकों को थोड़ा और समय देने की दृष्टि से, सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमी के लिए जुमनि को चरणबद्ध रूप देने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गयी। इस योजना को कुछ प्रमुख बातें नीचे दी जा रही हैं :

(1) 13 सितंबर 1985 तक दैनिक सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमियों के संबंध में दण्ड से सामान्य माफ़ी दे दी गयी। 14 सितंबर 1985 से दैनिक सांविधिक अनुपात की कमियों पर दण्ड लगाये गये थे।

(2) 14 सितंबर 1985 से ऐसी दैनिक कमियों के बारे में कमी के लिए दण्ड से छूट के आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया जिनमें कमी, रखी जाने के लिए अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात की राशि के चार प्रतिशत थी। ऐसे बैंकों जो पहले ही सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखे हुए थे या जिनकी कमी की राशि बहुत कम थी, उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए फिर से कमी करने की अनुमति नहीं दी गयी। बैंकों को यह बात स्पष्ट करते हुए सूचित किया गया कि वे अपने कार्यों की अधिम रूप से योजना बना लिया करें क्योंकि छूट-सुविधा धीरे-धीरे कम करते हुए, अंततः समाप्त कर दी जायेगी।

(3) 4 प्रतिशत की सीमा से अधिक की दैनिक कमी वाले दैनिक व्यतिक्रम करनेवाले माने जाते थे जिन पर दण्डस्वरूप ब्याज लगाया जाना था। इसके अलावा, इस तरह निर्धारित व्यतिक्रमों की राशि के केवल तब किये गये एक हिस्से पर ही दण्डस्वरूप ब्याज लगना था, क्रमिक कार्यक्रम के अंतर्गत दण्डात्मक ब्याज के अंतर्गत आनेवाले दैनिक व्यतिक्रमों का अनुपात जो, 14 सितंबर 1985 से 25 प्रतिशत था, उसे 26 अक्टूबर, 1985 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत, 26 अप्रैल 1986 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और

21 जून 1986 से और बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दिया गया।

53. 29 मार्च तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सहायता के सांविधिक चलनिधि तथा नकदी प्रारक्षित निधि अनुपातों में कमी के बराबर के हिस्से पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर ब्याज वसूल किया जा रहा था। सांविधिक चलनिधि अनुपात को दैनिक रूप से बनाये रखने के संबंध में चरणबद्ध रूप से जुमना लगाने की शुरुआत को देखते हुए निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

(1) औसत प्रारक्षित चलनिधि के अनुपात में बराबर पुनर्वित्त के हिस्से पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज 30. मार्च, 1985 और 13 सितंबर 1985 के बीच केवल एकान्तर शुक्रवारों को लगाया गया। 14 सितंबर 1985 से औसत प्रारक्षित चलनिधि में कमी के बराबर पुनर्वित्त के हिस्से पर 3 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त ब्याज उस पखवाड़े के प्रत्येक दिन लगाया गया जिसमें प्रारक्षित चलनिधि अनुपात में कमी हो।

(2) सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमियों के मामले में, चरणबद्ध रूप से दण्ड लगाने के दौरान 30 मार्च, 1985 और 20 जून 1986 के बीच पुनर्वित्त पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा। 21 जून 1986 से दैनिक सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमियों के बराबर रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त के हिस्से पर प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त ब्याज लगाया जायेगा।

नीतिगत उपाय-अनिवासी जमा करें

54. विदेशों में और खास तौर पर संयुक्त राज्य अमरीका में, ब्याज दरों में स्पष्ट गिरावट को देखते हुए विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना में एक वर्ष, और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 22 अगस्त 1985 से कम कर दी गयीं। इस तारीख से पहले ऐसी अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज की दरें धरेलू जमाराशियों के लिए निर्धारित दरों से दो प्रतिशत पाइंट ऊंची होती थीं। विदेशों में हुई गतिविधियों को देखते हुए फरवरी 1986 में इन दरों को और कम कर दिया गया। मई 1986 में समीक्षा करने पर, विदेशों में, खासतौर पर अमेरिकी डालर जमाराशियों पर ब्याज दरों में कमी को देखते हुए इन दरों को एक बार फिर कम कर दिया गया। यह भी उल्लेख कर दिया गया कि 5 मई, 1986 से विदेशी मुद्रा अनिवासी योजना के अंतर्गत 3 वर्ष से अधिक की मीयाद के लिए जमाराशियां स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अलबत्ता, अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों पर ब्याज की दरें, धरेलू जमाराशियों के लिए दरों से 2 प्रतिशत पाइंट

अधिक पर अपरिवर्तित रखी गयी। विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों और अनिवासी (विदेशी) जमाराशियों

के लिए ब्याज दरों में परिवर्तन नीचे दर्शाये गये हैं।

अवधि समाप्ति	अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें				(प्रतिशत वार्षिक)
	विदेशी, मुद्रा अनिवासी दरें				निवासी ब्याज
	8 अप्रैल 1985 से लागू	22 अगस्त 85 से लागू	10 फरवरी 86 से लागू	5 मई 1986 से लागू	8 अप्रैल 1985 से लागू
एक वर्ष से अधिक लेकिन					
2 वर्ष से कम	10.5	9.5	9.5	8.5	10.5
2 वर्ष से अधिक लेकिन					
3 वर्ष से कम	11.0	10.5	10.5	9.0	11.0
3 वर्ष से अधिक लेकिन					
5 वर्ष से कम	12.0	11.0	10.5	10.0*	12.0
5 वर्ष और अधिक	13.00(८)	12.0(८)	11.0(८)		13.0

* इस दर पर जमाराशियां केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं।

* इस दर पर जमाराशियां केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं।

संश्लिष्ट उपाय अक्टूबर 1985

55. 1985-86 की पहली छमाही के दौरान हुई गतिविधियों और 1985-86 की दूसरी छमाही के दौरान अपेक्षित ऋण आवश्यकताओं, जो आमतौर पर व्यस्त कामकाज की अवधि होती है, के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, 25 अक्टूबर 1985 को निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी।

अवरोध नकदी शेष राशियां जारी करना

56. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 14 जनवरी 1977 और 31 अक्टूबर, 1980 के बीच की वृद्धिशील शुद्ध मांग और मीमादी देयताओं के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रारक्षित निधि रखनी होती है। अक्टूबर-दिसंबर 1984 में, उन राशियों के पांचवें हिस्से को जारी करने के अलावा शेष राशियां अवरोध रहीं थीं। चूंकि यह अनुमान लगाया गया था कि बैंकों को अधिक कामकाज के समय के दौरान बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा, अतः 26 अक्टूबर, 1985 को इन नकद शेष राशियों का एक तिहाई हिस्सा जारी करने का फैसला किया गया। चूंकि अवरोध राशियां 1487 करोड़ रुपये की थीं, अतः लगभग 495 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी।

अनिवासी (विदेशी) खातों पर सांविधिक चल निधि अनुपात

57. विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर 25 प्रतिशत की अल्प दर पर सांविधिक चलनिधि अनुपात लागू होता है जबकि अनिवासी विदेशी रुपया खाते 37 प्रतिशत के सांविधिक चलनिधि अनुपात की सामान्य दर के अधीन आते थे। 26 अक्टूबर 1985 से अनिवासी विदेशी खातों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। इससे बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाओं में लगभग 360 करोड़ रुपये की कमी आयी।

निर्यात पुनर्वित्त

58. बैंकों को 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर निर्यात पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जा रहा था और इस प्रकार के पुनर्वित्त की सीमाएं 1983 में ऋण के मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर थीं। 22 नवंबर 1985 से बैंकों को 1984 के लिए मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर निर्यात पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया। निर्यात पुनर्वित्त के लिए आधार को आगे लाने की क्रिया एक सामान्य वार्षिक कार्य है और हालांकि निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंक शुरू-शुरू में कम मांग करते हैं लेकिन यह अनुभव रहा है कि जैसे-जैसे बैंक निर्यात ऋण बढ़ाते हैं, वे पुनर्वित्त के लिए और अधिक मांग करते हैं। इस प्रकार से अधिक निर्यात ऋण को प्रेरणा मिलती है।

रिजर्व बैंक के पास रखी बैंकों की नकद शेष राशियों पर ब्याज दर

59. रिजर्व बैंक के पास रखी जानेवाली पाछ नकद शेष राशियों पर देय ब्याज दर 26 अक्टूबर, 1985 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत कर दी गयी। (3 प्रतिशत सांविधिक न्यूनतम नकदी प्रारक्षित अपेक्षाओं के अंतर्गत रखी जाने वाली शेष राशियां कानून के अधीन ब्याज प्राप्त करने के लिए हक्कावर नहीं होतीं)। नकद शेष राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि से यह अनुमान लगाया गया था कि इससे बैंकों को निधियों की लागत पूरी करने और अपनी प्रारक्षित निधियां बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

विवेकाधीन पुनर्वित्त

60. बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित्त के रूप में 230 करोड़ रुपये से कुछ अधिक उपलब्ध कराये गये थे ताकि वे अल्पकालीन नकदी समस्याओं से निपट सकें। अवरोध नकद शेष राशियों का एक हिस्सा जारी करने तथा अनिवासी

विदेशी खातों पर सांविधिक अनुपात में कमी किये जाने के साथ बैंकों की नकदी में 26 अक्टूबर 1985 को 855 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और नियत पुनर्वित्त की सीमाओं में लगभग 380 करोड़ रुपये की हानि केवल 22 नवम्बर 1985 से ही महसूस की गयी। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उन्हें उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त स्रोतों का इस्तेमाल समस्त विवेकाधीन पुनर्वित्त की बकाया राशि को चुकाने के लिए करें और रखे जाने के लिए अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात की राशि के 4 प्रतिशत की सीमा से अधिक सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने में होने वाली कमियों को भी पूरा करें।

चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाना

61. अप्रैल 1985 से शुरू किये गये चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी रखी गयी और वस्तु शेषों तथा मूल्यों में उतार-चढ़ावों को देखते हुए 26 अक्टूबर 1986 को कुछ छूटों और रियायतों की घोषणा की गयी। न्यूनतम उधार दरों के निर्धारण, ऋण के स्तरों, विषयक शर्तों, वही ऋणों पर उधार मंजूर करने विषयक प्रतिबंधों तथा बेजमानती ऋणों में ऐसी मदों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किये गये जो इन नियंत्रणों के अधीन बनी रहें। इन परिवर्तनों के बारे में इस रिपोर्ट के भाग II में दिये गये हैं।

62. बैंकों को सूचित किया गया कि चयनात्मक ऋण नियंत्रणों से छूट प्राप्त वस्तुओं के मामले में स्टॉक संबंधी सामान्य मानदंडों, बैंकों द्वारा निर्धारित मार्जिनों तथा ऋण मानदंडों और अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि स्टॉकों को सटटेवाजी के लिए जमाखोरी के वास्ते इस्तेमाल न किया जाये। ऐसे मामलों में जहां ऊंचे मार्जिनों को थोड़ा बहुत उदार बनाया जा रहा था, संबंधित मदें चयनात्मक ऋण नियंत्रणों की सीमा के भीतर बनाये रखी गयीं और जहां कहीं ऋण की अधिकतम सीमाओं के स्तर लागू थे, वहां उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

1986-87 के लिए मौद्रिक तथा बैंकिंग दृष्टिकोण

63. अप्रैल 1986 में ऋण नीति की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि अपनाए गये विभिन्न नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप 1985-86 में कुल नकदी (एम 3) की वृद्धि दर में कमी आयी है। एक खास उपलब्धि यह रही कि मुद्रास्फीति की दर में प्रत्यक्ष गिरावट आयी। हालांकि उस समय 1986-87 के लिए गतिविधियों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं था, फिर भी यह मान लिया गया कि औसत मानसून और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ 1986-87 में अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि दर 1985-86 की वृद्धि दर की तुलना में थोड़ी अधिक होगी और यह 5 प्रतिशत के आसपास हो सकती है। 1986-87 के लिए ऋण नीति की रचना में जिस अन्य महत्वपूर्ण घटक की

वर्चा की जा सकती है, वह यह है कि हालांकि 1985-86 में कुल नकदी की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम थी, एक चिंताजनक बात यह रही कि 1985-86 में प्रारंभित मुद्रा की वृद्धि 1984-85 की तुलना में बहुत अधिक थी। और उसका प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने की संभावना थी। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम 3) की वार्षिक औसत दर 17.4 प्रतिशत रही थी। मुद्रास्फीति के दबावों को सीमित रखने की दृष्टि से यह जरूरी समझा गया कि 1986-87 में एम 3 की वृद्धि दर को पिछले 3 वर्षों के औसत से नीचे बनाये रखा जाये।

64. नकदी की कुल वृद्धि में कमी लाने के लिए वांछित लक्ष्य के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा वृद्धि में 1986-87 में 15,000 करोड़ रुपये (17.6 प्रतिशत) की वृद्धि का तर्कसंगत अनुमान लगाया गया। यह माना गया कि जमा राशियों में वृद्धि वर्ष की दोनों छमाहियों में लगभग बराबर होगी। 1986-87 की पहली छमाही में 7,500 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ बैंकों से उम्मीद की गयी कि वे ऋण जरूरतों को अपने खुद के स्रोतों से पूरा कर सकेंगे और काफी अधिक मात्रा में नकदी भी बनाये रखेंगे। यह अपेक्षा की गयी थी कि अप्रैल-जून 1986 की तिमाही के दौरान खाद्यान्न ऋण में तेज वृद्धि को काबू में लाने के लिए बैंकों को कुछ खाद्यान्न पुनर्वित्त की जरूरत पड़ेगी।

65. 1986 का रबी उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद थी और बड़ी मात्रा में खरीद की योजना को देखते हुए बैंकों को मार्च के अंत और जून 1986 के अंत के बीच खाद्यान्न ऋण में लगभग 1200 करोड़ रुपये की वृद्धि के लिए और उसके बाद सितम्बर 1986 को समाप्त होने वाली तिमाही में 900 करोड़ रुपये की गिरावट के लिए योजना बनाने की सलाह दी गयी। जैसी कि परम्परा रही है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली के लिए ऋण आवश्यकताएं पूरी हों। यह अनुमान लगाया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1986-87 की पहली छमाही में बैंक ऋण में 2,300 करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये खाद्यान्न के लिए और 2,000 करोड़ रुपये गैर खाद्यान्न के लिए) की वृद्धि के लिए व्यवस्था कर सकने की स्थिति में होंगे। इन ऋण आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था कर लेने के बाद भी बैंक 1986-87 की पहली छमाही में पर्याप्त नकदी रखने में समर्थ होंगे।

66. खाद्यान्न वसूली की जरूरतें पूरी करना सुनिश्चित करने के अलावा, इस नीति का उद्देश्य यह था कि बढ़े हुए उत्पादन में योगदान देनेवाले सभी उत्पादक कार्यों के लिए बैंकों द्वारा अपने खुद के स्रोतों से वित्त उपलब्ध कराया जाये। वर्ष की पहली छमाही बैंकों के लिए समेकन करने की अवधि होगी, अतः उन्हें सूचित किया गया कि वे प्रारंभिक विषयक अपेक्षाओं को बनाये रखने में यदि कोई कमी हो तो उसे सुधार लें।

नीतिगत उपाय अप्रैल 1986:

सांविधिक चलनिधि अनुपात — छूट की सीमाएं

67. 3 अप्रैल 1986 को निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी: जुलाई 1985 में जब सांविधिक अनुपात विषयक व्यतिक्रमों के लिए शरणबद्ध रूप से दण्ड लगाने की

योजना की घोषणा की गयी थी तो यह बता दिया गया था कि सांविधिक चलनिधि के अनुपात विषयक दण्ड में छूट धीरे-धीरे समाप्त कर दी जायगी और तदनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए 4 प्रतिशत छूट में निम्नलिखित के अनुसार शरणबद्ध रूप से कमी निर्धारित की गयी:

छूट	
छूट	(रखे जाने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात की राशि के प्रतिशत के रूप में कमी)
19 जुलाई 1986	3
16 अगस्त 1986	2
13 दिसम्बर 1986	1
11 अक्तूबर 1986	0

लानू होने की तारीख

68. सांविधिक चलनिधि अनुपात के व्यतिक्रम के बराबर रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर 3 प्रतिशत पाइंट की दर पर अतिरिक्त ब्याज न लगाने की रियायत 21 जून 1986 से 10 अक्तूबर 1986 तक बढ़ा दी गई है। 11 अक्तूबर 1986 से दैनिक सांविधिक चलनिधि अनुपात व्यतिक्रम की राशि के बराबर रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त के अंश पर दैनिक आधार पर 3 प्रतिशत पाइंट का अतिरिक्त ब्याज लगाया जायगा।

69. कुछ बैंक जो छूट की 4 प्रतिशत की सीमा से अधिक पर सांविधिक चलनिधि अनुपात में व्यतिक्रम कर रहे थे उन्हें सूचित किया गया है कि वे प्रारंभित अपेक्षाओं को बनाये रखने को अनिवार्य रूप से प्रमुखता दें।

व्यवसायिक ऋण नियंत्रण

70. अप्रैल और अक्तूबर, 1985 में शुरू किये गये व्यवसायिक ऋण नियंत्रणों को विवेकपूर्ण बनाने का कार्य आगे भी जारी रखा गया और 4 अप्रैल 1986 से कुछ और छूटों और रियायतों की घोषणा की गयी। इनके ब्यौरे भाग II में दिये गये हैं।

ऋण प्राधिकरण योजना में परिवर्तन

71. ऋण प्राधिकरण योजना की विस्तृत समीक्षा और समय के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के आकार और मात्रा में होनेवाली वृद्धियों को देखते हुए योजना में कुछेक परिवर्तन किये गये। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन नीचे दिये जा रहे हैं: निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी की सीमाओं के लिए न्यूनतम सीमा को 7 करोड़ के एक समान स्तर पर लाया गया। इससे पहले निर्माता निर्यातकों के लिए और व्यापारी निर्यातकों के लिए न्यूनतम सीमाएँ क्रमशः 5 करोड़ रुप और 4 करोड़ रुपये थी। अन्यो के लिए ऋण प्राधिकरण योजना कार्यशील पूंजी की सीमाओं के लिए न्यूनतम सीमा 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गयी। बैंकों

की विवेकाधीन शक्तियों में बड़ोतरी की गयी ताकि वे पहले की 75 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की अपेक्षा 2 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अधीन 3 महीने से अनधिक अवधि के लिए मौजूदा कार्यशील पूंजीगत सीमा के 10 प्रतिशत तक और/अथवा बैंकिंग ऋण सीमाओं के 25 प्रतिशत तक, अस्थायी रूप से अतिरिक्त सीमा मंजूर कर सकें। कार्यशील पूंजीगत सीमाओं के जिन मामलों की बैंकों को मंजूरी के बाद जांच के लिए रिपोर्ट देनी होती है, उनकी न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर दो करोड़ रुपये कर दी गयी। असबस्ता, सांख्यिकीय प्रयोजना के लिए बैंक को एक करोड़ रुपये और अधिक की मंजूरीयों के बारे में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करते रहनी होगी। इसके अलावा "तुरन्त कार्रवाई" (फास्ट ट्रैक) सुविधा के लिए पात्रता के वास्ते मानदण्डों में भी कई छूट दी गयी।

उधार खातों का अंतरण

72. समीक्षा करने के बाद, एक बैंक से दूसरे बैंक में उधार खाते अंतरित करने पर लगे नियंत्रणों में संशोधन किये गये। पांच करोड़ रुपये की सीमा तक वाले उधार खातों की कतिपय शर्तों के अधीन सौंपने के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अंतरणकर्ता की सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा को अब समाप्त कर दिया गया है। पहले इस सीमा को जुलाई 85 में 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया था। एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि उधारकर्ता की आकस्मिक देयताओं सहित सभी देयताएं अंतरिती बैंक को ले लेनी होंगी।

मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा, ऋण और मूल्यों की प्रवृत्तियां

73. वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान (मार्च के अंतिम शुक्रवार के आधार पर) मुद्रा विस्तार अपेक्षाकृत तेजी से कम हुआ। संकुचित मुद्रा (एम 1) में विस्तार की दर जो 9.7 प्रतिशत थी, 1984-85 के दौरान दर्ज की गयी 19.9 प्रतिशत की दर के आधे से भी कम थी। निरपेक्ष रूप में 3,827 करोड़ रुपये की वृद्धि 1984-85 के दौरान दर्ज की गयी 6,583 करोड़ रुपये की वृद्धि से भी काफी कम

थी। विस्तृत मुद्रा (एम 3) ने भी इसी तरह 1984-85 की 18.7 प्रतिशत की दर की तुलना में 15.7 प्रतिशत की नीची दर पर विस्तार की प्रवृत्ति दर्शायी। निरपेक्ष रूप में, 16,003 करोड़ रुपये का विस्तार पिछले वर्ष देखे गये 16,058 करोड़ रुपये के विस्तार की तुलना में मामूली सा कम था।

सारणी (5)। पक्ष-बाड़ों के औसतों के रूप में विचार करने पर पता चलता है कि वृद्धि दर में इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं। एम 1 1984-85 के 18.2 प्रतिशत से कम होकर 14.1 प्रतिशत और एम 3 18.0 प्रतिशत से कम होकर 17.0 प्रतिशत हो गया।

सारणी 5—मुद्रास्टॉक एम 3) में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान परिवर्तन**

अंतिम शुक्रवार	1984-85		1985-86		1985-86 (अप्रैल-जून)		1986-87 (अप्रैल-जून)	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. एम 3 (क+ख+ग)	+16,058	+18.7	+16,003	+15.7	+6527	+6.4	+7806	+6.4
(क) जनता के पास मुद्रा	+3111	+15.9	+2452	+10.8	+1263	+5.6	+1503	+6.0
(ख) बैंकों के पास कुल जमा राशियाँ (i+ii)	+12,662	+19.2	+13,896	+17.7	+5382	+6.8	+6245	+6.7
(i) मांग जमा राशियाँ	+3187	+24.2	+1720	+15.0	+1208	+7.4	+1250	+6.9
(ii) मीमांसी जमा राशियाँ	+9475	+17.9	+12,176	+19.5	+4174	+6.7	+4995	+6.7
(ग) भा. रि. बैं. के पास अन्य जमा राशियाँ	+285	+89.6	—345	—57.2	—118	—19.6	—142	—55.0
2. एम 1 (क+ख (i)+ग)	+6583	+19.9	+3827	+9.7	+2353	+5.9	+2611	+6.0
3. मुद्रा स्टॉक (एम 3) के अंत (1+2+3+4—5)								
1. सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (घ+घा)	+8445	+20.8	+9531	+19.5	+5510	+11.3	+6794	+11.6
घ. सरकार को भा. रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण (i-ii)	+3149	+11.8	+9127	+30.7	+6693	+22.5	+4890	+12.5
i. सरकार पर दावे (क+ख)	+8321	+31.0	+3881	+11.0	+1343	+3.8	+4767	+12.2
(क) केन्द्र सरकार	+7808	+30.5	+5639	+16.9	+2785	+8.3	+4767	+12.2
(ख) राज्य सरकारें	+513	+41.2	—1758	—100.0	—1442	—92.0	—	—
ii. भा. रि. बैंक के पास सरकारी जमा राशियाँ								
(क+ख)	+5172	+2044.3	—5246	—96.7	—5350	—98.6	—113	—63.1
(क) केन्द्र सरकार	+5173	+2095.9	—5261	—97.0	—5361	—98.9	—109	—68.1
(ख) राज्य सरकारें	—1	—20.0	+15	+375.0	+11	+275.0	—4	—21.1
घा. सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	+5296	+38.2	+404	+2.1	—1183	—6.2	+1914	+9.8
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (घ+घा)	+10,809	+18.0	+10,509	+14.8	+2196	+3.1	+1698	+2.1
(घ) वाणिज्य क्षेत्र को भा. रिजर्व बैंक का ऋण*	+389	+16.4	+301	+10.9	—32	—1.2	—17	—0.6
(घा) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य ऋण (i+ii+iii)	10,420	+18.1	+10,208	+15.0	+2228	+3.3	+1705	+2.2
i. वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	+7660	+18.5	+6965	+14.2	+1969	+4.0	+1109	+2.0
ii. सहकारी बैंकों द्वारा ऋण	+1013	+12.7	+1136	+12.6	—88	—1.0	—64	—0.6
iii. वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	+1747	+21.0	+2107	+20.9	+347	+3.4	+660	+5.4
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (घ+घा)	+1419	+89.8	+299	+10.0	—389	—13.0	+247	+7.5
(घ) भा. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (i-ii)	+1420	+87.4	+299	+9.8	—389	—12.8	+247	+7.4
i. सकल विदेशी धातुस्थायी	+1484	+25.9	+54	+0.7	—453	—6.3	+179	+2.5
ii. मुद्रांतर विदेशी देयताएं	+64	+1.8	—245	—5.9	—64	—1.5	—68	—1.7

सारणी 5—मुद्रास्टाक (एम 3) में घट-बढ़ (जारी)

(करोड़ रुपये)

	1	2	3	4	5	6	7	8
(घा) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा धातियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
4. जनता को सरकार की मुद्रा देयताएं	+ 57	+ 7.9	+ 99	+ 12.7	+ 22	+ 2.8	—	—
5. मीयादी जमाखानियों के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रा देयताएं								
(घा + घा)	+ 4672	+ 27.6	+ 4435	+ 20.6	+ 812	+ 3.8	+ 1123	+ 4.3
(घ) मा. रि. बैंक की शुद्ध मुद्रा देयताएं	+ 2581	+ 50.6	+ 2984	+ 38.8	+ 497	+ 6.5	+ 692	+ 6.5
(घा) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रा देयताएं	+ 2091	+ 17.7	+ 1451	+ 10.5	+ 315	+ 2.3	+ 431	+ 2.8

*माबाई की स्थापना के बाद से बैंकों को इसका पुनर्गठन शामिल नहीं है। **मास/माह के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित।

नोट : 1. आंकड़े अंतिम हैं।

2. चूंकि भ्रमण-भ्रमण मनी के आंकड़े पूर्णकृत किये गये हैं, इसलिए जोड़ों में वृद्धि नहीं करने।

74. एम3 के दो प्रमुख घटकों में से, जनता के पास 1 स 2,452 करोड़ रुपये अथवा 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि पिछले वर्ष की 3,111 करोड़ रुपये या 15.9 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम रही। परिणाम यह हुआ कि वृद्धिशील एम3 में मुद्रा का अनुपात 1984-85 के 0.19 प्रतिशत से कम हो कर 1985-86 में 0.15 प्रतिशत रह गया।

75. वृद्धिशील मुद्रा—एम3 अनुपात जो 1978-79 और 1983-84 के बीच, 0.21 और 0.23 के बीच

अधिकतर घटता-बढ़ता रहा है, उसके बाद की अवधि में घटता ही रहा है। शायद यह प्रवृत्ति पिछली ऊंची वृद्धियों में सुधार की चोतक हो। औसत मुद्रा एम3 अनुपात लगातार गिरावट दर्शाता रहा और यह 1978-79 के 0.26 प्रतिशत से कम हो कर 1985-86 में 0.21 प्रतिशत रह गया। 1985-86 में एम1 के मांग जमा घटक की वृद्धि दर की तीव्र गिरावट दर्शाते हुए, वृद्धिशील एम1 में मुद्रा का अंश काफी सुधरा और पिछले वर्ष के 47 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया (सारणी 6)।

सारणी 6—मौद्रिक अनुपात

वर्ष	औसत अनुपात				वृद्धिशील अनुपात			
	मु	मु	कु.ज.	मी.ज.	मु	मु	कु.ज.	मी.ज.
	एम1	एम3	एम3	एम3	एम1	एम3	एम3	एम3
1978-79	0.59	0.26	0.74	0.57	0.55	0.23	0.75	0.59
1979-80	0.59	0.25	0.74	0.57	0.55	0.21	0.76	0.61
1980-81	0.58	0.24	0.75	0.58	0.56	0.21	0.80	0.63
1981-82	0.59	0.23	0.77	0.60	0.64	0.15	0.88	0.77
1982-83	0.58	0.23	0.77	0.61	0.57	0.21	0.79	0.64
1983-84	0.59	0.23	0.77	0.62	0.64	0.22	0.77	0.65
1984-85	0.57	0.22	0.77	0.61	0.47	0.19	0.79	0.59
1985-86	0.58	0.21	0.78	0.63	0.64	0.15	0.87	0.76
	मु=मुद्रा		कु.ज.=कुल जमा		मी.ज.=मीयादी जमा			

76. सकल जमाराशियों ने, जो कि एम3 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं, निरपेक्ष रूप में 13,896 करोड़ रुपये की विशालकाय वृद्धि दर्शायी लेकिन वृद्धि की दर पिछले वर्ष की 19.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1985-86 में 17.7 प्रतिशत रह गयी। वृद्धि की दर में गिरावट के लिए मांग जमाराशियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिनकी 1984-85 में दर्ज की गयी वृद्धि पिछले छः वर्षों के दौरान दर्ज की गयी सर्वाधिक वृद्धि—3,187 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम होकर, केवल 1,720 करोड़ रुपये रह गयी। दूसरी ओर, मीयादी जमाराशियों की वृद्धि निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में तेज गति से रही और वृद्धि दर, 1984-85 की 17.9 प्रतिशत से बढ़ती हुई 1985-86 में 19.5 प्रतिशत तक आ पहुँची। परिणाम-स्वरूप, 1985-86 में वृद्धिशील कुल जमाराशियाँ, वृद्धिशील एम3 के लगभग 87 प्रतिशत के बराबर रहीं, जबकि 1984-85 में यह प्रतिशत 79 था। अकेली वृद्धिशील मीयादी जमाराशियों का अंश 59 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत तक जा पहुँचा।

77. इस समय 1985-86 में मुद्रा और मांग जमाराशियों में तीव्र गिरावट में योगदान देनेवाले घटकों को पूरी तरह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। अलवस्ता, खाद्यान्न, ऋण, सापेक्ष मूल्य स्थिरता, वित्तीय आस्तियों के प्रति बढ़ा हुआ आकर्षण, काले धन की बढ़ोतरी को रोकने के लिए किये गये उपाय तथा विदेशी मुद्रा आस्तियों का अपेक्षाकृत कम जमाव, ये सब ऐसे कारण प्रतीत होते हैं, जिन्होंने जनता द्वारा मुद्रा को अपने पास रखने में कमी में योगदान दिया है।

78. एम3 में परिवर्तनों के स्रोतों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण के विस्तार की धीमी दर और शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों के जमा होने में तीव्र कमी—ये ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने मुद्रा विस्तार की गति कम की। वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण में 10,509 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह 1984-85 के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में 300 करोड़ रुपये कम थी। इसमें से, वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का 301 करोड़ रुपये का ऋण 1984-85 के ऋण की तुलना में 88 करोड़ रुपये कम रहा। अन्य बैंकों के ऋणों में विस्तार की धीमी गति को खाद्यान्न ऋण में 71 करोड़ रुपये की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 1984-85 में इसमें, 1,643 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वाणिज्य

और सहकारी बैंकों द्वारा गैर-खाद्यान्न ऋणों में 8,172 करोड़ रुपये का विस्तार 1984-85 में हुए 7,030 करोड़ रुपये के विस्तार की तुलना में अधिक था। बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आस्तियों का विस्तारवादी प्रभाव 1985-86 में इतना उल्लेखनीय नहीं रहा। ये जमाराशियाँ 1984-85 के 1,419 करोड़ रुपये की तुलना में मात्र 299 करोड़ रुपये रहीं। सरकार को शुद्ध बैंक ऋण के संबंध में 1985-86 में 9,531 करोड़ रुपये का विस्तार काफी उल्लेखनीय रहा; 1984-85 में यह कुछ कम अर्थात् 8,445 करोड़ रुपये था। सरकार को रिजर्व बैंक के ऋणों का 9,127 करोड़ रुपये का काफी बड़ा विस्तार पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये उधारों की वजह से हुआ क्योंकि राज्य सरकारों को ऋणों में 1773 करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

79. राजकोपीय वर्ष 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान एम3 की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। हालाँकि निरपेक्ष रूप में इसने ऊँची वृद्धि दर्शायी, एम1 में वृद्धि निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों रूप में अधिक रही। जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास जमाराशियाँ, दोनों ने अधिक वृद्धियाँ दर्ज कीं। स्रोतवार, वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण में काफी कम वृद्धि की कमी सरकार को शुद्ध बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि ने पूरी कर दी थी, जबकि बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में, भले ही सामूली-सी ही हो, वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इनमें गिरावट दर्ज की गयी थी।

प्रारक्षित मुद्रा

80. 1985-86 में प्रारक्षित मुद्रा में बिन्दुवार आधार पर 6,323 करोड़ रुपये अथवा 20.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले वर्ष दर्ज की गयी 2,653 करोड़ रुपये अथवा 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के दुगुने से भी अधिक थी। इसके घटकों में से, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियाँ ने तीव्र विस्तार दर्शाया और इन्होंने वृद्धिशील प्रारक्षित मुद्रा में प्रमुख अंश के लिए योगदान दिया। (सारणी 7) बैंकों द्वारा सांविधिक और अतिरिक्त प्रारक्षित राशियों के रूप में रखी जाने वाली इन जमाराशियों में 4,140 करोड़ रुपये की विशाल वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसमें 891 करोड़ रुपये की कमी आयी थी। प्रारक्षित मुद्रा में यह तीव्र दर मुख्य रूप से सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋणों की वजह से संभव हो सकी। जिसमें 1984-85 के 3,149 करोड़ रुपये की तुलना में, लगभग तीन गुना, अर्थात् 9,127 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

सारणी 7—प्रारक्षित मुद्रा घट-बढ़ : घटक तथा स्रोत

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़

	1984-85		1985-86		1985-86 अप्रैल-जून		1986-87 अप्रैल-जून	
	निरपेक्ष	प्रतिशत	निरपेक्ष	प्रतिशत	निरपेक्ष	प्रतिशत	निरपेक्ष	प्रतिशत
प्रारक्षित मुद्रा (1 + 2 + 3 + 4)	+ 2,653	+ 9.2	+ 6,323	+ 20.1	+ 5,641	+ 17.9	+ 3,683	+ 9.7
1. जनता के पास मुद्रा	+ 3,111	+ 15.9	+ 2,452	+ 10.8	+ 1,263	+ 5.6	+ 1,503	+ 6.0
2. भा. रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां	+ 285	+ 89.6	—345	+ 57.2	+ 118	—19.6	—142	—55.0
3. बैंकों के पास नकदी	+ 148	+ 14.0	+ 76	+ 6.3	+ 445	+ 37.0	+ 352	+ 27.5
4. भा. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियां	—891	—11.3	+ 4,140	+ 59.1	+ 4,051	+ 57.8	+ 1,970	+ 17.7
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत (1 + 2 + 3 + 4 + 5 — 6)								
1. सरकार को भा. रि. बैं. का शुद्ध ऋण	+ 3,149	+ 11.8	+ 9,127	+ 30.7	+ 6,693	+ 22.5	+ 4,880	+ 12.5
2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के दावे @	+ 218	+ 8.4	—519	—18.5	—156	—5.6	—735	—32.2
3. वाणिज्य क्षेत्र का रिजर्व बैंक के ऋण	+ 389	+ 16.4	+ 301	+ 10.9	—32	—1.2	—17	—0.6
4. भा. रि. बैं. की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	+ 1,420	+ 87.4	+ 299	+ 9.8	—389	—12.8	+ 247	+ 7.4
5. जनता को सरकार की मुद्रा देनाएं	+ 57	+ 7.9	+ 99	+ 12.7	+ 22	+ 2.8	—	—
6. भा. रि. बैं. की शुद्ध मुद्रा देनाएं	+ 2,581	+ 50.6	+ 2,984	+ 38.8	+ 497	+ 6.5	+ 692	+ 6.5

*अंतिम

@नाबाब महित

टिप्पणी : — बैंक अलग-अलग मवों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं इसलिए वे जोड़ों में वृद्धि नहीं कर सकते।

81. प्रारक्षित मुद्रा में इस उल्लेखनीय विस्तार का कारण आंशिक रूप से इस रूप में सांख्यिकीय है कि बिन्दु-वार आधार पर यह वृद्धि मार्च 1985 के निम्नतर आधार अंक की तुलना में है, जो कि उस सप्ताह में केन्द्र सरकार की जमाराशियों में काफी अधिक वृद्धि का परिणाम था। इसके विपरीत, प्रारक्षित मुद्रा के वार्षिक औसत पाक्षिक-आंकड़ों ने 1984-85 के 19.3 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष के दौरान 13.6, प्रतिशत की अल्प वृद्धि दर प्रदर्शित की। संभवतः वार्षिक प्रवाह की दृष्टि से औसत आंकड़े ही विप्लवपूर्ण रूप में, विशेषतः प्रारक्षित मुद्रा में घटबढ़ के संदर्भ में, अधिक सार्थक हैं। हाल ही के महीनों में इस प्रकार की घटबढ़ बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाली नकदी शेष राशियों में अनिच्छापूर्ण बड़ोत्तरी की वजह से हुई है। ऐसी स्थितियों में बैंकों का स्रोत—आधार, जिस पर आमतौर पर ऋण का गीण विस्तार हुआ करता है, खुद ही संकुचित हो जाता है। नतीजा यह होता है कि प्रारक्षित मुद्रा और मौद्रिक विस्तार के बीच का संबंध

प्रभावित होता है। इसके अलावा, प्रारक्षित मुद्रा के सृजन में और मौद्रिक विस्तार पर उसके संभावित प्रभाव में अंतराल के लिए गुंजाइश रखना आवश्यक होता है।

82. राजकोषीय वर्ष 1986-87 की पहली तिमाही के दौरान प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 5,641 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम अर्थात् 3,683 करोड़ रुपये रही। इसका कारण मुख्य रूप से रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों के विस्तार में धीमी गति रहा। यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 4051 करोड़ रुपये के विस्तार के आधे से भी कम अर्थात् 1,970 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के दौरान प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि पर दर में धीमापन मुख्य रूप से सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण हुआ था। यह पिछले वर्ष के 6,693 करोड़ रुपये की तुलना में 4,880 करोड़ रुपये रहा।

बैंकिंग ऋण राशियों में घट-बढ़

83. वर्ष 1985-86 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों, बैंक ऋण तथा निवेशों की वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिली। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कम थी, हालांकि निरपेक्ष रूप में वृद्धि 1984-85 में दर्ज की गयी। 11,648 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में अधिक अर्थात् 13,044 करोड़ रुपये थी (सारणी 8)। राष्ट्रीय आय वृद्धि हानांकि 1984-85 की तुलना में मामूली-सी अधिक थी, मुद्रा स्फीती

की दर काफी कम थी और इससे सामान्य रूप में जमा राशियों में कम वृद्धि का प्रांशिक रूप से पता चलता है। बैंक ऋणों में 6,963 करोड़ रुपये अथवा 14.2 प्रतिशत का विस्तार निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में पिछले वर्ष के 7,659 करोड़ रुपये अथवा 18.5 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में कम था। खाद्यान्न ऋण ने 71 करोड़ रुपये की गिरावट दर्शायी जबकि इसके ठीक विपरीत 1984-85 में इसमें 1,643 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। गैर-खाद्यान्न ऋणों ने पिछले वर्ष दर्ज की गयी 6,016 करोड़ रुपये अथवा 16.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7,034 करोड़ रुपये अथवा 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सारणी 8-महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशकों में उत्तर-चढ़ाव

(अनुसूचित वाणिज्य बैंक)

(करोड़ रुपये)

मदें	(निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि)			निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में घट-बढ़		तिमाही उत्तर-चढ़ाव	
	29 मार्च 1985	28 मार्च 1986*	27 जून 1986*	1984-85	1985-86	1985 (अप्रैल-जून)	1986 (अप्रैल-जून)
	1	2	3	4	5	6	7
कुल भाग एवं बीमावी देयताएं (इसमें भा. रि. बैं. भा. छो. बि. बैं. और नाबाहं से लिये गये उधार शामिल नहीं हैं)	81885	96828	102939	+13435	+14943	+5700	+6111
कुल जमा राशियाँ	72244	85288	91454	+11648 (+19.2)	+13044 (+18.1)	+4831 (+6.7)	+6186 (+7.2)
भा. रि. बैंक से उधार	1558	954	544	+222	-604	+305	-410
बैंक ऋण	48953	55916	57025	+7659 (+18.5)	+6963 (+14.2)	+1968 (+4.0)	+1109 (+2.0)
खाद्यान्न ऋण	5665	5594	6439	+1643	-71	+1100	+845
गैर-खाद्यान्न ऋण	43288	50322	50586	+6016 (+16.1)	+7034 (+16.2)	+868 (+2.0)	+264 (+0.5)
निवेश (क+ख)	28138	30536	33081	+6892 (+32.4)	+2398 (+8.5)	-886 (-3.1)	+2545 (+8.3)
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	18697	19013	20898	+5223 (+38.8)	+316 (+1.7)	-1230 (-6.6)	+1885 (+9.9)
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9441	11523	12183	+1669 (+21.5)	+2082 (+22.1)	+344 (+3.6)	+660 (+5.7)
हाथ में भकदी	1044	1113	1464	+116	+69	+375	+351
भा. रि. बैं. के पास क्षेत्र राशियाँ	6884	11053	12940	-899 (-11.6)	+4169 (+60.6)	+4002 (+58.1)	+1887 (+17.1)
ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	67.8	65.6	62.4				
गैर-खाद्यान्न ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	59.9	59.0	55.3				

*अंशतः संशोधित

टिप्पणी : 1. मुक्ति पुनर्भूनाई बिल योजना के अंतर्गत पुनर्भूनाई किये जाने वाले जिले नहीं हैं, अतः गणन बैंक ऋण बैंक ऋण के बराबर ही है।

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े घट-बढ़ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

84. ऋण के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े बताते हैं कि 1985-86 में उद्योग को ऋण में 4,436 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 2,483 करोड़ रुपये थी। इस तीव्र वृद्धि को औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की 6.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1985-86 में 6.3 प्रतिशत की कम वृद्धि और पिछले वर्ष के साप्ताहिक औसत आधार पर थोक मूल्य सूचक में 7.1 प्रतिशत का तुलना में 5.7 प्रतिशत की अल्प वृद्धि की तुलना में देखना होगा। गैर-खाद्यान्न ऋणों में जहाँ पिछले वर्ष की 16.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1985-86 में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं उद्योग (छोटे, मझौले तथा बड़े) को ऋण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 12.4 प्रतिशत की तुलना में 19.7 प्रतिशत बढ़ा। ऋण के उद्योगवार वितरण को देखने से पता चलता है कि वृद्धिशील ऋण का बड़ा भाग गैर-परंपरागत उद्योगों जैसे इंजीनियरी और रसायनों को मिला। इससे यह भी पता चलता है कि 1985-86 में अधिकतर उद्योग समूहों को दिये गये ऋण 1984-85 में दिये गये ऋणों की तुलना में अधिक थे। इन आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र को ऋण जरूरतें वर्ष के दौरान अच्छी तरह पूरी होती प्रतीत होती हैं।

85. बैंकों के निवेश में 2,398 करोड़ रुपये की अवधि 8.5 प्रतिशत की वृद्धि 1984-85 में दर्ज किये गये 6,892 करोड़ रुपये के विस्तार की लगभग एक तिहाई बैठती है। 1984-85 में विस्तार आंशिक रूप से सांविधिक चलनिधि अनुपात में एक प्रतिशत पाइंट की वृद्धि करने की वजह से हुआ था, जबकि वर्ष के दौरान 1985-86 में सांविधिक चलनिधि अनुपात में उतनी ही वृद्धि के बावजूद निवेशों में कम वृद्धि हुई है। अलबत्ता, ऐसा लगता है कि बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास बड़ी मात्रा में नकद शेष राशियां रख कर श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की अल्पतर धारकता की कमी पूरी कर ली है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकद राशियों में 1984-85 की 899 करोड़ रुपये की गिरावट के विपरीत, 4,169 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक से उधारों में कमी आयी और उनमें पिछले वर्ष के 222 करोड़ रुपये की वृद्धि के विपरीत 604 करोड़ रुपये की कमी आ गई।

86. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 6,166 करोड़ रुपये (7.2 प्रतिशत) की जमा वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि 4,831 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। अलबत्ता, बैंक ऋण में 1,109 करोड़ रुपये (2.0 प्रतिशत) का विस्तार एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान हुए 1,968 करोड़ रुपये (4.0 प्रतिशत) की वृद्धि से कम था। खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न, दोनों ऋणों ने 845 करोड़ रुपये और 264 करोड़ रुपये की वृद्धियां दर्ज कीं, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गयीं क्रमशः 1,100 करोड़ रुपये तथा 868 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम थीं। बैंक के निवेशों में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 886 करोड़ रुपये (-3.1) प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2,545 करोड़ रुपये (8.3 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1986-87 की पहली तिमाही में बड़ी वृद्धियों से, कुछ हद तक, बैंकों के द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात की कमियों को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का पता चल सकेगा।

ऋण का क्षेत्रवार वितरण

87. वित्तीय वर्ष 1985-86 और 1984-85 में ऋण उपलब्धता की दिशा के बारे में, ऋण के क्षेत्रवार वितरण से संबंधित सारणी 9 में संकेत दिया गया है। 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित ये आंकड़े जो, कुल बैंक ऋण के लगभग 95 प्रतिशत के लिए हैं, दर्शाते हैं कि 1985-86 के दौरान सकल बैंक ऋण में 7,255 करोड़ रुपये (15.1 प्रतिशत) की वृद्धि, 1984-85 के दौरान 7,535 करोड़ रुपये (18.6) प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम थी। यह गिरावट खाद्यान्न वसूली के लिए ऋण में 71 करोड़ रुपये की कमी की वजह से हुई। इसके विपरीत पिछले वर्ष इनमें 1,643 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अलबत्ता, गैर-खाद्यान्न ऋणों में पिछले वर्ष के 5,892 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत) के विस्तार की तुलना में 7,326 करोड़ रुपये (17.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 1985-86 में हुई वृद्धि मुख्य रूप से मझौले और बड़े उद्योगों को ऋण की मात्रा में अधिक विस्तार की वजह से हुई थी जबकि पिछले वर्ष विस्तार का मुख्य कारण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण रहा।

सारणी 9—मुख्य क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण*

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित महीने के प्रतिम शुक्रवार को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	मार्च	मार्च	मार्च	1984-85	1985-86
	1984	1985	1986		
	1	2	3	4	
1. सकल बैंक ऋण (1+2)	40421	47956	55211	7535	7255
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	4022	5665	5594	1643	-7
2. गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण (अ+ब+ई+ई)	36399	42291	49617	5992	7326
				(100.0)	100.0)

*अंतिम

1	2	3	4	5	6
अ. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	14899	18409	21584	3510 (59.6)	3175 (43.3)
1. कृषि	6144	7660	9071	1316 (23.7)	1411 (19.3)
2. लघु उद्योग	5447	6612	7808	1165 (19.8)	1196 (16.3)
3. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3308	4137	4705	829 (14.1)	568 (7.7)
आ. उद्योग (मझोले और बड़े)	14621	15939	19179	1318 (22.4)	3240 (44.2)
इ. थोक व्यापार (खाद्य वस्तुओं के अलावा)	2343	2649	3048	306 (5.2)	399 (5.4)
1. भारतीय रुई निगम	193	103	160	—90 (—1.5)	57 (0.8)
2. उर्वरक वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम	241	166	127	—75 (—1.3)	—39 (—0.5)
3. भारतीय जूट निगम	49	116	141	67 (1.1)	25 (0.3)
4. अन्य व्यापार	860	2264	2620	404 (6.9)	356 (4.9)
(ई) अन्य क्षेत्र	4536	5294	5908	758 (12.9)	512 (7.0)
II—नियमित ऋण (मद 2 के अन्तर्गत शामिल)	2041	2335	2409	294	74

टिप्पणी 1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं, जिनका हिस्सा सकल बैंक ऋण में 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में भारतीय, भारतीय, निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य अनुसूचित वित्तीय संस्थाओं के पुनः धूँये गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गैर-खाद्यान्न वृद्धिशील ऋण के अनुपात हैं।

88. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋण मार्च 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार शुद्ध बैंक ऋण का 40.9 प्रतिशत बने रहे और इस तरह इन्होंने 40 प्रतिशत का लक्ष्य पार कर लिया। इन्होंने 1984-85 में 3,175 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की और ये 1985-86 में कुल वृद्धिशील गैर-खाद्यान्न सकल बैंक ऋण का 43.3 प्रतिशत रहे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋणों में वृद्धि में से कृषि और लघु उद्योगों का अंश क्रमशः 1,411 करोड़ रुपये (44.4 प्रतिशत) और 1,196 करोड़ रुपये (37.7 प्रतिशत) रहा जबकि पिछले वर्ष इनमें 1,516 करोड़ रुपये (43.2 प्रतिशत) तथा 1,165 करोड़ रुपये (33.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मार्च 1986 के अंत की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र पर बकाया ऋणों की राशि, एक वर्ष पहले के 7,660 करोड़ रुपये की तुलना में 9,071 करोड़ रुपये थी। कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में इसका अनुपात वर्ष के दौरान 0.4 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि के साथ 42.0 प्रतिशत हो गया। लघु उद्योगों को दिये गये 7,808 करोड़ रुपये के ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल ऋणों का 38.2 प्रतिशत रहे जबकि एक वर्ष पहले यह प्रतिशत 35.9 था। अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को, जिनमें कमजोर वर्ग, छोटे परिवहन चालक, स्वतंत्र व्यक्ति और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, ऋण बढ़कर 4,705 करोड़ रुपये हो गये

और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के कुल ऋणों में मार्च 1986 में इनका अंश 21.8 प्रतिशत रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित मझोले और बड़े उद्योगों पर बकाया ऋणों की राशि मार्च 1986 के अंत में 19,179 करोड़ रुपये थी जबकि एक वर्ष पहले यह 15,939 करोड़ रुपये थी। उद्योग, अर्थात्, लघु, मझोले, तथा बड़े उद्योगों को मिला कर कुल ऋणों में 1985-86 में 4,436 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये गैर-खाद्यान्न वृद्धिशील ऋणों का 60.6 प्रतिशत रहे। यह स्थिति पिछले वर्ष के 2,483 करोड़ रुपये और 42.1 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार की ओर है।

89. बैंक ऋण का उद्योगवार (लघु उद्योग सहित) वितरण सारणी 10 में दिया गया है। 1985-86 में ऋण की वृद्धि में जिन उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे थे इंजीनियरी समूह (1,153 करोड़ रुपये), रसायन समूह (821 करोड़ रुपये), शेष उद्योग (1,136 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र (326 करोड़ रुपये), पेट्रोलियम (301 करोड़ रुपये), अन्य वस्त्र (269 करोड़ रुपये) तथा अन्य धातु तथा धात्विक उत्पाद (139 करोड़ रुपये), लोहे और इस्पात (163 करोड़ रुपये) तथा नयी योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों से खरीदे गये जहाज (50 करोड़ रुपये) के मामले में भारी गिरावट देखने को मिली थी।

सारणी 10—सकल बैंक ऋण का उपयोगवार वितरण

(करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित महीने के अंतिम शुक्रवार में बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	मार्च 1984	मार्च 1985	मार्च 1986	1984-85	1985-86
	1	2	3	4	5
उद्योग (सबु उद्योग, मशीने और बड़े उद्योगों का जोड़)	20068	22551	26987	2493	4436
1. कोयला	147	119	93	—28	—26
2. लोहा और इस्पात	1594	1430	1267	—164	—163
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद	670	801	940	131	139
4. सभी इंजीनियरिंग	4815	5560	6713	745	1153
5. बिजली (उत्पादन और प्रेषण)	303	415	493	112	78
6. सूती वस्त्र	1644	1869	2195	225	326
7. जूट वस्त्र	211	263	277	52	14
8. अन्य वस्त्र	1192	1365	1634	173	263
9. चीनी	599	428	538	—171	110
10. चाय	247	295	321	48	26
11. वनस्पति तेल (वनस्पति भी सहित)	265	311	341	46	30
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	169	159	184	—10	25
13. कागज और कागज उत्पाद	486	596	664	110	68
14. रबर और रबर उत्पाद	390	434	456	44	22
15. रसायन, रंग, पेण्ट आदि जिनमें से उर्वरक	2088 (397)	2325 (361)	3146 (700)	237 (—36)	821 (339)
16. सीमेंट	237	282	353	45	71
17. धमड़ा और धमड़े के उत्पाद	267	323	388	56	65
18. निर्माण	216	265	286	49	21
19. पेट्रोलियम	374	72	373	—302	301
20. नदी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज	368	376	326	8	—50
21. बाकी उद्योग	3786	4863	5999	1077	1136

*अंतिम

90. थोक व्यापार (खाद्यान्न वसुली के अलावा) के अग्रिमों में पिछले वर्ष की 306 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 1985-86 में 399 करोड़ रुपये की थोड़ी अधिक वृद्धि दर्ज की गयी। 'अन्य क्षेत्र', जो शेष क्षेत्रों के द्योतक हैं और जिनके अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों पट्टे का काम करने वाली एजेंसियों को दिये गये अग्रिम और व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं, को दिये गये अग्रिमों में 1985-86 के दौरान 512 करोड़ रुपये की अस्य वृद्धि दर्ज की जबकि 1984-85 में इनमें 758 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

91. विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं के उपयोग की गति-विधियां आगे दी गयी हैं।

खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त

92. जून 1985 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों की खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त सीमायें, 2,100 करोड़ रुपये की थीं, जिसमें से केवल 742 करोड़

रुपये या 35.3 प्रतिशत ही उपयोग में लाये गये थे। (सारणी 11)। खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त सीमायें 5 जुलाई 1985 को 2,150 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर तक जा पहुंची। अधिकतम बकाया राशियां 1,306 करोड़ रुपये (सीमाओं का 64.4 प्रतिशत), 26 जुलाई, 1985 को रही थीं। सीमाओं के उपयोग का अनुपात 20 सितम्बर 1985 को 89.5 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया था। अगस्त-सितम्बर, 1985 के दौरान खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा को तीन चरणों में 4,600 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5,800 करोड़ रुपये कर देने और खाद्यान्न ऋण के बकाया स्तरों में गिरावट होने के कारण ये सीमायें जुलाई 1985 के बाद तेजी से नीचे आ गयीं। जून 1986 के रिपोर्टवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक 736 करोड़ रुपये की सीमा तक खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त सीमाओं के लिए पात्र थे और इन सीमाओं के विरोध 34 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

**सारणी 11—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता
(जहाजरानी ऋणों पर विशेष पुनर्वित्त तथा शुल्क वापसी को छोड़कर)**

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त		निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आपाती पुनर्वित्त पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा बकाया		सीमा बकाया		सीमा बकाया		सीमा बकाया		सीमा बकाया	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून 1985	2099.8	742.4	653.5	173.7	—	—	—	2753.3	916.1	
सितम्बर 1985	47.4	225.4	562.5	258.4	10.0	—	50.0	50.0	669.9	553.8
दिसम्बर 1985	159.7	—	208.9	127.3	30.0	—	22.3	—	420.9	127.3
मार्च 1986	—	—	339.3	252.7	50.0	40.0	398.0	336.5	787.3	629.2
जून 1986	736.1	33.6	510.4	68.6	—	—	46.0	1.0	1292.5	103.2

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

93. बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमायें 5 जुलाई 1985 को 640 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर तक आ पहुँची। वर्ष के दौरान सर्वाधिक बकाया राशियों का स्तर 12 जुलाई 1985 को था, जब 439 करोड़ रुपये की राशियाँ बकाया थीं और सीमाओं का 70.5 प्रतिशत उपयोग में लाया गया था। आधार वर्ष को 1983 से बदलकर 1984 किये जाने से सीमायें दिसम्बर 1985 और जनवरी 1986 के दौरान कम हो गईं। उसके बाद सीमाओं ने बढ़ना शुरू किया और जून 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमायें 510 करोड़ रुपये हो गईं जिनमें से 69 करोड़ रुपये अथवा 13.4 प्रतिशत सीमायें उपयोग में लायी गयी थीं। जून 1985 के अंत की स्थिति से तुलना करने पर पता चलता है कि जब ये सीमायें 654 करोड़ रुपये थीं, उपयोग 174 करोड़ रुपये का किया गया था। इस तरह उपयोग दर 26.6 प्रतिशत रही।

सह-वर्ती पुनर्वित्त सीमायें

94. जून 1985 और जून 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों को मंजूर की गयी सहवर्ती पुनर्वित्त सीमायें शून्य थीं। बैंकों को मंजूर की गयी सहवर्ती पुनर्वित्त की अधिकतम सीमायें मार्च 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये थीं और इन सीमाओं में से 40 करोड़ रुपये बकाया थे।

विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमायें

95. 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों को काफी मात्रा में विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गईं। सीमाओं ने सितम्बर 1985 के अंत से बढ़ना शुरू किया और वे 25 अक्टूबर 1985 को 233 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गईं, जब कुछ बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमायें मंजूर की गईं थी ताकि वे खाद्यान्न ऋण पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमाओं में वृद्धि में समायोजन कर सकें। उसके बाद सीमाओं

में तेजी से कमी की गयी थी लेकिन ये 11 अप्रैल 1986 को 430 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गयीं मार्च 1986 के अंत में नकदी पर सामान्य तौर पर पहुँचने वाला मौसमी दबाव वर्ष के दौरान काफी बढ़ गया। अधिकतम बकाया राशियाँ 337 करोड़ रुपये, 28 मार्च 1986 को रहीं जब सीमाओं का 84.5 प्रतिशत उपयोग में लाया गया था जून 1986 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमायें 46 करोड़ रुपये की थीं और इनमें से एक करोड़ रुपये बकाया थे।

समग्र स्थिति

96. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध विभिन्न रिजर्व बैंक पुनर्वित्त सुविधाओं (जहाजरानी ऋणों तथा शुल्क वापसी पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) की सीमाओं की कुल राशि जो जून 1985 के रिपोर्ट वाले अंतिम शुक्रवार को 2,753 करोड़ रुपये थी, 1985-86 के दौरान धीरे-धीरे कम हो गयी। 20 जून 1986 की स्थिति के अनुसार सीमायें 1,293 करोड़ रुपये की थीं जोकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा-राशियों के 1.45 प्रतिशत के बराबर थीं।

ऋण बजट

97. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1985-86 के लिए बजटों पर सभी प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ चर्चा की गयी थी। बैंकों को अपने ऋण कार्यक्रमों की योजना, अपने ही स्रोतों से यह बात देखते हुए बनाने के लिए सूचित किया गया था ताकि खाद्यान्न पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम सीमाओं में वरणवृद्धि वृद्धि को सुचारू रूप से समायोजित किया जा सके। बैंकों को यह बात सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सूचित किया गया था कि प्रारक्षित-निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके ऋण बजटों में पर्याप्त प्रावधान किया जाय और उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि बैंक-कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के संशोधनों

के लागू हो जाने के साथ सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाये रखने में दैनिक व्यतिक्रमों पर दृष्टि लगा करेगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ऋण बजटों में प्रमुख घटकबहुओं के अनुमान लगाने और उनके वास्तविक परिणामों के बीच अधिक फेर-बदल करने से बचें। नवम्बर 1985 में बैंकों को, नीति में किये गये परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में अपने ऋण बजटों में संशोधन करने के लिए सूचित किया गया था। कुछ ऐसे अनुसूचित धाणिज्य बैंकों के साथ, जो सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने में नियमित रूप से व्यतिक्रम करने वाले थे, फरवरी 1986 में चर्चा के दूसरे दौर का आयोजन किया गया।

98. 3 अप्रैल, 1986 को 1986-87 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति की घोषणा के साथ बैंकों को 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के लिए अपने ऋण बजट तैयार करने के लिए

सूचित किया गया और जून 1986 में प्रमुख धाणिज्य बैंकों के साथ चर्चा की गयी।

मूल्य स्थिति :

99. वर्ष 1985-86 में मुद्रा स्थिति के दबाव में स्पष्टतः कमी आयी। लगातार तीसरे वर्ष मुद्रास्फीति की रफ्तार कम रहते हुए थोक मूल्यों में किन्तुवार आधार पर 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1984-85 में 7.6 प्रतिशत और 1983-84 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (सारणी 12)। साप्ताहिक औसत आधार पर भी मूल्य सूचकांक 5.7 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस मात्रा की कमी मांग और आपूर्ति की कुशल व्यवस्था के कारण संभव हो सकी थी।

सारणी 12—प्रमुख पण्य समूहों का मूल्य वृद्धि और थोक मूल्य सूचकांक में भार की दृष्टि से योगदान
(1970-71=100)

	थोक मूल्य सूचकांक					
भार	मार्च 1984 के अंत में	मार्च 1985 के अंत में	मार्च 1986 के अंत में	जून 1985 के अंत में	जून 1986 के अंत में	
1	2	3	4	5	6	
सभी पण्य	1000.00	321.7	346.3	359.3	358.6	372.5
प्राथमिक वस्तुएं	416.67	308.1	321.6	330.7	335.4	343.5
ईंधन , बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	84.59	508.6	559.2	609.2	568.7	614.8
निर्मित उत्पाद	498.74	301.4	330.8	340.9	342.3	355.6

	प्रतिशत घट-बढ़				भार की दृष्टि से योगदान			
	वित्तीय वर्ष		पहली तिमाही		वित्तीय वर्ष		पहली तिमाही	
	1984-85	1985-86	1985-86	1986-87*	1984-85	1985-86	1985-86	1986-87
	7	8	9	10	11	12	13	14
सभी पण्य	+7.6	+3.8	+3.6	+3.7	100.0	100.0	100.0	100.0
प्राथमिक वस्तुएं	+4.4	+2.8	+4.3	+3.9	+22.9	+29.0	+46.8	+40.6
ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	+9.9	+8.9	+1.7	+0.9	+17.5	+32.4	+6.5	+3.7
निर्मित उत्पाद	+9.8	+3.1	+3.5	+4.3	+59.6	+38.6	+49.7	+55.7

*अंतिम

100. सामान्य मौसमी स्थिति के अनुरूप वर्ष 1985-86 में मूल्य के उतार चढ़ाव के तीन विशिष्ट चरण स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जैसा कि सारणी 13 में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है। पिछले वर्ष की तरह ही अप्रैल से जुलाई 1985 के पहले चार महीनों में थोक मूल्यों के सामान्य

सूचकांक में लगातार और तीव्र वृद्धि हुई। इस सूचकांक में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। वर्ष 1984-85 की तुलना में अवधि में यह और भी तीव्र, 7.2 प्रतिशत थी। अगस्त-नवम्बर, 1986 में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आयी, उसके बाद वर्ष के अंतिम चार महीनों में 1.0 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि हुई।

सारणी 13—थोक दरों में घट-बढ़ के तीन चरण

(प्रतिशत में)

	1985-86				1984-85				
प्रतिशत भार	मार्च के अंत से जुलाई के अंत तक	जुलाई के अंत से नवम्बर के अंत तक	नवम्बर के अंत से मार्च के अंत तक	मार्च के अंत से मार्च के अंत तक	मार्च के अंत से जुलाई के अंत तक	जुलाई के अंत से नवम्बर के अंत तक	नवम्बर के अंत से मार्च के अंत तक	मार्च के अंत से मार्च के अंत तक	
सभी पण्य	100	+5.4	-2.5	+1.0	+3.8	+7.2	-1.5	+1.9	+7.6
प्राथमिक वस्तुएं	42	+6.6	-4.2	+0.7	+2.8	+9.7	-1.1	-0.8	+4.4
ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई वाली वस्तुएं	8	+1.7	+2.4	+4.6	+8.9	+1.4	+0.9	+7.4	+9.9
विनिर्मित उत्पाद	50	+5.4	-2.5	+0.2	13.1	+6.8	—	+2.7	+9.8

101. हालांकि सामान्य सूचकांक और तीनों प्रमुख समूहों के सूचकांक की वृद्धि की रफ्तार कम रही है, जो स्वागत योग्य है, किंतु अलग-अलग पण्यों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के विश्लेषण से कुछ चिन्ताजनक प्रवृत्तियों का पता चलता है। यह सारणी 14 से स्पष्ट है। प्राथमिक वस्तुओं में से चावल और गेहूं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष चावल के मूल्य में थोड़ी गिरावट आयी थी और गेहूं में थोड़ी-सी वृद्धि हुई थी। जिन अन्य पण्य समूहों में तीव्र वृद्धि हुई, वे थे—फल और सब्जियाँ: 21.8 प्रतिशत (पिछले वर्ष 11.1 प्रतिशत), कोयला: 13.8 प्रतिशत (पिछले वर्ष स्थिति में स्थिरता बनी रही थी) और चीनी: 23.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 7.0 प्रतिशत)। जिन महत्वपूर्ण पण्य समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई अथवा भारी गिरावट आयी, वे हैं—तेल, चाय, रेश्म, कपास, गुड़, वस्त्र, कागज और कागज के उत्पाद और सीमेंट। प्राथमिक वस्तुओं के अन्तर्गत उप-समूह

रेश्म (—36.9 प्रतिशत) और विनिर्मित उत्पादों के अन्तर्गत वस्त्र (—7.9 प्रतिशत) में गिरावट विशेष रूप से अधिक रही, और यही वह बात है जिसकी वजह से सामान्य सूचकांक में वृद्धि को दूर धोयी रहना संभव हो सका। रेश्म समूह में कच्चे जूट, सन और मेस्ता के मूल्यों में, जिनका भार सामान्य सूचकांक में लगभग 0.6 प्रतिशत है, 1985-86 में 70 प्रतिशत की गिरावट आयी है। फिर, वस्त्र समूहों में जूट, सन और मेस्ता के रस्सों के मूल्य में, जिनका भार लगभग 1.2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान 43 प्रतिशत की गिरावट आयी। यह मानते हुए कि इस उद्योगका मूल्य सूचकांक मार्च 1985 और मार्च 1986 के बीच अस्थिर रहता है, मार्च 1986 के अंत में सामान्य सूचकांक 359.3 के बजाय 363.6 बनता है। इस प्रकार विस्तृत आधार पर 1985-86 में प्रतिशत वृद्धि 5.0 हुई है। वर्ष 1984-85 में तदनु रूप प्रतिशत वृद्धि 6.9 हुई थी।

सारणी 14—थोक मूल्यों के सूचकांक में घट-बढ़

(1970-71=100)

प्रमुख समूह/समूह/उपसमूह/पण्य	प्रतिशत घट-बढ़ (विन्दुवार) विनिर्मित वित्तीय वर्षों में				
	भार	1984-85	1985-86	1985-86 (अप्रैल-जून)	1986-87* (अप्रैल-जून)
	1	2	3	4	5
सभी पण्य	1000.00	+7.6	+3.8	+3.6	+7.7
I. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	+4.4	+2.8	+4.3	+3.9
लाभ वस्तुएं	297.99	+5.8	+7.8	+7.7	+4.5
(क) अनाज	107.43	+0.2	+11.9	+4.0	-1.6
(i) चावल	51.31	-0.8	+7.7	+6.3	+4.8
(ii) गेहूं	34.17	+1.6	+16.4	-0.9	-8.3
(ख) तेल	21.79	+14.9	+4.0	+0.3	-9.5
(ग) फल और सब्जियाँ	61.32	+11.1	+21.8	+22.3	+14.9
(घ) दूध और दूध उत्पाद	61.50	+1.4	+2.4	+3.6	+3.8

*अप्रैल-जून

	1	2	3	4	5
(क) ग्रैन्य खाद्य वस्तुएं	18.04	—1.0	—21.3	+0.3	+20.3
खाद्य	11.49	—7.0	—23.9	—1.2	+22.1
गैर-खाद्य वस्तुएं	106.21	+1.9	—9.7	—3.5	+3.3
(क) रेशे	31.73	+14.6	—36.9	—12.0	—5.4
पटसन	22.46	—4.6	—25.2	—5.2	—7.8
(ख) तिलहन	42.01	—5.7	—4.1	—3.8	+14.6
खनिज	12.47	+1.4	+0.6	+0.5	—
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6.02	+0.7	—	—	—
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश, और विकनाई वाली वस्तुएं	84.59	+9.9	+8.9	+1.7	+0.9
फोयला	10.39	—	+13.8	—	—
खनिज तेल	49.12	+12.8	+2.7	—	—
III. निर्मित उत्पाद	498.74	+9.8	+3.1	+3.5	+4.3
चीनी, खाइसारी और गुड़	72.41	+13.3	+9.9	+17.5	+13.3
(i) चीनी	21.91	+7.0	+23.2	+14.3	—4.2
(ii) गुड़	45.58	+14.7	+4.8	+18.1	+21.1
(iii) खाइसारी	4.92	+21.4	+21.7	+22.0	—1.0
खाद्य तेल	37.16	—2.0	—0.3	—7.8	+15.0
वस्त्र	110.26	+8.6	—7.9	—1.5	+1.7
कागज और कागज उत्पाद	8.51	+11.2	+3.9	—	—
सीमेंट	7.03	+15.7	—6.0	+3.3	—
रसायन और रसायन उत्पाद	55.48	+6.7	+5.1	+1.5	+0.6
लोहा, इस्पात और लोहमिश्र धातुएं	34.73	+27.7	+1.1	+0.7	+0.2

*अनर्गल

102. सामान्य सूचकांक की प्रवृत्ति के विपरीत, कुछ अर्निचार्ज पण्यों के मूल्य वर्ष के दौरान वास्तव में बढ़े हैं। ये पण्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं में महत्वपूर्ण हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पण्यों के समूहों के आधार पर "सामान्य मूल्य सूचकांक" की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना अधिक उपयुक्त होगा। यदि इस प्रकार की वस्तुओं के 24 पण्य/उपसमूहों के सूचकांकों पर, जिनका सामान्य सूचकांक में कुल भार 57.5 प्रतिशत है, अलग से विचार किया जाये और अधिक समायोजित 'थोक मूल्य सूचकांक' निकाला जाये, तो मूल्य सूचकांक में वृद्धि 7.5 प्रतिशत बनती है, जबकि 1984-85 में यह 6.1 प्रतिशत थी। यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति के अनकूल प्रतीत होती है जिसमें बिन्दुवार आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। किन्तु औसत आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 6.4 प्रतिशत की वृद्धि 1984-85 की वृद्धि के लगभग बराबर ही थी।

103. पण्य समूहों के भार के अनुसार सामान्य मूल्य सूचकांक की वृद्धि में योगदान से संबंधित पण्य समूहों और साथ ही प्रत्येक समूह में महत्वपूर्ण पण्यों व योगदान के आंकड़े सारणी 15 में दिये गये हैं। "ईंधन, बिजली, प्रकाश और विकनाई के पदार्थ" के प्रमुख समूह ने सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि में 32.4 प्रतिशत का योगदान दिया है, जबकि 1984-85 में यह 17.5 प्रतिशत था। यह वृद्धि मुख्यतः बिजली के अधिक योगदान के कारण थी। प्राथमिक वस्तुओं का भार की दृष्टि से 29.0 प्रतिशत का योगदान 1984-1985 से 6.1 प्रतिशत अधिक था। अनाज और फल और सब्जियों जैसे पण्यों के योगदान में जहाँ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं रेशे तथा अन्य खाद्य वस्तुओं ने स्पष्ट ऋणात्मक योगदान दिया है। तिलहनों का योगदान लगातार दूसरे वर्ष ऋणात्मक रहा है। मूल्य वृद्धि में निर्मित उत्पादों का अंश उल्लेखनीय रूप से कम होकर 60 प्रतिशत से 39 प्रतिशत रह गया, जो मुख्य रूप से जूट के धस्त्रों, डेरी उत्पादों, खाद्य तेलों और सूती वस्त्रों के कारण भव हुआ।

सारणी 15—थोक मूल्य सूचकांक:
पण्य समूहों के भारित योगदान में प्रवृत्तियाँ

	भार	1984-85	1985-86
सभी पण्य	1100.00	100.0	100.0
I प्राथमिक वस्तुएं	416.7	22.9	29.0
1. अनाज	107.43	0.2	24.0
2. दालें	21.79	4.9	2.8
3. फल और सब्जियाँ	61.32	7.7	31.6
4. दूध और दूध से बनी वस्तुएं	61.60	1.0	3.0
5. अंडे, मछली और मांस	18.97	5.0	7.1
6. अन्य खाद्य पदार्थ	16.04	-0.3	-11.2
7. विनोद	42.01	-3.0	-3.8
8. रेस्ते	31.73	4.9	-26.8
II ईंधन, पावर, बिजली और चिकनाई वाले पदार्थ	84.59	17.5	32.4
9. कोयला खनन	11.47	0.1	7.4
10. खनिज तेल	49.12	13.7	6.1
11. बिजली	24.00	3.6	19.1
III विनिर्मित वस्तुएं	498.74	59.6	38.6
12. डेयरी उत्पादों	3.88	1.0	नगण्य
13. ग्लास मिल उत्पाद	4.64	-0.7	0.5
14. बेकरी उत्पादों	1.85	0.2	0.2
15. चीनी, कन्फेक्शनरी आदि	0.53	—	0.1
16. चीनी, खाण्डमारी और गुड़	72.41	11.8	18.8
17. खाद्य तेल	37.16	-0.9	-0.3
18. तैयार तम्बाकू	19.49	0.6	12.3
19. सूती वस्त्र	81.02	4.1	-1.0
20. जूट, सन तथा मेस्ता वस्त्र	12.14	3.4	-16.7
21. जूट तथा समूह की वस्तुएं	0.90	0.1	0.5
22. परिवहन उपकरण	16.73	1.7	6.4

टिप्पणियाँ: भारित योगदान 'सभी पण्य' के प्रतिशत के रूप में है।

104. वर्ष के दौरान निर्देशित मूल्यों में कई बार वृद्धि की गयी, जिसके ध्योरे आगे दिये गये हैं। सामान्य मूल्य स्तर पर इन परिवर्तनों का भारी असर पड़ा, किन्तु यह असर काफी समय बाद हुआ। सामान्य मूल्य स्तर पर केवल सीधे प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान है कि थोक मूल्य सूचकांक में निर्देशित मूल्यों का भार में परिवर्तन की दृष्टि से योगदान 1985-86 में 35.7 प्रतिशत रहा, जबकि 1984-85 में यह 37.3 प्रतिशत था।

105. इस तरह, यह सब है कि थोक मूल्यों की वृद्धि की गति 1985-86 में घाटी में रहा है, किन्तु इसके साथ यह बात है कि कुछ अतिव्यय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की दर उच्चतर रहा है। इस अलग-अलग विश्लेषण से उचित का मूल्य नाति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेषकर तब जब कि स्थूल आर्थिक नाति का उद्देश्य मुद्रास्फोटिकारी प्रभावों से औसत व्यक्ति को रक्षा करना हो।

106. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मूल्य वृद्धि विद्युत् आधार पर 3.7 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष

की तदनुसूची तिमाही 3.6 प्रतिशत से कुछ ही अधिक थी। निर्मित उत्पादों ने मूल्य वृद्धि को और बढ़ावा दिया। इनमें मुख्य वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 4.3 प्रतिशत हुई थी, जबकि 1985-86 की पहली तिमाही में यह वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुओं और ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाई दोनों में अपेक्षित कम वृद्धि हुई जो 4.3 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत थी। इस अवधि में जिन वस्तुओं ने मूल्य वृद्धि को बढ़ावा दिया वे हैं खाद्य तेल, जो 7.8 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 15.0 प्रतिशत बढ़े, और परिवहन, जो 3.8 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 14.6 प्रतिशत बढ़े। इनके मुकाबले अनाजों के मूल्यों में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 1.6 प्रतिशत की गिरावट और दालों में 0.3 प्रतिशत की अल्प वृद्धि के विपरीत 9.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में चीनी उप-समूह में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की इस तिमाही में हुई 17.5 प्रतिशत वृद्धि से कम थी।

107. चालू वित्तिय वर्ष को पहला तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1986 के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोगा मूल्य सूचकांक में 1985-86 का इसी अवधि में हुई 3.4 प्रतिशत की तुलना में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई अलवत्ता, औसत आधार पर 8.4 प्रतिशत की वृद्धि, 1985-86 का इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि का तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक था।

निर्देशित मूल्यों में परिवर्तन

108. लागत वृद्धि को प्रति करने, उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक सहायता (उपदान) का मात्रा कम करने, कतिपय वस्तुओं का उपभोग-दर में कमी लाने और विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अधिक साधन जुटाने के बहुमुखी उद्देश्य से इस वर्ष विभिन्न वस्तुओं के निर्देशित मूल्यों में अनेक परिवर्तन किये गये।

109. खरीफ तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष अक्तूबर 1985—सितम्बर 1986 के लिए 27 सितम्बर 1985 को घोषित किये गये थे। ये मूल्य मूंगफलों के लिए 350 रुपये, सोयाबेन (काला) के लिए 250 रुपये और सोयाबेन (पला के लिए) 275 रुपये सूरजमुखी के बीजों के लिए 335 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो विपणन वर्ष 1984-85 के लिए निश्चित किये गये मूल्यों से उपर्युक्त प्रत्येक तिलहन के लिए 10 रुपये अधिक थे। इस मूल्य वृद्धि को तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के मूल उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

110. धान और मोटे अनाजों के वसूलों मूल्य और मूंग, उड़द और तूर (अरहर) के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 1985-86 के लिए 8 अक्तूबर 1985 को घोषित किये गये थे। धान के वसूला मूल्य 5 रुपये का एकजमान वृद्धि करके साधारण, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट किस्मों के लिए क्रमशः 142 रुपये, 146 रुपये और 150 रुपये तन कर दिये गये। मोटे अनाजों का वसूला मूल्य पिछले वर्ष 130 रुपये प्रति क्विंटल दर हा रहा गया। मूंग, उड़द और अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किये गये, जो विपणन वर्ष 1984-85 के स्तर से 25 रुपये की वृद्धि दर्शाते हैं। चावल का साधारण, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट किस्मों के निकास मूल्यों में 9 रुपये की एक समान वृद्धि करके 10 अक्तूबर 1985 से क्रमशः 217 रुपये, 229 रुपये और 244 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये और पहली फरवरी 1986 से 14 रुपये रुपये और बढ़ाकर उन्हें क्रमशः 231 रुपये, 243 और 258 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। जनवरी 1986 में केन्द्र सरकार ने विपणन वर्ष 1986-87 के लिए गेहूं के वसूलों मूल्य और जो चारा, और तोरिया/सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये। गेहूं का वसूल मूल्य 5 रुपये बढ़ाकर 162 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। जो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 रुपये बढ़ाकर 132 रुपये और चने का 20 रुपये बढ़ाकर 260 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। तोरिया/सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया, जो 15 रुपये की वृद्धि दर्शाता

है। गेहूं का निकास मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भाटे की रोलर मिलों, दोनों के लिए पहली फरवरी 1986 से 18 रुपये बढ़ाकर 190 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया तथा भाटे की रोलर मिलों के लिए उसे पहली अप्रैल 1986 से और बढ़ाकर 220 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

111. सरकार ने रुई की मशीली और श्रेष्ठतर किस्मों के समूहों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1985-86 के विपणन वर्ष के लिए 11 नवंबर 1985 को 15 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप एफ 414 और एच-777 किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रु. प्रति क्विंटल तय किया गया। एच-4 किस्म (अर्थात् श्रेष्ठ लम्बे रेणु वाली) के लिए यह मूल्य पिछले वर्ष का 535 रु. प्रति क्विंटल ही बना रहा। जूट के डब्ल्यू-5 ग्रेड का सांविधिक न्यूनतम मूल्य असम में विपणन वर्ष 1986-87 के लिए 10 रुपये बढ़ाकर 255 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया।

112. 1985-86 के मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 16.50 रु. प्रति क्विंटल और 1986-87 के मौसम के लिए 17.00 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया जो नवंबर 1985 में घोषित 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल प्राप्ति से संबंध था। इससे लेवो चीनी का निकास मूल्य पहली दिसंबर 1985 से 40 पैसे बढ़ाकर 4.80 रु. प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

113. सरकार ने 15 नवंबर 1985 से आयातित खाद्य तेल के निकास मूल्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वनस्पति उद्योग दोनों के लिए बढ़ा दिये। वनस्पति का खुदरा मूल्य भी बढ़ा दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को दिये जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निकास मूल्य में थोक आपूर्ति के लिए 1,000 रु. की वृद्धि करके उसे 9,000 रु. प्रति टन और टिनों में आपूर्ति के लिए 10,500 रु. प्रति टन कर दिया गया। वनस्पति उद्योग को दिये जाने वाले आयातित तेलों का मूल्य 2,000 रु. बढ़ाकर 11,500 प्रति टन कर दिया गया। वनस्पति का खुदरा मूल्य 20 किलोग्राम के टिन के लिए 313 रु. से बढ़ाकर 345 रु. एक किलो की थैलों का 16.70 रु. से बढ़ाकर 18.05 रु. और आधा किलो की थैलों का 8.60 रु. से बढ़ाकर 9.30 रु. कर दिया गया, जो उद्योग को दिये जाने वाले आयातित तेलों के निकास मूल्य परिकल्पित करता है। वनस्पति उद्योग के साथ किया गया स्वैच्छिक मूल्य करार जनवरी 1986 में समाप्त कर दिया गया।

114. सरकार ने एल्यूमीनियम धातु के कारण मूल्य में 20 दिसम्बर 1985 को 1,000 रुपये प्रति टन से भी अधिक की वृद्धि की। इससे वाणिज्यिक ग्रेड का धातु का विक्र मूल्य (उत्पादन कर छोड़कर) 18,405 रु. से बढ़कर 19,435 रु. प्रति टन हो गया और विद्युत संवाहक (इलेक्ट्रिक कंडक्टर) ग्रेड का धातु का मूल्य 18,505 रु. से बढ़कर 19,635 रु. प्रति टन हो गया। अथवा औसत वृद्धि

6 प्रतिशत हुई। उर्वरकों के सांविधिक खुदरा मूल्य 31 जनवरी 1986 से बढ़ा दिये गये। मुख्य उर्वरक अर्थात् यूरिया और डाइअमोनियम फास्फेट का मूल्य पहले के 2,150 रु. और 3,350 रु. प्रति टन के बजाय अब क्रमशः 2,350 और 3,600 रु. प्रति टन होगा। सरकार ने कोयले का खदान पर औसत मूल्य 9 जनवरी 1986 से कोल इंडिया के मामले में 27 रु. बढ़ाकर 210 रु. प्रति गट्टर कर दिया और सिंगरेनी कोलियरीज के मामले में 219 रु. प्रति टन कर दिया। यह वृद्धि वेतन विल, उच्चतर मूल्यहास और ब्याज प्रभार, भंडारों, बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और परिवहन में हुई वृद्धि तथा अन्य बातों के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण आवश्यक हो गयी थी। सरकार ने पहली फरवरी 1986 से पेट्रोलियम उत्पादों में 6 से 23 प्रतिशत तक मूल्यवृद्धि की घोषणा की। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के आधार मूल्य में प्रति किलोलिटर 500 रु., उच्च गति डीजल तेल में 180 रु., मिट्टी के तेल में 225 रु. और विमान टर्बाइन ईंधन में (केवल स्वदेशी एयरलाइनों के लिए) 500 रु. प्रति किलोलिटर की वृद्धि की गयी। खाना पकाने की गैस के मूल्य में 700 रु. प्रति टन की वृद्धि कर दी गयी। 6 फरवरी 1986 से इनमें कुछ कमी की गयी और यह कमी पेट्रोल के लिए 100 रु., उच्च गति डीजल के लिए 72 रु., और मिट्टी के तेल के लिए 90 रु. प्रति किलोलिटर थी। खाना पकाने की गैस के मामले में यह कमी 280 रु. प्रति टन थी।

115. कुछ अलौह धातुओं के गोदाम पर मूल्य अंतर-राष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियों, डालर के मूल्य में बढ़ोत्तरी और देश की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रावधिक रूप से संशोधित किये जाते रहे।

सरकारी वित्त

116. राजकोषीय क्षेत्र में वर्ष 1985-86 की मुख्य बातों में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा थी, जिससे संपूर्ण राजकोषीय उपायों में स्थिरता आयगी। अन्य मुख्य बातें थी-केन्द्रीय सरकार के राजकोष में अमूलपूर्व वृद्धि और इस वृद्धि के बावजूद राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए पूंजीगत बजट की विन्यास संगत सतत समस्या। राज्यों के वित्त के संबंध में, संसाधनों का केन्द्र से भारी अंतरण और राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट न होने देने की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन प्रमुख बातें थीं। इन्हें निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तार से बताया गया है।

दीर्घकालीन राजकोषीय नीति

117. वर्ष 1985-86 के बजट से दीर्घकालीन राजकोषीय नीति बनाने की सरकार की मंशा का पता चलता है। इस नीति की अग्रधि सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त होगी। दिसंबर 1985 में घोषित दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का लक्ष्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जो

जिससे उत्पादन और रोजगार की वृद्धि हो, ताकि निर्धनता का दोष क्रमिक रूप से कम हो सके। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य समय के साथ-साथ राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ाना और ऐसे उपाय करना है जिससे कर चोरी न हो, ताकि राजकोषीय प्रणाली समग्र रूप से और अधिक प्रगतिशील हो सके। इसके द्वारा अनिवार्य वस्तुओं पर करों की कम दरों और अनाज, खाद्य तेलों और घी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आर्थिक सहायता दोनों ही माध्यमों से परोक्ष कर प्रणाली के प्रवर्तन को और प्रगतिशील बनाने के प्रयासों में बराबर सहायता भी देने की योजना है। इसमें कर विन्यास का बारीकी से जायजा लेने और विकास और सामाजिक न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुधारों के साथ जिन दिशाओं में देश को आगे बढ़ाना है, उनका पता लगाने और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने की राजस्व में कोई विशेष उल्लेखनीय हानि न हो, का प्रस्ताव है। इसका एक और लक्ष्य सुधारों के कार्यान्वयन की गति को इस बात को ध्यान में रखकर नियंत्रण में रखना है ताकि उत्पादन के मौजूदा ढांचे में, जो अतीत की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप विकसित हुआ है, कोई गड़बड़ी न हो। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने को उच्च प्राथमिकता देने के कारण, योजना के लिए इस तरह अधिक से अधिक वित्तपोषण करना होगा जिससे मुद्रास्फीति न बढ़े और इसके लिए बजट और सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठानों द्वारा निमित्त अधिशेष राशियों पर निर्भर रहना क होगा और उसी के अनुरूप उधार ली गयीं निधियों पर निर्भरता को कम करना होगा। दीर्घकालीन वित्तीय नीति का यह अनिवार्य तत्व है।

केन्द्र सरकार का बजट 1986-87

118. करों की 1985-86 दर पर 1986-87 में बजट घाटा अनुमानतः 4,095 करोड़ रुपये होगा। कर संबंधी प्रस्तावित उपायों और राहतों को हिसाब में लेने पर केन्द्र सरकार को 445 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है, जिससे अगूरित घाटा 3,650 करोड़ रुपये रहेगा। यह घाटा 4,490 करोड़ रुपये के घाटे के संशोधित अनुमान से 840 करोड़ रुपये या 18.7 प्रतिशत कम होगा और 1985-86 के 3,316 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 334 करोड़ रुपये या 10.1 प्रतिशत अधिक होगा (अंतिम आंकड़े बजट के बाद किये गये संशोधनों को हिसाब में लेकर हैं)।

119. 1985-86 के जट में जहां प्रत्यक्ष करों के संबंध में अनेक नयी बातें थीं, वहीं इस साल के बजट में संशोधित योजित मूल्य कर (मॉडवैट) के माध्यम से परोक्ष करों में सुधार लाने के लिए नयी प्रक्रिया शुरू की गयी।

120. दीर्घकालीन वित्तीय नीति के अनुसरण में आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, किन्तु वेतन-

भौमी लोगों के लिए मानक कटौती बेतन-भ्राय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी और इसकी उच्चतम सीमा पहले के 6,000 रु. में बढ़ाकर 10,000 रु. कर दी गयी। इन छूटों में लगभग 3.5 लाख कर्जाताओं को लाभ होगा।

121. उपहार कर में किए गए परिवर्तनों में निम्न-लिखित शामिल हैं: (i) आधारभूत छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना, (ii) कर-योग्य उपहारों के मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर एक समान कर लगाना, (iii) उपहारों के एकीकरण से संबंधित प्रावधान को हटा देना, और (iv) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980, पति-पत्नी को उपहार, भोमा की पालिसियों के उपहार, कारोबार करते समय दिए जानेवाले उपहारों और किसी व्यक्ति को अधिकतम 500 रुपए तक के उपहारों से संबंधित कतिपय छूटों को समाप्त करना।

122. जहाँ तक पूंजीगत लाभों पर कराधान का संबंध है, आस्तियां प्राप्त करने की लागत या उसके उचित बाजार मूल्य निर्धारण की तारीख 1-1-1964 से बढ़ाकर 1-4-1974 कर दी गयी है और हमारतों और भूमि से होने-वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के लिए 50 प्रतिशत की एकसमान कटौती दर तय की गयी तथा अन्य के लिए यह 60 प्रतिशत थी। प्रारंभिक कटौती की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तय कर दी गयी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य अधि-सूचित एजेंसियों द्वारा जारी किये गये अधिसूचित बांडों को उन निवेशों की सूची में शामिल किया गया, जिन्हें पूंजीगत लाभों पर आयकर अधिनियम की धारा 54उ के अन्तर्गत कराधान से छूट के लिए पात्र निवेश माना गया है। जिन मामलों में पूंजीगत लाभ पुराने मकान के बेचने से मिला हो, वहाँ आवासीय मकान खरीदने के लिए एक वर्ष की शर्त बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गयी है। सरकार ने यह भी अधिकार प्राप्त कर लिया है कि वह ऊँचे मूल्य की संपत्ति को खरीद ले, जो बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की गयी हो। यह खरीद हस्तांतरण करने वाले के द्वारा तय किये गये मूल्य पर की जा सकेगी।

123. कंपनियों पर प्रभार, जो मुख्यतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा रहता है, निर्धारण वर्ष 1987-88 से समाप्त कर दिया जायेगा और साथ ही नयी निधि योजना लागू की जायेगी। यह नयी योजना, निवेश अनुसूति-योजना के स्थान पर होगी और यह निर्धारित की कटौती लाभ के 20 प्रतिशत तक के बराबर उस स्थिति में होगी, जब लाभ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा हो या संयंत्र और मशीनों की खरीद के लिए उपयोग में लाए गए हों। कंपनी आय पर अधिकार निर्धारण वर्ष 1987-88 से समाप्त करने की योजना दीर्घकालीन वितीय में की गयी थी जिसे राजस्व संबंधी बातों को ध्यान में रखकर एक साल के

लिए स्थगित कर दिया गया। कंपनी क्षेत्र से संबंधित बजट की अन्य बातें थीं—मूल्यह्रास व संबंधित उपबंधों को औचित्यपूर्ण बनाना, सम्पत्ति का पहले उपयोग कर लेने के बाद व्याज अदायगी के पूंजीकरण की अनुमति न देना और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उद्यम निधि का निर्माण करना।

124. अनेक चरणों में जो उत्पादन-शुल्क लगता, उसके व्यापक प्रभाव को कम करने का दृष्टि से उत्पादन कराधान को प्रणाली सुधारने और उद्योगिताओं के लिए लागत और मूल्य कम करने की दृष्टि से संशोधित योजित मूल्य कर (साइवैट) लागू करना एक प्रमुख उपाय था। लघु उद्योग के लिए उत्पादन-शुल्क में छूट का योजना को उदार बनाना और खाद्य तेलों के देश में उत्पादन और स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को पर्याप्त सहायता देने की भाँति अभिकल्पना की गयी। राजस्व बढ़ाने के प्रस्ताव का बोझ समाज के संयंत्र वर्ग पर पड़ता था। आयत को जाने वाला वस्तुओं के प्रतिस्थापन और निर्यात संबंधन के लिए प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव से संबंधित उपाय नुसार गये थे भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायक संस्था के रूप में नवी पारस्परिक निधि का स्थापना और सत्कारा क्षेत्र के बांडों का एक और शृंखला, जिन पर प्राप्त लाभ कर-मुक्त होगा, लागू करने के लिए प्रस्ताव किए गए। केन्द्र सरकार के बजट-घाटे का धारणा में संशोधन करने के सिद्धांत को स्वीकार करना और मौद्रिक प्रणाली पर चक्रवर्ती समिति को सत्कारण के अनुसार तत्पर मौद्रिक लक्ष्यों का स्थापना करना जिनके बारे में रिपोर्ट में अत्यंत विस्तार से बताया गया है और भविष्य निधि पर व्याज को दर में बढ़ोतरी बजट की अन्य प्रमुख बातें हैं।

राज्यों के बजट 1986-87

125. 1986-87 के लिए 22 राज्यों के बजटों में से 21 बजट विधानसभाओं द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर विनियोग (च. 2) अधिनियम, 1986 को राज्य के गवर्नर द्वारा 25 मार्च 1986 को अधिनियमित किया गया। करों का 1985-86 का दरों पर ये राज्य बजट 1986-87 में 537 करोड़ रुपए का संयुक्त घाटा दर्शाते हैं, जबकि 1985-86 में 844 करोड़ रुपए का अधिशेष था। किन्तु 380 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाने (छूट निकालकर शुद्ध) और 1986-87 में केन्द्र द्वारा दत्त किए जाने वाले अतिरिक्त करों में राज्यों के 43 करोड़ रुपए के हिस्से को हिसाब में ले लें तो समग्र घाटा कम होकर 164 करोड़ रुपए रह जाता है।

126. राज्यों के 1985-86 के बजट अनुमानों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बाद 100 करोड़ रुपए के समग्र घाटे का अनुमान लगाया गया था। अलग-अलग 1984-85 में 1,438 करोड़ रुपए के अधिशेष के विपरीत संगठित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अंत में 844 करोड़ रुपए का अधिशेष रहा था, जो राज्यों द्वारा आवरकाप्ट अर्थात् करने के

लिए केन्द्र से प्राप्त मध्यावधि ऋणों को पूँजगत खाते में से निकाल देने के बावजूद था। राज्यों का वित्तीय स्थिति में यह बदलाव संसाधनों के केन्द्र से राज्यों को अंतरण के कारण था, जो आंशिक रूप से 8 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव दर्शाता है, जिनमें ऐसे अंतरणों का स्तर बढ़ गया था। वास्तव में 1985-86 वह पहला वर्ष था, जब ये सिफारिशें कार्यान्वित क. गयीं। राज्यों के 1986-87 के बजटों के अनुसार उनके लिए 1985-86 में अंतरित किए गए शुद्ध संवर्धन 17,710 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थे, जो बजट अनुमानों से 21 प्रतिशत की अधिकता दर्शाते हैं। केन्द्र सरकार की कर संबंधी अधिक वसूलियों, अधिक ऋण सहायता और केन्द्र से अधिक अनुदान से भी राज्यों को लाभ मिला।

समेकित स्थिति :

केन्द्र और राज्य : 1986-87

127. केन्द्र और राज्यों का संयुक्त वित्तीय स्थिति के आंकड़े अंतरण 16 में दिए गए हैं। केन्द्र और 22 राज्यों का संयुक्त बजट घाटा 1986-87 में 3.814 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 1985-86 के संशोधित अनुमानों से 168 करोड़ रु. या 4.6 प्रतिशत अधिक बजट अनुमानों से 398 करोड़ रु. या 11.6 प्रतिशत अधिक है (राज्यों के आभ्युदाय चुकाने के लिए केन्द्र द्वारा उन्हें दिए गए 1,628 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण केन्द्र सरकार के पूँजगत वितरणों और राज्य सरकारों का पूँजगत प्राप्तिियों में शामिल नहीं किए गए हैं)।

सारणी 16--केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्राप्तियां और वितरण: 1984-85 से 1986-87 तक

(करोड़ रुपये)

महें	1984-85 (संशोधित अनुमान)	1984-85 (लेखे)	1985-86 (बजट अनुमान)	1985-86 (संशोधित अनुमान)		1986-87 (बजट अनुमान)*	
				राशि	पिछले वर्ष के तदनु रूप संशोधित अनुमानों से प्रतिशत घट-बढ़	राशि	पिछले वर्ष के बजट अनुमानों में प्रतिशत घट-बढ़
				4	5	6	7
i. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	66920	66471	73690	79852	+19.3	85456	+16.0
अ. राजस्व प्राप्तियां	45932	45296	50995	53543	+16.6	58296	+14.3
आ. वित्तों से कर प्राप्तियां	35902	35808	40358	42359	+18.0	47022	+16.5
भा. पूँजगत प्राप्तियां	20988	21175	22695	26309	+25.3	27160	+19.7
ii. कुल वितरण (अ+आ+अ)	72864	71657	77106	83498	+14.6	99270	+15.8
अ. विकासार्थक व्यय (क+ख+ग)	46693	46265	47525	52990	+13.5	54800	+15.3
क. राजस्व	27929	27676	29735	32632	+16.8	34320	+15.4
ख. पूँजी	11327	11383	11441	12934	+14.2	13395	+17.1
ग. ऋण और अधिम	7442	7206	6349	7424	+0.2	7085	+11.6
आ. गैर विकासार्थक व्यय (क+ख+ग)	23846	23393	27913	28321	+19.8	32442	+16.2
क. राजस्व	21978	21683	25926	26149	+19.0	29851	+15.1
ख. पूँजी	1308	1374	1652	1750	+33.8	2161	+30.8
ग. ऋण और अधिम	360	336	335	422	+17.2	430	+28.4
द. अन्य	2520	1999	1668	2187	+13.2	2028	+21.6
iii. कुल अधिशेष (+) या घाटा (—) (i-ii)	—5944	—5186	—3416	—3646		—3814	

टिप्पणियां: (1) राज्यों के संबंध में आंकड़े 21 राज्यों के नियमित बजटों और जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट से संबंधित हैं, इसके अलावा आंकड़ों में विधान सभा वाले क्षेत्र शामिल क्षेत्र शामिल नहीं हैं। नागालैण्ड तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 1984-85 (लेखे) के आंकड़े संबंधित अनुमानों से संबंधित हैं।

(2) अन्य वितरणों में आंतरिक और बाह्य ऋण चुकाना, स्थान या विकासों और पंचायत, राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और द. गरी राशियां, आकस्मिक निधियों में वित्तियोजन और शुद्ध प्रेषण शामिल हैं और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित बजटों में शामिल किये गये केन्द्र सरकार को किये गये ऋण भुगतान के आंकड़ों के लिए उन्हें समायोजित किया गया है।

* इसमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं। बजट के बाव कर-परिवर्तन को नहीं लिया गया है।

128. केन्द्र और राज्यों को कुल प्राप्तियाँ 1986-87 में 85,456 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जो 73,690 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 16.0 प्रतिशत और 79,852 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 7.0 प्रतिशत अधिक होंगे। उनका राजस्व प्राप्तियाँ 58,296 करोड़ रुपए और पूँजीगत प्राप्तियाँ 27,160 करोड़ रुपए 1986-87 में पिछले वर्ष के बजट अनुमानों से क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत अधिक होंगी। पिछले वर्ष शुरू किए गए राजकोषय सुधारों से केन्द्र सरकार के प्रमुख करों का वसूला 1985-86 (संशो. अनु.) में 1984-85 (लेखा) से 22 प्रतिशत अधिक हुई, जो एक दशक में सर्वाधिक है। प्रत्यक्ष कर भाँ बजट अनुमानों से 15 प्रतिशत अधिक थे। गैर निगमित क्षेत्र के कर दाताओं से आयकर का वसूलियाँ 1985-86 के बजट अनुमान से 36 प्रतिशत अधिक हुई। वसूलियाँ में हुई इस अभूतपूर्व वृद्धि से केन्द्र और राज्य दोनों को लाभ हुआ। केन्द्र के हिस्से में 1984-85 (लेखा) का तुलना में 19 प्रतिशत और राज्यों के हिस्से में 30 प्रतिशत (लेखा) का वृद्धि हुई। हालाँकि यह वृद्धि 1986-87 में रह सकती है, यह 1985-86 को तरह उतनी स्पष्ट नहीं होगी। केन्द्र बजट मानता है कि 1985-86 में कराधान को दरों पर 1986-87 में करों से प्राप्त कुल अतिरिक्त राशियाँ 1985-86 (संशो. अनु.) से केवल 7.2 प्रतिशत अधिक होंगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुल कर राजस्व के अनुपात में प्रत्यक्ष करों से कुल राशियाँ 1985-86 (संशो. अनु.) के 20.2 प्रतिशत से घटकर 1986-87 (बजट अनु.) में 19.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित परोक्ष करों के माध्यम से 467 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साधनों में सबसे बड़ा हिस्सा (407 करोड़ रुपए या 87 प्रतिशत) समा-शुल्क का होगा। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त कर से राज्यों के हिस्से के कारण उन्हें अंतरित शुद्ध संसाधन लगभग 40 करोड़ रुपए हों हैं।

129. केन्द्र और राज्यों के कुल संवितरण अनुमानतः 89,270 करोड़ रुपये हैं, जो 1985-86 के संशोधित अनु-

मानों से 5,772 करोड़ रुपये या 6.9 प्रतिशत और बजट अनुमानों से 12,164 करोड़ रुपये या 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। 1986-87 का केन्द्रीय योजना के लिए 22,300 करोड़ रुपये का राशि आवंटित का गया है, जो 1985-86 के बजट अनुमान से 3,800 करोड़ रुपये या 20.5 प्रतिशत अथवा संशोधित अनुमान से 2,206 करोड़ रुपये या 11.0 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में सातवीं योजना के परिव्यय के 40 प्रतिशत (1984-85 के मूल्यां पर) से अधिक का व्यय वास्तविक अर्थों में का जायगा। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र का कुल योजना परिव्यय 1986-87 के लिए क्रमशः 15,880 करोड़ रुपये और 872 रुपये नियत किया गया है, जो 1985-86 के तदनुसार संशोधित अनुमानों से क्रमशः 21 प्रतिशत और 36 प्रतिशत अधिक है। गरीबों हटाने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1986-87 में प्रतिशत रूप में अधिक आवंटन किया गया है।

बाजार से उधार

130. राजकोषीय वर्ष 1985-86 में केन्द्र सरकार ने बाजार से आठ बार उधार लिए—दो बार 500 करोड़ रुपए (प्रत्येक बार) को प्रारंभिक राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में रखी गयी—और कुल 5,764 करोड़ रुपए उधार लिए। वर्ष के दौरान जिन ऋणों को अवधि पूरी होती है (3 प्रतिशत अल्पमापनीय ऋण 1986-87 को मिलाकर, जिसे सरकार ने चुकता करने का निर्णय किया है), उनके लिए 663 करोड़ रुपए का राशि का चुकौता का प्रावधान करने के बाद बाजार से लिए गए उधारों को शुद्ध राशि 5,101 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष को उधार राशि से 1,001 करोड़ रुपए या 24.4 प्रतिशत को पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है (सारणी-17)। बाजार से लिए गए 5,764 करोड़ रुपए के सकल उधार में 5,554 करोड़ रुपए के नकद अभिदान थे और 210 करोड़ रुपए के परिवर्तन थे। केन्द्र सरकार के शुद्ध बाजार ऋण पिछले दो वर्षों की भाँति ही बजट अनुमानों के अनुकूल थे।

सारणी 17—केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा बाजार के लिए गए ऋण—1984-85 और 1985-86 राजकोषीय वर्ष

(करोड़ रुपये)

	सकल बाजार ऋण		चुकीतियाँ (कुल ऋण जिनकी अवधि पूरी हुई)		शुद्ध बाजार ऋण	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
1. केन्द्र सरकार	4591	5764	491	863	4100	5101
2. राज्य सरकारें	1301	1414	529	441	772	973
3. सरकार के कुल ऋण (1+2)	5892	7178	1020	1104	4872	6074
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएँ	1309	1644	92	177	1217	1467
5. राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाएँ (स्थानीय निकायों सहित)	1080	1311	398	569	682	742
6. संस्थाओं के कुल ऋण (4+5)	2389	2955	490	746	1899	2209
7. कुल बाजार ऋण (3+6)	8281	10133	1510	1850	6771	8283

131. राज्यों को सकल उधार राशियाँ 1985-86 में 1,414 करोड़ रुपए थीं, जिनमें से 1,189 करोड़ रुपए नकद अभिदान के माध्यम से और शेष 225 करोड़ रुपए परिवर्तन के द्वारा थे। बाजार से ली गयीं राज्यों की 973 करोड़ रुपए की शुद्ध उधार राशियाँ, अवधि पूरी होने वाले ऋणों (441 करोड़ रुपए) की चुकीता की हिसाब में लेने के बाद, पिछले वर्ष से 201 करोड़ रुपए या 26.0 प्रतिशत अधिक थीं। स्थानीय प्राधिकरणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा 1985-86 में ली गयीं सजग उधार राशियाँ 2,955 करोड़ रुपए थीं। अवधि पूरी होने वाले ऋणों (746 करोड़ रुपए) की चुकीता के बाद शुद्ध उधार राशियाँ 2,209 करोड़ रुपए थीं जो 1984-85 के स्तर से 310 करोड़ रुपए या 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। सरकार (केन्द्र और राज्यों) की कुल शुद्ध उधार राशियाँ चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में 1985-86 में 2.5 प्रतिशत थीं, जबकि 1984-85 में 2.3 प्रतिशत थीं। सरकार द्वारा उधार ली गयीं राशियों की शुद्ध प्राप्ति से, 1985-86 में, योजना-परिचय के 18.8 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ, जबकि 1984-85 में यह 16.0 प्रतिशत था।

132. बाजार से उधार ली गयीं जित राशियों की ऊपर चर्चा की गयी है, उनके अलावा केन्द्र और राज्यों ने भविष्य निधि और अल्प बचत जैसे साधनों से भी उधार लिए। केन्द्र और राज्य सरकारों की आंतरिक ऋण एवं अन्य देयताओं में शुद्ध वृद्धि 1985-86 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.3 प्रतिशत के बराबर हुई, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी।

133. छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा शुद्ध बाजार उधारों में वार्षिक वृद्धि वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 32.7 प्रतिशत, 11.6 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत थी। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, 1985-86 में शुद्ध बाजार उधार 5,101 करोड़ रुपए हो गया या 1984-85 की राशि की तुलना में उसमें 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सकल देशी उत्पाद में उसका अनुपात 2.1 प्रतिशत हो गया। 1986-87 के केन्द्रीय बजट में शुद्ध बाजार उधार 5,300 करोड़ रुपए हो गया या पिछले वर्ष की तुलना में उसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1986-87 में सांकेतिक सकल देशी उत्पाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि का कल्पना के साथ, शुद्ध बाजार उधार चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के 2.0 प्रतिशत बैठेगा, जबकि सातवीं योजना के लक्ष्यों के आधार पर वार्षिक राजकोषीय नीति में इसके 1.6 प्रतिशत होने का लक्ष्य रखा गया है।

134. 1986-87 के वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने बाजार में 12 मई 1986 को पहली बार नकदी व परिवर्तन आधार के तीन ऋणों, अर्थात् 10 प्रतिशत ऋण,

1991, 10.50 प्रतिशत ऋण, 1996 और 11.50 प्रतिशत ऋण 2006 के जरिये प्रवेश किया और 1,320 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाया। केन्द्रीय सरकार ने दूसरी बार 14 जुलाई 1986 को बाजार में दो ऋणों, अर्थात् 10.20 प्रतिशत ऋण, 1993 और 11.50 प्रतिशत ऋण, 2006 (दूसरा निर्गम) के साथ प्रवेश किया और नकदी व परिवर्तन आधार पर 1,200 करोड़ रुपए का अधिसूचित राशि प्राप्त की। अधिसूचित राशि पर 10 प्रतिशत अधिक अभिदान की शर्तें पाठ रखने के अधिकार के साथ केन्द्रीय सरकार ने उक्त ऋणों से 1,320 करोड़ रुपए की सकल राशि प्राप्त की। वर्ष 1986-87 के दौरान उक्त ऋणों से प्राप्त राशि को मिलाकर भारत सरकार के कुल सकल उधार की राशि अब तक 2,640 करोड़ रुपए हो गयी है या उक्त राशि 1986-87 के लिए बजट की गयी सकल राशि का 41.6 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर कूत दरें

135. हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर कूत दरों की बढ़ावा की सजग मुद्रा नीति 1985-86 में जारी रही। 1984-85 के दौरान, पहली बार 10.50 प्रतिशत की कूत दर के साथ 30 वर्षों की अवधि समाप्ति-वाला दार्यावधि प्रतिभूतियाँ जारी की गयीं थीं। 1985-86 में भी इसी प्रकार की प्रतिभूतियाँ जारी की गयीं किन्तु वे 11.50 प्रतिशत की उच्च कूत दर पर थीं। 1984-85 की प्रतिभूतियों की अनुपलब्ध अन्य अवधि समाप्तिवाली प्रतिभूतियों की कूत दरों में 1.00 से 1.24 प्रतिशत अंकों की वृद्धि का प्रावधान किया गया था। चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का सम्मान करते हुए, 1986-87 में जारी किए गए ऋणों के पहले भाग में, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष के ऋणों पर कूत दरें क्रमशः 10 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत और 11.50 प्रतिशत निर्धारित की गयी थीं जबकि 1985-86 में उक्त दरें क्रमशः 9.00 प्रतिशत, 9.50 प्रतिशत और 10.50 प्रतिशत थीं।

केन्द्रीय ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंक का समर्थन

136. जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, केन्द्रीय सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में निरमित वृद्धि के साथ-साथ, अव्यवस्था में प्रारंभित मुद्रा निर्माण के गंभीर निहितार्थों और मुद्रा आपूर्ति के साथ ही केन्द्रीय सरकार के ऋणों के लिए रिजर्व बैंक के समर्थन में भी पिछले वर्षों में वृद्धि होती रही। केन्द्रीय सरकार के लिए रिजर्व बैंक का ऋण समर्थन 1980-81 में कुल के 43.1 प्रतिशत अधिकतम स्तर तक पहुँच गया था, यह अनुपात घटकर 1981-82 में 38.6 प्रतिशत और 1982-83 में 25.2 प्रतिशत रह गया किन्तु 1983-84 में उक्त अनुपात बढ़कर 30.5 प्रतिशत और 1984-85 में 35.9 प्रतिशत हो गया, तबकि 1985-86 में यह अनुपात घटकर 6.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 13)। 1985-86 में निर्धारित प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक का समर्थन कम अर्थात्

367.9 करोड़ रुपए था, यह वही मूल्य के आधार पर है। अलबत्ता, अंकित मूल्य के आधार पर दिनांकित प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की धारिताएं 604.0 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कूपन दरों में वृद्धि और इस समा की सर्वोच्च व्याज दर, अर्थात् 11.5 प्रतिशत की दर के साथ 30 वर्षीय ऋण का शुरुआत के कारण बाजार में साधन स्त्रोतों की जुटान में सहायता मिली। 1985-86 में जारी किए गए ऋणों की कुल राशि के 72.4 प्रतिशत अंश पर सर्वोच्च कूपन दर, अर्थात् 11.50 प्रतिशत की दर लगायी गया थी जबकि 1984-85 में 10.5 प्रतिशत की सर्वोच्च कूपन दर वाले ऋण का अंश

38.2 प्रतिशत था। इसके साथ ही 1985-86 के दौरान दैनिक आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात के कड़ाई से प्रवर्तन के साथ ही, बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात 36.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.0 प्रतिशत कर दिया गया। यद्यपि 1985-86 में दिनांकित प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक समर्थन 1985-86 में कम था, लेकिन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की रिजर्व बैंक के ऋण का शुद्ध राशि 6,469.2 करोड़ रुपए था जो 1984-85 के 6,054.9 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में अधिक थी। बांडों, प्रमाणपत्रों और जमा योजनाओं के जरिए साधन जुटाने से संबंधित विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

सारणी 18—केन्द्र सरकार बजट घाटा, बाजार ऋण और बाजार ऋणों में रिजर्व बैंक की सहायता (1983-84 से 1986-87 तक)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1983-84 (लेख)	1984-85 (लेख)	1985-86 (बजट अनुमान)	1985-86 (संशोधित अनुमान)	1986-87(क) (बजट अनुमान)
1. राजस्व लेखा					
(क) राजस्व	20492.4	24383.7	27116.5	29021.3	31400.2
(ख) व्यय	22890.2	27881.2	32717.8	34961.5	38273.8
(ग) अधिशेष (+)/घाटा (—)	—2397.6	—3497.5	—5601.3	—5940.2	—6873.6
2. पूंजीगत लेखा					
(क) प्राप्तियां	15861.0	17768.9	20862.7	23610.5	24896.8
(ख) संवितरण	14880.6(ख)	18018.6	18577.6	22160.7(ग)	21673.0
(ग) अधिशेष (+)/घाटा (—)	+980.4(ख)	—250.3	+2285.1	+1449.8(ग)	+3223.8
3. कुल प्राप्तियां [1(क) + 2(ग)]	36353.6	42152.0	47979.2	52631.8	56297.0
4. समग्र अधिशेष (+) घाटा (—)	—1417.2 (ख)	—3747.8	—3316.2	—4490.4 (ग)	—3649.8
5. (3) के प्रतिशत के रूप में (4)	3.9	8.9	6.9	8.5	6.5
6. सकल बाजार ऋण	4381.7	4583.7	5754.0	5763.0	5350.0
7. (3) के प्रतिशत के रूप में (6)	12.1	10.9	12.0	10.9	11.3
8. रिजर्व बैंक के अधिकार में दिनांकित प्रतिभूतियां (वृद्धियां)*	1338.1	1644.0	367.9	367.9	
9. (6) के प्रतिशत के रूप में (8)	30.5	35.9	6.4	6.4	

टिप्पणी—(क) इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं और बजट के बाद के परिवर्तन शामिल नहीं हैं।

(ख) इनमें राज्य सरकारों के 31 मार्च 1983 तक के प्रोपरक्वाप्टों को पूरा करने के लिए उन्हें दिये गये 400 करोड़ रुपये के ऋण शामिल नहीं हैं।

(ग) इनमें प्रोपरक्वाप्ट विनियमन के अन्तर्गत पहली प्रमुख 1985 को राज्य सरकारों को दिये गये 1.628 करोड़ रुपये के मध्यकालिक ऋण शामिल नहीं हैं।

* रिजर्व बैंक के अधिशेषों के अनुसार वही मूल्यों के आधार पर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड (दूसरा निर्गम)

137. बांडों, प्रमाणपत्रों तथा जमा योजनाओं के जरिये स्रोत जुटाने के ब्योरे आगे के पैराग्राफों में दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड (दूसरा निर्गम) 3 वर्ष का अवधि समाप्ति के साथ 7 जुलाई 1983 को जारी किए गए और उनकी व्याज दर 7.5 प्रतिशत थी। जैसा कि 9 जुलाई 1979 से प्रारंभ किए जाने वाले सात वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों के मामले में था, उक्त बांड

की आस्तियों के अंतरण/विक्रय पर, पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निवेश सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से प्रारंभ किए गए। 1986-87 के बजट में 3 वर्षीय बांडों का बिक्रय से 20 करोड़ रुपयों का प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। बांडों का बिक्रय के प्रारंभ से अब तक 3 वर्षीय बांडों की कुल बकाया राशि 30 जून 1986 को 89 करोड़ रुपए था और 7 वर्षीय बांडों का 183 करोड़ रुपए था।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र

138. 1 जून, 1982 से जनता के उपयोग के लिए विशेष रूप से छोटे वचनकर्ताओं की निजी वचन राशियों को जुटाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किये गये। उनको व्याज दर (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर) 11.3 प्रतिशत वार्षिक थी। 31 मार्च 1986 को सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों में किया गया कुल अभिदान 17.5 करोड़ रुपये था।

पूंजी निवेश बांड

139. 28 जून, 1982 से पूंजी निवेश बांड शुरू किये गये थे। इन बांडों की अवधि संपाति 10 वर्ष और व्याज दर वार्षिक 7.0 प्रतिशत है। इन बांडों की बिक्री से 1986-87 के बजट में 60 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था। प्रारंभ से लेकर इन बांडों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशियां 30 जून, 1986 को 162.4 करोड़ रुपये थीं।

राष्ट्रीय जमा योजनाएँ

140. सार्वजनिक निवेश के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन स्रोतों को जुटाने के लिए 30 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय जमा योजना प्रारंभ की गयी। मोटे तौर से इसकी मुख्य बातें बैंकों को दीर्घवधि जमा योजनाओं जैसी ही हैं। उक्त योजना के अग्रेज चार वर्षों की अवधि के लिये जमा राशियां रखी जाती हैं जिन पर प्रति वर्ष 10.50 प्रतिशत व्याज लगाया जाता है। उक्त जमा राशियों में विशेष संपत्ति कर और आय कर लाभ शामिल हैं। इन जमा राशियों से प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80D के अंतर्गत इस समय उपलब्ध 10 हजार रुपये तक (भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त 3000 रुपये को राशि को मिलाकर) को छूट के अतिरिक्त 2000 रुपये तक छूट के लिये पाव है। सभी आस्तियों के संवर्ध में उक्त 5 लाख रुपये की समेकित छूट सीमा के अलावा, केवल जमा राशियों के लिए संपत्ति कर से 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। 1986-87 के बजट में उक्त जमा राशियों से 200 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इन जमा राशियों के प्रारंभ से लेकर इनके द्वारा प्राप्त अभिदान की राशि 18 अप्रैल 1986 को 58.7 करोड़ थी जबकि निश्चित अवधि के दौरान सरकार द्वारा नियत की गयी राशि का लक्ष्य 500 करोड़ रुपये था। एल. टी.एफ.पी ने सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय जमा योजना (नयी शृंखला) की रूपरेखा सूचित की है। आगे आगे के लिए इस प्रस्ताव को व्यय पर क्रयिक काराधान से संबंधित अध्ययन दल को भेजा गया है।

राष्ट्रीय वचन प्रमाणपत्र

141. छह वर्षीय राष्ट्रीय वचन प्रमाण पत्र VI और VII निर्गम जो 1 मई 1981 से प्रारंभ किये गये थे, वे आयकर अधिनियम और संपत्ति कर अधिनियम के अधीन उच्च अर्जन तथा उदार लाभों के कारण निरन्तर लोकप्रिय

और आकर्षक होते गये हैं। इन प्रमाणपत्रों में किये गये निवेश आयकर अधिनियम की धारा-80G के अधीन 40,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक अन्य वित्तीय आस्तियों के साथ कर योग्य आय से छूट के लिये पात्र होते हैं और इन प्रमाणपत्रों पर व्याज भी आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ के अधीन अन्य विशिष्ट निवेशों पर अर्जित व्याज के साथ 7,000 रुपये तक छूट के योग्य होता है। इसके साथ ही, अन्य विशिष्ट आस्तियों के साथ 5 लाख रुपये की सीमा तक संपत्ति कर से छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रमाणपत्रों की बिक्री से बड़ी मात्रा में प्राप्ति की प्रवृत्ति 1985-86 के दौरान जारी रही। 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के दौरान कुल जमा की गयी राशि 3,155 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी जबकि 1984-85 के दौरान यह राशि 2,598 करोड़ रुपये थी।

राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट

142. पिछली रिपोर्टों में राज्य सरकारों द्वारा बराबर ओवरड्राफ्टों का लगातार आश्रय लेने की प्रवृत्ति की आलोचना की गयी थी। वित्तीय अनुशासन लाने की दृष्टि से केन्द्र ने राज्य सरकारों को 4 फरवरी, 1985 को यह सूचित किया कि वे अपने अनधिकृत ओवरड्राफ्टों को राजकोषीय वर्ष 1984-85 में 1,808.83 करोड़ रुपये के उस स्तर तक सीमित रखें, जिस पर 17 राज्यों के ओवरड्राफ्ट 28 जनवरी 1985 को थे। उस तारीख को बकाया राशि के स्तरों पर राज्यवार ओवरड्राफ्टों की उच्चतम सीमा भी निर्धारित कर दी गयी। राज्यों को यह भी सूचित किया गया कि यदि ओवरड्राफ्ट 28 जनवरी, 1985 की स्थिति से पहले ही ऊपर जा चुके हों और सात कार्य दिवसों तक जारी रहें तो रिजर्व बैंक संबंधित राज्य के लिये भुगतान बन्द कर देगा। दरमसल रिजर्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल 1985 में दो राज्यों के भुगतान बन्द कर दिये। 11 राज्यों के संवर्ध में ओवरड्राफ्टों का स्तर मार्च 1985 के अंतिम कार्य दिवस को घटकर 947.66 करोड़ रुपये रह गया। 31 मार्च, 1984 को 8 राज्यों के खाते में बकाया राशि 257.57 करोड़ रुपये थी। 27 जून 1985 को 7 राज्यों के संवर्ध में 351.25 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट केन्द्रीय सहायता से निपटाये गये। फिर भी जुलाई 1985 को पुनः ओवरड्राफ्ट लिये जाने लगे और 24 जलाई, 1985 को 9 राज्यों के संवर्ध में व 935.74 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा पर (1985-86 में) पहुंच गया। सितंबर 1985 के अंत में उक्त ओवरड्राफ्ट 5 राज्यों के संवर्ध में घटकर 311.55 करोड़ रुपये हो गये। ओवरड्राफ्टों को विनियमित करने के लिये तैयार की गयी योजना के अधीन, केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 1985 को 17 राज्यों को 1628.01 करोड़ रुपये के मध्यवर्धि ऋण जारी किये जोकि 28 जनवरी, 1985 को उक्त राज्यों के बकाया ओवरड्राफ्टों के 90 प्रतिशत के बराबर थे। केन्द्र ने राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया कि अब इसके बाद रिजर्व बैंक के पास उनके कोई ओवरड्राफ्ट नहीं होने चाहिए और यदि किसी राज्य सरकार के खाते में कोई ओवरड्राफ्ट बकाया रहने लगे और सात कार्य

दिवसों से अधिक समय तक जारी रहते हैं तो रिजर्व बैंक उनके खाते में भुगतान बन्द कर देगा। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्यों ने उक्त योजना की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

पूँजीगत बाजार

निर्गत और जुटायी गयी पूँजी

143. 1985-86 के अधिकांश समय के दौरान पूँजी बाजार में काफी उछाल परिलक्षित हुआ था किंतु 1986-87 के लिये केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत होने के बाद उसमें अस्थायी मंदी दिखलाई पड़ी। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नये पूँजी निर्गमों की राशि 1985-86 के दौरान, 1,527.9 करोड़ रुपये थी

जो 1984-85 में जारी किये गये 1,336.5 करोड़ रुपये के पूँजी निर्गमों की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक वृद्धि को दर्शाते हैं। ईक्विटी शेयर दुगने हो गये जबकि डिबेंचरों के निर्गमों में 22.6 प्रतिशत की गिरावट आयी। साथ ही, इस वर्ष सितंबर 1985 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की तीन कंपनियों ने 265 करोड़ रुपये की राशि के बांड जारी किये।

144. अन्तिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा 1985-86 के दौरान बोनस निर्गमों को छोड़कर जुटाई गयी पूँजी 934.5 करोड़ रुपये हो गयी। पिछले वर्ष जुटाई गयी 858.3 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में यह वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी।

सारणी 19—गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम और जुटायी गयी पूँजी

(सार्वजनिक और निजी)

(करोड़ रुपये)

प्रतिभूतियाँ	पूँजीगत निर्गम		जुटायी गयी पूँजी* (चुक्ता)	
	1984-85 (संगोधित)	1985-86 (अग्रतिम)	1984-85 (संगोधित)	1985-86 (अग्रतिम)
ईक्विटी शेयर	385.87	793.15	242.75	227.46
अधिमाल शेयर	4.86	2.46	1.93	2.87
डिबेंचर	945.74	732.28	613.61	704.19
(i) परिवर्तनीय	164.88	57.81	उत्पन्न नहीं	उत्पन्न नहीं
(ii) अपरिवर्तनीय	780.88	674.47	"	"
जोड़	1,336.47	1,527.89	858.29	934.52

* ये आंकड़े पूँजीगत निर्गमों के नियंत्रक द्वारा प्रदान की गयी सहमति/स्वीकृति के प्रयोजन जुटायी गयी पूँजी से संबंधित हैं और इनमें बोनस निर्गम शामिल नहीं हैं।

स्रोत : ग्रामपुलब्ल

टिप्पणी : 23 फरवरी, 1985 से पूँजीगत निर्गमों के लिये सहमति/स्वीकृति प्राप्त करने की छूट सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। अतः 1984-85 से संबंधित आंकड़े, 1985-86 से पूर्ण तरह तुलनाय नहीं हैं।

स्रोत : पूँजीगत निर्गम नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता

145. अन्तिम आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ऋण संस्थाओं (जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जाया व संभा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सामान्य व संभा निगम तथा उत्तक सहायता संस्थाओं द्वारा कुल मंजूर और वितरित सहायता क्रमशः 6,349.8 करोड़ रुपये और 4,293.2 करोड़ रुपये रहे। इससे पिछले वर्ष का तदनुसृत अधिक तुलना में मंजूर

और वितरित सहायता में क्रमशः 20.0 प्रतिशत और 36.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। 1985-86 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित राशियों और पूँजी निर्गमों में हुई वृद्धि औद्योगिक निवेश को वृद्धिगत प्रवृत्ति को सूचित करता है। 1986-87 में भा इस प्रवृत्ति के बने रहने का संभावना है क्योंकि 1985-86 में पूँजी निर्गमों के नियंत्रक द्वारा प्रदान की गयी सहमतियाँ/स्वीकृतियाँ 3,055 करोड़ रुपये थीं जो 1984-85 के 1,699 करोड़ रुपये के स्तर से 80 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं (सारणी 20)।

सारणी 20 :— गैर-सरकारी कंपनियों (सार्वजनिक और निजी) को पूंजी निर्गम के नियंत्रक द्वारा मंजूर की गयी सहमतियाँ/स्वीकृतियाँ

	(करोड़ रुपये)		
	1983-84	1984-85	1985-86
1. ईक्विटी और अधिमान शेयर (क+ख)	319.46	779.53	1,066.31
(क) प्रारम्भिक	192.09	557.37	645.48
(ख) योगात्मक	127.37	222.16	420.83
2. डिबेंचर	609.36	919.55	1,989.01
जोड़ (1+2)	928.82	1,699.08	3,055.32

टिप्पणी : 2. फरवरी 1985 से पूंजी निर्गमों के लिए सहमतियाँ/स्वीकृतियाँ की प्राप्ति करने की छूट सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी। अतएव 1984-85 से सम्बंधित आंकड़े 1985-86 के आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

नौतिगत परिवर्तन

146. 1986-87 के केन्द्रीय बजट में पूंजी बाजार को मजबूत बनाने और निवेश संबंधी बाधावरण को सुधारने के बारे में प्रस्ताव शामिल है। इन प्रस्तावों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एक अनुसूचियों के रूप में सरकार के क्षेत्र में एक नये पारस्परिक निधि के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि छोटे निवेशकर्ताओं के लिए अतिरिक्त निवेश माध्यम का व्यवस्था हो सके।

147. भारत सरकार द्वारा घोषित दीर्घावधि राजकोषीय नीति के जरिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वह जोखिम पूंजी निधि के संचालन की देखरेख और दीर्घावधि विकास प्रयोजनों के लिए निधियों को जुटाये। इन उद्देश्यों से आयकर अधिनियम की धारा 54ड के अधीन पूंजीगत लाभ कर से मिलनेवाली छूट को मिलाकर कनिष्ठ राजकोषीय स्थितियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उपलब्ध कराये गये हैं।

148. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 इस ट्रस्ट के परिचालन संबंधी कार्य को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के जरिये भारतीय यूनिट ट्रस्ट प्रत्यक्ष ऋण, अचल संपत्ति ग्रहण/करना/बिचना, पट्टा, बिल पुनर्भाजन, व्यापार बैंकिंग आदि से संबंधित कार्य कर सकता है और अनिवार्यता भारतीयों को निवेश/निधि/संविभाग प्रबंध को भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

149. लोकसभा द्वारा पारित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1985 के जरिये भा.औ.वि. बैंक को प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने की तथा भा.औ.वि. बैंक अधिनियम के अंतर्गत अनेकाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पारिभाषिक विस्तार का व्यापक अनाले को व्यवस्था की गयी है ताकि आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों, सेवाक्षेत्रों और छोटे उद्यम-कर्ताओं द्वारा का जानेवाली महायुक्त गतिविधियों को सहायता प्रदान का जा सके तथा इनके साथ ही भा.औ.वि. बैंक को मर्यादित-निर्माण को भूमिका को मजबूत बनाया जा सके।

150. 1985-86 के दौरान सरकार ने पूंजी बाजार को मजबूत बनाने और उसके विविधकरण के लिए अनेक कदम

उठाये। इनमें ये शामिल हैं: कर्मचारी शेयर विकल्प योजना का प्रारंभ जिसके अधीन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी कंपनियों का ईक्विटी पूंजी में हिस्सा दिया जा सकता है, नये इकाइयों के आधुनिक करण, विस्तार और स्थापना संबंधी उद्देश्यों के लिये पूंजी जुटाने के वास्ते संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर (क्यूम्युलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस) नामक नया लिखित का प्रारंभ और सरकार क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा बांडों का जारी करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों को घोषणा।

151. सरकारने क्षेत्र के बांडों को नये योजना ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्रों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इमारत प्रकार के अन्य क्षेत्रों में स्थित सरकारों निगमित निकायों पर लागू है। ये बांड वर्तमान और नये निगमित प्रतिष्ठानों दोनों के ही द्वारा जारी किये जा सकते हैं। बांडों का व्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जायेगी और वह व्याज दर अल्पचया या संचयी हो सकता है। उच्चतम व्याज दर प्रति वर्ष 14 प्रतिशत तय का गया है। बांडों का अंकित मूल्य, जो शेयर बाजारों में सूचेबद्ध होंगे, 500/- रु. या 1000/- रु. हो सकता है। ये बांड सामान्यतः 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले विमोच्य नहीं होंगे और न ही उनकी विमोच्य अवधि 10 वर्ष से अधिक होगी। इन बांडों को बिना किसी संभा के संपत्ति कर से छूट प्रदान की जायेगी। इन बांडों से निवेशकर्ताओं को जो व्याज अर्जित होता है उसके मूल स्रोत पर कर का कोई कटौति नहीं होंगे, और उक्त बांडों के व्याज से प्राप्त आय, आयकर अधिनियम, 1961 क धारा 80ड के अधीन छूट प्राप्त करने का पाव होगा। जैसाकि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में होता है, इन बांडों के मामले में पुनः क्रय सुविधा का अनुमति दी गयी है। साथ ही इन बांडों को पराक्रम और सुपुर्ण के जरिये अंतरित किया जा सकता है।

ईक्विटी मूल्य

152. 1985-86 के अधिकांश भाग के दौरान प्रमुख शेयर बाजारों में ईक्विटी मूल्य उछाल पर थे। स्टॉकवाला को प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए शेयर बाजार के प्राधि-

कारियों द्वारा अपनाये गये विभिन्न विनियामक उपायों के बावजूद, 1985-86 के लिए केन्द्रीय बजट पेश होने के बाद ईक्विटी मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई, जून और जुलाई में उनमें पर्याप्त सट्टाबाज़ी की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ी और अगस्त के मध्य में वे एक नये शिखर स्तर तक पहुँच गये। बाद में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की निरंतर बिक्री के कारण उनमें गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हुई, जो मुख्य रूप से बाज़ार की अनिश्चितताओं के कारण नवंबर तक जारी रही। दिसंबर 1985 में दोषावधि राज-कोषीय नीति के घोषणा के बाद बाज़ार में पुनः दृढ़ता आयी और फरवरी 1986 के मध्य में ईक्विटी मूल्य एक नये शिखर स्तर तक पहुँच गया। 1986-87 के लिए केन्द्रीय बजट पेश होने के बाद जो गिरावट की प्रवृत्ति आयी थी वह अपवादोत्प्रेक्षक रूप में थोड़ी अवधि के सुधार की छोड़कर, जून के अंत तक जारी रही। मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल के मध्य तक ईक्विटी मूल्यों में दृढ़ता आयी जो कि प्रारंभ में सरकार द्वारा बाज़ार की प्रवृत्ति में मंदी लानेवाले कुछ बजट प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने और बाद में कतिपय बजट प्रस्तावों, विशेष रूप से आय कर से अंतर-कंपनी लाभांश के 60 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था पुनः प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव में संशोधन करने के आश्वस्तन के कारण आयी थी। इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप, सामान्य शेयर मूल्यों के लिये रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचकांक (1980-81=100) जो मार्च, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह के लिये 164.4 था, 10 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के लिये बढ़कर 247.0 हो गया और 9 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह के लिए गिरकर 211.6 पर पहुँच गया। उक्त सूचकांक में दिसंबर 1985 और जनवरी 1986 में तेज़ी से बढ़ने के बाद वह 15 फरवरी 1986 को समाप्त हुए सप्ताह में 268.1 के नये शिखर स्तर पर पहुँच गया।

तदनंतर उक्त सूचकांक में गिरावट का प्रवृत्ति आयी और 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में वह 237.9 पर पहुँच गया। बाद में उक्त सूचकांक 230.5 और 248.6 के बीच घटता-बढ़ता रहा और जून के अंतिम सप्ताह में 240.0 पर पहुँच गया।

विदेशी क्षेत्र विषयक गतिविधियां

भुगतान संतुलन

153. राजकोषीय वर्ष 1985-86 के लिये भुगतान मंजूरियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1984-85 की तुलना में 1985-86 में भारत को विदेशों मुद्रा को प्रारक्षित निधियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और वाणिज्यिक आसूचन और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1985-86 में व्यापार घाटे में आया हुआ भारी अन्तर यह दर्शाता है कि भारत में विदेशों भुगतान स्थिति, जिसमें 1984-85 में सुधार परिलक्षित हुआ था, 1985-86 के दौरान तनावपूर्ण था। 1985-86 के राजकोषीय वर्ष के दौरान विदेशों मुद्रा प्रारक्षित निधियों (विशेष आहरण अधिकार, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा) में 577 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त वृद्धि 1984-85 के दौरान हुई 1,271 करोड़ रुपये की वृद्धि के आधे से कम थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को भुगतान किये गये 253 करोड़ रुपये को छोड़कर 1985-86 के दौरान प्रारक्षित निधियों ने 830 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी जबकि 1984-85 के दौरान (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त 70 करोड़ रुपये के शुद्ध आहरणों को छोड़कर) यह वृद्धि 1,201 करोड़ रुपये थी। सारणी 21 में हाल ही के वर्षों में भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त आहरणों तथा पुनः खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1.1 भारत की विदेशी मद्रा प्रारक्षित निधियां

लिप्यलिखित माह के घन में	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां					कोय से	कोय से	गुन:खरीद*	गुद्व शाहरण
	वि भा प्र (मिलि.)	वि भा प्र** (लाख रु.)	स्वर्ण (लाख रु.)	विदेणी मुद्रा (लाख रु.)	जोड़ (लाख रु.)	भ्रतिपूति	(मिलि. वि		
						निधि	भा. प्र)		
						मुविधा तथा विस्तारित निधि मुविधा के (स्तंभ 2+3 + 4)	(मिलियन विभाप्र.)		
						ग्रनगन सकल शाहरण (मिलि. विभाप्र.)	(6-7)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
मार्च 1983	216.4	248.24	225.58	5497.85	5971.67	3966.00	66.50	3899.50	
जून 1984	330.8	382.05	225.58	5712.18	6319.81	4166.00	99.75	4066.25	
मार्च 1985	146.5	180.50	245.78	6816.73	7213.06	4166.00	199.50	3966.50	
जून 1985	303.7	376.89	246.67	6679.80	7303.36	4166.00	251.50	3914.50	
मार्च 1986	115.1	161.40	274.28	7381.35	7820.03	4163.00	397.25	3768.75	
जून 1986	126.9	186.26	274.28	7084.91	7545.45	4166.00	466.00	3700.00	

टिप्पणी :—सकल प्राद्वरण और पुनः खरीद गणियां अगस्त 1980 से हैं, जब क्षतिपूर्ति निधि सुविधा का प्राद्वरण किया गया था।

* पुनः खरीद क्षतिपूर्ति निधि सूविधा और बिस्तारित निधि सूविधा के अन्तर्गत हैं।

****** संबंधित महीनों के अंत में रुपया-वि. आ. अ. विनिमय दर बढ़ते गये ।

154. विशेष आहरण अधिकारों (एम.डी. प्रार.) के संदर्भ में भारत का प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां* मार्च 1986 के अंत में 5,728 मिलियन विशेष आहरण अधिकार थीं। उनमें 1985-86 में 276 मिलियन विशेष आहरण अधिकार का गिरावट आया, जबकि पिछले वर्ष उक्त वृद्धि 696 मिलियन थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होने वाले ऊपर उल्लिखित पूंजा संशोधन लेनदेनों को छोड़कर, उक्त प्रारक्षित निधियों में, 1985-86 में 78 मिलियन विशेष आहरण अधिकार का गिरावट आया, जबकि 1984-85 में उसमें 629 मिलियन विशेष आहरण अधिकार में का वृद्धि हुई थी।

व्यापारिक कारोबार

155. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय वर्ष 1985-86 के दौरान व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़कर 7,951 करोड़ हो गया, जबकि 1984-85 के दौरान यह 5,188 करोड़ रुपये था। व्यापार घाटे में उक्त उल्लेखनीय गिरावट निर्यातों में कमी और आयातों में तब वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

156. 10,420 करोड़ रुपये के निर्यातों से 7.8 प्रतिशत का गिरावट परिलक्षित होता है जबकि पिछले वर्ष के दौरान उसमें 20.2 प्रतिशत का वृद्धि हुई थी। निर्यातों में हुई गिरावट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कच्चे तेल के निर्यातों में भारी गिरावट आया और वह 1984-85 के 1,563 करोड़ रुपये से घटकर 1985-86 के दौरान 135 करोड़ रुपये रह गये। ये दोनों परिष्करण क्षमताओं में और विकास के संकेतक थे।

157. कच्चे तेल से उतर निर्यातों में यद्यपि 1984-85 में हुई 17.5 प्रतिशत का वृद्धि दर का तुलना में 5.7 प्रतिशत को सामान्य वृद्धि हुई, किन्तु विशेष आहरण अधिकारों के रूप में, गैर-तेल निर्यातों में 1984-85 में हुई 7.7 प्रतिशत का वृद्धि का तुलना में 2.4 प्रतिशत का गिरावट आई। भारत के निर्यातों में हुई गिरावट का व्यापार के बृद्धि संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में धामान आने और कुछ विकसित देशों द्वारा संरक्षणवाद को तेज़ कर दिए जाने के फलस्वरूप विकासशील देशों के समूह में से गैर-तेल निर्यातक देशों के समूह के निर्यातों में, विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में, वस्तुतः अधिक तेज़ी से गिरावट आई और उनमें 1984 का 17 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, 1985 में एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई।

158. 1985-86 का प्रथम तीन तिमाहियों के लिए उपलब्ध पण्यवार सूचना से यह पता चलता है कि गेहूं, हरे जवाहरात, तैयार कपड़े, कच्चा लोहा, चावल, काजू और समुद्री उत्पादों के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उक्त मर्चों में गेहूं, चावल, काजू और कच्चे लोहे के निर्यातों में मात्रा को दृष्टि से काफी अधिक सुधार हुआ। दूसरा ओर,

कुछ महत्वपूर्ण पारम्परिक पण्यों, जैसे अपरिष्कृत तंबाकू और खलों के निर्यातों में उनका मात्रा में कमी होने के कारण विशेष गिरावट आई। चाय और रासायनिक पदार्थों के निर्यातों में भी पर्याप्त गिरावट आई।

159. 1985-86 के दौरान कुल आयातों में 11.4 प्रतिशत का वृद्धि हुई और वे 18,371 करोड़ रुपये हो गये। यह वृद्धि 1984-85 में परिलक्षित हुई 7.4 प्रतिशत का वृद्धि दर का तुलना में अपेक्षाकृत तब थी। कच्चा-तेल-निर्यातों के समक्ष तेलों को छोड़कर, आयातों में 1985-86 के दौरान 22 प्रतिशत का वृद्धि हुई जबकि 1984-85 के दौरान 4.8 प्रतिशत का वृद्धि हुई थी। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों (अपरिष्कृत तेल के निर्यात को छोड़कर) में 34.4 प्रतिशत का गिरावट हुई जबकि 1984-85 के दौरान उसमें 0.4 प्रतिशत का वृद्धि हुई थी। 1985-86 के दौरान गैर-तेल आयातों का वृद्धि दर में 18.4 प्रतिशत का वृद्धि हुई जो कि 1984-85 के दौरान हुई वृद्धि का तुलना में लगभग तिगुना था।

160. विशेष आहरण अधिकार के रूप में 1985-86 के दौरान कुल आयातों में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसका तुलना में 1984-85 में 1.5 प्रतिशत का गिरावट हुई थी। गैर-तेल आयातों में, 1984-85 हुई 2.6 प्रतिशत की गिरावट का तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तब दर से 9.3 प्रतिशत का वृद्धि हुई।

161. 1985-86 का प्रथम तीन तिमाहियों के लिए उपलब्ध मदवार सूचना से यह ज्ञात होता है कि कच्चे तेल, लोहा और इस्पात तथा कुछ औद्योगिक कच्चे मालों जैसे, थोक पण्यों के आयात में हुई तब वृद्धि हो आयातों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण था। इसके अलावा, कुछ सरकार उद्यमों जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और निजी क्षेत्र द्वारा पूंजागत सामान के आयातों में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण भी आयात में बढ़ोतरी हुई।

परोक्ष वस्तुएं

162. परोक्ष वस्तुओं के विषय में उपलब्ध आंशिक सूचना से यह पता चलता है कि सरकारों और गैर-सरकारों दोनों ही क्षेत्रों द्वारा लिए गए विदेशी ऋणों पर निरन्तर बढ़ते हुए भारी व्याज भुगतानों के परिणामस्वरूप और संभवतः निजी अंतरणों में कुछ गिरावट के कारण मुख्य रूप से शुद्ध परोक्ष वस्तुओं का प्राप्ति में 1985-86 में गिरावट आई। 1984-85 का तुलना में 1985-86 के दौरान पर्यटन से प्राप्त अर्जन अधिक थे क्योंकि 1985-86 के दौरान विदेशी प्रयत्नों के आयमन को सं. में 9 प्रतिशत का वृद्धि हुई थी, जबकि इसकी तुलना में 1984-85 में 11 प्रतिशत का गिरावट आई थी। विदेश यात्रा, परिवहन और विविध मदों के भुगतान उध्व-गामों प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

*स्वर्ण का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी में दिये गये अनुसार 35 विशेष आहरण अधिकार प्रति औंस लगाया गया है।

विदेशी सहायता और द्विपक्षिय लेनदेन

163. हाल ही के वर्षों में सकल विदेश सहायता में सामान्य तौर पर बल आ रहा है। वहीतर, का प्रवृत्ति 1985-86 के दौरान भोजार रहा। 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उक्त सहायता बढ़कर 3,165 करोड़ रुपये हो गई जो कि 1984-85 की तुलना में 811 करोड़ रुपये अधिक था। विदेशी ऋणा के परिणाम भुगतान में 1984-85 के 647 करोड़ रु० का तुलना में अधिक अर्थात् 737 करोड़ रुपये थे। इसके फलस्वरूप 1985-86 के दौरान विदेश सहायता (पुनः भुगतान) घटाया का शुद्ध आगमन 2,428 करोड़ रुपये रहा जबकि 1984-85 में यह 1,707 करोड़ रुपये था। अमेरिका डालरों के रूप में 1985-86 में विदेश सहायता का शुद्ध आगमन 1,984 मिलियन अमेरिकी डालर था जबकि 1984-85 में यह 1,436 मिलियन अमेरिकी डालर था। 1985-86 के दौरान देशों के द्विपक्षीय खाते में हुए लेन देन में 166 करोड़ रुपये का शुद्ध बहिर्गमन परिलक्षित हुआ जबकि पिछले वर्ष उसमें 195 करोड़ रुपये का आगमन दिखाई पड़ा था।

अनिवास (विदेश) रुपया खातों तथा विदेशी मुद्रा अतिवासों खाता योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि

164. पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 के दौरान अनिवासों भारतियों से जमा खातों में पूँज का आगमन अपेक्षाकृत कम था किन्तु विदेशी मुद्रा अनिवास खाता योजना के अंतर्गत वह पर्याप्त रूप में अधिक था। 1985-86 के दौरान अनिवास (विदेश) रुपया खाता योजना (अनुमानित ब्याज को शामिल न करते हुए) के अंतर्गत 281 करोड़ रुपयों का वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसका तुलना में 1984-85 के दौरान 354 करोड़ रुपयों का वृद्धि हुई था। विदेशी मुद्रा अनिवासों खाता योजना के अंतर्गत शुद्ध आगमन 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 1,151 करोड़ रुपये रहा जबकि 1984-85 में उक्त आगमन केवल 275 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासों खाता योजना में स्थित जनराशियों का ब्याज दरों में दो बार कमी किए जाने के बावजूद 1985-86 में उक्त आगमन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा अनिवासों खाता योजना के अधीन निधियों के भारी आगमन ने आलोच्य वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन को समर्थन प्रदान किया।

विदेशी मुद्रा आस्तियां

165. विदेशी मुद्रा आस्तियों के तीनों घटकों में से, भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा आस्तियों और उसका स्वर्ण धारिताओं में 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान बढ़ोतरी आयी जबकि विशेष आहरण अधिकार धारिताओं में गिरावट परिलक्षित हुई। 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा आस्तियों में 405 करोड़ रुपयों का वृद्धि हुई जबकि 1984-85 का समकक्ष अवधि के दौरान उसमें 968 करोड़ रुपयों का वृद्धि हुई था।

विशेष आहरण अधिकार

166. 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान विशेष आहरण अधिकार धारिताओं में 177 मिलियन का गिरावट आई जबकि 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान उनमें 27 मिलियन का गिरावट आयी थी। 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान विशेष आहरण अधिकार धारिताओं के स्तर में यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 384 मिलियन विशेष आहरण अधिकार धारिताओं के प्रभाव/ब्याज के रूप में भुगतान और निधि में 214 मिलियन विशेष आहरण अधिकार धारिताओं को पुनः खरीद के कारण था, जोकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा पर 390 मिलियन विशेष आहरण अधिकार धारिताओं का खरीद से आंशिक रूप में संभजित हो गई।

स्वर्ण

167. 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान रिजर्व बैंक का स्वर्ण धारिताओं में 28 करोड़ रुपयों का वृद्धि हुई और वे जून 1986 के अंत में 274 करोड़ रु. (84.39 रुपये प्रति 10 ग्राम के संवधिक धारिता मूल्य पर मूल्यांकित) हो गई। 1984-85 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण धारिताओं में 21 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।

अंतराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां

168. 1985 के दौरान अंतराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में आणकाए व्यवस्था की गयी थी। वे दुर्भाग्य से सहां प्रमाणित हो गयीं। विश्व उत्पादन में वृद्धि 1984 के 4.4 प्रतिशत से घटकर 1985 में 3 प्रतिशत रह गया और उक्त वृद्धि में विकासशील देशों के मामले में यह गिरावट 4.1 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत रह गया। माया की दृष्टि से विश्व व्यापार में केवल 2.9 प्रतिशत का वृद्धि हुई अर्थात् पिछले वर्ष यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत थी। ईंधन से इतर निर्यात विकासशील देशों के समूह के निर्यातों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1978 से न्यूनतम द्वितीय स्तर पर था। विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में, उनके निर्यातों में 1984 के 17 प्रतिशत के मुकाबले 1985 में एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई। गैर-तेल पण्य मूल्यों में 12 प्रतिशत से अधिक का ताज़ गिरावट आया जो 1978 से दूसरे तत्काल गिरावट था, ईंधन से इतर निर्यातों के व्यापार के संदर्भ में गिरावट को जो प्रवृत्ति 1983 और 1984 के दौरान रुक गयी थी वह पुनः दिखाई पड़ी। अंतराष्ट्रीय ब्याज दरों में कुछ गिरावट के बावजूद, पूजा आयातक देशों के ऋण सेवा अनुपात में 1985 में पुनः 24 प्रतिशत से अधिक का वृद्धि हुई।

1985 के दौरान एक समूह के रूप में विकासशील देशों का मूल्य स्थिति और अधिक बिगड़ गया। मुद्रास्फोति दबावों को कम करने में औद्योगिक देशों ने और प्रगति की, इसके लिए उन्हें तेल और प्रमुख पण्यों के मूल्यों में हुई गिरावट से मदद मिली। अंतराष्ट्रीय ब्याज दरों में

भो नरमों आये, यद्यपि यह कम पिछले वर्ष की तुलना में कम था। छह महीनों की यूरो डालर जमा दर जून 1985 के 7.68 प्रतिशत से घटकर जून 1986 में 6.80 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार छह महीनों की यूरो येन जमा दर 6.25 प्रतिशत से घटकर 4.63 प्रतिशत हो गया और यूरो इयूरो मार्क जमा दर 5.50 प्रतिशत से कम होकर 4.56 प्रतिशत हो गया। वर्ष के अधिकांश भाग में अमेरिकी डॉलर की जो प्रमुख दर 9.50 प्रतिशत पर स्थिर थी, वह घटकर अप्रैल 1986 में 8.50 प्रतिशत रह गयी और जून 1986 के अंत तक उसी स्तर पर बनी रही।

170. तेल के मूल्यों में तीव्र गिरावट के कारण विकासशील और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में तेल के आयातकों के लिए सुविधापूर्ण स्थिति बनी, यद्यपि औद्योगिक देश इसके प्रमुख हितधारक। हागे जिनके तेल आयात के बिल बहुत भारी हैं। किन्तु तेल संबंधी मूल्य स्थिति अनिश्चित बना हुई है। अलग-अलग देशों में बाह्य स्थिति में तेल मूल्यों में आये गिरावट का शुद्ध प्रभाव कई तथ्यों पर निर्भर होगा जिनमें तेल आयातों पर कम तेल मूल्यों का प्रभाव, तेल निर्यातक देशों की किए जाने वाले निर्यातों पर विपरीत प्रभाव और तेल निर्यातक देशों द्वारा विकसित देशों को प्रेषण तथा सहायता प्राप्तियां शामिल हैं। आय राशियों में भारी अंतर के परिणामस्वरूप जो कि विशेष रूप से औद्योगिक देशों को तेल निर्यातक देशों द्वारा किये जाने वाले तेल मूल्यों में गिरावट के कारण था, औद्योगिक देशों में वृद्धि की संभावनाओं में सुधार की प्रत्याशा की जाती है और इसका कुछ विकसित देशों का निदेश स्थिति पर अनुकूल प्रभाव होता चाहिए।

171. इन अवधि में एक और महत्वपूर्ण बात अमेरिकी डालर का भारी मूल्यह्रास था, विशेषकर एन और इयूरोमार्क के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप विनिमय दरें पुनर्निर्धारित की गयीं, जो विशिष्ट आर्थिक वास्तविकताओं को स्पष्ट परिलक्षित करते हैं। ये वास्तविकताएं संबंधित आर्थिक व्यवस्थाओं की प्रतिवृद्धि के संबंध में अधिक हैं। हालांकि विनिमय दरों के इस पुनर्निर्धारण का भारी अंतर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और पश्चिम जर्मनी के भार, चालू खाते, भुगतान असंतुलनों पर तुरन्त नहीं पड़ा, किन्तु उसके प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगे। इन पुनर्निर्धारण के संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह था कि केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरणों के समन्वित हस्तक्षेप के माध्यम से इसे काफी गति मिली। यह पुनर्निर्धारण बाजार की स्थिति को अत्यधिक प्रभावित किये बिना किया गया, जिससे बड़े औद्योगिक देशों को एक-दूसरे के आर्थिक उद्देश्यों और नीतियों पर और अधिक निर्भरता रखने की प्रेरणा मिले ताकि वे अपने विकास की गति बनाये रखें और बाजार स्थिति को भी सुव्यवस्थित रख सकें। हालांकि यह बात स्वागत योग्य है, किन्तु सार्वभौमिक विकास दृष्टि से यह वांछनीय है कि बहु-पक्षीय निगरानी के लिए प्रयास किया

जाय। इससे विकासशील देशों के हितों और उनके कठिनाई का भी ध्यान में रखा जा सकेगा।

172. विकासशील देशों की आय-वृद्धि में काफी सुधार करने और उसे अधिक समान रूप से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय माहौल से उनके प्रयासों में बाधा पड़ती रहती है। यह माहौल अतमान वृद्धि मुद्रा के अपस्फटिकार प्रवृत्तियों और अपने-अपने व्यापार को संरक्षण देने की प्रवृत्तियों से बना है। औद्योगिक संसार का बेहतर आर्थिक कार्य स्पष्ट सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि अब मुद्रास्फटि नियंत्रण में लाया जा चुका है। औद्योगिक देशों में भारी आर्थिक गतिविधियों का पण्य मूल्यों पर जो कि एक लंबे समय तक उनमें गिरावट दर्शाते रहे हैं, और विकासशील देशों के अत्यन्त निर्यातों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। विश्व वृद्धि के समग्र उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए मांद्रिक और राजकोषीय नीतियों के उचित भूमिश्रण के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक ब्याज दरों की और कम करने की आवश्यकता है। निम्न ब्याज दरों से कई देशों को बाह्य ऋण सेवा संबंधी समस्याएं भी कम होंगी। तेल के मूल्यों में गिरावटों में बड़ा मात्रा में आय का रख औद्योगिक देशों का और मांड दिया है। इन मंदर्भ में, कम आय वाले देशों को दी जाने वाली पर्याप्त रियायतता ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर भी जोर दिया जाना अपेक्षित है। औद्योगिक देशों के बीच बढ़ा हुई गरभणवाद की प्रवृत्ति से विकासशील देशों के बीच समायोजन का बोझ बढ़ता है और ऋण समस्या के समाधान के मंदर्भ में प्रगति का मार्ग अवरोध होता है, अतः एव संरक्षणवादी उपायों पर नये तौर से विचार की आवश्यकता है।

173. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति में विद्यमान सिद्धांत संबंधी तथा अन्य कमियों का बोझ देशों के समूह (विकासशील देश) और इन देशों के समूह (औद्योगिक देश) के उप अधिकारियों की समितियों द्वारा पता लगा लिया गया है किन्तु उक्त प्रणाली का कार्य पद्धति में सुधार लाने के संबंध में गुंजाये गये उपायों को देखते हुए उनका रिपोर्टों में महत्वपूर्ण अंतर है। इन रिपोर्टों में अंतर्राष्ट्रीय मांद्रिक मुद्धार पर चर्चाओं के जरिए सामान्य तौर तरीकों के अभाव कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। यह आशा की जानी चाहिए कि विश्व के विकास के लिए उपयुक्त समाधानों के मंदर्भ में आने वाले वर्ष में अधिक तेजी से प्रगति होगी।

विनिमय दर संबंधी गतिविधियां

174. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अधिकांश प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की दरों में चिर प्रतीक्षित गिरावट आलोच्य वर्ष के दौरान आयी। फरवरी 1985 के अंत से अमेरिकी डालर में पाया गई गिरावट की प्रवृत्ति ज-5 मंत्रियों के बीच, विशेष रूप से येन और इयूरो मार्क की और जिन देशों के चालू खाते में भारी मात्रा में अधिशेष है, उन देशों की

मुद्राओं को अमेरिकी डालर के मुकाबले अधिक मजबूत बनाने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशों में मुद्रा बाजारों में सरकार हस्तक्षेप को सक्रिय रूप में काम में लाने के वास्ते सितम्बर, 1985 के करार के बाद और भी स्पष्ट हो गया। मई 1986 में हुए टोकियो शिखर सम्मेलन में वित्तिमय दरों में सापेक्ष स्थिति का आवश्यकता पर बल दिया गया था। तथापि उक्त सम्मेलन में कुछेक मुद्राओं का घटबढ़ के स्वरूप के संदर्भ में महत्वपूर्ण मतभेद उभर आये। अलवत्ता, यह स्वीकार किया गया कि जी-7 के वित्त मंत्रियों का एक दूसरे के आर्थिक लक्ष्यों और नीतियों पर निगरानी रखने के लिए और जल्दी-जल्दी बैठकें होंगी। यदि इसके फलस्वरूप इन देशों के बीच सामयिक, उचित एवं समन्वित नीतिगत परिवर्तन लाये जा सकें। तो प्रमुख देशों का वित्तिमय दरों में अधिक स्थायिता आ सकती है।

175. 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान वित्तिमय बाजार पहले की तरह सक्रिय बना रहा, तथापि कुछेक अवधियों में उसमें मंदी का व्यापार पाया गया। जुलाई और अगस्त 1985 के दौरान अमेरिकी डालर में पायी गयी गिरावट की प्रवृत्ति में सितम्बर 1985 में परिवर्तन आया। तदनंतर जून 1986 तक प्रमुख चलमुद्राओं और विशेष आहरण अधिकार की तुलना में औसत मासिक डालर दर में कुछेक अपवादों को छोड़कर महीना-दर-महीना गिरावट आती गयी। इसी प्रकार सितम्बर 1985 और जून 1986 के बीच औसत मासिक दरों के रूप में अमेरिकी डालर में येन के संदर्भ में 29.7 प्रतिशत का, ड्यूश मार्क के संदर्भ में 21.3 प्रतिशत का, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में 11.7 प्रतिशत का और पौंड स्टर्लिंग के संदर्भ में 9.5 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ।

176 वर्ष 1985-86 के दौरान विश्व की प्रमुख मुद्राओं और विशेष आहरण अधिकारों के मुकाबले अमेरिकी डालर का समान्यतः मूल्यह्रास हुआ और मूल्यह्रास की यह दर 1984-85 में उसमें हुई मूल्यवृद्धि कहीं ज्यादा बढ़ गयी। इसी प्रकार औसत वार्षिक दर के रूपों में विशेष आहरण अधिकार और पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले अमेरिकी डालर की दर में क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि 1984-85 के दौरान उसमें क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। ड्यूश मार्क की तुलना में अमेरिकी डालर में 1984-85 में जहाँ 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1985-86 में उसमें 19.2 प्रतिशत की गिरावट हुई। येन के मुकाबले उसमें 20.8 प्रतिशत की कमी आयी जबकि 1984-85 में उसमें 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1985-86 में पौंड स्टर्लिंग और ड्यूश मार्क की तुलना में येन में हुई वृद्धि की मात्रा क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत थी। 1985-86 के दौरान पौंड स्टर्लिंग सामान्यतः मजबूत रहा जिसका संभवतः कारण यह रहा होगा कि व्याज दरों का विभेद आकर्षक था और ईक्विटी

बाजार तेज था। तेल के मूल्य गिरने के कारण घिता व्याप्त होने में अगस्त 1985 के बाद इस प्रवृत्ति पर कुछ-कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्ष 1985-86 के दौरान विशेष आहरण अधिकार के मुकाबले पौंड स्टर्लिंग में 6.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 10.9 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ था। विशेष आहरण अधिकार और पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले ड्यूश मार्क में उल्लेखनीय रूप में सुधार होने (क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत) का कारण संभवतः यह है कि वास्तविक वृद्धि और न्यून मुद्रास्फीति की दर के अर्थों में पश्चिम जर्मनी की संभावनाओं के बारे में वातावरण अनुकूल था, इसके अलावा भुगतान संतुलन की स्थिति भी मजबूत थी।

रुपये की वित्तिमय दर

177. भारत के प्रमुख व्यापारी साझेदारों के भारत मुद्रा समूहों के तथा मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में पौंड स्टर्लिंग के संदर्भ में रुपये का मूल्य बराबर निर्धारित होना रहा है। वर्ष 1985-86 जुलाई-जून के दौरान रुपया स्टर्लिंग दर में हुए परिवर्तनों की कुल संख्या 149 थी जबकि पिछले वर्ष वह 164 थी। जून 1985 के अंत और जून 1986 के अंत के बीच अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये में 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट को छोड़कर रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले कमोवेश स्थिर बना रहा, अलवत्ता येन, स्विस फ्रांक, ड्यूश मार्क, पौंड स्टर्लिंग और विशेष आहरण अधिकार और साथ ही अमेरिकी डालर में तीव्र वृद्धि दर्शाते हुए, रुपये ने इन मुद्राओं की तुलना में गिरावट दर्शायी।

रुपया-रुबल वित्तिमय दर

178. वर्ष 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान रुपया रुबल वित्तिमय दर में छ बार अर्थात् 13 जुलाई, 9 सितम्बर और 10 नवम्बर, 1985 को तथा 20 जनवरी, 6 फरवरी और 24 अप्रैल 1986 को परिवर्तन किया गया। एक वर्ष की अवधि में रुपया-रुबल वित्तिमय दर में 12.5 प्रतिशत की गिरावट आयी और वह जून 1985 के अंत के 11.34 रुपये प्रति रुबल घटकर जून 1986 के अंत में 12.96 रुपये प्रति रुबल हो गयी।

मूल्यांकन और संभावनाएँ

179. वर्ष 1984-85 के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य-कलापों की उत्साहजनक विशेषताएँ इस प्रकार थीं: मुद्रास्फीति में निरंतर कमी आ रही थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास खाद्यान्तों का काफी अधिक भंडार उपलब्ध था, वस्तुों स्तर काफी उँचा था और व्यापक व्यापार घाटा होने के बावजूद विदेशी मुद्रागत प्रारक्षित निधियों का स्तर काफी

संतोषजनक था। अलबत्ता, लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर गिरकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गयी। यह वह वृद्धि दर है जिसे सातवीं योजना में 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान बनाये रखने का लक्ष्य रखा गया है। वृद्धि दर में उक्त कमी आंशिक रूप से प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण हुई।

180. वर्ष 1986-87 में अर्थव्यवस्था के कार्यकलाप पिछले दो वर्षों की अपेक्षा बेहतर होने की प्रत्याशा की जा सकती थी। इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि पिछले दो वर्षों के विपरीत इस वर्ष मानसून अच्छा होगा। इसका यह अर्थ है कि वर्ष 1986-87 में कृषि उत्पाद की वृद्धि दर पिछले दो वर्षों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक होगी। आलोच्य वर्ष के दौरान सरकार ने उद्योग क्षेत्र में निवेश की गति को बढ़ाने के वास्ते तैयार किये गये कई नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया। अमल में आ रहे विभिन्न नीतिगत उपायों और निवेश में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1986-87 के दौरान औद्योगिक विकास की संभावना अधिकांशतः मूलभूत सामग्री के उद्योगों, विशेष रूप से विजली उत्पादन उद्योग के कार्य-निष्पादन पर निर्भर होगी। कृषि उत्पादन में सुधार आने से भी द्रुततर औद्योगिक कार्य-निष्पादन करने में सहायता मिलेगी। कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों के तेज गति से विकास करने की संभावना से यह प्रत्याशा उचित प्रतीत होती है कि वर्ष 1986-87 में वार्षिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की मात्रा कम से कम 5 प्रतिशत रहेगी।

181. मध्यावधि संभावनाओं पर नजर डालते समय यह ध्यान में रखना होगा कि सातवीं योजना के दौरान समग्र वृद्धि के लिए मुख्य सहायता औद्योगिक विकास से मिलने वाली है। आय की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि, योजना के छेप वर्षों में उद्योग क्षेत्र द्वारा 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की जाये। वर्ष 1981-82 से औद्योगिक विकास की दर 6 प्रतिशत के आसपास बनी रही है और विकास के इस अपेक्षाकृत न्यून स्तर में परिवर्तन लाने के लिए उपाय करने होंगे। संभावित औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उपाय करने तथा संजीवित बाजार में तेजी आने का पूरा प्रभाव 1986-87 से देखने में आने लगेंगा क्योंकि इसमें लगभग दस वर्ष का समय लग सकता है उक्त परिवर्तन लाने के इन प्रयासों में स्थूल आर्थिक नीति में मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर करने का सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

182. सातवीं योजना के लिये अमायी गयी औद्योगिक नीति में उत्पादकता में तथा टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। सातवीं योजना में वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद-अनुपात लगभग 5 अभिप्रेत होगा। योजना में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त अनुपात अब 5.5 की प्रवृत्ति के मुकाबले कम था। तथापि योजना में

यह भी कहा गया है, “कार्यक्षमता पर जोर दिये जाने के कारण, जो कि सातवीं योजनागत नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, न्यूनतर अनुपात में सुधार होने की प्रत्याशा है।” कार्यक्षमता में सुधार लाने के परिणामस्वरूप उत्पाद में निश्चित ही वृद्धि होगी और उत्पादन की प्रति युनिट लागत कम होगी। इसके कारण मांग संबंधी प्रतिबंध उभरने की गुंजाइश कम होने में सहायता मिलनी चाहिए।

183. कृषि क्षेत्र की समस्या अलग प्रकार की है। कृषि संबंधी नीति ने बहुत बड़े लाभ दिये हैं : खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास विद्यमान खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार से पता चलती है—ये इस नीति की सफलता के ठोस प्रमाण हैं। साथ ही, क्षेत्रीय और फसल संबंधी असंतुलन कृषि संबंधी परिदृश्य की विशेष बात है।

184. इन असंतुलनों ने कई रूपों में अपने आपको प्रगट किया है। उदाहरण के लिए, खाद्यान्नों का स्टॉक जून 1986 के अंत में लगभग 28.6 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह स्तर उस स्तर से निश्चित ही काफी अधिक है जो कृषि की दृष्टि से खराब वर्षों में भी परिचालनगत अपेक्षाओं और बफर स्टॉकों के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार असाधारण रूप से अधिक भंडार होने से भी राष्ट्रीय राजकोष पर पड़ने वाली लागत और गुणवत्ता में आनेवाली संभावित गिरावट, दोनों तरह की समस्याएं उभरती हैं। खाद्यान्न और उर्वरकों के लिए उपदान की राशि 1980-81 के लगभग 1200 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 1985-86 में 3,700 करोड़ रुपये हो गयी है। इसी प्रकार कई पटसन और भेस्ता का उत्पादन सातवीं योजना के लक्ष्य को पार कर चुका है। इसके विपरीत खाद्य तेल और चोनी ऐसे पण्य हैं जिनके आयात भूगतान संतुलन पर काफी दबाव पैदा कर रहे हैं।

185. पिछले लगभग एक दशक में कृषि उत्पादन का जा दृश्य उभरकर आया है उम्मे यह विदित होता है कि गेहूं के उत्पादन में अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। वर्ष 1967-68 और 1985-86 के बीच गेहूं का उत्पादन लगभग 6.0 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। इसी अवधि के दौरान चावल के उत्पादन में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दालों के उत्पादन में वृद्धि नगण्य थी। मोटे अनाजों के उत्पादन में लगभग 0.6 प्रतिशत की गिरावट दर्जायी। वर्ष 1983-84 में ही जाकर चावल का उत्पादन 53-54 मिलियन टन के पिछले उत्पादन से आगे निकल पाया। वर्ष 1984-85 में वह 60 मिलियन टन के नये शिखर पर पहुंच गया। वर्ष 1985-86 में वह और बढ़कर 63.0—63.5 मिलियन टन हो गया। इसके विपरीत मोटे अनाजों

और दानों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि हरित क्रांति से गेहूं और कुछ सीमा तक चावल की फसल को ही लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही कारगर मूल्य समर्थन और वसूली संबंधी नीतियों के परिणामस्वरूप इन पण्यों का, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां पानी की सुनिश्चित आपूर्ति होती है, उत्पादन बढ़ गया है। वर्षा आधारित और सूखे क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता खराब ही रही है। एक ओर खाद्यान्नों और खाद्यन्नों से इतर फसलों के बीच तथा दूसरी ओर विभिन्न खाद्यन्नों के बीच, फसलों की पैदावार की वृद्धि में असमताएं विद्यमान हैं। इसका जुड़ परिणाम यह है कि गेहूं, चावल और पटसन के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने के साथ ही तिलहन की नीची दानों और मोटे अनाजों की कमी रही है।

186. आगामी वर्षों की कृषि संबंधी नीति में सूखी भूमि/वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजों में सुधार लाने और अधिक समन्वित कृषि मूल्य और खरीद नीतियां अपनाने पर जोर देना होगा ताकि विभिन्न फसलों के उत्पादन में मौजूदा असंतुलनों को ठीक किया जा सके। सूखी भूमि पर फसलों के उत्पादन पर अब तक निवेश और टेक्नालाजी की दृष्टि से काफी कम ध्यान दिया गया है, अतः सूखी भूमि/वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाये जा सके हैं। सूखी भूमि का कृषि क्षेत्र समग्र फसल क्षेत्र का 70 प्रतिशत बनता है और कुल कृषि उत्पादन में वह लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देता है। इन क्षेत्रों में उगायी जाने वाली फसलें दालें, मोटे अनाज, तिलहन और रुई हैं और ये फसलें कृषि में बहुत कम निवेश के, अविकसित टेक्नालाजी की सहायता से पैदा की जाती हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों से पार पाने और ऐसे क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर और कठिन प्रयास करना आवश्यक होगा।

187. कृषि उत्पादन में तेजी लाने तथा फसल संबंधी असंतुलनों को दूर करने की आवश्यकता के संदर्भ में एक समेकित कृषि मूल्य नीति तैयार करने का मामला महत्वपूर्ण हो गया है। भारत सरकार यह घोषित कर चुकी है कि ऐसी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकारों के समन्वयन के साथ बनायी गयी राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल किये जा सकते हैं, पहले कृषि पण्यों के परस्पर मूल्यों को फसल प्रणाली में उभरने वाले असंतुलनों को दूर करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक ही फसल के संदर्भ में भी मूल नीति इस प्रकार बनाने की आवश्यकता हो सकती है कि विभिन्न किस्मों का उचित सम्मिश्रण हो सके। तीसरी बात यह है कि मजदूरी और उपदानों से संबंधित नीतियों के लिए कृषि मूल्य सीधा अर्थ रखने हैं और उक्त

नीतियों को राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति में शामिल करना होगा। अंतिम बात यह है कि इस प्रकार बनायी गयी कृषि मूल्य नीति का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इसे उपयुक्त वसूली और वितरण तंत्र की पूरी मदद मिलती रहे।

188. स्थायिता और सामाजिक न्याय के साथ अर्थ-व्यवस्था के विकास में तेजी लाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रणाली पहले की तरह वास्तव में, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहेगी। संसाधन जुटाने और अपेक्षित माध्यमों में उनका विनियोजन करने में इसकी भूमिका हमकी सुदृढ़ता पर एवं वह जो सेवाएं प्रदान कर सकती है, उनकी गुणवत्ता पर निर्भर होगा। इस संदर्भ में, बैंकिंग तंत्र ने अब तक जो लाभ अर्जित किये हैं उन्हें समेकित करना और उनमें सुधार लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

189. बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य ने समेकन की दिशा में पहले ही से कदम उठाये जा रहे हैं। नयी शाखा लाठमें ठीकरण नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक अंतराल को दूर करने पर ध्यान देने/करने के साथ-साथ केवल सुस्पष्ट आवश्यकताओं और मंभाव्य वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर शहरी और महानगरीय बैंक शाखाएं खोलने की परिकल्पना की गयी है। राष्ट्रीय-कन बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत बनाया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाते वाले निवेशों पर तथा बैंकों की प्रारक्षित नकदी निधियों पर मिलने वाले प्रतिलाभों में वृद्धि की गयी है। काफी समयान्तर के बाद बैंकों ने अपने सेवा प्रसारों को सशोधित किया है। इन सभी उपायों से बैंकिंग प्रणाली की अर्थ क्षमता सुदृढ़ होने में सहायता मिलनी चाहिए।

190. प्रत्येक बैंक ने अपने सन्नत कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए एक व्यापक द्विवर्षीय योजना तैयार की है। इन योजनाओं में निम्नलिखित के संबंध में उपाय शामिल हैं: (क) बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के वास्ते आंतरिक विन्यास को मजबूत बनाना, (ख) जहां कहीं आवश्यक हो वहां प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना; (ग) ऋण मूल्यांकन और ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना, (घ) चयनात्मक आधार पर कार्य संबंधी नयी टेक्नोलॉजी अमल में लाना और (ङ) बैंकों की प्राप्ति राशियों की वसूली के स्तर में सुधार लाना, लागतों को नियंत्रित करना तथा उत्पादकता बढ़ाना इन उपायों के फलस्वरूप उक्त योजनाएं पूरी होने पर बेहतर ग्राहक सेवा और सुधरी हुई अर्थक्षमता प्राप्त की जानी चाहिए।

191. दावों अपर्याप्त बसूली एक की चिता की बात है जो निधियों का पुनः नियोजन करने को बैंकों की क्षमता को प्रभावित करता है और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्रतिबंधित करता है। कृषिक्षेत्र में प्राप्य राशियों की समग्र बसूली का माला हाल ही के वर्षों में मांग के 50 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच रही है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों और बैंकों के बीच व्यापक असमानताएं विद्यमान हैं।

192. इन स्थिति के लिए जिम्मेदार तत्वों में से कुछ इस प्रकार हैं: विशेष रूप से बड़े उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझ कर चूक करना, ऋणों का गलत उपयोग, प्राकृतिक आपदाएं ऋण आवेदनपत्रों को त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन और अपर्याप्त वित्तपोषण ऋण के उपयोग पर अपर्याप्त निगरानी और बसूली का क्रियविधियों में विद्यमान कमजोरियाँ। चूंकि वाणिज्य बैंक अपने ऋणों का 40 प्रतिशत अब मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के देने के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें चाहिए कि वे ऐसे ऋणों का गुणवत्ता तथा बसूली में अवश्य सुधार लाएं। ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को नियमित रूप से क्षेत्रों का दौरा करके अपने ग्राहकों के साथ अधिक संपर्क स्थापित करना चाहिए ताकि हिताधिकारियों का पता लगाने में और ऋण आवेदनपत्रों के मूल्यांकन में सुधार आ सके, ऋण के उपयोग पर मजबूतों के बाद निगरानी मजबूत किया जाए और ऋणों का बसूली के लिए नियमित रूप से कारगर ढंग से कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कम वित्तपोषण करने से बचा जाए चुकौती के कार्यक्रम व्यावहारिक ढंग से तैयार किए जाएं और जब प्राकृतिक विपदाएं आये तब निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार अल्पाविधि ऋणों को तत्काल ही मंजूरविधि ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए। प्राप्य राशियों का बसूली के लिए अनुकूल बनाये रखने के महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है। यहाँ राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है।

193. असंतोषजनक बसूली कार्य केवल कृषि अधिम तक हो सोमित नहीं है। उससे दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित हैं, बड़े मासोले और लघु उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता विशेष रूप से चिता का विषय है। इस समस्या को गंभीरता इस राज्य से प्रकट होती है कि बैंक ऋण का लगभग 8 प्रतिशत इन रुग्ण यूनियों में अवरुद्ध हो गया है। संभाव्य रूप से अग्रिम यूनियों को फिर से सक्षम बनाने के उद्देश्य से कारोबारी दृष्टिकोण अपनाता और जिन मामलों में निर्णय नहीं किए गए हैं, उन मामलों में डील निर्णय लेना न्याय संगत प्रवृत्त होता है यह आशा की जाती है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल दृष्टिकोण को प्रवृत्ति करेगा। इस दिशा में उद्योग में प्रारंभिक रुग्णता का शांति पता लगाना, औद्योगिक खातों का समय पर पुनराक्षण करना और सुधारतात्मक उपाय तेजा से सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

194. बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तबीन प्रक्रियाएं विश्वभर में समग्र की मांग बन गई हैं और भारत में बैंकिंग कारोबार के अगले चरण में काफी मातक नई तकनीक अपनाती होगी। कार्यकलापों में तेज सान के बास्ते चयनात्मक आधुनिक टेक्नोलॉजी अन्तर्गत के अन्तर्गत उद्योग और व्यापार में आनेवाले परिवर्तनों के फलस्वरूप बैंक कारोबार के विन्यास में भी परिवर्तन होगा।

गैर-निधिरु कारोबार को अधिक महत्व प्राप्त हो सकता है। पूँजी बाजार में जैसे-जैसे प्रगति होगी और उससे पूर्णता आयेगी उसके अनुरूप वणिज बैंकिंग सेवाओं का विकास होगा। पट्ट पर उपकरण देने का कारोबार तो पहले से ही बढ़ रहा है और न्यास कार्यों जैसे अन्य सेवाओं को भी महत्व प्राप्त हो सकता है। विदेशी बैंकिंग और पूँजी बाजारों के साथ अधिक संपर्क स्थापित हो जाने के बाद विदेशी साक्षीदारी की व्यवस्थाओं बाह्य वाणिज्यिक उधारों और अतिवाते निवेशों जैसे क्षेत्रों में योगदान के लिए अधिक अग्रसर जाना चाहिए। तथापि बैंकों को अन्य संस्थाओं से बचते जुटाने के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना होगा क्योंकि उसमें वचनकर्ताओं को निवेश के अधिक व्यापक माध्यम उपलब्ध होते हैं। उन्हें अपने आप को इन चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा।

195. हाल ही के वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध ऋण का माला बढ़ रही है। लब्ध को प्राप्ति के लिए उच्चतर वित्तीय बचते जुटाने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस की गयी जिस पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वित्तीय साधनों के संबंध में समन्वित दृष्टिकोण तैयार किए जा सकें तदनुसार रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद स्थापित की है जो उद्योग कृषि और व्यापार के लिए वित्त एवं अल्पाविधि और दीर्घाविधि दोनों प्रकार के ऋणों की उपलब्धता का समग्र पुनराक्षण करने के अलावा उनके वित्तीय निपुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से पूँजी और मुद्रा बाजारों की गतिविधियों पर विचार करेगा।

196. जहाँ तक विदेशी लेनदेन का संबंध है योजना के पहले वर्ष के दौरान हुए भारी व्यापार घाटे के परिप्रक्ष्य में सातवीं योजना के लिए भुगतान संतुलन की स्थिति पर फिर से नजर डालनी होगी। व्यापार संतुलन की स्थिति वर्ष 1985-86 के दौरान काफी बिगड़ गयी और उसके फलस्वरूप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त संसाधनों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह 1984-85 के 1.3 प्रतिशत से बढ़कर अगले वर्ष में 2.0 प्रतिशत हो गया भारतीय निर्यातों की वृद्धि भी परिणाम के रूप में पहले का तरह कम हो रहा है। और यह योजना अधि के लिए निर्धारित 6.8 प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि के आधे से भी कम रहा है। इसके विपरित तेल, (निर्यात घटाकर) और तेन के इतर पणों के आयातों में तेज वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक व्यापार घाटे को जो राशि पिछली योजना अधि के दौरान 5,500 करोड़ रुपये के आसपास रही, वह वर्ष के दौरान बढ़कर लगभग 8000 करोड़ रुपये के शिखर पर पहुँच गयी बढ़ती हुई बाज अदायगियों और संभवतः गैर सरकारी अंतरणों में कुछ गिरावट आने के कारण शुद्ध अदुण्य प्रतियाँ भी कम रहीं। तथापि विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खातों की जमा राशियों में अर्याधिक वृद्धि हो जाने और विदेशी सहायता में सामान्य वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर निर्भरता सामित हो गया और उससे प्रारंभित निधि संबंधी स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो जाने में सहायता मिला। इसके बावजूद 1985-86 में भुगतान संतुलन में देखे गया गिरावट के चिह्नों से पता चलता है कि चालू खाते के घाटे की, मुख्यतः व्यापार घाटे में कमी लाकर, कम करने के बास्ते

सत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। निर्यातों का अत्यधिक महत्व सर्वविधित ही है और निर्यात बढ़ाने के लिए नौतियों पर कड़ाई से पालन किये जाने की जरूरत है। विशेष रूप से, बड़े उद्योगों को चाहिए कि वे निर्यातों में अधिकाधिक योगदान दें। हालांकि विश्व व्यापार में वृद्धि की संभावनायें इस पूर्वधारण पर कुछ बेहतर हैं कि तेल के मूल्य मौजूदा स्तरों के आसपास बने रहेंगे, फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में निकट भविष्य में किसी उल्लेखनीय सुधार की आशा नहीं है, इसके बावजूद भारत से बड़ी मात्रा में निर्यातों की काफी गुंजाइश है, खास तौर पर उन औद्योगिक देशों को, जिन्हें तेल मूल्य में सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है।

197. भारतीय निर्यातों की प्रतियोगिता में सुधार लाने के लिए ऐसी नीति अपनाकर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है जिसे विश्व बाजार के हमारे प्रतियोगियों द्वारा अपनाया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं वाले उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग तथा उद्योगों की स्थापना और उनके कार्यन्वापों की लागत के प्रति अधिक सतर्कता पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्यात की अत्यधिक संभावना वाले पण्यों के संदर्भ में निर्यात-योग्य अधिशेषों का निर्माण यथासंभव शीघ्र किया जाए। बड़े औद्योगिक इकाइयों को निर्यात बढ़ाने में अधिक मात्रा में योगदान देना होगा।

198. जहां तक आयातों का संबंध है तेल के शुद्ध आयातों में मूल्य के संदर्भ में वर्ष 1986-87 तथा योजना के शेष वर्षों के दौरान योजना में दिखायी गयी मात्रा के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कमी आने की प्रत्याशा है। इसका कारण तेल मूल्यों में मौजूदा और लक्षित उदारता रहेगा। हमें इन गतिविधियों से निश्चित ही अधिकतम लाभ उठा लेना चाहिए। अलबत्ता, तेल मूल्यों की स्थिति अनिश्चितताओं से भरी रहेगी और उसमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। अतएव, संतोष करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, विशेष रूप से इसलिए भी कि तेल उत्पादों के लिए मांग तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मध्यम से दीर्घ-कालीन दृष्टि से देखा जाये तो ऊर्जा की खोज और उसे सुरक्षित रखने पर बराबर बल दिया जाना चाहिए।

199. तेलों से इतर पण्यों के आयातों में 1985-86 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। पूरे वर्ष के लिए पण्यवार आयातों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं; परन्तु पहले नौ महीनों के लिए उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पूंजीगत वस्तुओं, उर्वरकों, लोहा और इस्पात एवं अन्य आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तेल मूल्यों में गिरावट आने से 1986-87 में निश्चय ही उर्वरकों के मूल्यों में नरमी आयेगी तथापि योजना के अधीन निवेश कार्यक्रम बनाये जाने के कारण पूंजीगत वस्तुओं तथा लोहा और इस्पात के आयातों में वृद्धि जारी रहेगी। फिर भी, आयात

के कुशल प्रतिस्थापन के दोहरे प्रयासों के जरिए ऐसे आयातों को न्यूनतम रखने के लिए गुंजाइश है। वर्ष 1986-87 के बजट में खाद्या तेलों के उच्चतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। खाद्य-तेलों और चीनी के आयातों पर निर्भरता कम करना बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हाल ही के वर्षों में काफी अधिक रही है। इसी तरह से अपरिष्कृत तेल, इस्पात तथा उर्वरकों जैसी भारी मात्रा की मदों के आयात प्रतिस्थापन के लिए कठोर प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए, बिजली, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और कागज उद्योग आदि की स्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग करने और अधिक कृषि उत्पादन, विशेष रूप से उन पण्यों का उत्पादन करने की आवश्यकता है जो निर्यातों को बढ़ावा देते हों और आयातों में कमी लाते हों।

200. गैर-सरकारी अंतरण प्राप्तियां, शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों का महत्वपूर्ण घटक हैं। पिछले दशक में उनमें हुई अत्यधिक वृद्धि का प्रांशिक कारण मध्यपूर्वीय देशों में किये जानेवाले ऐसे अंतरणों में वृद्धि होना था। तेल के मूल्यों में गिरावट आने के कारण इस क्षेत्र से जानेवाले प्रेषणों में कमी आने की संभावना है। वर्ष 1985-86 के दौरान पर्यटकों के आगमन में हुए सुधार को बनाये रखने की आवश्यकता है। हालांकि विभिन्न व्याज दरों पर हमारे विदेशी ऋण का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, यद्यपि अंतर-राष्ट्रीय व्याज दरों में कमी के कारण व्याज-प्रदायगियों के संबंध में होने वाली निछत्ती वर्ष की इस तरह की व्याज प्रदायगियों की तुलना में कमी होगी। वस्तुतः 1986-87 के दौरान रियायती और वाणिज्यिक दरों पर विदेशी ऋण लिये जाने के कारण शुद्ध व्याज-प्रदायगियों की राशि अधिक होगी। समग्र रूप से शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों की राशि में 1986-87 के दौरान मामूली-सी गिरावट आ सकती है।

201. पूंजीगत खाते के संदर्भ में, जहां शुद्ध विदेशी सहायता की राशि के उच्चतर होने की प्रत्याशा है, अंतर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो जानेवाली पूर्व निर्धारित चुकौतियों की राशि भी 1986-87 के दौरान अधिक होगी। वाणिज्यिक उधारों से संबंधित वर्तमान नीति को देखते हुए, विदेशी मद्रागन प्रारम्भित निधियों की मात्रा अधिकांशतः व्यापार घाटे की मात्रा द्वारा निर्धारित होगी। किचनूक प्रारम्भित निधियों का स्तर संतोषजनक है और 1986-87 के दौरान विदेशी प्रदायगियों की स्थिति के प्रबन्ध में किसी कठिनाई की परिकल्पना नहीं की जाती है।

202. इसी प्रकार, 1986-87 के दौरान और उसके बाद सातवीं योजना के सकल कार्यान्वयन के लिए भुगतान संतुलन की स्थिति चिंता की बात होगी। इसका यह अभि-प्राय है कि रियायती सहायता के लिए कोई भी उज्ज्वल संभावना न होने, विदेशों से प्रेषणों का घटती हुई संभावना होने और भारी मात्रा में आयात न की जाने वाली मदों

के आयातों में वृद्धि होने की संभावना होने के कारण निर्यातों में वृद्धि करने के हमारे प्रयासों को काफी मजबूत करने की आवश्यकता है।

203. राजकोषीय मंत्र पर एक स्वागत योग्य बात रही है कि कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रमुख केन्द्रीय करों की वसूली में 1985-86 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष से 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट अनुमानों में भी आयकर वसूलियों में 36 प्रतिशत की नाटकीय वृद्धि हुई। इन सब के बावजूद चिंता का विषय राजस्व खाते में बड़ी मात्रा में चल रहा घाटा है, जिसे पूंजीगत बजट के अधिशेषों से पूरा किया जाता है। 1986-87 के बजट अनुमानों में 6,874 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की परिकल्पना की गयी है जो 1985-86 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में 934 करोड़ रुपये या 15.7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। यह आशा है, राजस्व व्यय की तीन प्रमुख मदें अर्थात् रक्षा, व्याज और उपदान, 1986-87 में राजस्व आय के 67.8 प्रतिशत का उपयोग कर लेंगी जबकि 1985-86 में यह प्रतिशत 66.3 था। राजस्व घाटे के व्यापक बन जाने का आंशिक कारण घाटवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद संसाधनों का अधिक अंतरण होता है। पूंजीगत खाते में अधिशेष की राशि 3,224 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 1,450 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) के मुकाबले काफी अधिक थी। इस अधिशेष से राजस्व घाटे के 46.9 प्रतिशत का वित्तपोषण होगा जबकि पिछले वर्ष इसकी मात्रा 24.4 प्रतिशत थी। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि वित्ताजनक प्रवृत्ति के बने रहने का यह अभिप्राय है कि चाबू व्यय में, जिसमें व्याज-अदायगियां भी शामिल हैं, संसाधनों को अधिक मात्रा में विकास से हटार कार्यों के लिए खर्च करना। सरकारी ऋण में होने वाली वृद्धि, जो कि पूंजीगत खाते में अधिशेष का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। व्याज के बढ़ते हुए भार की ओर संकेत करती है। अतः राजस्व बजट की सहायता करने वाले पूंजीगत बजट की विन्यासगत कमी को दूर करने के उद्देश्य से एक मध्यावधि नीति बनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार संप्रति विद्यमान संसाधनगत प्रतिबन्धों के परिप्रेक्ष्य में व्यय संबंधी नीतियों और क्रियाविधियों का गहराई से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि घाटे को उचित सीमाओं के भीतर सीमित रखा जा सके।

204. पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में पायी गयी निरंतर कमी स्वागतयोग्य विशेषता है। स्थूल मुद्रा (एम3) के विस्तार की दर में उल्लेखनीय गिरावट आयी है और वह 1983-84 के 17.9 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 15.7 प्रतिशत हो गयी है। इस कमी के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में, विशेष रूप से 1986-87 में, मुद्रा नीति का स्वरूप क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह याद रखना होगा कि

1985-86 में थोक मूल्यों में आयी गिरावट में उपभोक्ता मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति निहित है, बिन्दुवार आधार पर उपभोक्ता मूल्यों में 1984-85 के 5 प्रतिशत के मुकाबले 1985-86 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। औसत आधार पर भी 1985-86 में हुई 6.4 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष के समान ही थी। इनका अर्थ यह है कि मूल्य स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाये रखने की आवश्यकता है। यह मान लेने पर कि वर्ष 1986-87 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में होनेवाली वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत होगी जोकि पिछले दो वर्षों के दौरान हुई वृद्धि की अपेक्षा उच्चतर है, यह जरूरी होगा कि 1986-87 में एम3 में होनेवाले विस्तार को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि वह 17.5 प्रतिशत की तीन वर्षीय औसत वृद्धि से काफी नीचे बना रहे। इसीलिए वर्ष 1986-87 में ऋण नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्याप्त ऋण सहायता मुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने की सावधानी बरती जाए।

205. मध्यावधि दृष्टि से भारत सरकार द्वारा चक्रवर्ती समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लेने को एक महत्वपूर्ण बान माना जा सकता है कि बजट घाटे की परिभाषा को इस प्रकार व्यापक बनाया जाए कि दिनांकित प्रतिभूतियों के संबंध में दी जानेवाली रिजर्व बैंक की सहायता को उसमें शामिल किया जाए। सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी चक्रवर्ती समिति की एक अन्य सिफारिश ऐसे मुद्रागत समग्र लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित है जिन पर निगरानी रखी जा सके। बजट घाटे की व्यापक संकल्पना अपनायी जाने और मुद्रागत लक्ष्य निर्धारित करने से, मुद्रागत और राजकोषीय नीतियों में अधिक सामंजस्य लाने में काफी सहायता करनी चाहिए।

भाग II बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियां

206. इस रिपोर्ट के भाग I में वर्ष 1985-86 में विद्यमान समग्र आर्थिक स्थिति का तथा वर्ष के दौरान किये गये मुद्रा और ऋण नीति संबंधी उपायों का पुनरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के इस भाग में रिजर्व बैंक के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की चर्चा की गयी है। वर्ष 1985-86 के लिए बैंक के तुलन पत्र और लेखे रिपोर्ट के अंत में दिये गये हैं :

मुख्य बातें :

207. आलोच्य वर्ष के दौरान की गतिविधियों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि को व्याप्त करने वाली नयी शाखा लाइसेंसकरण नीति अप्रैल 1985 में लागू की गयी।

(ख) ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत अपने ऋण संबंधी कार्यकलापों के संदर्भ में बैंकों को अधिक विधिकार अधिकार दिये गये।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीगत आधार को क्रमबद्ध रूप से मजबूत करने की दिशा में शुद्धता की गयी।

(घ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों को अधिक तर्कसंगत बनाया गया।

(ङ.) वायदा रक्षा सुविधाओं के कार्यक्षेत्र और व्यापकता को बढ़ाया गया ताकि विदेशी भुगतान संबंधी स्थिति में हुए परिवर्तनों और उभर आये नये प्रकार के कार्यकलापों को शामिल किया जा सके।

वाणिज्य बैंकिंग से संबंधित गतिविधियाँ

शाखा विस्तार नीति और प्रगति

208. अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि से संबंधित तीन वर्षीय शाखा विस्तार नीति के सफल कार्यान्वयन के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। इस अवधि के दौरान 12,366 नये कार्यालय खोले गये जिससे मार्च 1985 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 50,980 हो गयी। इन नये खोले गये कार्यालयों में से लगभग 10,876 कार्यालय ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में खोले गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में प्रति कार्यालय औसत जनसंख्या 17,000 के लक्ष्य के मुकाबले सुधरकर 15,500 हो गयी।

209. अप्रैल 1985 से मार्च 1990 तक की अवधि से संबंधित नयी शाखा लाइसेंसिकरण नीति भारत सरकार के परामर्श से तैयार की गयी। इसकी अवधि सातवीं पंच-वर्षीय योजना की अवधि के साथ समाप्त होनेवाली रही गयी है; और यह बैंकिंग सेवाओं के पहले ही प्राप्त कर लिये गये स्तर और विस्तार तथा शेष रह गये अंतरालों और साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा, स्रोत आधार, ऋण कार्य, आंतरिक कार्यों, पर्यवेक्षण और नियंत्रण प्रणालियों तथा वित्तीय व्यावहार्यता में सुधार करके अपनी स्थिति को समेकित करने पर ध्यान देने के आवश्यकता को देखते हुए बनायी गयी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ स्पष्ट स्थानिक अंतराल विद्यमान हैं, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। इस नीति में प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में (1981 की जनगणना के आधार पर) 17,000 की जनसंख्या का लक्ष्य रखा गया है। पहाड़ी इलाकों, कम, आबादी वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परिकल्पना की गयी है कि बैंक सुविधा वाले ग्रामीण केन्द्र में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर की औसत भूमि व्याप्त हो और सामान्यतः 10 किलोमीटर के भीतर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो। शहरी और महानगरीय/पत्तन शहरों में, जहाँ बैंकिंग सेवाओं का विस्तार पहले से ही काफी सघन है शाखाओं का विस्तार पहले की तरह प्रतिबंध वाला रहेगा और अत्यधिक चयनात्मक आधार

पर उनकी जरूरत और वित्तीय व्यावहार्यता को देखते हुए इन क्षेत्रों में नये शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस विस्तार कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा—पहले चरण में अप्रैल 1985 से मार्च 1988 तक की और दूसरे चरण में अप्रैल 1988 से मार्च 1990 तक की अवधि शामिल होगी।

210. जून 1986 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 81 थी जबकि एक वर्ष पहले वह 83 थी। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि निजी क्षेत्र के तीन बैंकों के संदर्भ में उनकी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली को देखते हुए अधिस्थगन आदेश जारी किए गए थे। 26 शाखाओं वाले मिज स्टेट बैंक लिमिटेड को 30 जुलाई 1985 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, 231 शाखाओं वाले लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड को 24 अगस्त 1985 को केनरा बैंक के साथ और 108 शाखाओं वाले बैंक आफ कोचीन को 26 अगस्त 1985 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलित किया गया। इन समामेलनों के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या घटकर 80 हो गयी परंतु ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ. को, जिसने बंबई शाखा खोली, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने के कारण उक्त संख्या बढ़कर 81 हो गयी।

211. 1985-86 (अप्रैल-मार्च) की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों ने 1566 शाखाएं खोली। जिससे शाखाओं की कुल संख्या बढ़कर 52,936 हो गयी। नये कार्यालयों में से लगभग 77 प्रतिशत कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में और 73 प्रतिशत कार्यालय बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये। मार्च 1986 के अंत में विद्यमान सभी कार्यालयों में ग्रामीण कार्यालयों का प्रतिशत 56 था जबकि जून 1969 में यह 22.1 प्रतिशत था। खोले गये 1566 नये बैंक कार्यालयों में से 191 कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंकों के, 583 कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों के, 747 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तथा शेष कार्यालय निजी क्षेत्र के बैंकों के थे।

212. जून 1986 के दौरान समाप्त अवधि के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में कोई नयी शाखा नहीं खोली। इसके विपरीत सात विदेश स्थित शाखाओं को बंद किया गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: भारतीय स्टेट बैंक की श्रीलंका में कार्यरत अनुराधापुरा शाखा और ब्रिटेन में कार्यरत ब्रिस्टल शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा को ब्रिटेन में बोल्टन तथा काबेन्टरी स्थित दो शाखाएं, यूको बैंक की मोंग-काँक और नार्थ पाइंट में स्थित दो शाखाएं और इंडियन ओवरसीज बैंक की हांगकांग में क्वाइचंग स्थित एक शाखा। इसके फलस्वरूप तेरह भारतीय बैंकों को विदेश स्थित कुल शाखाओं की संख्या जून 1986 के अंत में 134 हो गयी। वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का मनोला (फिलीपाइन्स)

प्रतिनिधि कार्यालय बंद किया गया जिससे 4 भारतीय बैंकों की 9 देशों में कार्यरत प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या घटकर 11 हो गयी। सहायक बैंकों, विदेशी बैंकों से संबद्ध संस्थाओं और विविध कंपनियों को संज्ञा क्रमः 7, 4 और 11 पर अपरिवर्तित रही।

213. आलोच्य वर्ष के दौरान ओमान इंटरनेशनल बैंक, एसएओ ने तथा बैंक ऑफ बहरीन एण्ड कुवैत, बीएससी ने बंबई में अपनी एक-एक शाखा खोली और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने नयी दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इसके फलस्वरूप विदेशी बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या, जून-1986 के अंत में, क्रमशः 136 (21 बैंकों के संदर्भ में) और 14 (14 बैंकों के संदर्भ में) थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

214. अप्रैल 1985 से अब तक ग्यारह नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिससे उनकी कुल संख्या जून 1986 के अंत में 194 हो गयी। उन्होंने देश के 342 जिलों को व्याप्त किया। सूचना देनेवाले 190 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशियाँ और अग्रिमों की राशि (अन्तिम आंकड़े) जून 1986 के अंत तक क्रमशः 1364 करोड़ रुपये और 1.510 करोड़ रुपये थी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों और अन्य विशेष योजनाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायता

215. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जहाँ मार्च 1985 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिमों के संदर्भ में शुद्ध बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त किया था वहाँ उन्होंने आलोच्य अवधि के दौरान और प्रगति कर ली। उनके द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिसंबर 1985 के अंत तक दिये गये 20,544 करोड़ रुपये के अग्रिमों की राशि उनके शुद्ध ऋण की 42.7 प्रतिशत बैठती थी। उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार मार्च 1986 के अंत तक शुद्ध अग्रिम 20,853 करोड़ रुपये तक पहुँच गये। शुद्ध बैंक ऋण में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त प्रत्यक्ष अग्रिमों का अंश जहाँ मार्च 1985 में 15 प्रतिशत था, वहाँ दिसंबर 1985 के अंत में 15.3 प्रतिशत था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के भीतर कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों का उक्त तारीख को विद्यमान 10.2 प्रतिशत का अंश भी मार्च 1985 तक प्राप्त किये जानेवाले 10 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

216. 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को प्रदत्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायता की राशि प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 1986 के अंत में, 7,107 करोड़ रुपये थी और यह राशि 140.13 लाख खातों से संबंधित थी जबकि एक वर्ष पहले 114.83 लाख खातों के संदर्भ में उक्त राशि 5,531 करोड़ रुपये थी। इन बैंकों से

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को उपलब्ध कराये जानेवाले ऋण में भी आलोच्य वर्ष के दौरान तेजी आयी तथा इन श्रेणियों के बकाया अग्रिमों में मार्च 1986 में वृद्धि दर्ज हुई और वह 296 करोड़ रुपये से बढ़कर 1394.00 करोड़ रुपये हो गयी और इसके अन्तर्गत 58.30 लाख उधार खाते थे (अन्तिम आंकड़े)।

विभेदक व्याज दर योजना

217. दिसंबर 1985 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान विभेदक व्याज दर योजना के अधीन ऋण खातों की संख्या में 2.79 लाख की बढ़ोतरी हुई और वह 45.51 लाख हो गयी तथा बकाया ऋणों की राशि में 44.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह 486.08 करोड़ रुपये हो गयी। इसी अवधि के दौरान प्रति खाता ऋण की औसत राशि 1,033 रुपये से बढ़कर 1,068 रुपये हो गयी। दिसंबर 1985 के अंत में विद्यमान ऐसे अग्रिमों की राशि पिछले वर्ष के अंत में बैंकों के कुल अग्रिमों का 1.15 प्रतिशत थी। मार्च 1986 के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार विभेदक व्याज दर योजना के अन्तर्गत लगभग 45.70 लाख खातों में 505.5 करोड़ रुपये लगे हुए थे।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

218. नितंबर 1983 में शुरू की गयी, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1985-86 के राजकोषीय वर्ष के लिए 2.50 लाख हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य में से वर्ष के दौरान मंजूर किये जानेवाले औद्योगिक उपक्रमों का अनुपात 50 प्रतिशत से अन्य होना चाहिए था और कारोबारी उपक्रमों का अनुपात 30 प्रतिशत से अनधिक होना चाहिए था। तथापि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में पिछले वर्ष की गयी छूटें 1985-86 के दौरान भी जारी रहीं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों का न्यूनतम प्रतिशत 50 के बदले 30 था और कारोबारी उपक्रमों के लिए कोई उच्चतर सीमा निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। 1985-86 के लिए अन्तिम आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 2.50 लाख हिताधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले 2.18 लाख हिताधिकारियों को 415 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये।

बैंक और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

219. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान 28.23 लाख हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी और बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) 606.27 करोड़ रुपये के मियादी ऋण प्रदान किये गये। छठी योजना की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16.56 मिलियन परिवारों को सहायता दी गयी जबकि 15 मिलियन परिवारों

का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लगभग 3,102 करोड़ रुपये का भिदादी ऋण वितरित किया गया।

220. चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्टों में यह संकेत किया गया था कि सहायता प्राप्त परिवारों में से 60 प्रतिशत बिना किसी अपनी गलती के गरीबी की रेखा पार करने में असफल रहे हैं, अतः नये हिताधिकारियों को योजना में शामिल करने के अलावा छठी योजना अवधि के दौरान सहायता पानेवाले ऋणकर्ताओं की कतिपय पात्र श्रेणियों को अनुपूरक सहायता प्रदान करने की योजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गयी। यह अनुपूरक सहायता उन ऋणकर्ताओं को मदद करने के वास्ते थी जो चूककर्ता नहीं थे और जिन्होंने पहले वित्तपोषित की गयी अपनी आस्तियों को अच्छी हालत में बनाय रखा था या जो अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपनी आस्तियां खो बैठे थे। सातवीं योजना अवधि के दौरान अनुपूरक सहायता के लिए 10 मिलियन परिवारों का भौतिक लक्ष्य रखा गया है जिसे प्रथम तीन वर्षों में पूरा कर लेना है। नये हिताधिकारियों के संदर्भ में सातवीं योजना अवधि के लिए 10 मिलियन परिवारों का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय की राशि 1186.79 करोड़ रुपये है।

221. भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। गरीबी की रेखा पहले जहां 3500 रुपये वार्षिक की पारिवारिक आय के स्तर पर निर्धारित की गयी थी वहां उसे अब बढ़ाकर 6,400 रुपये कर दिया गया है। तथापि, ऐसे परिवारों को निर्धारित करने के लिए 4,800 रुपये के वार्षिक आय स्तर पर न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट की गयी है। इसके अलावा, अंतर राज्याय भिन्नता और गरीबी के स्वरूप में विद्यमान अंतर को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन निधियों का आवंटन प्रत्येक राज्य के गरीबी के स्वरूप के संदर्भ में किया जाएगा। महिला हिताधिकारियों को इस कार्यक्रम के अधीन व्याप्त करने के वास्ते 30 प्रतिशत का अलग से लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

222. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और आस्तियों के हिताधिकारियों को ऋण की उपलब्धता तथा निविष्टियों और आस्तियों को आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने नवंबर 1985 में उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया था ताकि गरीबी विरोधी कार्यक्रम के पूरे लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। अध्ययन दल की अंतरिम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर बैंकों को यह सूचित किया गया है कि प्रायोगिक आधार पर, एक अप्रैल 1986 से देश भर के 22 निर्दिष्ट खण्डों में कुछ चुने हुए प्रयोजनों के लिए,

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सहायता की नकद संचित की प्रणाली लागू करें।

अग्रणी बैंक योजना

223. जिला ऋण योजनाओं के चौथे दौर के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिये जाने तक सितंबर 1985 में अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक द्वारा 1985 की वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के संबंध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ही वर्ष 1986 के लिए स्थूल रूप से वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करें। तथापि, प्राप्त अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में उनमें जो भी परिवर्तन आवश्यक समझे जाएं किये जा सकते हैं। तदनुसार वर्ष 1986 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गयीं और नागालैंड के तीन जिलों को छोड़कर देश के शेष सभी जिलों में उनका कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया।

224. नव निर्मित 3 जिलों अर्थात् तलवारी (असम), अन्ना (तमिलनाडु) और उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के संदर्भ में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी क्रमशः यूको बैंक, केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को सौंपी गयी है।

ऋण प्राधिकरण योजना

225. आलोच्य वर्ष के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना का विस्तृत पुनरीक्षण किया गया और इस बीच वित्तीय लेन-देनों की मात्रा और आकार में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिकांशतः बैंकों को भारी मात्रा में विवेकाधिकार देने के उद्देश्य से उसमें कुछ परिवर्तन किये गये। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भाग 1 में चर्चा की गयी है।

226. वित्तीय अनुशासन में कमी लाये बिना 'शीघ्र कार्रवाई' (फास्ट ट्रैक) प्रणाली के प्रयोग में अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से उसमें कतिपय परिवर्तन किये गए जिन ऋणकर्ताओं ने पूर्व में मानक मानदंडों के मुकाबले के स्तर के स्टाक और प्राप्य वस्तुओं से काम चलाया है, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष के लिए अनुमानित स्टाक और प्राप्य वस्तुएं पूर्व की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी "शीघ्र कार्रवाई" सुविधा के लिए पात्र होंगी बशर्ते उक्त स्टाक और प्राप्य वस्तुएं मानक मानदंडों से अधिक न हों। जिन ऋणकर्ताओं ने इसके पूर्व मानक मानदंडों का पालन किया हो परंतु जिन्होंने चालू/आगामी वर्ष के अनुमानों/प्रक्षेपणों में पर्याप्त एवं वैध कारणों से मानदंडों से विचलित होना आवश्यक समझा हो, वे "शीघ्र कार्रवाई" सुविधा के लिए पात्र समझे जायेंगे बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन मानक मानदंडों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और ऐसे स्तरों के मानदंडों के अनुसरण में एक वर्ष के भीतर कमी लाने की प्रत्याशा की गयी हो। यह सुविधा उन ऋणकर्ताओं को भी उपलब्ध होगी जिनके पास, रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व के मूल्यांकन में

स्वीकृत मानदंडों से उच्चतर स्तर के स्टाक हों बशर्ते वर्तमान वर्ष के लिए मानदंडों से विचलन की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक न हो। तथापि, यदि ऋण प्राधिकरण योजना प्रस्ताव की बाद में की गयी, जांच के बाद उसे तर्कसंगत पाया जाए, तो रिजर्व बैंक ऐसे परिवर्तन के लिए दी गयी अनुमति को वापस ले सकता है। पिछली दो तिमाहियों के लिए तिमाही परिचालन विवरण को समय पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा को इस प्रकार आशोधित किया गया कि उसमें पिछली चार तिमाहियों का कार्य निष्पादन व्याप्त हो जाए। यह भी व्यवस्था की गयी कि वह पिछली दो तिमाहियों में से किसी तिमाही में विवरण प्रस्तुत करने में विलंब भी कर दे तब भी वह "शीघ्र कार्रवाई" प्रणाली के लिए पात्र होगा, अगर वह पहली दो तिमाहियों में वक्त का पाबंद रहा हो।

227. जुलाई 1985 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आने वाली पार्टियों की संख्या में 25 की वृद्धि हुई और वह 843 हो गयी। योजना में शामिल पार्टियों के संबंध में अमल में रहने वाली कुल सीमाओं की राशि मार्च 1986 के अंत में 21,671 करोड़ रुपये थी; इनमें से 63.0 प्रतिशत अंश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित था। कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में उद्योग का अंश 54.4 प्रतिशत और व्यापार क्षेत्र, खास तौर पर सरकारी क्षेत्र, का अंश 43.3 प्रतिशत था।

228. जुलाई 1985 से जून 1986 तक के वर्ष के दौरान 19 शहरी बैंकों से कुल 56.3 करोड़ रुपये की राशि के लिए 113 प्रस्ताव प्राधिकरण के लिए प्राप्त हुए जिनमें से 37.4 करोड़ रुपये को राशि के 85 प्रस्ताव मंजूर किये गये।

ऋण संबंधी अन्य मानदंड

229. मियादी ऋणदात्री संस्थाओं की सहभागिता में उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले मियादी ऋणों में बैंकों के अंश से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को जुलाई 1985 में संशोधित किया गया; इनमें से महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। राज्य स्तरीय संस्थाओं की सहभागिता में बैंक 3 करोड़ रुपये तक (पहले की सीमा 1.50 करोड़) की परियोजनाओं का वित्तपोषण कर सकते हैं। जिन परियोजनाओं की लागत 3 करोड़ रुपये और 7.50 करोड़ रुपये (इसके पूर्व 1.50 करोड़ रुपये और 5.00 करोड़ रुपये) के बीच है उनको बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। 7.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के संदर्भ में बैंक आस्थगित भुगतान गारंटी सहित मियादी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के 25 से 30 प्रतिशत तक की सीमा के लिए सहभागी हो सकते हैं। जिन परियोजनाओं के संदर्भ में बैंकिंग तंत्र का अंश 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है उन्हें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समरूप आधार पर या भा. औ. वि. बैंक/नाबाई की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत मंजूर किये जाने वाले प्राधिकरण प्राप्त करने की

आवश्यकता नहीं है। 3 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए (जिनमें वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः सहभागी नहीं होतीं) बैंकों को चाहिए कि वे ऋण-इक्विटी-अनुपात और वित्तपोषण के स्वरूप के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें तथा संदेह वाले मामले पूर्व-अनुमति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास भेजे जाने रहें।

230. चूंकि पूंजीगत याजार में विद्यमान स्थितियों के परिणामस्वरूप मटेरिवाजी बाजार गतिविधि का बल मिला है, बैंकों को अगस्त 1985 में यह सूचित किया गया कि वे शेयरों एवं कंपनी क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर वित्तीय और निवेश कंपनियों सहित सभी पार्टियों को ऋण प्रदान करते समय अधिक सावधानी तथा नियंत्रण बरतें। कंपनी क्षेत्र की हर तरह की प्रतिभूतियों पर अग्रिम प्रदान करने समय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विभिन्न अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जून 1986 में पुनः बल दिया गया।

विशिष्ट पण्यों/उद्योगों के लिए ऋण

231. पटसन की अत्यधिक फसल पैदा होने तथा उसके फलस्वरूप उसके मूल्य में गिरावट आ जाने के कारण भारतीय जूट निगम को, उसके मूल्य समर्थन कार्यक्रमों के अंतर्गत पटसन की वसूली करने के वास्ते, संघीय सहायता व्यवस्था के अधीन 100 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी। इस सीमा को अप्रैल 1986 में बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये कर दिया गया। निगम को अपने वाणिज्यिक कार्यक्रमों के लिए अक्टूबर 1985 में 34 करोड़ रुपये की सीमा मंजूर की गयी।

232. भारतीय रई निगम को 1985-86 के मौसम के दौरान उसके वाणिज्यिक कार्यक्रमों के लिए मंजूर की गयी 40 करोड़ रुपये की सीमा के अलावा मूल्य समर्थन कार्यक्रमों के अंतर्गत रई की वसूली के लिए संघीय व्यवस्था के अधीन 210 करोड़ रुपये के शिखर स्तर की ऋण सीमा मंजूर की गयी।

233. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) को, जोकि तिलहनों से संबंधित मूल्य समर्थन-कार्यकलाप करने के लिए केन्द्रीय शीर्षस्थ एजेंसी है, 1985-86 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर विभिन्न तिलहनों की वसूली करने के वास्ते 60 करोड़ रुपये की कुल ऋण सीमा प्राधिकृत की गयी। नाफेड को भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार खोपरे में बाजार मध्यस्थता कार्यक्रमों करने के वास्ते 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी मंजूर की गयी थी।

234. चीनी उद्योग के संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अलग-अलग चीनी मिलों के चीनी उत्पादन के अनुमानों को देखते हुए, उनके द्वारा 1984-85 के मौसम के दौरान प्राप्त की गयी अधिकतम राशि के 100 प्रतिशत तक की ऋण सीमाएं 1985-86 के मौसम के लिए आवश्यकताओं

के आधार पर मंजूर कर सकते हैं। ऋण प्राधिकरण योजना में शामिल अलग यूनितों को अतिरिक्त ऋण सोपाए मंजूर करने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण आवश्यक था।

रुण औद्योगिक उपक्रम

235. आलोच्य वर्ष के दौरान रुण यूनितों से संबंधित नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। पुनः स्थापन के वास्ते केवल ऐसी यूनितों का चयन करने पर जोर दिया गया जो पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर व्यवहार्य थीं। पहले जहाँ रुण यूनितों का तदर्थ आधार पर उपचार किया जाता था वहाँ अब नीति में परिवर्तन किया गया और मुनियोजित एकीकृत उपायों के तहत सहायता उपलब्ध करायी जाने लगी जिसमें रुणता के कारणों को दूर करना तथा न केवल बैंकों और मियादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपितु प्रायोजकों, सरकार और श्रमिक वर्ग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की राहतों और रियायतों पर जोर देना शामिल है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि रुणता को रोक्काम के उपाय करना, रुणता के प्रारंभ हो जाने के बाद मुधारात्मक उपाय करने की अपेक्षा आने वाले समय में कम खर्चीला और अधिक उत्पादन-मूलक सिद्ध होगा, बैंकों को अक्टूबर 1985 में यूनित की रुणता का यथाशीघ्र पता लगाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। रुणता के जिन लक्षणों पर नजर रखना था उनकी और रुणता के सामान्य कारणों की विस्तृत सूची तैयार की गयी और शाखा स्तर पर समय पर रिपोर्ट करने तथा मुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की जिम्मेदारी निर्धारित करने की संकल्पना प्रारंभ की गयी ताकि लक्षणों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के बीच के अंतराल को कम किया जा सके। नवंबर 1985 में जारी किये गये तथे मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिए बैंकों को यह मुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि रुण यूनित की अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने में तथा इस उद्देश्य के लिए बनाये गये विस्तृत मानदण्डों की स्थल रूपरेखा के भीतर उभयुक्त पुनः स्थापन का कार्यक्रम तैयार करने में उनके तथा मियादी ऋणदात्री संस्थाओं के बीच समन्वित दृष्टिकोण बना रहे। इसके अतिरिक्त रुण औद्योगिक उपक्रमों से संबंधित निवारक कमेटी द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर एक विधेय विधेयक पारित किया गया है ताकि औद्योगिक रुणता के बारे में कारगर ढंग से उपाय किये जा सकें।

236. अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 597 बड़ी रुण औद्योगिक यूनितें विद्यमान थीं जिनके संदर्भ में जून 1985 के अंत में 2,655 करोड़ रुपये के कुल बैंक ऋण बकाया थे; इसके मुकाबले दिसंबर 1984 के अंत में 545 यूनितों के संदर्भ में व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरे किये गए। व्यवहार्य समझी गयीं 357 यूनितों में से 264 यूनितों बैंकों ने उपचार कार्यक्रम के अधीन रखा। जून 1985 के अंत में रुण लघु उद्योग यूनितों की संख्या 97,890 थीं जिनसे संबंधित बैंक वित्त की राशि 954.65 करोड़ रुपये थी जबकि दिसंबर 1984 के अंत में 91,540 यूनितों के संबंध में बैंक वित्त की राशि 879.69 करोड़ रुपये थी। 97,890 रुण

यूनितों में से बैंकों द्वारा 6,505 यूनितों को संभाव्य रूप से सक्षम माना गया जिनमें से 2,079 यूनितों को उपचार पर कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। यह मुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि उन सभी मामलों में, जहाँ रुण रकाइयों की संभावित सक्षमता का पता चल चुका हो मही उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

237. इस रिपोर्ट के भाग 1 में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को तर्कसंगत बनाने के लिए किये गये उपायों के बारे में उल्लेख किया गया था। इस संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं: 26 अक्टूबर 1985 से समस्त पण्यों के संबंध में प्रति ऋणकर्ता 50,000 रुपये की समग्र सीमा तक के अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के समस्त प्रावधानों से छूट दी गयी वगैरह ऋणकर्ता का केवल एक ही बैंक के साथ लेन-देन रहा हो तब तक इस प्रकार की सीमा 25,000 रुपये थी। उक्त सीमा को 4 अप्रैल 1986 से और बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया। जिन पण्यों के मामले में 1980-81 से 1982-83 तक की तीन वर्षीय अवधि के आधार पर ऋण की स्तर संबंधी शर्त लागू थी वहाँ उक्त आधार को एक वर्ष और आगे ले जाया गया अर्थात् उसे उसी तारिख से 1980-81 से 1983-84 तक कर दिया गया। गेहूं का आपूर्ति की स्थिति में आये संतोषजनक सुधार और बड़े पैमाने पर विद्यमान सार्वजनिक स्टाकों को दखने हुए गेहूं पर दिये जाने वाले अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के समस्त उपबंधों से छूट दी गयी। इसी तरह से कच्ची रूई की संतोषजनक आपूर्ति स्थिति और नयी वस्त्र-उद्योग नीति के परिप्रेक्ष्य में कच्ची रूई और कपास पर मित्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों को चयनात्मक नियंत्रण के समस्त उपबंधों से छूट दे दी गयी। तथापि बैंकों को यह मुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि स्टाक संबंधी मानदण्डों का पालन किया जाय और उन पण्यों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर सामान्य मार्जिन निर्धारित किये जायें।

238. 25 अक्टूबर 1985 से धान/चावल पर दिये जाने वाले सभी अग्रिमों और मिलों से इतर पार्टियों को रूई और कपास पर दिये जानेवाले अग्रिमों के मामले में न्यूनतम मार्जिनों में 15 प्रतिशत अंकों की कमी लायी गयी थी। आपूर्ति की स्थिति में और सुधार होने तथा पर्याप्त मात्रा में स्टाक विद्यमान होने के फलस्वरूप धान/चावल और रूई/कपास के स्टाकों पर दिये जाने वाले समस्त अग्रिमों को 4 अप्रैल 1986 से चयनात्मक ऋण नियंत्रण के समस्त उपबंधों से छूट दे दी गयी।

239. तिलहनों के लिए निर्धारित किये गये बहुविध मार्जिनों का घटाकर उनमें समायोजन किया गया और उन्हें तर्क संगत बनाया गया। अभिसंस्करण यूनितों/मिलों के पास रहने वाले वनस्पति तेलों के स्टाकों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को भी घटा दिया गया है। तिलहनों और वनस्पति तेलों से संबंधित न्यूनतम मार्जिनों में 4 अप्रैल 1986 से 15 प्रतिशत अंकों की कटौती की गयी। बिनीले और उस के तेल के स्टाकों पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों को

चयनात्मक ऋण नियंत्रणों से पूरी तरह से छूट दे दी गयी। इस तरह से अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त अधिक उपज वाली और संकर बीजों के मामले की तरह तिलहन की पैदावार

के लिए प्रयुक्त इस प्रकार के बीजों पर अपने बहिर्देशीय प्रतिभों को भी इस तरह की छूट दी गयी। इन परिस्थितियों के बाद न्यूनतम माजिनों का संशोधित विन्यास सारणी में दिया गया है:

बैंक ऋणों पर न्यूनतम माजिन

(प्रतिशत में)

पण्य	26 अक्टूबर 1985 से लागू			4 अप्रैल 1986 से लागू		
	स्टाकों पर			स्टाकों पर		
	अभिसंस्करण यूनिटों/मिने	अन्य	गोशाम रसीदों पर	अभिसंस्करण यूनिटों/मिने	अन्य	गोशाम रसीदों पर
धान/चावल	30	45	30	—	—	—
गेहूं	—	—	—	—	—	—
अन्य खाद्यान्न	45	60	45	45	60	45
दालें	45	60	45	45	60	45
तिलहन*	45	60	45	40	45	30
वनस्पति तेल*	45**	75	60	30**	60	45
रूई और कपास	—	45	30	—	—	—
चीनी :						
(क) समीकरण (अफ़र) संझार	0	—	—	0	—	—
(ख) अविलरित स्टॉक	17.5	—	—	17.5	—	—
(ग) विलरित स्टॉक	75	75	60	75	75	60
गुड़ और खाण्डसारी	45	75	60	45	75	60

— इन मदों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सभी उपबंधों से पूरी तरह छूट दे दी गयी।

* चिनी और चिनी के तेल के दान, जिन्हें 4 अप्रैल 1986 से पूर्णतः छूट प्राप्त है।

** पंजीकृत तेल मिनों और वनस्पति निर्माताओं पर लागू।

240. बैंकों को यह सूचित किया गया कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट प्राप्त पण्यों के मामले में स्टॉक संबंधी मानदण्डों, बैंकों द्वारा निर्दिष्ट माजिनों और ऋण संबंध मानदण्डों और अनुगणन को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि सट्टेबाजों के उद्देश्य से स्टॉक बनाने के वास्ते ऋण का उपयोग नहीं किया जाय। मूल्यों में उतार-चढ़ाव वाले अलग-अलग पण्यों के संबंध में उस समय विद्यमान तथा प्रत्याशित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में ये सभी उपाय किये गये।

पट्टे पर देना

241. बैंककारी विनियमन अधिनियमन के अंतर्गत सरकार द्वारा दिसम्बर 1984 में आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने के बाद वाणिज्य बैंक अब अपने एक कार्यकलाप के रूप में पट्टे पर देने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई भी बैंक अब 51 प्रतिशत से अधिक गेहर धारिता के साथ उपकरण पट्टे पर देने के कारोबार को बनाने के लिए अथवा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर गेहरों में निवेश करने के लिए सहायक कंपनी स्थापित कर सकता है। तथापि इस प्रकार प्रायोजित सहायक कंपनी पर किराया-बरीद कारोबार करने और उपकरण पट्टे पर देने के काम में लगी हुई अन्य कंपनियों या संस्थानों

का वित्त पोषण करने के बारे में रोक लगायी गयी है। बैंकों पर उपकरणों को पट्टे पर देने का विभागीय कारोबार करने तथा जिन कंपनियों (उनको अपने अनुबंधी कंपनियों के अभाव में) वे संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश कर सकते हैं उनके प्रायोजक के रूप में कार्य करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सहायक कंपनी में और/पट्टे पर देने का कार्य करने वाली अन्य कंपनियों के शेयरों में किसी बैंक का कुल निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी और प्रारक्षित निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अप्रैल 1986 के अंत तक रिजर्व बैंक ने छः बैंकों से उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनियों में संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का तथा व्यापार बैंकिंग कारोबार और उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार प्रारंभ करने के लिए पूर्णतः स्वाधिकृत कंपनी स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता

242. रिजर्व बैंक पहले की तरह ऋणों और मध्यावधि तथा अल्पावधि ऋण सुविधाओं के द्वा में सीमादी ऋणदात्री संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा। वर्ष 1985-86

(जुलाई-जून) के दौरान रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा. औ. वि. बैंक) को 300 करोड़ रुपये की राशि के दीर्घावधि ऋण वितरित किये जबकि पिछले वर्ष 260 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर और वितरित किये गये थे। भा. औ. वि. बैंक ने 30 जून 1986 को समाप्त अवधि तक 30.90 करोड़ रुपये की राशि चुकायी है। इस निधि में से इस तारीख को विद्यमान बकाया ऋण राशि 2,590 करोड़ रुपये थी। अप्रैल 1986 में भा. औ. वि. बैंक को उसके द्वारा पुनः भूनाये गये पात्र मीयादी बिलों पर 200 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी थी। अब तक इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया और अवधि 30 जून 1981 को समाप्त हो गयी। वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों को भा. औ. वि. बैंक की बिल पुनर्भनाई योजना के जरिये 200 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी थी जिसे दिसंबर 1984 से प्रारंभ होने वाली 16 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था। इनमें से जून 1986 को समाप्त तिमाही तक सात किस्तें प्राप्त हो गयी थीं। इस सीमा में से 30 जून 1986 को 112.5 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

243. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से वर्ष 1985-86 के दौरान 80 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर और वितरित की गयी जबकि पिछले वर्ष मंजूर और वितरित की गयी राशि 55 करोड़ रुपये थी। एक्जिम बैंक ने पूरी राशि का उपयोग किया जिससे इस निधि से लिये गये बकाया ऋणों की राशि 30 जून 1986 तक बढ़कर 260 करोड़ रुपये हो गयी।

244. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी, जिसने 20 मार्च 1985 में अपना कार्य प्रारंभ किया, राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से सहायता लेने के लिए पात्र है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस निधि में से भा. औ. पु. बैंक को 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी। दिसंबर 1985 में इस सीमा का पूर्णतः उपयोग किया गया और वह अभी बकाया है।

245. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कैलेण्डर वर्ष 1986 के लिए पिछले वर्ष की तरह 15 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी। इस सीमा का नकदी ऋण सीमा के रूप में उपयोग किया जाना है। भा. औ. वि. निगम ने 30 जून 1986 तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया था।

246. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का कैलेण्डर वर्ष 1986 के लिए 15 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी और निगम ने कई बार अल्प अवधियों के लिए ऋण लिये। 30 जून 1986 को इस निगम के नाम 13.10 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

247. रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय निगमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर कुल 38.65 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ ऋण सीमाएं जारी कीं। ये सीमाएं 25 जून 1986 तक वैध थीं। इन सीमाओं के संबंध में 30 जून 1986 को कोई राशि बकाया नहीं थी।

248. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रा. कृ. ग्र. वि. बैंक) ने सहकारी बैंकों क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में अल्पावधि ऋण और अग्रिम प्रदान करने के वास्ते वर्ष 1985-86 के लिए 1300 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएं मंजूर कीं। इस सहायता पर व्याज दर 1984-85 के दौरान बैंक दर से 4.50 प्रतिशत कम थी, उसे पहली जुलाई 1985 से बढ़ाकर बैंक दर से 4.25 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इस ऋण सीमा में से अधिकांश बकाया राशियों का स्तर पहली अप्रैल 1986 को 1,288 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

बैंकों का निरीक्षण

249. जून 1986 को समाप्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 51 बैंकों का वित्तीय पुनरीक्षण का कार्य तथा सहकारी क्षेत्र के 7 बैंकों, निजी क्षेत्र के 25 बैंकों, और 9 विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण के कार्य पूरे किये गये। साथ ही, उस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐसे सात बैंकों के, जिनकी विदेशी शाखाएं कार्यरत थीं, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों के संविभाग (पोर्टफोलियो) निरीक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अलावा बैंकों/उनके कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों/घोषाघड़ियों/आरोपों की जांच भी की गयी।

ग्राहक सेवा

250. ग्राहक सेवा में संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों का बैंकों द्वारा किये जाने वाले कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अलावा बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी कई कदम उठाये गये। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के वास्ते जुलाई-अगस्त 1985 के दौरान एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया। इसमें पाये गये निष्कर्षों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे लुटियां दूर करें और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनमें उनके द्वारा इस संबंध में की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया हो। बैंकों से यह भी कहा गया कि जिन शाखाओं के खिलाफ बारंबार शिकायतें आती हैं वहां आनेवाली ऐसी शिकायतों की मौके पर तत्काल जांच करने के वास्ते वे विशेष दस्ते गठित करने पर विचार करें और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राहक सेवा को सम्मिलित करें। मई/जून 1986 में भारत सरकार के कहने पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित करके, सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के स्तर के

बारे में स्थिति मालूम करने के लिए, देशभर में व्याप्त सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की प्रतिनिधिक स्वरूप की चुनी हुई शाखाओं में एक और सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है।

251. सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे बाहरी केन्द्रों के चेकों की वसूली से संबंधित शिकायतों से बचने के लिए कदम उठावें। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : अलग-अलग ग्राहकों के 2,500 रुपये की राशि के बाहरी केन्द्रों के चेकों के लिए तत्काल जमा सूचना देना, उसी बैंक की शाखाओं पर आहरित लिखतों के मामले में 14 दिन से अधिक और अन्य बैंकों पर आहरित चेकों के मामले में 21 दिन से अधिक विलंब से वसूली होने पर बचत बैंक खाते के लिए लागू व्याज दरों पर अदायगी करना और लिखतों के प्रेषण के लिए बाह्य सेवा (कूरियर सर्विस) का अधिक मात्रा में उपयोग करना। बैंकों को यह भी अनुदेश दिये गये कि वे सभी ग्राहकों को, अपने यहां खाता रखने पर जोर दिये बिना मंग झूठ जारों करें। यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के कामकाज के पूरे समय के दौरान गणक-खाते खुले रहें, और यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाओं में जमाराशि धारकों को नामत मुद्रिणाएं प्रदान की जायें।

252. भारत सरकार ने सभी स्तरों के बैंक कर्मचारियों से कहा है कि वे प्रत्येक महीने में निर्दिष्ट तारीखों को ग्राहकों से मिलें ताकि ग्राहकों की समस्याओं की असंविलयत का उन्हें पता चल सके। इसके अलावा, शिकायतों को दूर करने के वास्ते सभी राज्यों का राजधानियों में ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गये हैं/खोले जा रहे हैं।

बैंकों में जालसाजी

253 हाल ही में बचत बैंक खातों में से जालसाजी से आहरण किये जाने के संबंध में प्राप्त कई शिकायतों को देखते हुए बैंकों से अपनी शाखाओं को यह अनुदेश देने के लिए कहा गया कि वे खाते खोलने, आहरण करने, पास बुकों को भरने आदि से संबंधित नियमों और क्रियाविधियों का कड़ाई से पालन करें। जालसाजी की घटनाओं के बारे में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने की क्रियाविधि को स्पष्ट किया गया। बेईमान ऋणकर्ताओं द्वारा की जाने वाली जालसाजी के मामलों की सूचना देने के संबंध में भी अनुदेश जारी किये गये। ऐसी वणिक्-वस्तुओं/विलों पर दिये जाने वाले अधिमों के, जो अत्यधिक जालसाजी की संभावनाओं वाले थे, कतिपय पहलुओं की ओर बैंकों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। जून 1986 को समाप्त अवधि के दौरान बैंकों के 114 कार्यालयों में 22 जालसाजियों/शिकायतों की जांच की गयी और उनके निष्कर्ष संबंधित बैंकों को सुधारात्मक उपाय के लिये सूचित किये गये। ऐसी जांचों

के परिणामों से जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां सरकार को भी अवगत कराया गया।

बैंकों का अधिस्वगन

254. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणालियों को देखते हुए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को विकारिण पर, 24 मई 1986 को कारोबार की समाप्ति से उसके बारे में एक अधिस्वगन आदेश जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ उसका समामेलन करने के वास्ते कदम उठाये जा रहे हैं।

बैंकों का पूंजीगत आधार

255. आलोच्य वर्ष के दौरान भारताय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गयी। उसकी अभिवृद्ध और चुकता पूंजी की राशि को भी 44,37,500 शेयरों के अतिरिक्त निर्गम द्वारा 5.625 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 1985 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की प्राधिकृत पूंजी में प्रति बैंक 10 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी। इन सभी सहयोगी बैंकों की जारी की गयी पूंजी और चुकता पूंजी की राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.45 करोड़ रुपये कर दी गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए पहले प्रयास के रूप में भारत सरकार द्वारा 1985-86 में 400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी। इन बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार द्वारा किया गया अंशदान, साथ-साथ ही सरकार द्वारा जारी की गयी 7.75 प्रतिशत व्याज दर वाली विशेष अपरकाम्य प्रतिभूतियों में निवेश किया हुआ माना जाएगा।

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1935

256. विभिन्न संविधियों, मुख्यतः बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करते हुए बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 को दिसंबर 1985 में पारित किया गया। अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 30 दिसंबर 1985 से और शेष उपबन्धों को पहली मई 1986 से प्रमल में लाया गया। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संशोधन निम्न प्रकार हैं : राज्य वित्तीय निगमों की ऋण लेने की शक्तियों को चुकता शेयर पूंजी के 90 प्रतिशत से बढ़ाकर चुकता पूंजी का दुगुना बना दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधियों से संबंधित उच्चतम सीमा को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि उनके ऋण-ईकित्व अनुपात और लाभप्रवता में सुधार लाया जा सके। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नाम बदलकर यूको बैंक कर दिया गया ताकि बंगलादेश में उसी नाम एक बैंक कार्यरत होने के कारण बैंक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में कोई धक्का न हो।

बैंकों का राष्ट्रीय समाशोधन :

257. बैंकों का राष्ट्रीय समाशोधन आरंभ करने और बैंकों के प्रशिक्षण विधायन के लिए मैनेजिक इंफ़रस्ट्रक्चर रिक्लीनअप (एम. आई. सी. आर.) टेक्नोलॉजी अपनाने की परियोजना के एक अंग के रूप में बंबई, मद्रास और नई दिल्ली के अधिकांश बैंकों ने आह्वानों को एम. आई. सी. आर. बैंक जारी करना शुरू किया। कलकत्ता में लगभग 50 प्रतिशत बैंकों ने एम. आई. सी. आर. बैंक जारी किये हैं। बैंक अपने क्लाइंट फार्मों को भी संशोधित रूप में छपवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बंबई में प्रस्तुत और नई दिल्ली और मद्रास के बैंकों/बैंक शाखाओं पर आह्वित बैंकों के संबंध में, एम. आई. सी. आर. राष्ट्रीय समाशोधन परियोजना के अग्रणी अंतरराष्ट्रीय समाशोधन 8 जुलाई 1986 से आरंभ हो चुका है। नई दिल्ली और मद्रास में भी इन नगरों में प्रस्तुत किये जाने वाले बैंकों के द्वारे में इसी प्रकार की सुविधा शीघ्र ही आरंभ की जायेगी। बंबई, नई दिल्ली और मद्रास में एम. आई. सी. आर. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंकों के विधायन का कंप्यूटरीकृत स्थानीय समाशोधन भी अगले तीन महीने के भीतर शुरू हो जाने की आशा है।

कार्यकारी बल/समितियां :

258. इस रिपोर्ट के भाग I में रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद् गठित किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस परिषद् के लघु निम्न प्रकार हैं : (1) उद्योग, कृषि और व्यापार के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के वित्त और ऋण की उपलब्धता के संबंध में समग्र रूप से स्थिति का आलोचन करना; (2) अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण की उपलब्धता से संबंधित नीतियों को समीक्षा करना; और (3) पूंजी और मुद्रा जाद्वारों की गतिविधियों में उनकी भूमिका और प्रभावशालिता को बढ़ाने की दृष्टि से विचार करना।

259. बैंकों में विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का पुनरीक्षण करके, उसका समन्वयन करके, उन पर निगरानी रखने तथा उनका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने मार्च 1986 में एक समिति गठित की; प्रशिक्षण के प्रभारी उप-गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के कार्य निम्न-प्रकार हैं : (i) उद्योग स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच आपस में तथा दूसरी ओर बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ तालमेल लागू, (ii) वर्तमान व्यवस्थाओं में विद्यमान शिक्षण के संबंध में उभरने वाली कठिनाइयों और उनमें कोई अंतराल हों तो उनका मूल्यांकन करना और बैंकों के लिए उपयुक्त कार्रवाई सुझाना, (iii) प्रशिक्षण संबंधी मूलभूत सुविधाओं का पुनरीक्षण करना तथा संकाय में स्टाफ को तैनात करने और उनके प्रशिक्षण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं की पर्याप्तता का निरीक्षण करना, प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन की क्रियाविधि तथा प्रशिक्षण के पश्चात् उनके नियोजन का तथा सामान्यतः प्रशिक्षण प्रणाली की प्रसिद्धिपुष्टा का मूल्यांकन करना, (iv) बैंकिंग तन्त्र में प्रशिक्षण को और

बढ़ावा देने के वास्ते विशेष अध्ययनों/अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना और (v) बैंक स्टाफ की समस्त श्रेणियों को प्रशिक्षित करने की एक व्यापक प्रणाली तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के वास्ते बैंकों की उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना।

260. रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध संस्थागत ऋण तथा अन्य संबंध सामलों का पुनरीक्षण करने के लिए उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक स्थायी परामर्शदात्री समिति गठित की है। इस समिति के विचारणीय विषय निम्नप्रकार हैं : (i) लघु उद्योग के क्षेत्र लिए उपलब्ध संस्थागत ऋण की मात्रा का पुनरीक्षण करना, यदि कोई परिवर्तन संबंधी खामियां हों, तो उनका पता लगाना और सुधारात्मक उपाय सुझाना; (ii) राज्य सरकारी एजेंसियों, विशेष रूप से जिला उद्योग केन्द्रों में वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध होने वाली सहायता की, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करना कि लघु उद्योगों को पर्याप्त और सहज ऋण उपलब्ध हो और जहां आवश्यक हो वहां सुधार के उपाय सुझाना;

(iii) उद्यम संबंधी निपुणताओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की तथा लघु उद्योग यूनिटों के संदर्भ में आधुनिक टेक्नोलॉजी की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें करना और (iv) संबंधित विभिन्न एजेंसियों की भूमिका को तलना में लघु उद्योग यूनिटों की क्षमता की समस्या का पुनरीक्षण करना और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई सुझाना।

261. फरवरी 1986 में रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग यूनिटों का पता लगाने और उनके पुनः स्थापन की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति को निम्नलिखित का जांच करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था : (i) शासकीय यूनिटों की परिभाषा; (ii) लघु उद्योग यूनिटों में आरंभिक क्षमता का पता लगाना; (iii) क्षमता का पता लगाने के लिए उपयुक्त तन्त्र स्थापित करना, प्रबंधनता की संभावना वाली यूनिटों के मामले में पुनः स्थापन के कार्यक्रम तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में प्रमुखी कार्रवाई करना और उसपर निगरानी रखना; तथा (iv) वाणिज्य बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य सरकारों तथा प्रबंधनता की संभावना युक्त संपत्ति गयी लघु उद्योग यूनिटों के लिए प्रस्तावित पुनः स्थापन कार्यक्रमों के अग्रणी आवेदकों अन्य एजेंसियों द्वारा राहतें/रियायतें दिये जाने के लिए मानवबल तैयार करना। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति :

262. 30 जून 1986 की स्थिति के अनुसार देश में 1346 प्राथमिक सहकारी बैंक थे। इनमें से 1247 सहकारी

सहकारी बैंक और 99 बेतन भोगियों की समितियाँ थी। वर्ष (जुलाई 1985-जून 1986) के दौरान 33 बैंकों (नये बैंकों और मौजूदा दोनों) को कारोबार शुरू करने/जारी रखने के लिए लाइसेंस जारी किये गये। इस तरह लाइसेंस प्राप्त बैंकों की कुल संख्या 461 हो गयी। प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या (प्रधान कार्यालयों सहित) जून 1985 के अंत के 2897 से बढ़कर 31 मार्च, 1986 को 2995 हो गयी। लाइसेंसप्राप्त राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और वह क्रमशः 8 और 35 ही रही।

पुनर्वित्त सुविधाएं

263. राजकोषीय वर्ष 1985-86 के दौरान व्याज की रियायती दर पर कुटीर तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण के लिए 43 शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में 5 राज्य सहकारी बैंकों को कुल 24.61 करोड़ रुपये की अत्यावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं। वर्ष के दौरान 16 शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए कुल 23.77 लाख रुपये के ऋणों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा मणिपुर की राज्य सरकारों से आबेबन प्राप्त हुए थे। इसमें से 9 शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए कुल 14.77 लाख रुपये की राशि मंजूरी के लिए नाबार्ड से सिफारिश की गयी। शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण मंजूर करने की नाबार्ड, के साथ यह व्यवस्था पहली अप्रैल 1986 को समाप्त हो गयी।

सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के लिए कार्यशील पूंजीगत सीमाएं

264. 1985-86 के पेराई मौसम के लिए राज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे नाबार्ड के पूर्व प्राधिकरण के बिना, सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को चीनी के स्टाकों पर पिछले मौसम के दौरान ली गयी अधिकतम राशि के शत प्रतिशत सीमा तक गिरवी सीमाएं मंजूर कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग चीनी फैक्ट्रियों के उत्पादन कार्यक्रमों के संबंध में राशियों के लिए आवश्यकता आधारित जरूरतों को ध्यान में रखा जाना था। चीनी फैक्ट्रियों को अतिरिक्त गिरवी सीमाओं की जरूरत पड़ने पर राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना था। अलबत्ता, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अलग-अलग मामलों में 150 लाख रुपये की सीमा से अधिक की कार्यशील पूंजीगत सीमाओं की मंजूरी के लिए नाबार्ड से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करते रहना था।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को शहरी बैंकों के ऋण

265. शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी गयी थी कि जून 1985 के अंत तक उनके ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 60 प्रतिशत धारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को मिलने लगे और इसमें से 25 प्रतिशत ऋण सहाज के कमखोर वर्गों को मंजूर किये जायेंगे। जिन बैंकों का प्राथ-

मिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का स्तर 30 जून 1983 को 40 प्रतिशत से कम था, उन्हें इन क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की सलाह दी गयी थी। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि जहाँ तक शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत छोटे शहरी बैंकों का प्रश्न है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किये हैं, किन्तु बड़े बैंकों की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही। स्थायी सलाहकार समिति द्वारा इस मामले की समीक्षा की गयी थी और सक्षम की तारीख को जून, 1986 के अंत तक बढ़ाने के लिए सहमति हो गयी।

अनिवासी (विदेशी) खाते स्वीकार करने की अनुमति

266. शहरी सहकारी बैंकों से अनुरोध प्राप्त होने पर यह निर्णय किया गया कि छुने हुए बैंकों को अनिवासी (विदेशी) रुपये खाता खोलने और रखने की अनुमति दी जाये। आलोच्य वर्ष के दौरान 7 शहरी बैंकों को इस प्रकार के खाते खोलने और रखने के लिए प्राधिकार जारी किये गये।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति

267. शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति ने विभिन्न मामलों, जैसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यवहार्यता मानवर्द्धों में संशोधन, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रबंधक मंडल में शहरी बैंकों का प्रतिनिधित्व और शहरी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति के लिए प्रणाली को सरल बनाने की जरूरत पर विचार किया। समिति ने लघु उद्योगों के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं से संबंधित नीतियों, मौजूदा बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका की भी समीक्षा की।

ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन और कार्यकारी बल

268. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नाबार्ड-1 ऋण परियोजना के हिस्से के रूप में भारत में कृषि ऋण प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जानी है। इस समीक्षा में पांच अध्ययन शामिल होंगे। ये हैं: (क) कृषि ऋण प्रणाली की भूमिका और परिचालन, (ख) अलग-अलग ऋण संस्थाओं की भूमिका और प्रभावशीलता, (ग) ऋण के क्षेत्र में शीर्षस्तर की संस्थाओं के पर्यवेक्षी और नियामक कार्यों की संभावना, (घ) ऋण की लागत तथा मार्जिन, और (ङ) नाबार्ड के कार्यों की प्रभावशीलता। ये अध्ययन एक वरिष्ठ स्तर के विशेषज्ञ दल के मार्गदर्शन और अर्थक्षेत्र में किये जायेंगे जो कृषि ऋण प्रणाली को इस समय प्रभावित कर रही प्रमुख समस्याओं और मामलों का मूल्यांकन करेगा और क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम की सिफारिश करेगा।

269. जून 1984 में बैंक ऋण के संबंध में राज्य हथ-करवा विकास निगमों की परिचालनगत समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कार्यकारी बल ने कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में फील्ड

अध्ययन पूरे कर लिए हैं। कोल्ड वॉरों से कार्यकारी बल को बहुत सी परिचालनगत समस्याओं जैसे बुनकरों को धागे की आपूर्ति और वितरण, हथकरघा उत्पादनों का वितरण और स्थानीय स्थितियों के संबंध में उत्पादन और विपणन के लिए वित्त जुटाने आदि को सभलने में बहुत मदद मिली। कार्यकारी बल की प्राथमिक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।

270. रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को संस्थागत ऋण की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए उपलब्धता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति कमजोर वर्गों के अधिक फायदे के लिए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुझायेगी। समिति को निम्नलिखित कार्य दिये गये हैं: (i) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की आवश्यकता और उपलब्धता की समीक्षा का मूल्यांकन करना; (ii) ऐसी परिचालनगत कमियों का पता लगाना जो अभीष्ट हिताधिकारियों तक संस्थागत ऋणों के कारगर वितरण में बाड़े आती हैं और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना; (iii) कृषि ऋण, और संबंधित सुविधाओं के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने की प्रगति की समीक्षा करना और सुधार के लिए उचित उपायों की रिकारिश करना; (iv) ऐसे उपाय सुझाना जिससे राज्य और जिला स्तरों पर सहकारी और भूमि विकास बैंक ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए कारगर एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकें (v) समाज के कमजोर वर्गों को ऋण और अनुपूरक निवेश वस्तुओं की उपलब्धता की प्रगति की समीक्षा करना और सुधार के लिए उपाय सुझाना; (vi) ऋण संस्थाओं और विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों के बीच जिला या उससे नीचे के स्तर पर कारगर तालमेल में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना; (vii) अपेक्षित प्रौद्योगिक सहायता सहित आधारभूत समर्थन और अनुपूरक निवेश वस्तुओं में सुधार सुझाना ताकि ग्रामीण ऋण को और कारगर बनाया जा सके; (viii) ऐसे तत्वों का पता लगाना जो ग्रामीण ऋण की समय पर वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और ऋण संस्थाओं की निधियों को फिर से इस्तेमाल करने में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना और (ix) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण से संबंधित ऋण संस्थाओं और अन्य एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तालमेल बढ़ाना।

271. इस समिति ने निम्नलिखित पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी बल गठित किया: (i) सहकारी ऋण के नये और वृद्धिक्रम न करने वाले सदस्यों को ऋण उपलब्ध न कराये जाने के बारे में समस्याएं तथा इन उधाराकर्ताओं को आसानी से ऋण मिलना सुनिश्चित करना; तथा (ii) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की जपेट में आने वाले क्षेत्रों और ऋणों की वसूली पर उनके प्रभाव के बारे में सहकारी ऋण तंत्र की सहायता के लिए किये जा सकें।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अन्य मामलों से संबंधित गतिविधियां बायबा बाजार रक्षा

272. विदेशी व्यापार और भुगतान मंच पर होनेवाले परिवर्तनों और बड़े पैमाने पर कार्यों के नये क्षेत्रों के सामने आने को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले विदेशी मुद्राओं के बायबा खरीद और बिक्री करारों से संबंधित विनियमों की समीक्षा की गयी। यह जरूरी समझा गया कि कुछ मौजूबा सुविधाओं के बायरे और सीमा क्षेत्र को बढ़ाया जाए और उभरकर आने वाले कुछ नये कारोबारों के संबंध में बायबा तथा रक्षा सुविधाएं शुरू की जायें। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ने 28 दिसम्बर 1975 से बायबा तथा रक्षा सुविधाओं में कई परिवर्तन किये। कुछ नये क्षेत्र जहां बायबा रक्षा सुविधाएं पहली बार शुरू की गयी हैं, इस प्रकार हैं: (i) विदेशी मुद्रा ऋणों की प्रवायगी के लिए आकर्षी बायबा रक्षा, (ii) विदेशी मुद्रा ऋणों से वित्तपोषित आयातों के भुगतान के लिए अंतःमुद्रा (क्रास करेंसी) बायबा रक्षा, जहां माल के भुगतान के लिए बीजक, ऋण वाली विदेशी मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्रा/मद्राओं में बनाया गया हो; (iii) किसी भारतीय एयरलाइन अथवा शिपिंग कंपनी द्वारा अन्य विदेशी मुद्राओं में हुई राजस्व आय में से एयरक्राफ्ट/जहाज खरीदने के लिए किसी एक विदेशी मुद्रा में ऋण की किस्त की अदायगी के संबंध में क्रास करेंसी बायबा रक्षा; (iv) इंडियन एयरलाइन और शिपिंग कंपनी-शेयर द्वारा किराए के भुगतान के लिए बायबा रक्षा; (v) तकनीकी जानकारी का शुल्क भेजने के लिए बायबा रक्षा; (vi) निर्माण करने और स्थापित करने संबंधी प्रचार भेजने के लिए बायबा रक्षा; और (vii) ऐसी भारतीय कंपनियों/फर्मों द्वारा, जो विदेशों में टर्न-की सिविल निर्माण/सेवा ठेके लेती हैं, भारत में अस्थायी रूप से लायी गयी निधियों को फिर से विदेश भेजने के लिए बायबा रक्षा।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रणाली में छूट

273. निर्यात और आयात के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत के निर्यातों की आय की वसूली के लिए निर्धारित अवधि को पहली अक्टूबर 1985 से पोलसदान की तारीख से तीन महीने से बढ़ाकर छः महीने कर दिया गया।

भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा हफ्तवारी योजना

274. भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा हफ्तवारी योजना के अन्तर्गत 26 दिसम्बर, 1985 से पहले स्थायी रूप से बसने के लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्र-फता अथवा मूल के पात्र अनिवासी, भारत में लायी गयी और इनके अनिवासी विदेशी छातों या विदेशी मुद्रा अनिवासी छातों में जमा शेष राशियों अथवा अग्रवास के बबलने के समय "विदेशी मुद्रा अनिवासी छातों" की कुल राशि के 25 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा पाने के हकदार थे। इस योजना के अन्तर्गत

26 दिसम्बर, 1985 से विदेशी मुद्रा हकबारी की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी।

विशेष यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेशी यात्रा

275. विदेशी यात्रा योजना के अन्तर्गत भारतीय निवासी (नेपाल और भूटान को छोड़कर) किसी भी देश की, दो कैलेंडर वर्ष में एक बार यात्रा करने के लिए पात्र थे और प्रति व्यक्ति 500 अमेरिकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा लेने के हकदार होते थे। इसी तरह, पड़ोसी देशों की यात्रा की योजना के अन्तर्गत भारतीय निवासी आठ पड़ोसी देशों के समूह (अर्थात् बंगला देश, बर्मा, मलेशिया, मालदीव द्वीप, मारीशस, पाकिस्तान, सेशेल्स द्वीप और श्रीलंका) में से किसी भी देश की दो कैलेंडर वर्ष में एक बार यात्रा करने के पात्र थे और प्रति व्यक्ति 250 अमेरिकी डालर के बराबर की विदेशी मुद्रा पाने के हकदार होते थे। सात अप्रैल 1986 से किये गये परिवर्तनों के अनुसार, इन योजनाओं के अन्तर्गत विदेश यात्रा दो वर्ष के बजाय तीन कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार की जा सकती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा पाने के प्रयोजन के लिये विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा की योजना को मिलाते की अनुमति नहीं है।

आयात-निर्यात पासबुक योजना

276. भारत सरकार ने निर्माता निर्यातकों के लिए आयात निर्यात पासबुक योजना शुरू की है ताकि वे निर्यात उत्पादन के लिए आयातित निवेश वस्तुओं को शुल्क मुक्त रूप में प्राप्त कर सकें। अग्रिम लाइसेंस योजना से बड़े वायरे वाली इस योजना का उद्देश्य नियमित पंजीकृत निर्माता निर्यातकों को अपने उत्पादन/निर्यात के समय कार्यक्रमों के अनुरूप अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल जैसे आयातित सामान शुल्क मुक्त रूप में प्राप्त करने में सहायता करता है। आयात के उद्देश्य से पासबुक की बंधता, जारी करने की तारीख से 18 माह तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए 27 माह है। पासबुक में सहाय्य गये लाइसेंस पर लाइसेंस धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में साख पत्र खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही ऐसे लाइसेंस पर प्राधिकार पत्र की अनुमति है।

एशियाई समाशोधन यूनियन

277. पहली अगस्त 1985 से रिजर्व बैंक ने एशियाई समाशोधन यूनियन की मुद्राओं की खरीद और बिक्री के लिए बैंकिंग आधार पर बरें घोषित करने की व्यवस्था की है। यह एशियाई समाशोधन यूनियन द्वारा लेखा अर्द्धिके लिए निर्धारित बरों तथा वास्तविक दैनिक बरों के बीच भिन्नता की समस्या से निपटने के लिये किये गये निर्णय की प्रतिक्रिया में किया गया है।

विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के संबंध में स्थायी परामर्शदात्री समिति

278. निर्यातों और आयातों विषयक समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित मामलों पर निरन्तर आधार पर सलाह देने के लिए एक स्थायी

समिति गठित की है। इस समिति में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अलावा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय निर्यात अणु गारंटी निगम, भारतीय व्यापार प्राधिकरण, कुछ वाणिज्य, उद्योग तथा यात्रा संघों के प्रतिनिधि तथा भारत में एयर लाइनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण

279. जून 1986 की समाप्त वर्ष के दौरान 3 और कंपनियों के अनिवार्य हित को अशेषित स्तर तक कम करने विषयक निवेश का पालन किया और इस तरह ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़कर 382 में से 359 हो गयी, जिनके खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) के अन्तर्गत भारतीयकरण और/या विदेशी ईक्विटी कम करने के लिए अंतिम आदेश पारित किया गया था और जिन्होंने उक्त आदेश का अनुपालन कर दिया है।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित कार्यकारी दल

280. रिजर्व बैंक द्वारा गठित विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित कार्यकारी दल ने, जिसकी उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, जनवरी 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बेहतर ग्राहक सेवा के हित में विदेशी मुद्रा नियंत्रण नीतियों के सरलीकरण और अधनात्मक उद्घाटन से संबंधित, उक्त कार्यकारी दल की अनेक सिफारिशों को बैंक पहले ही स्वीकार और कार्यान्वित कर चुका है। इनका संबंध ग्रन्थ बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है: विशेष यात्रा योजनाओं के अधीन विदेशी यात्रा, भारतीय राष्ट्रियता अथवा मूल के अनिवारियों को उपलब्ध प्रेषण सुविधायें, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली कंपनियों द्वारा साक्षात् प्रेषण और निर्यातों पर एजेंसी कमीशन।

अनिवार्य भारतीयों के निवेश के संबंध में समिति

281. रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा अनिवार्य भारतीयों के लिए निवेश योजनाओं के संबंध में अनायास जाने वाली विदेशी मुद्रा नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा करने और इन पद्धतियों को सरल बनाने और सुधारने के लिए सुझाव देने के द्वास्ते गठित समिति ने अक्टूबर, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की कई सिफारिशों भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और उन्हें रिजर्व बैंक ने लागू कर दिया है।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम

282. दिसम्बर 1985 के अंत में, विदेशों में 208 भारतीय संयुक्त उपक्रम थे। इनमें से 156 पर कार्य चल रहा था और 52 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। कार्यरत संयुक्त उद्यमों में भारतीय उद्यमियों की शेयर पूंजी का मूल्य 93.84 करोड़ रुपये के आसपास थे और कार्यान्वित होने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 23.48 करोड़ रुपये लगे हुए थे। इन

विदेशी परियोजनाओं के कारण भारत से 147.91 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात संभव हुए हैं।

अन्य गतिविधियाँ

283. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान 52 विदेशी कंपनियों को भारत में नये संयुक्त प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों/फर्मों को विभिन्न विदेशी केन्द्रों पर 20 व्यापारिक और 32 गैर-व्यापारिक कार्यालय खोलने और 24 प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुमति दी गयी। एक विदेशी केन्द्र पर एक शास्त्रज्ञ तथा विशेष ठेके पूरे करने के लिए 16 परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति भी दी गयी।

निकेय बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम

284. वर्ष के दौरान निकेय बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम ने बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा रक्षा देने और समाज के कमजोर और अब तक के उपेक्षित वर्गों के छोटे उधारकर्ताओं की कुछेक श्रेणियों को पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गयी ऋण सुविधाओं को गारन्टी समर्थन देने के अन्तर्गत बोहरे लक्ष्यों को पूरा करने में खाते तरक्की को। इस प्रयोजन के लिए निगम पहली जुलाई 1984 से गुरु की गई लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारन्टी योजना, 1984 सहित पांच ऋण गारन्टी योजनाएँ चला रहा है।

285. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई और वह 1851 हो गयी। इनमें 83 वाणिज्य बैंक, 193 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,575 सहकारी बैंक शामिल हैं। बीमा योजना इस समय 14 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों में फैली हुई है। पुरो तरह रक्षित खातों की कुल संख्या जून 1984 के अंत के 2,000 लाख खातों से बढ़ कर जून 1985 के अंत में 2,145 लाख खाते हो गयी। ये खातों को कुल संख्या के 95.8 प्रतिशत थे। इसी अवधि के दौरान बीमाकृत जमा-राशियाँ 46,340 करोड़ रुपये से बढ़कर 56,211 करोड़ रुपये हो गयीं। ये जून 1985 के अंत की स्थिति को कुल कर योग्य जमा राशियों का 73.5 प्रतिशत थीं।

286. 1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान लघु ऋण गारन्टी योजना 1971 में हिस्सा लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या में 19 की वृद्धि हुई और ये कुल बिजाकर 251 हो गयीं। इनमें 71 वाणिज्य बैंक तथा 180 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। तथा सहकारी सहित विदेशी गारन्टी योजना 1971 में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं की संख्या चार की वृद्धि के साथ 173 हो गयी। इनमें 58 वाणिज्य बैंक, 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 सहकारी बैंक शामिल थे। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारन्टी योजनाएं 1971 में हिस्सा लेने वाले वित्तीय निगमों (राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित)

को संख्या भी एक की वृद्धि के साथ 20 ही गयी। जून 1986 के अंत में 44 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारन्टी योजना 1984 में भाग ले रहे थे। उपर्युक्त चारों योजनाओं के अन्तर्गत लघु उधारकर्ताओं की कुल गारन्टीकृत अग्रिम जून 1985 के अंत में 8,923 करोड़ रुपये के थे जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

287. निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारन्टी योजना 1981 में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1986 के अंत तक बढ़कर 462 हो गयी। इनमें 69 वाणिज्य बैंक, 143 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 14 राज्य वित्तीय निगम, 8 अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ तथा 228 सहकारी बैंक शामिल थे। लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये गारन्टीकृत अग्रिम 4,891 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 5,844 करोड़ रुपये हो गये।

288. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम को छोटे उधारकर्ताओं को अपनी गारन्टी योजनाओं के संबंध में 114.23 करोड़ रुपये के लिए, 4,86,577 ढाबे तथा लघु उद्योगों के लिए योजना के संबंध में 84.05 करोड़ रुपये के लिए, 34,838 ढाबे प्राप्त हुए। पहली योजना के संबंध में इसी अवधि के दौरान कुल निवृत्तान 151.42 करोड़ रुपये के लिए 6,16,449 ढाबे तथा दूसरी योजना के संबंध में 52.83 करोड़ रुपये के लिए 28,316 ढाबे रहा।

गैर-बैंकिंग कंपनियाँ चिड-फंड अधिनियम, 1982

289. आलोच्य वर्ष के दौरान चिड फंड अधिनियम, 1982 के उपबन्ध और उसके अन्तर्गत बनाये गये निगम उद्घोषा तथा अद्यतन निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमन और दीव में लागू किये गये थे। इसके साथ चिड अधिनियम छः राज्यों और पांच संघशासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी ने अपने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और उनके द्वारा आगामी कार्रवाई की प्रतीक्षा को जा रही है। शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा उनके ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा राशियाँ स्वीकार किया जाना

290. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, में अध्याय III-इ के उपबन्ध, जो एक सीमित सीमा को छोड़कर, गैर-निगमित कंपनियों द्वारा जमा राशियाँ स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित हैं, फरवरी, 1984 को लागू हो गये। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, केरल और तमिलनाडु ने अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र तैयार कर लिया है। फरवरी 1983 में रिजर्व बैंक ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में अध्याय III-इ के उपबन्धों के अधीन कई निजी

वित्तीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अधिनियम के अध्याय III इ के उपखण्डों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं अदालतों में दायर की गयीं, परन्तु खारिज कर दी गयीं। इन फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपील याचिकाओं पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियों की प्रवृत्ति

291. 31 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट करने वाली 7508 वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों तथा विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा रखी गयी कुल जमाराशियां 16,140 करोड़ रुपये की थीं जबकि एक वर्ष पहले 6,798 रिपोर्ट करनेवाली कंपनियों के पास 11,124 करोड़ रुपये की जमाराशियां थीं। इसी अवधि के दौरान जमाखानों की संख्या 88.97 लाख से बढ़कर 124.14 लाख हो गयी। 1984-85 (अप्रैल-मार्च) में विनियमित जमाराशियों में 481 करोड़ रुपये की और छूट प्राप्त जमाराशियों में 4,536 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। गैर-वित्तीय कंपनियों के पास रखी वि-

नियमित जमाराशियां उनके द्वारा रखी गयी कुल शुद्ध निधियों का 15.8 प्रतिशत बैठती हैं। यह 35 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा से, जिस तक कि ये कंपनियां जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं, काफी कम है। विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों वर्ग में भी चिट फंड कंपनियों को छोड़कर, विनियमित जमाराशियां, निवेश के अन्तर्गत निर्धारित संबंधित अधिकतम सीमाओं के भीतर ही रहें। गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र द्वारा 31 मार्च 1985 की स्थिति के अनुसार रखी गयी 16,140 करोड़ रुपये की कुल जमाराशियां सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित कुल जमाराशियों का 22.2 प्रतिशत बैठती हैं। मार्च 1984 में यह प्रतिशत 18.3 था। गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास विनियमित जमाराशियों में 1984-85 में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी। बैंक जमाराशियों के मामले में वृद्धि दर 19.5 प्रतिशत थी।

292. मार्च 1985 और 1984 के अंत विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के पास रखी जमाराशियों के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

गैर-बैंकिंग निगमित क्षेत्र में जमाराशियों में वृद्धि

(राशि करोड़ रुपये में)

	1983-84 रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या	राशि	1984-85 रिपोर्ट करनेवाली कंपनियों की संख्या	राशि
कुल जमाराशियां इनमें से :				
नियमित जमाराशियां	6798	11124	7508	16140
छूट प्राप्त जमाराशियां		2334		2815
निम्नलिखित के पास जमाराशियां		8790		13325
(i) सरकारी कंपनियां	48	5744	55	8923
	(0.7)	(51.6)	(0.7)	(55.3)
(ii) सरकारी लिमिटेड कंपनियां	2346	4580	2516	5617
	(34.5)	(41.2)	(33.5)	(34.8)
(iii) निजी लिमिटेड कंपनियां	4404	800	4937	1600
	(64.8)	(7.2)	(65.8)	(9.9)
घ. वित्तीय कंपनियां,	3599	2779	4134	3914
	(53.0)	(25.0)	(55.1)	(24.3)
घा. गैर-वित्तीय कंपनियां	2558	7963	2510	11784
	(37.6)	(71.6)	(33.4)	(73.0)
इ. विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां	641	382	864	442
	(9.4)	(3.4)	(11.5)	(2.7)

कोष्ठकों में आंकड़े रिपोर्ट करने वाली कंपनियों/कुल जमाराशियों जैसी भी स्थिति हो, की कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं।

सर्वेक्षण

293. घरेलू क्षेत्रों की आस्तियों और देयताओं से संबंधित (अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 1981-82 के निष्कर्षों के आधार पर) एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संवर्धाधीन अवधि की शुरूआत अर्थात् पहली जुलाई 1981 को प्रकाशन के लिए तैयार की गयी। संवर्धाधीन अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय, उधार और भ्रष्टाचारियों के और बकाया ऋणों के ब्योरे देनेवाली इसी तरह की एक रिपोर्ट प्रकाशन के लिए तैयार की जा रही है।

294. संवर्धाधीन अवधि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 1983-84 के दौरान देश भर में फीले कुछ चुने हुए शहरों में किये गये, कार्यक्रम के हिताधिकारियों और गैर-हिताधिकारियों के सर्वेक्षण का फील्ड कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण के नतीजों की एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लघु उद्योग इकाइयों, निजी कंपनी इकाइयों और कारीगरों तथा शिल्पकारों के लिए 1983-84 के सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े निकालने का कार्य भी चल रहा है।

करंसी चेस्ट

295. मार्च 1986 के अंत में देश भर में करंसी चेस्टों की कुल संख्या (487 रिपिटिटरों को छोड़कर) 3506 थी। इनमें से 17 करंसी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास, 2610 चेस्ट बैंक समूह के पास, 502 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास, 372 छाजनों, उप छाजनों के पास और 5 जम्मू और कश्मीर बैंक लि. के पास बने रहे।

संगठनात्मक मामले और बैंक के लेख

मशीनीकरण कंप्यूटरीकरण

296. वर्ष के दौरान बंबई में स्थापित मिनी-कंप्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बैंक में मशीनीकरण/कंप्यूटरीकरण के कार्यक्रम में कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया गया। माध्यमता कार्यालय में सफल प्रयत्नों के बाद निर्गम विभाग में छोट और लेखा परिचालनों के लिए इसी तरह के मिनी-कंप्यूटर ग्रहमदाबाद, नागपुर तथा नई दिल्ली में लगाये गये। ग्रहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद तथा कानपुर में समायोजन गृह के कार्य करने के लिए मिनी-कंप्यूटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बैंक के लिए ही समर्पित दूरसंचार नेटवर्क को विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है और अगले दो वर्षों में इसे किस्तों में पूरा कर लिया जायेगा।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंबई

297. रिजर्व बैंक तीन महाविद्यालयों और चार प्रांतीय केन्द्रों वाले अपने प्रशिक्षण संस्थानों के जरिये अपने अधिकारियों तथा बाणिज्य सहकारी तथा क्षेत्रीय प्रांतीय बैंकों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों और साथ ही विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देता है। बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने बाणिज्य बैंकों, बिलीय संस्थाओं, रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के कुछ संवर्गों के अधिकारियों को कर्मभूतक और प्रबंधकीय प्रशिक्षण देने की दृष्टि से सामान्य बहु-आयामी कार्यक्रम चलाना जारी रखा। इन कार्यक्रमों में आमतौर पर नगरियों के विकास पर ध्यान दिया जाता है और कार्य-भूतक क्षेत्रों जैसे ऋण प्रबंध और मूल्यंकन, विदेशी मुद्रा, निराजन और विशेष कार्यक्रमों जैसे कार्मिक प्रबंध आदि में संकल्पनात्मक कुशलता पर विशेष जोर दिया जाता है। नियमित कार्यक्रमों के अलावा, महाविद्यालय ने कुछ नए कार्यक्रम जैसे संकाय विकास (कंप्यूटर), कंप्यूटरीकरण (पद्धति विश्लेषण), कंप्यूटर उन्मुख कार्यक्रम; बैंकों में मशीनीकरण; जोडिल कम की सेवा-परीक्षा मुद्रा/तिरका प्रबंध; विधि अधिकारी कार्यक्रम; अजिमान (पोर्टफोलियो) और निधि प्रबंध; बैंकों से जन संपर्क; अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध; अतिवासी निवेश और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का बिलपोषण (क्षेत्रीय माध्यम) भी संचालित किये। संसदीयान्तरण अधि के दौरान महाविद्यालय ने 81 कार्यक्रम चलाये और

2030 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। 1954 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक 30,827 सहभागी कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं।

298. महाविद्यालय ने ग्रन्थ बैंकों से अनुरोध प्राप्त होते पर उनके महाविद्यालयों के लिए भी संकाय सहायता उपलब्ध करायी। बैंक मरकाजी, ईरान के अनुरोध पर सितम्बर-अक्तूबर 1985 के दौरान संकाय सदस्यों के एक दल ने ईरान में विदेशी मुद्रा पर एक कार्यक्रम संचालित किया। मार्च 1986 में मारीशस में विदेशी मुद्रा कारोबार और ऋण मूल्यंकन पर कार्यक्रम संचालित किये गये थे।

299. 'बी. टी. सी. बुलेटिन' के अलावा महाविद्यालय ने बैंकों की वजह को पूरा करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान "गाइडलाइन्स फार इंटर्नल बैंक इन्वेस्टमेंट" नाम का प्रकाशन भी प्रकाशित किया।

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

300. मद्रास स्थित रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय बैंक के विभिन्न विभागों में स्टाफ अधिकारी ग्रेड 'ए' से 'सी' की प्रशिक्षण जरूरतों को, प्रशिक्षण को सामय संसाधन विकास को एक अभिन्न अंग के रूप में इस्तेमाल करने के लक्ष्य के साथ, पूरा करता रहा। महाविद्यालय ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आर्थिक बिलीय समीक्षा, आयोजना और बजटीय नियंत्रण, कार्यपालक का स्वास्थ्य, समय प्रबंध और संचार कार्यशालाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। महाविद्यालय ने हाल ही में ग्रेड 'ए' में पदोन्नत स्टाफ अधिकारियों को भी अधिकारी विकास कार्यक्रम शृंखला के अंशगत विशेष रूप से संचार किये गये कार्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित किया। विभिन्न राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ के लिए विशेष, ग्रहमदाबाद, और हैदराबाद में बाहरी कार्यक्रम भी चलाये गये। देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों तथा केरला, गुजरात, जाम्बिया, तंजानिया और बोटासाला के केन्द्रीय बैंकों अग्र्य संस्थाओं के अधिकारियों ने महाविद्यालय द्वारा संचालित कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वर्ष के दौरान निम्नलिखित नये कार्यक्रम शुरू किये गये: बैंकों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण, अधिकारी विकास कार्यक्रम, आयोजना और बजट नियंत्रण पर कार्यशाला निरीक्षण अधिकारियों के लिए कार्यक्रम (उत्कृष्ट), अधिकारियों के लिए पद्धति विश्लेषण और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा पुनर्गठन/कैश कार्यक्रम।

301. जनवरी 1986 में प्रशिक्षण का 5वां धनन शुरू हो जाने से अब महाविद्यालय प्रति वर्ष लगभग 2500 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की स्थिति में आ गया है। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 92 प्रतिजन कार्यक्रम आयोजित किये और 2037 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक यहाँ अतिरिक्त कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 18,421 अधिकारी हिस्सा ले चुके हैं।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

302. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, वाणिज्य सहकारी बैंकों, नागार्ड तथा रिजर्व बैंक से संबंधित कर्मचारियों के लिए कृषि वित्त और संबंधित विषयों से जुड़े विषयों पर विभिन्न बहु उद्देशीय और विविध कार्यक्रम संयोजित करता रहा। वर्ष के दौरान शुरू किये गये नये विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल थे : आर्थिक विकास संस्थान द्वारा प्रायोजित प्रतिष्ठकों के लिए आसोज वित्त पर क्षेत्रीय कार्यक्रम, जनजाति विकास पर विशेष ध्यान देने हुए आसोज के वित्तियोग पर कार्यक्रम, शुष्क भूमि परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने पर कार्यक्रम, भारतीय अखंड पर कार्यक्रम और मछली पालन पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। इनके अलावा, महाविद्यालय ने 84 नियमित कार्यक्रम, 2 बाहरी कार्यक्रम, जिनमें से एक ताम्रपुर में तथा दूसरा बंगलूर में बताया गया, बैंक के साथ संयुक्त रूप से विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा दो सेमिनार आयोजित किये। इन कार्यक्रमों में कुल 2379 अधिकारियों ने भाग लिया। इस तरह महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रतिष्ठित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 28,279 हो गयी है।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

303. भायडला (बंबई), फलकता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थित बैंक के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र बैंकों के विविधीय और गैर-विविधीय स्तर के कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करते हैं। वे वित्तिक ग्रेड II को तृती के समय विशेष पाठ्यक्रम गणक विज्ञान-नोट परीक्षक ग्रेड II के त्रि-विधेय कार्यक्रम तथा आगुनियिकों/टंककों के लिए तथा श्रेणी IV के स्टाक के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष के दौरान वित्तिकीय और गैर-वित्तिकीय स्टाक के श्रेणी III के 2146 कर्मचारियों तथा श्रेणी IV के 501 कर्मचारियों ने चारों केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस तरह इन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से लेकर अब तक प्रतिष्ठित कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 29,940 और 1092 हो गयी है।

वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण

304. वाणिज्य बैंकों के कार्य के विभिन्न पहलुओं से बैंक के अधिकारियों की परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक ने वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण के लिए तीन योजनाएं बनायी हैं। पहली योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रेड 'ए', 'बी' और 'सी' के अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रामाण्य और शहरी शाखाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। दूसरी योजना के अंतर्गत ग्रेड 'डी' और 'ई' के अधिकारियों को छः माह की अवधि के लिए बैंकों के निरंतर प्रदान कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जायेगा जहां उन्हें आंतरिक निरीक्षण/निवारण विभाग सहित प्रमुख विभागों का गहराई से परिचय कराया जायेगा। तीसरी योजना के अंतर्गत बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के जुड़े हुए बैंकों

के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उनके मजूरियों की विस्तार बना और उनके अनुभवों को समृद्ध करना है। पहले चरण में उपर्युक्त तीन योजनाओं में क्रमशः 40,4 तथा 6 अधिकारी लिये जायेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों में ध्यायक रूप से प्रतिष्ठित अधिकारियों का एक ऐसा समूह तैयार हो जायेगा, जिन्हें बैंक के विभिन्न विभागों में बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकेगा।

भारत और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए स्टाफ को प्रतिनियुक्त करना

305. बैंक ने भारत में उपातिप्राप्त प्रबंध संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 188 अधिकारी प्रतिनियुक्त किये और विभिन्न विदेशों प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखा। कुल मिलाकर बैंक के 27 अधिकारी अमेरिका, इंग्लैंड, स्विटजरलैंड, पश्चिमी जर्मनी और जापान आदि सहित अन्य देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये।

विदेशों बैंकों के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी प्रशिक्षण सुविधाएं

306. बैंक ने विदेशों केन्द्रीय तथा वाणिज्य बैंकों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर उनके सहभागियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित सहभागियों को प्रशिक्षण तथा अध्ययन सुविधाएं देना जारी रखा। जिन 77 विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण/अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं, उनमें से 15 श्रीलंका से, 10 तंजानिया से, 9 नेपाल से, 6 इथियोपिया से, 4-4 सूडान, त्राइजीरिया, भूतान, केन्या और बर्मा से, 5 बोटस्वाना से, 2-2 विएतनाम और गाम्बिया से तथा एक एक यूगांडा, ईरान, घाना, काम्बिया, बर्मा, सेनेगल, इंडोनेशिया तथा कोरिया से थे।

नियोजता-कर्मचारी संबंध

307. अधिकारियों के वेतन-संशोधन की अंतिम रूप दिया गया और 27 सितम्बर 1985 को उनकी घोषणा की गयी। संशोधित वेतनमान पहली फरवरी 1984 से लागू किये गये। अनिर्णित मामलों पर मान्यताप्राप्त श्रेणी III और IV स्तरों से आतपीत की गयी और कामगार कर्मचारियों से संबंधित कई समस्याओं के संतोषजनक हल निकाले गये। मार्च 1986 में हुए प्रबंधकों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मामलों पर जैसे, बैंक में औद्योगिक संबंधों की स्थिति, स्टाफ, उद्बोधन, अनुशासन और समय की पाबंदी लागू करना कम्प्यूटरों और मशीनों का इस्तेमाल, ग्राहक सेवा में सुधार मूद्रा और रेजिस्ट्री से संबंधित मामले तथा शाखा प्रबंधक की सुमिका पर चर्चा की गयी।

308. स्टाफ अधिकारी ग्रेड 'ए' में पदोन्नति की बैंक की योजना के कई उपबंध मार्च 1981 में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने निरस्त कर दिये थे। उसके बाद बैंक ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। दिनांक 10 अप्रैल 1986 को उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ बेंच ने उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य करार दिया है। बैंक द्वारा संशोधित पदोन्नति की योजना की वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है क्योंकि यह योजना सेवा को दो महत्वपूर्ण घटकों को सुचारु ढंग से मिलाती है—पहला है नये लिपिकीय कर्मचारियों का सन्निवेश करना और दूसरा है अनुसूची लोगों का सन्निवेश। बैंक की अपील को मानते हुए अदालत ने मत जाहिर किया कि सेवा शर्तों के मामले में सेवा की विभिन्न शर्तों को शांति करने वाले आदेश मानवण्ड संसार करना बहुत मुश्किल होता है। और सेवा नियमों के प्रवर्तन के ऐसे क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक राय होना संभव है, वहाँ तर्क और सहज बुद्धि का परित्याग किये बिना, अतिम निर्णय विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार करना आवश्यक है कि वह यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों

के प्रति न्याय और कम से कम के प्रति अन्याय सुनिश्चित करने की भावना से प्रभावित हो।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व :

309. पहली जनवरी 1986 की स्थिति के अनुसार बैंक में श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या 2,317 थी। इनमें 1829 अनुसूचित जातियों और 488 अनुसूचित जनजातियों के थे। श्रेणी III में इन जातियों के कुल 3034 कर्मचारियों में से 2065 अनुसूचित जातियों और 969 अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी थे। श्रेणी I में कुल 386 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों में से 320 अनुसूचित जातियों के और 66 अनुसूचित जनजातियों के थे। कैलेंडर वर्ष 1985 के दौरान सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती के धोरे और कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ज्योरे सारणी में दिये गये हैं :

श्रेणी	कुल भर्ती किये गये अभ्यर्थी	उनमें से		प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I.	21	5	14	23.8	66.7
श्रेणी III	110	17	6	15.5	5.5
श्रेणी IV					
स्वीचरों से इतर.	86	23	12	26.7	14.0
स्वीचर	6	4	1	66.7	16.7

310. फरवरी 1986 में जारी किए गये बैंक के विज्ञापन के उत्तर में स्टाफ अधिकारी ग्रेड 'ए' के पद के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएं की गयीं।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार :

311. बैंक द्वारा श्रेणी III और IV के पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के बास्ते क्रमशः 14½ तथा 24½ प्रतिशत की दर पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। 1985 के दौरान श्रेणी III में भरे 110 में से तथा श्रेणी IV में 112 पदों में से 16 तथा 27 स्थान आरक्षण की निर्धारित दर के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे जाने थे। इनमें से, वास्तव में श्रेणी III में 9 रिक्तियां तथा श्रेणी IV में 11 रिक्तियां भरी गयीं। 31 दिसम्बर 1985 की स्थिति के अनुसार श्रेणी III में 569 तथा श्रेणी IV में 877 भूतपूर्व सैनिक कार्यरत थे।

हिन्दी की प्रगति :

312. बैंक के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। हिन्दी के प्रयोग के धारे में 1985-86 के लिए

वार्षिक समयबद्ध कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यान्वयन के लिए परिवर्तित किया गया। कार्यालय के पांच प्रमुख विभागों में उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी कक्ष खोले गए। परिपत्र, कार्यालय आदेश तथा अन्य सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये और बैंक के प्रकाशन/रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती रहीं। कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं के जरिये में टिप्पण और प्राकृषण तथा पत्राचार का प्रशिक्षण दिया गया और अनिवार्य/स्वैच्छिक हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्दी कक्षाएँ चलायी जाती रही।

313. रिजर्व बैंक के विभागों/कार्यालयों द्वारा की जाने वाली प्रगति पर मजर रखने की दृष्टि से केन्द्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपनी तिमाही बैठकें आयोजित करती रही और उसमें लिये गये निर्णयों को लागू करण के लिए उन्हें विभागों/कार्यालयों को भेजा गया। 'राजभाषा शीर्ष' प्रतियोगिताओं के अलावा केन्द्रीय कार्यालय के सभी

विभागों में तथा क्षेत्र 'ग' के कार्यालयों में विभागीय शील्ड योजना भी शुरू की जा रही है ताकि उनके कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। भाव-विवाद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिताएं, हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण की प्रतियोगिताएं तथा अन्य हिन्दी समारोह भी वर्ष के दौरान आयोजित किये गये। बैंक ने दिन प्रतिदिन के काम में हिन्दी के प्रयोग को सुविधा के लिए संदर्भ साहित्य प्रकाशित करना जारी रखा।

कार्यालय परिसर तथा रिहायशी बसाटें:

314. वर्ष के दौरान कार्यालय, भग्नों और रिहायशी बसाटों के निर्माण/अधिग्रहण मौजूबा परिसरों में बुद्धियों/परिश्रमियों तथा जमीन पर खरीद पर 28.03 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस तरह पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल व्यय 71.31 करोड़ रुपये बैठता है जबकि 5 वर्षीय अवधि में 161.31 करोड़ रुपये के कुल परिसरों की व्यवस्था की गयी है।

315. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नागपुर कार्यालय में अतिरिक्त कार्यालय भवन और बैंकर प्रतिक्षण महाविद्यालय में विस्तार योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। बंगलूर में मौजूबा कार्यालय भवन में अतिरिक्त मंजिलें बनाने का कार्य सितम्बर 1986 तक पूरा हो जाने की संभावना है। चंडीगढ़, कोचीन, बंबई, में बाब्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स तथा कानपुर में कार्यालय भग्नों के निर्माण का कार्य चल रहा है। भोपाल, कोचीन, जम्मू तथा मई बंबई में प्रस्तावित कार्यालय भग्नों का कार्य योजना स्तर पर है और यह कार्य 1986-87 में शुरू हो जाने की संभावना है। बैंक के स्वर्ण जयंती समारोहों के हिस्से के रूप में स्थापित किये जा रहे बंबई के 'इंदिरा-गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च' को इमारत का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और तेजी से चल रहा है।

316. बंबई, नई दिल्ली तथा मद्रास में राष्ट्रीय समा-शोधन गृह के लिए प्रस्तावित कंप्यूटर स्थापित करने के लिए

अपेक्षित विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था में प्रगति हुई। इनमें वातानुकूलन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ऊँचे उठे हुए फर्श, आभासी छत (फाल्स सीलिंग) तथा डीजल जनरेटर सेट शामिल हैं। बंबई में कार्य अगस्त 1986 तक तथा नई दिल्ली और मद्रास में सितम्बर 1986 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन तीन केन्द्रों पर कुल लागत लगभग 180 लाख रुपये आने की संभावना है।

317. वर्ष के दौरान केन्द्रों पर 734 प्लेटों तथा 8 एकल कमरों का निर्माण पूरा किया गया। इनमें से अधिकारियों के लिए 136 प्लेट तथा 8 एकल कमरे, श्रेणी III के लिए 196 प्लेट तथा श्रेणी IV के लिए 402 प्लेट शामिल हैं। हैदराबाद में 251 प्लेटों को शामिल करते हुए, जिन्हें 1984-85 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और जो वास्तव में 1985-86 में ही पूरे हो सके हैं, स्टॉक की विभिन्न श्रेणियों के लिए योजना के पहले तीन वर्षों में कुल 2,560 प्लेट तथा अपने आप में पूर्ण 36 एकल कमरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। संवर्गवार वितरण इस प्रकार है—अधिकारियों के लिए 589 प्लेट तथा 36 एकल कमरे, श्रेणी III स्टॉक के लिए 987 प्लेट तथा श्रेणी IV स्टॉक के लिए 984 प्लेट। 12 केन्द्रों पर अधिकारियों के लिए 1202 प्लेटों, श्रेणी III स्टॉक के लिए 1,563 प्लेटों तथा श्रेणी IV स्टॉक के लिए 320 प्लेटों के निर्माण का कार्य चल रहा है। विभिन्न केन्द्रों पर स्टॉक के लिए रिहायशी बसाटों के बास्ते कई परियोजनाओं पर योजना के विभिन्न चरणों पर कार्य चल रहा है।

आवास ऋण :

318. जून 1986 को समाप्त वर्ष के दौरान नीचे सारणी में बताये गये के अनुसार कुल 5.69 करोड़ रुपये के आवासीय ऋण मंजूर किये गये :

	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	मंजूर राशि (लाख रुपये)
अ. सहकारी आवास समितियाँ			
नये ऋण	12	208	139.31
अतिरिक्त ऋण	27	185	37.55
कुल	39	393	176.86
आ. वैयक्तिक ऋण			
नये ऋण		218	141.00
अतिरिक्त ऋण		6	1.04
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर ऋण*		626	250.51
कुल		850	392.55

* मार्च 1986 के अंत तक।

केन्द्रीय बोर्ड :

319. प्रोफेसर एम. एल. वांतवाला ने 20 दिसम्बर 1985 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक का पद त्याग दिया। बोर्ड अपनी बैठकों की कार्यवाहियों में उनकी सेवाओं और उनके योगदान की भूरि भूरि सराहना करता है। श्री एन. एस. मराठे की, दिनांक 16 जनवरी 1986 को प्रो. वांतवाला के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया। श्री एम. एस. पटवर्धन एक सीजुरा रिक्ति में इसी तारीख से निदेशक के रूप में नियुक्ति किये गये।

स्थानीय बोर्ड :

320. केन्द्रीय बोर्ड में श्री एस. एन. मराठे की नियुक्ति 16 जनवरी 1986 से प्रो. एम. एल. वांतवाला के स्थान पर पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड में सदस्य के रूप में उन्हें नामित किये जाने के फलस्वरूप हुई थी।

321. बैंक के स्थानीय बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) के एक सदस्य श्री जी. आर. रानास्थानी की 26 मार्च 1986 को हुई बुखय मृत्यु की बोर्ड सखेब सूचना देता है तथा उनकी मूल्यवान सेवाओं की भूरि भूरि सराहना अभिलेखित करता है।

लेखा :

322. 30 जून 1986 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रायश्चित्तों के लिए समायोजन कर लेने के बाव में बैंक की आय 1,381.40 करोड़ रुपये रही। पिछले वर्ष बैंक की 1,246.98 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

323. वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय प्रामाण्य ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय प्रामाण्य ऋण (स्थिर-करण) निधि तथा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में प्रशासन की राशि क्रमशः 350 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये रही। वर्ष 1984-85 में इनमें क्रमशः 300 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये तथा 350 करोड़ रुपये डाले गये थे।

324. वर्ष के दौरान, कुल व्यय के लिए 411.40 करोड़ रुपये की व्ययस्था कर लेने के बाव में आय 621.40 करोड़ रुपये की शेष राशि (1984-85 में आय की शेष राशि 571.98 करोड़ रुपये तथा व्यय 361.98 करोड़ रुपये के मुकाबले) केन्द्र सरकार को भुगतान करने के लिए अलग रखी गयी। शुद्ध लाभ की राशि 210 लाख रुपये (पिछले वर्ष की राशि के बराबर ही) रही।

325. पिछले वर्ष के 1,246.98 करोड़ रुपये के स्तर के मुकाबले बैंक की आय 134.42 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ वर्ष के दौरान 1381.40 करोड़ रुपये हो जाने के पीछे मुख्य योगदान वर्षा खजाना किलों पर अर्जित अंशों पर वट्टा तथा बैंकों को दिये गये ऋणों और अधिनियों पर अंशों पर अर्जित व्याज का रहा। इनका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को अधिप्राय अधिनियों पर अर्जित व्याज में कमी तथा बैंक के पात अनुप्राय बाणिज्य बैंकों द्वारा रखी उनकी अतिरिक्त नकदी प्रारंभित निधियों पर अर्जित व्याज में वृद्धि में खप गया। व्यय में 49.42 करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिभूति मुद्रण की लागत में वृद्धि तथा सरकारी लेन देन करने के लिए एजेंसी बैंकों को देय कुल फनीशन में वृद्धि रहा।

लेखा परीक्षक :

326. बैंकों के लेखों की लेखा परीक्षा मेसर्स के० सी० खन्ना एण्ड कं. नई दिल्ली, मेसर्स वेब एंड कं. गाजियाबाद, मेसर्स हाउ गुप्ता एण्ड कं. नई दिल्ली, मेसर्स सी. सी. ओकसी एण्ड कं. बंबई, मेसर्स एल. आर. बाटलीवाय एण्ड कं. कलकत्ता तथा मेसर्स ब्रह्मणा एण्ड कं. मद्रास ने की है। सभी लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त किये गये थे। इस वर्ष भी बैंक के सभी कार्यालय तात्कालिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किये गये थे। लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंक के सभी कार्यालय छः क्षेत्रों में बांटे दिये गये थे और प्रति क्षेत्र लेखा परीक्षा के लिए 75,000 रुपये लेखा परीक्षा शुल्क आवा किया गया। शाखा लेखों के समेकन के लिए केन्द्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों को 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क आवा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1986 की स्थिति का तुलना-पत्र

निर्भर विभाग

देयताएं	मास्तियां			
	रु.	पै.	रु.	पै.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए मोट	15,38,14,668.00		सोने का तिरका और मुद्रियन	
संचालन में मोट	273,76,84,16,312.50		(क) भारत रखा हुआ	274,27,76,380.85
			(ख) भारत से बाहर रखा हुआ	
			विदेशी प्रतिभूतियां	1584,05,75,253.50
जारी किये गये कुल मोट	27392,22,30,980.50		गोड़	1838,33,51,634.15
			रुपये का तिरका	22,51,68,331.20
			भारत सरकार का रुपया	
			प्रतिभूतियां	25631,37,10,515.15
			देसी विनिमय बिल और	
			दूसरे बाणिज्य पत्र	
कुल देयताएं	27392,22,30,980.50		कुल मास्तियां	273,92,22,30,980.80

वैयक्तिक विभाग

देयताएं	प्रास्तियां	
	रु.	पै.
प्रदत्त पूंजी	5,00,00,000.00	मोट
प्रारम्भित निधि	150,00,00,000.00	रखे सिकके
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीर्वाविधि प्रवर्तन) निधि	3295,00,00,000.00	छोटे सिकके
जयाराशियां		खरीदे तथा भुनाये गये बिल
(क) सरकार		(क) आंतरिक
(i) केन्द्र सरकार	57,09,03,373.31	(ख) बाहरी
(ii) राज्य सरकारें	14,01,33,635.35	(ग) सरकारी खजाना बिल
(ख) बक		विदेशों में रखे गये बकाया शेष
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12616,58,36,433.76	निवेश ¹
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	171,70,80,711.49	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रष्टिम
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,93,85,498.77	(i) केन्द्र सरकार
(iv) अन्य बैंक	25,51,30,796.64	(ii) राज्य सरकारें ²
(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जयाराशियां		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रष्टिम
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (बीर्वाविधि प्रवर्तन) निधि		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण)	266,87,20,915.61	(ii) राज्य सहकारी बैंक
(घ) भ्रष्टिम	5901,50,25,855.62	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
देय बिल	129,16,08,519.88	(iv) अन्य
अन्य देयताएं	8627,95,57,694.61	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीर्वाविधि प्रवर्तन) निधि से ऋण भ्रष्टिम तथा निवेश :
		(अ) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रष्टिम
		(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
		(i) भारतीय निर्यात-आयात बैंक
		(ब) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांधों/डिबेंचरों में निवेश
		(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
		(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक
		अन्य प्रास्तियां ³
कुल देयताएं	31266,33,83,435.04	कुल प्रास्तियां

1. विदेशों में विदेशी मुद्राओं में रखे गए 1760,82,12,788.79 रुपये शामिल हैं।

2. भ्रष्टिम भ्रष्टिम शामिल हैं।

3. विशेष व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी या उन्हें भ्रष्टिम के रूप में दी गयी राशियां शामिल हैं।

के. जी. पाटकर

मुख्य लेखाकार

तारीख 14 अगस्त 1986

भार. एन. मल्होत्रा

ए. घोष

सो. रंगराजन

भार. के. शील

पी. जी. भोष्ठा

गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

उप गवर्नर

30 जून 1986 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	रु.	पै.
भाय		
भ्याज, घट्टा, विनियम शुल्क, कमीशन आदि*	621,40,12,853.38	
	जोड़	621,40,12,853.38
व्यय		
स्थापना व्यय	128,12,08,682.12	
निवेशकों और स्थायी बोर्ड के सदस्यों की फीस और व्यय	3,37,985.01	
लेखा परीक्षकों की फीस	7,08,633.50	
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	6,37,98,291.34	
विधि प्रभार	34,53,597.76	
ढाक और तार खर्च	1,46,17,550.44	
कोष प्रेषण	4,08,34,355.50	
लेखन सामग्री आदि	1,47,79,459.38	
प्रतिभूति छपाई (बैक, मोट फार्म आदि)	100,07,82,422.27	
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत	6,64,16,997.37	
एजेन्सी प्रभार	150,01,19,357.24	
स्टाफ उपदान और भर्गवापिकी निधिषों में भ्रंशदान	2,15,00,000.00	
विविध व्यय	10,54,64,541.40	
	जोड़	411,40,11,853.33
		210,00,01,000.05
उपलब्ध शुद्ध शेष राशि	जोड़	621,40,12,853.38
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष		210,00,01,000.05

* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अन्तर्गत सांख्यिक अंशदान और नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाध।

प्रारक्षित निधि लेखा

	रु.	पै.
30 जून 1985 को शेष	150,00,00,000.00	
लाभ-हानि लेख से अंतरित		
	जोड़	150,00,00,000.00
के. जे. पाटकर	आर. एन. मल्होत्रा	गवर्नर
मुख्य लेखाकार	ए. घोष	उप-गवर्नर
	सी. रंगराजन	उप-गवर्नर
	भार के कीत	उप-गवर्नर
तारीख 14 अगस्त 1986	पी. डी. भोत्रा	उप-गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1986 की स्थिति के रिजर्व बैंक के तुलनपत्र तथा लेखों पर, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने हैं।

हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखों और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों और बाउचरों के साथ उपर्युक्त तुलनपत्र की जाँच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं, कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी माँगी, वह सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार भातियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। यह तुलनपत्र, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक के बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

तारीख 14 अगस्त, 1986

मैमर्स ब्रह्म मुन्या एण्ड कं.

मैमर्स सी. सी. चौकशी एण्ड कं.

मैमर्स एम. भार. बाटलीबाय एण्ड कं.

मैमर्स दासमुन्दा एण्ड कं. लेखा परीक्षक

मैमर्स वेद एण्ड कं.

मैमर्स के. सी. शर्मा एण्ड कं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का विवरण

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष							
	30 जून 1984				30 जून 1985			
	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
निर्गम विभाग								
देयताएं								
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	5,63,23,572.00				39,68,97,530.00			
संचलन में नोट	21776,91,60,554.50				24795,60,11,721.50			
जारी किये गये कुल नोट			21782,54,84,126.50				24795,29,09,251.50	
कुल देयताएं			21782,54,84,126.50				24795,29,09,251.50	
प्रास्तियां:								
सोने का सिक्का और बुलियन								
(क) भारत में रखा हुआ	225,58,28,485.81				246,68,66,362.28			
(ख) भारत के बाहर रखा हुआ								
विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75,253.50				1564,05,75,253.50			
रुपये का सिक्का	16,10,91,167.06				15,00,32,662.85			
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	19976,79,89,220.13				22969,56,34,972.87			
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र								
कुल प्रास्तियां			21782,54,84,126.50				24795,29,09,251.50	
बैंकिंग विभाग								
देयताएं								
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000.00				5,00,00,000.00			
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00				150,00,00,000.00			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीवैकालीन प्रवर्तन)	2545,00,00,000.00				2895,00,00,000.00			
निधि								
जमा राशियां								
(क) सरकारी								
(i) केन्द्रीय सरकार	2919,08,02,336.88				59,86,10,234.95			
(ii) राज्य सरकारें	13,07,55,456.28				14,87,27,256.98			
(ख) बैंक								
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8104,86,78,299.28				10886,01,46,502.08			
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	111,34,14,266.56				142,83,62,962.37			
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,71,21,135.00				4,57,75,099.57			
(iv) अन्य बैंक	16,25,80,279.50				25,16,33,462.00			
(ग) नावाह की जमा राशियां								
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (बीवैकालीन प्रवर्तन) निधि	249,58,65,242.03				117,53,65,242.03			
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्विकरीकरण) निधि	281,28,55,673.58				231,28,55,673.58			
(घ) अन्य	6123,01,90,647.87				6461,81,25,057.68			
देय बिल	86,30,48,132.88				22,28,24,900.36			
अन्य देयताएं	4198,73,43,967.16				6074,47,42,053.11			
कुल देयताएं			25438,26,55,437.02				27140,73,68,450.04	

टिप्पणी: 30 जून, 1984—अतिरिक्त देयता अंगत चुक्ता शेयरों पर 50,000 पैसे के बराबर रु. 7,57,495.42

30 जून, 1985—अतिरिक्त देयता अंगत चुक्ता शेयरों पर 50,000 पैसे के बराबर रु. 8,04,997.42

भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का विवरण—(जारी)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष							
	30 जून, 1984				30 जून 1985			
	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
बैंकिंग विभाग								
घास्तियाँ								
नोट			5,63,23,572.00				39,68,97,530.00	
बचत का सिक्का			3,30,353.00				7,20,074.00	
छोटा सिक्का			1,83,897.40				2,19,447.75	
खरीदे और मुद्राये गये बिल			
(क) देशी								
(ख) विदेशी			
(ग) सरकारी खजाना बिल			9374,62,39,191.70				8394,06,37,831.32	
विदेशों में रखा हुआ धन			3277,95,38,619.45				3732,00,89,774.67	
निवेश			4369,15,45,657.57 (ख)				6952,77,49,529.59 (ग)	
ऋण और अधिम								
(i) केन्द्रीय सरकार को			
(ii) राज्य सरकारों को (क)			460,47,00,000.00				315,58,00,000.00	
(iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को			1768,66,06,105.87				1863,00,79,190.68	
(iv) राज्य सहकारी बैंकों को			44,88,60,000.00				21,66,25,000.00	
(v) नाबार्ड को			1039,05,76,000.00				761,83,41,000.00	
(vi) दूसरों को			166,00,00,000.00				182,05,00,000.00	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीचकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अधिम और निवेश								
(क) ऋण और अधिम								
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को			2084,78,11,075.00				2320,78,30,750.00	
(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक को			125,00,00,000.00				180,00,00,000.00	
(ख) सा. औ. वि. बैंक/भा. नि. आ. बैंक द्वारा जारी बांडों/चिबेंचरों में निवेश			
अन्य घास्तियाँ (घ)			2721,99,61,065.03				2377,23,78,323.03	
कुल घास्तियाँ			25438,26,55,437.02				27140,78,68,450.04	

(क) अधीनस्थ अधिम शामिल हैं।

(ख) विदेशों में मुद्राओं में रखे हुए रु. 870,16,68,177.87 शामिल हैं।

(ग) विदेशों में मुद्राओं में रखे हुए रु. 13,83,73,65,508.44 शामिल हैं।

(घ) विशेष व्यवस्थाओं के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अधिम दिये गये या उनमें जमा की गयी राशियाँ शामिल हैं।

30 जून 1984 और 1985 को समाप्त वर्षों का लाभ और हानि लेखा

	1984		1985	
	रु.	पै.	रु.	पै.
आय				
ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन आदि*	459,68,22,728.03		571,97,87,340.93	
	459,68,22,728.03		571,97,87,340.93	
व्यय				
स्थापना व्यय	93,33,56,946.98		142,25,62,666.01	
निवेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	2,22,702.85		2,64,677.99	
लेखा परीक्षकों की फीस	8,43,227.00		6,68,793.90	
किराया, कर, बीमा, विभक्त आदि	4,83,44,920.97		4,77,58,619.79	
विधि प्रभार	6,05,114.99		8,56,772.00	9
डाक और तार खर्च	1,29,43,134.35		1,30,13,462.74	
कोष प्रेषण	1,97,86,226.57		2,27,86,300.80	
लेखन सामग्री आदि	1,40,17,921.72		1,50,83,724.29	
प्रतिभूति छपाई (बैक, नोट फार्म आदि)	43,41,63,205.58		59,28,05,493.05	
बैंक संपत्ति का मूल्यांकन और मरम्मत	4,23,54,739.96		6,63,11,994.66	
एजेंसी प्रभार	93,92,73,197.30		132,84,76,907.52	
कर्मचारी उपदान और अधिवार्षिकी निधियों में अंशदान	1,60,00,000.00		1,70,00,000.00	
विविध व्यय	3,49,06,250.00		10,21,97,196.67	
उपभोग्य शुद्ध देय राशि	210,00,00,239.77		210,00,00,824.47	
जोड़	459,68,22,728.03		571,97,87,340.93	
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	210,00,00,239.77		210,00,00,824.47	

* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अन्तर्गत सांविधिक अंशदान और नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

प्रारक्षित निधि लेखा

30 जून को शेष	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
लाभ हानि लेखों से अन्तरित	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोड़	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 13th October, 1986

S.O. 3954.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1986 :—

[No. F. 19/21/86-BO. I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

THE ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1985—June 30, 1986

PART I—THE ECONOMIC SITUATION

The performance of the economy in 1985-86 assumes special significance because it is the first year of the Seventh Plan. During the Sixth Plan (1980—85) it was possible to attain an average annual growth rate of 5.3 per cent in real national income, although this was achieved over the somewhat low base of 1979-80. Nevertheless, the improved performance of the economy since 1974-75 has helped to raise the trend rate of growth of the economy. The Seventh Plan (1985—90) aims at sustaining the growth rate in national income at 5 per cent. The main support to growth during this period is expected to emanate from the industrial sector which is targeted to grow at 8 per cent per annum as against the realised growth rate of around 5.6 per cent in the Sixth Plan period. Further, with a modest decline expected in the domestic saving rate and the limitations on the inflow of external savings, increasing reliance will have to be placed on enhanced productivity and efficiency in the use of capital for attaining the growth rate envisaged in the Seventh Plan.

2. The estimated growth rate in real national income during 1985-86 is around 4 per cent, which means that for the second year in succession, the rate has been well below 5 per cent. In the agricultural sector, with an anticipated growth of about one per cent, the economy has only regained what it lost in 1984-85. The growth in the industrial sector, estimated at only 6.3 per cent, is also a matter of concern as in none of the four successive years after 1981-82 when industrial production recorded a growth rate of 8.6 per cent, has the growth rate reached even 7 per cent. One important factor inhibiting higher growth in industry is the continued shortage of power in relation to demand. However, assuming that the time lag between the various policy measures introduced to boost industrial investment and their impact on output is around two years, 1986-87 may witness a better performance. A breakthrough in industrial growth holds the key to putting the economy on the higher growth path envisaged in the Seventh Plan.

3. There are several sources of strength in the current economic scenario which should help promote higher growth. Inter alia, these are : declaration in inflation, sizeable stocks of foodgrains with the public distribution system, a high level of domestic savings, a reasonably comfortable level of foreign exchange reserves and credit-worthiness in external financial markets.

4. Wholesale prices. On a point-to-point basis, recorded a sustained declaration from 8.9 per cent in 1983-84 to 7.6 per cent in 1984-85 and further to 3.8 per cent in 1985-86. On a weekly average basis also, there was a declaration from 9.5 per cent in 1983-84 to 7.1 per cent in 1984-85 and further to 5.7 per cent in 1985-86. The foodgrains stocks with the public distribution system are estimated around 28.6 million tonnes at the end of June 1986. These large stocks provide not only an insurance against any undue rise in prices in agriculturally bad years, but also afford some scope for promoting employment and capital formation.

5. Preliminary data available on savings show that net domestic saving as percentage of NNP at current market prices stood at 16.1 per cent in 1985-86. Although this percentage has remained more or less unchanged since 1983-84, it is relatively high as compared to the saving rates in most developing countries.

6. On the external front, the foreign exchange reserves recorded a rise in 1985-86 in rupee terms though the magnitude of the rise was substantially lower than that during the previous year. In SDR terms, however, there was a modest decline in 1985-86. Even so, at present the reserves are the equivalent of 4.5 months' imports.

7. Among the worrying features of the economy, besides the inadequate industrial growth referred to earlier, are the trend in consumer prices and the pressures on the external payments position. The declaration in wholesale prices, discussed above, co-exists with the rise in consumer prices which on a point-to-point basis, recorded a rise of 8.9 per cent in 1985-86 as against 5.0 per cent in 1984-85 though, on a monthly average basis, the rise in 1985-86 at 6.4 per cent was of the same order as during the previous year. Prices of essential commodities would, therefore, need careful watching.

8. The pressure on the balance of payments is reflected most conspicuously by the sizeable trade deficit. Although the recent fall in the oil price may escape the pressures to some extent, the size of the trade deficit would continue to be a cause for concern in the remaining years of the Seventh Plan. In this context, the need to ensure a high rate of export growth assumes critical importance.

Agricultural Production

9. Agricultural production during 1985-86, the first year of the Seventh Plan, is estimated to have recorded only a growth of about 1.0 per cent over a marginal decline of 0.9 per cent in the previous year. This only means restoration of the production level to that of 1983-84. In contrast, the average rate of growth worked out to 5.1 per cent during the two years 1982-83 and 1983-84.

10. The performance of the agricultural sector during 1985-86 was affected by unfavourable weather conditions. There were floods in parts of Uttar Pradesh, while parts of southern, western and central India suffered from severe drought conditions. Of the 35 meteorological sub-divisions, rainfall during the year was deficient or scanty in as many as 9 sub-divisions as against 7 sub-divisions in the previous year. This, together with un-favourable timing and duration of rainfall, adversely affected the production of coarse grain, which declined by 4.7-5.2 million tonnes to reach a low, in recent years, of 26.0-26.5 million tonnes. As a result, despite rice production recording a peak of 63.0-63.5 million tonnes, overall kharif foodgrains output during the year was marginally lower than that in the previous year.

11. The marginal fall in foodgrains output during the kharif seasons was made up by improved production during the rabi season. Output of wheat at 45.5-47.0 million tonnes was not only higher than the previous year's production of 44.2 million tonnes, but also better than the earlier record of 45.5 million tonnes achieved during 1983-84. However, production of pulses remained stagnant at the earlier year's level of 12.0-12.5 million tonnes.

12. Overall, foodgrains production during 1985-86 is placed in the range of 148.0-149.5 million tonnes i.e. about 223 million tonnes more than the 1984-85 level of 146.2 million tonnes. As regards commercial crops, while jute and mesta scaled a new peak, the output of cotton was maintained at the previous year's high level. There was a marginal increase in sugarcane production but oilseeds production showed a sharp decline. The production of raw jute and mesta at 126 lakhs bales set a new record, far in excess of the previous peak of 84 lakh bales attained during 1981-82. The sizeable increase in output in 1985-86 is attributable to the enlargement of area under cultivation following the steep rise in raw jute prices in the previous year. The record crop, which is in excess of the consumption requirements, has severely depressed the price forcing the Jute Corporation of India (JCI) to purchase substantial quantities at support prices.

With production of cotton at 86—88 lakh bales—marginally higher than that in the previous year—the supply situation remained comfortable leading to fall in prices. Sugarcane production at 175 million tonnes was only marginally higher than 173.6 million tonnes registered during 1984-85 but was lower by 14.5 million tonnes than the record output of 1982-83. Oilseeds production at 11.6 million tonnes was lower by 1.5 million tonnes and 1.1 million tonnes respectively than in 1984-85 and 1983-84.

13. As concomitant of the increase in production of both wheat and rice, the procurement of these grains has remained at high levels. During the current marketing year so far (October 1985 to June 30, 1986) the procurement of rice at 9.6 million tonnes is about the same as in the corresponding period of last year; the total procurement during the year is likely to reach the previous year's record level of 9.8 million tonnes. Wheat procurement during the 1986-87 marketing season is likely to touch a new high as procurement till June 30, 1986 at 10.41 million tonnes has already surpassed the previous season's (April-March) record purchase of 10.34 million tonnes.

14. The Government of India took various measures during the year to increase offtake of foodgrains, particularly that of wheat, from the public distribution system. These included supply of wheat to roller flour mills at a reduced price of Rs. 172 per quintal, auctioning of wheat to traders, increased allocation for rural employment programme and issue of wheat to the public without any quantitative restrictions. As a result, the offtake of wheat during the financial year 1985-86 went up by almost 3.0 million tonnes or by 46 per cent to 9.8 million tonnes over the previous year. A major part of the increase in offtake (1.7 million tonnes) was accounted for by roller flour mills. The remaining increase (1.3 million tonnes) was almost equally shared by sale to traders and the offtake under the National Rural Employment Programme. The offtake of rice during 1985-86 at 7.1 million tonnes was also higher than 6.6 million tonnes in 1984-85.

15. Larger procurement of foodgrains, facilitated by higher output and increase in procurement prices over the years in construction with relatively lower off take from the public distribution system due to easy availability in the open market, had resulted in stocks of foodgrains with Government agencies touching a record level of 29.2 million tonnes in June 1985. These were made up of 21.0 million tonnes of wheat and 8.0 million tonnes of rice and 0.2 million tonnes of coarse grains. The foodgrains stocks at the end of June 1986, are estimated at around 28.6 million tonnes comprising 19.1 million tonnes of wheat, 9.4 million tonnes of rice and 0.1 million tonnes of coarse grains.

16. The procurement of raw jute and cotton also touched new records. Raw jute purchases by Jute Corporation of India in the 1985-86 season were 28 lakh bales as against 10.1 lakh bales in the previous year and the earlier record of 17.6 lakh bales in 1981-82. Similarly, the Cotton Corporation of India (CCI) procured, during 1985-86 seasons (till June 26), 15.3 lakh bales and the Maharashtra State Co-operative Cotton Growers' Marketing Federation 27.6 lakh bales. In the corresponding period of the previous year, their respective purchases were 6.4 lakh bales and 16.5 lakh bales. The earlier peak level purchases by the CCI were 11.8 lakh bales in 1980-81 while under the Maharashtra Cotton Monopoly Scheme, these were 18.2 lakh bales in 1982-83.

17. The situation on the oilseeds front continues to cause concern since production has fallen well below demand. The production of oilseeds after having picked up in 1983-84 and 1984-85 declined sharply to 11.6 million tonnes in 1985-86 due to drought in groundnut producing areas of Gujarat and Andhra Pradesh. Around one-third of the consumption requirements of edible oils was met through imports at an average annual cost of about Rs. 1,000 crores in the past three years. These imports accounted for around 10 per cent of export earnings.

18. The Seventh Five Year Plan aims at raising the level of oilseeds production to about 18 million tonnes. Even at

this level, the production would not be sufficient to meet the country's edible oils requirements necessitating continued imports. In recent years though the production of rapeseed/mustard and soyabean has shown substantial improvement, much of the edible oils requirement is still being met by groundnut oil, the production of which is largely subject to the vagaries of monsoon. There is an urgent need to raise the oilseeds production within a reasonably short span of time so as to reduce the pressure on balance of payments.

19. With a view to encouraging the use of new oil like cottonseed oil, rice bran oil and other minor oils by the vanaspati manufacturers, rebates on excise duties have been announced depending upon the extent of such use in the manufacture of vanaspati. The Government of India has also imposed excise duty on expensive refined oils—groundnut and rapeseed/mustard—so as to provide a competitive regime for the new oils. The Government has also provided crop insurance cover to oilseeds production. The Reserve Bank has, in April 1986, reduced across-the-board, minimum margins on bank advances against oilseeds and vegetable oils by 15 percentage points, and exempted advances against high yielding and hybrid seeds used for growing oilseeds certified by appropriate authorities from all the provisions of selective credit controls.

20. A substantial increase in the output of oilseeds would depend on the success of a comprehensive package of measures. With very low yields, higher market prices alone cannot ensure remunerative return to the farmer. Stepping up the yield is essential. Besides, the benefit of high market prices does not always percolate to the farmers. The imposition of informal restrictions on the movement of groundnut and groundnut oil out of some major producing States has tended to keep the prices low within such State. Further, although the Government fixes support prices for important oilseeds, the procurement agencies have not always been able to prevent some distress sales. It is necessary to ensure that such situations do not arise.

21. To encourage oilseeds production in a big way, in addition to assuring right prices and provision of crop insurance further developments in oilseeds technology would be necessary. Farmers also need proper inputs like good quality seeds, pesticides, credit, extension services and irrigation facilities. Timely reimbursement of losses under crop insurance also needs to be ensured. The State Governments may adopt an approach to encourage oilseeds production and strive to bring about a systematic shift from other crops namely wheat and paddy to oilseeds in areas where there is a definite income advantage to farmers.

22. Overall, while the country is now comfortable with regard to wheat, rice, cotton and raw jute, shortages persist in oilseeds, pulses and sugarcane. Some of these shortages are associated with the lags in productivity in rain-fed and dry areas. In addition, there are also varietal imbalances, as for example, in the case of cotton, where the production of long and extra long staple is much higher than the present level of consumption. These surpluses and shortages are a cause for concern. While the surpluses pose problems of storage and marketing besides resulting in increased subsidies, shortages create serious strains on prices and the balance of payments.

23. These imbalances—cropping regional—in the agricultural scene, call for policies that should aim at better allocation of resources to the crops taking into account the comparative endowments of the different regions. An integrated agricultural policy which encompasses production, pricing and marketing can play a useful role in correcting these imbalances.

Trends in Industrial production and Investment

24. The Seventh Five Year Plan envisages a significant acceleration in the rate of growth of the industrial sector. The manufacturing sector is projected to grow at 8.0 per cent per annum while the compound annual growth rate of electricity generation is placed at 12.1 per cent and that of

the mining sector at 13 per cent. During 1985-86, the first year of the Seventh Five Year Plan, the rise in the index of industrial production (adjusted index) is estimated at 6.3 per cent on the basis of provisional data (Table 1).

TABLE 1—TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION*

(Base 1970=100)

Industry	Weight	Financial year			
		1984-85		1985-86	
		Index Number	Percentage growth rate	Index Number	Percentage growth rate
1. Mining and Quarrying	9.69	234.8	+8.1	245.5	+4.6
2. Manufacturing	81.08	183.0	+5.7	194.1	+6.1
3. Electricity	9.23	285.0	+12.0	309.4	+8.6
4. General Index	100.00	197.4	+6.8	209.8	+6.3

*Based on adjusted indices of industrial production.

25. As against this, the growth rate in 1984-85 was 6.8 per cent on the basis of revised data. There appears to be some decline in the growth rate of industrial production in 1985-86. The deceleration was the sharpest in electricity where the growth rate in 1985-86 was 8.6 per cent as compared with 12.0 per cent in the previous year. In the manufacturing sector the growth rate at 6.1 per cent was higher than in the previous year.

Sectoral Trends

26. The Central Statistical Organisation (CSO) has prepared, beginning with 1983-84, the index of industrial production using adjusted weights on account of non-receipt of data for 137 items with a combined weight of 11.69 per cent in the index. The following analysis is based on the adjusted weights reflected in the index. The lower growth in 'mining and quarrying' sector of 4.6 per cent in 1985-86 as compared with 8.1 per cent in 1984-85 was mainly accounted for by coal (excluding lignite) and petroleum crude. The output of the former at 154.3 million tonnes during the year recorded an increase of 4.7 per cent as against 6.7 per cent in the previous year; the lower increase was influenced by a decision to reduce the accumulation of pithead stocks. The output of petroleum crude at 30.2 million tonnes in 1985-86 indicated a rise of 4.1 per cent which was in line with the Seventh Plan target although considerably lower than the rate of growth of 11.4 per cent during the preceding year.

27. In the electricity sector the generation of thermal including nuclear power increased by 15.8 per cent during the year as compared with a rise of 14.2 per cent during the previous year but hydel power recorded a fall of 5.3 per cent on account of deficient rainfall in contrast to a rise of 7.9 per cent during the preceding year. Consequently, the share of hydel power in total electricity generation dropped sharply from 34.3 per cent in 1984-85 to 30.0 per cent in 1985-86. The all-India average shortfall in supply of electricity as a proportion to demand went up to 7.9 per cent during the year as compared with 6.7 per cent in 1984-85. The shortfall was the highest in the eastern region—13.8 per cent—followed by the northern region—10.7 per cent—and the southern region—9.3 per cent. In view of the lower availability of electricity in relation to demand, several States had to impose power cuts—restrictions ranging from 5—30 per cent in the case of West Bengal and 60—70 per cent in the case of Haryana. Severe power cuts were also in force in other States such as Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. In spite of the lower increase in the rate of growth of the electricity sector, the output of the manufacturing sector grew by 6.1 per cent during the year, representing a better performance than in the previous year.

Quarterly Trends

28. An analysis of the trends in industrial production on a quarterly basis reveals that the rate of growth picked up in the second half of 1985-86 unlike in the previous year which witnessed considerably higher rates of growth during the first half of the year (Table 2).

TABLE 2—QUARTERLY GROWTH RATES IN INDUSTRIAL PRODUCTION*

(Base : 1970=100)

(In percentage)

Period	General Index		Mining and Quarrying		Manufacturing		Electricity	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
April-June	+6.9	+5.8	+14.1	+1.1	+4.4	+6.1	+15.6	+7.8
July-September	+8.6	+5.3	+5.4	+3.0	+8.2	+4.9	+13.8	+9.9
October-December	+5.2	+7.2	+4.3	+5.3	+4.3	+7.3	+11.4	+7.0
January-March	+6.4	+6.6	+8.9	+7.8	+5.8	+6.0	+7.7	+9.5

*Based on adjusted indices of industrial production.

It may be noted that the manufacturing sector achieved a higher rate of growth during the latter half of the year as compared to the growth achieved during the first half of the year as also during the latter half of 1984-85.

Infrastructure

29. The composite index of six infrastructure industries [viz., electricity, coal (excluding lignite), petroleum crude, petroleum refinery products, saleable steel and cement] having a revised weight of 24.25 per cent in the general index of industrial production, recorded a lower growth rate of 8.2 per cent during 1985-86 as compared with 9.9 per cent in the previous year.

TABLE 3—GROWTH IN INDUSTRIAL PRODUCTION : USE-BASED CLASSIFICATION

(In percentage)

Industrial group	Weight	Financial year	
		1984-85	1985-86
Basic industries	33.23	+9.5	+7.2
Capital goods industries	14.98	+2.6	+3.5
Intermediate goods industries	21.33	+9.5	+10.2
Consumer goods industries	30.46	+3.2	+3.8
(a) Durables	3.81	+19.1	+14.4
(b) Non-durables	26.65	+0.4	+1.6

32. The significantly lower rate of growth of the basic industries group was caused mainly by the lower growth rate of coal production. The performance of this group was also adversely affected by lower rate of increase in output of cement and a decline in aluminium production reflecting the impact of power shortage on these energy-intensive industries. In the capital goods group the output of boilers, cement machinery and ball and roller bearings industries grew at a higher rate in 1985-86 than in 1984-85, while industries such as paper and pulp machinery, agricultural tractors and machine tools experienced a decline in production in 1985-86. The output of railway wagons rose marginally in contrast to the sharp decline of 25.1 per cent in 1984-85. In the intermediate goods group higher rates of increase in the output of cotton yarn, newsprint, and nylon filament yarn were achieved in 1985-86 as compared with those registered in the previous year. Jute textiles, synthetic rubber and viscose tyre cord belonging to this group recorded a decline in production in 1985-86. Among the consumer goods industries group the durable goods segment again recorded a notable growth of 14.4 per cent following a growth of 19.1 per cent witnessed in the previous year. Higher growth rates were recorded in 1985-86 over those in the previous year by durable goods such as motor cycles, scooters, three wheelers and electric fans. The output of non-durable consumer goods group recorded a growth of 1.6 per cent as compared to 0.4 per cent in 1984-85. Industries in this group such as sugar, paper and paper board, matches, razor blades and rubber footwear, staged a recovery in 1985-86 and recorded higher production levels than those achieved in the previous year which had witnessed a decline in production in many of these industries. Decline in production was noticed in 1985-86 in industries such as cloth (mill sector), vanaspati, soaps and cigarettes.

33. According to input-based classification, the agro-based industries group recorded a lower growth of 2.9 per cent in contrast to a growth of 4.3 per cent observed during the preceeding year. The output of metal-based industries recorded a higher growth of 5.4 per cent compared with 4.9 per cent in the previous year. In the case of chemical-based industries, the rate of increase at 6.6 per cent was the same as in 1984-85.

Capacity, Creation and Utilisation

34. An analysis of data on capacity creation in 1985-86 in selected industries with a revised weight of 53.64 per cent in the index of industrial production reveals that selected basic goods industries (weight 17.31 per cent) and intermediate goods industries (weight 13.77 per cent) added to capacity at a faster rate of 7.9 per cent each as compared to 6.3 per cent and 5.4 per cent, respectively, in 1984-85. In the case of selected consumer goods industries (weights 16.33

30. Production of petroleum refinery products rose by 20.1 per cent while the output of saleable steel achieved a growth rate of 11.1 per cent. Of the remaining industries which registered lower growth rates during the year as compared with the previous year, electricity generation and crude petroleum marginally exceeded their targetted growth rates of 8.5 per cent and 4.0 per cent, respectively, fixed for 1985-86. Trends based on Use-based and Input-based Classification.

31. The data on use-based classification of industrial production show that capital goods, intermediate goods, and consumer goods recorded higher growth rates in 1985-86. The basic industries group, however, was an exception and recorded lower growth compared to the previous year (Table 3).

per cent), the high rate of capacity creation achieved in 1984-85 could not be sustained. Sufficient information is, however, not available in respect of the capital goods group to assess its performance in regard to additions to capacity. Overall, the increase in installed capacity was of the order of 9.5 per cent in 1985-86 as compared to 7.9 per cent in the previous year in respect of the selected industries.

35. While data on additions to capacity in selected industries throw some light on investment activity in the industrial sector, it must be noted that these data do not cover the industrial sector as a whole. Further in view of the lags involved in the case of long gestation projects the trends partly represent the fructification of investments made in previous years. Trends in industrial investment in the private corporate sector during the year under review are more clearly discernible from the disbursements made by all-India term lending institutions and from the figures of total capital raised from the market. Disbursements by the three term lending institutions (IDBI, IFCI, ICICI) amounting to about Rs. 3,387 crores were 31.2 per cent higher in 1985-86 as compared to the previous year. Even after allowing for increase in prices of investment goods, these data would indicate a rise in industrial investment in the private corporate sector. Provisional data on capital raised by non-government companies reveal that Rs. 935 crores were mobilised by them from the capital market in 1985-86 as compared with Rs. 857 crores in 1984-85.

36. Capacity utilisation ratios worked out for 51 industries with a weight (adjusted) of 61.66 per cent in the index of industrial production throw some light on the performance of the industrial sector during 1985-86. As many as 22 industries (weight 19.12 per cent) recorded capacity utilisation ratios of 80 per cent or more in 1985-86. These include phosphatic fertilisers, ball and roller bearings, petroleum refinery products, newsprint, cycle tyres, nylon filament yarn, and electric fans which recorded higher capacity utilisation ratios and production levels in 1985-86, as compared to those in 1984-85. There was a decline in capacity utilisation as also in production levels as compared to the previous year in industries such as tractors, machine tools, jute manufactures, soaps and electric lamps, even though capacity utilisation ratio was above 80 per cent in both years. Automobile tyres, polyester fibre, paints and varnishes and two wheelers recorded lower capacity utilisation ratios despite higher production levels as a result of higher capacity creation. Among other industries, the performance of cement, diesel engines, storage batteries, synthetic detergents, leather footwear, and cotton spinning was notable inasmuch as they recorded increases in capacity production and capacity utilisation ratios as compared to 1984-85.

37. An analysis of the phenomenon of build-up of inventories in some of the industries appears warranted especially in the context of apprehensions in certain quarters that demand recession has hit some sections of industry. Provisional data in respect of commercial vehicles indicate that production in 1985-86 increased by 4.6 per cent as against 6.6 per cent in the previous year. On the other hand, the rate of growth in sales decelerated from 4.3 per cent in 1984-85 to a negative growth of 0.8 per cent in 1985-86. A further analysis, however, shows that within this sub-group, there is a divergent trend of sales between medium and heavy vehicles and light commercial vehicles. The rate of growth in production of medium and heavy commercial vehicles declined from 2.5 per cent in 1984-85 to 0.7 per cent in 1985-86 whereas sales declined by 5.2 per cent in 1985-86 after having risen by only 1.3 per cent in the previous year. In fact, growth in sales in 1982-83 and 1983-84 was no more than 1.1 per cent and 0.7 per cent, respectively. There was thus a mis-match between production and sales leading to a gradual inventory build-up even though the rates of growth in production were quite low during the past few years. The sales of medium and heavy commercial vehicles have probably been adversely affected by growing competition from light commercial vehicles and improved performance of the railways. The rate of growth in sales of light commercial vehicles exceeded 9 per cent per year in each of the three years 1983-84—1985-86, although a slight deceleration in the rate of growth of sales appears to be emerging even in this sector over the last two years.

38. In the cement industry, stock build-up during the year was not significant, production and despatches being in balance. As against a level of production of 32 million tonnes in large cement plants during 1985-86, stocks at the end of the year were of the order of 0.6 million tonnes. During 1985-86 there was a further build-up of stocks of nitrogenous fertilisers although growth rate in production declined from 12.2 per cent in 1984-85 to 10.5 per cent in 1985-86. Sales of fertilisers, which went up by 7.2 per cent in 1984-85 are expected to have increased by 8.6 per cent in 1985-86. In the wake of rising stocks of nitrogenous fertilisers, imports for 1986-87 need to be suitably adjusted.

Industrial Sickness

39. Sickness in industry continues to be a cause for concern. Remedial steps need to distinguish between different causes of sickness, particularly between those which are specific to an industry as a whole, and those which are peculiar to individual units. Careful assessment of the potential viability of sick units is another area which must continue to receive close attention. While every effort should be made to revive potentially viable units, hard decisions on those that are beyond rehabilitation should not be avoided. Guidelines have been issued to banks in November 1985 to ensure a co-ordinated approach between the banks and term lending institutions in assessing the viability of a unit once it is identified as sick and in framing a suitable rehabilitation package for it. With a view to detecting incipient sickness in industrial units and rehabilitating viable sick units, the Government has passed an Act viz., the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 which provides for the establishment of a Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). Further the Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) was converted into a statutory corporation viz., Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) with a view to strengthening its role as the principal credit and reconstruction agency for industrial revival and enabling it to co-ordinate the work

of other institutions engaged in the revival of industries. The dimensions of the problem of industrial sickness which results in loss of employment, wastage of capital assets, loss of production, and reduction in revenue to the exchequer are evident from the fact that about 8 per cent of total bank credit is frozen in these sick units. Between June 1983 and 1985, the number of identified sick units in the large, medium and other sectors showed an increase from 66,062 to 99,668 and the outstanding amount of credit locked up with them increased from Rs. 2,793 crores to Rs. 3,805 crores.

Outlook for Industrial Growth during 1986-87

40. As indicated earlier the successful implementation of the Seventh Plan depends crucially on the performance of the industrial sector for which an average annual growth rate of 8 per cent has been envisaged. The Government has announced a series of measures aimed at removing the constraints hitherto faced by the industrial sector in achieving a high rate of investment. The impact of these measures by way of increased output may perhaps take some more time to materialize. Import of technology and of capital goods has been facilitated with a view to modernising industry and increasing its competitiveness. Further, during the last two years, the industrial sector has not had the benefits of a high rate of agricultural growth. An improvement in agricultural production in 1986-87 should help achieve a better growth rate in industrial production. According to current expectations the monsoon this year has been favourable and a step up in agricultural production is likely to be achieved. A good monsoon will also help generate more hydel power. It might therefore be reasonable to expect a higher rate of industrial growth in 1986-87 than that of 6.3 per cent recorded in 1985-86.

National Income, Saving and Investment

41. The rate of growth in GNP in real terms is estimated to be slightly higher at around 4 per cent in 1985-86 as compared with 3.7 per cent in 1984-85. In 1985-86 agricultural production is estimated to have recorded a slight rise of one per cent over the previous year whereas it had declined by 0.9 per cent in 1984-85. The growth rate in industrial production at 6.3 per cent was, on the other hand, somewhat lower than that in 1984-85. Aggregate net domestic saving has been provisionally estimated at 16.1 per cent of NNP at current market prices in 1985-86, which is almost the same as in the previous two years. Net saving of the household sector as percentage of NNP which had increased from 14.1 per cent in 1983-84 to 14.5 per cent in 1984-85, is estimated to have risen further to 14.9 per cent in 1985-86. The public sector's saving as percentage of NNP which had declined from 1.8 per cent in 1983-84 to 1.1 per cent in 1984-85 is estimated to have declined further to 0.6 per cent in 1985-86. The net saving of the domestic private corporate sector which had increased from 0.4 per cent of NNP in 1983-84 to 0.6 per cent in 1984-85 is estimated at the same level in 1985-86.

42. Provisional data indicate an increase in the rate of aggregate net investment from 17.5 per cent of NNP at current market prices during 1984-85 to 18.1 per cent in 1985-86. The data relating to estimated net domestic saving and investment as percentage of NNP are provided in Table 4.

43. Even though as mentioned earlier, the household sector's saving as proportion of NNP is estimated to have increased in 1985-86, the proportion of saving in the form of financial assets to NNP recorded a marginal decline. On the other hand, saving in the form of physical assets which had declined from 6.2 per cent of NNP in 1983-84 to 5.2 per cent in 1984-85 is estimated to have gone up to 5.7 per cent in 1985-86.

TABLE 4—ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT

(At current market prices)

(In percentages)

Sector/Item	Fiscal Years		
	1983-84	1984-85 (Provisional)	1985-86 (Quick Estimates)
1. Net household sector's saving to NNP	14.1	14.5	14.9
Of which :			
Saving in financial assets	7.9	9.3	9.2
2. Net public sector's saving to NNP	1.8	1.1	0.6
3. Net domestic private corporate sector's saving to NNP	0.4	0.6	0.6
4. Total net domestic saving to NNP (1+2+3)	16.3	16.2	16.1
5. Inflow of foreign resources to NNP	1.7	1.3	2.0
6. Aggregate net investment to NNP (4+5)	18.0	17.5	18.1

Note :—The net ratios for 1983-84 and 1984-85 differ from those given in the previous year's Annual Report because of the substantial revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of further data.

44. The saving of households in the form of financial assets which had spurted from 7.9 per cent of NNP in 1983-84 to 9.3 per cent in 1984-85 is estimated to have declined marginally to 9.2 per cent in 1985-86. However, the rise in saving in the form of financial assets in absolute term was of the order of Rs. 1,829 crores. The estimated marginal decline in the proportion of saving in financial assets of the household sector to NNP was mainly on account of the relatively lower saving in the form of currency and bank deposits, a sharply reduced rate of currency expansion has resulted in the fall in saving in the form of currency from 1.5 per cent of NNP in 1984-85 to 1.0 per cent in 1985-86. Even though the aggregate deposits of commercial banks (excluding FCNR and NR(E) deposits) increased by Rs. 11,243 crores in 1985-86 as compared with Rs. 10,892 crores in 1984-85, the growth rate has declined from 18.8 per cent in 1984-85 to 16.4 per cent in 1985-86. Accordingly, as a proportion of financial saving, the household sector's saving in the form of bank deposits declined from 42.7 per cent in 1984-85 to 41.4 per cent in 1985-86 reflecting the attractiveness of non-bank saving media, particularly small savings. Saving of the household sector in the form of bank deposits works out to 4.8 per cent of estimated NNP in 1985-86 as compared with 5.1 per cent in 1984-85.

45. Claims on Government are, however, estimated to have shown a rise from 1.5 per cent of NNP in 1984-85 to 1.9 per cent in 1985-86. Deposits with non-banking companies are also expected to show a rise from 0.5 per cent of NNP in 1984-85 to 0.6 per cent in 1985-86. The liabilities of the household sector which had declined from 2.9 per cent of NNP in 1983-84 to 2.6 per cent in 1984-85 are estimated to have dropped further to 2.4 per cent in 1985-86.

46. The public sector's saving is expected to decline further from 1.1 per cent of NNP in 1984-85 to 0.6 per cent in 1985-86 due mainly to dissaving of the Central Government. It may be added that while estimating the public sector's saving, the surplus funds of oil companies transferred to the Oil Co-ordination Committee are not included, as in the past years, and therefore, there is some underestimation of the level of public sector's saving.

47. The net inflow of foreign resources which had decreased from 1.7 per cent of NNP in 1983-84 to 1.3 per cent in 1984-85 is estimated to have risen to 2.0 per cent in 1985-86. Consequently, aggregate net investment as percentage of NNP is estimated to have moved up from 17.5 per cent in 1984-85 to 18.1 per cent in 1985-86.

DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY

Main Features of Policy

48. Moderation of the rate of growth of overall liquidity (M3) in the economy continued to be the main objective of credit policy during 1985-86 and the early part of the fiscal 1986 GI/86—18

year 1986-87. In view of the large increase in the volume of reserve money and overall liquidity during the past three years it was considered essential to continue the cautious credit policy in order to avoid a resurgence of inflation. It was, therefore, decided to contain the overall growth in liquidity in 1985-86 to a rate lower than that in 1984-85. Unlike in the previous three years when the raising of reserve requirements was the key element of macro monetary management, in 1985-86 there were no increases in reserve requirement, other than the increase in the Statutory Liquidity Ratio (SLR) announced in March 1985 which was implemented in two phase by July 1985. Reserve requirements, however, continued to remain a major instrument of policy but the emphasis was on effective maintenance of the SLR on a daily basis; with this end in view, penalties were introduced for defaults in SLR. A detailed review of the Credit Authorisation Scheme (CAS) was also undertaken and taking into account the increase over time in the volume and size of financial transactions, certain changes were made in respect of the cut-off point for working capital limits for manufacturer, trader exporter and the discretionary powers of banks to sanction ad hoc limits. Changes were also made in the 'fast track' scheme and the regulation of transfer of large borrowal accounts from one bank to another in order to impart greater flexibility in the operation of schemes without dilution of financial discipline. Furthermore, selective credit controls were rationalised and interest rates on term deposits of one year and above under the Foreign Currency (Non-Resident) (FCNR) Scheme were revised downwards in line with trends in interest rates abroad. Overall, the recent policy responses were more in the nature of rationalisation of measures and the stress was on more effective implementation of existing measures.

Change in the Concept of the Budget Deficit and Monetary Targeting

49. The Chakravarty Committee had recommended that the definition of the budget deficit should be altered to net Reserve Bank credit to Government as this would better reflect the monetisation of the budgetary deficit. This recommendation of the Committee has been accepted by the Government and the modalities of a phased change in the concept of the budgetary deficit are being worked out. Against this backdrop, banks were advised to eschew volatile movements in their cash balances with the Reserve Bank and in their holdings of treasury bills as these movements generate instability in net Reserve Bank credit to Government. Banks were advised that the facility of averaging the cash reserve requirement (CRR) was meant to provide some flexibility to banks in their cash management but this facility should not be used to generate large fluctuations in cash balances. Another recommendation of the Chakravarty Committee which has been accepted by the Government relates to the introduction of monetary targeting. This will

imply that policy responses both fiscal and monetary will be related more closely to movements in the monetary aggregates.

Policy Measures—April 1985

50. The first half of 1985-86 was to be a period for the banking system to conserve its resources and to rectify any shortfalls in the maintenance of reserve requirements. Banks were required to ensure that in this period there was an effective and smooth transition to the adequate maintenance of the SLR on a daily basis. In view of the need to contain growth of overall liquidity and to meet the likely credit requirements in the first half of 1985-86, certain policy measures were announced in April 1985. Upward adjustments were made in the threshold levels over which 100 per cent refinance is provided to banks for food procurement credit and the refinance rates which had remained unchanged for a number of years were also appropriately aligned. The selective credit controls which had, over the years, become far too complex and needed some rationalisation without departing from the central objective of preventing bank credit from being utilised for speculative hoarding of essential commodities were simplified. Multiplicity of prescriptions for certain commodities was reduced and controls which were felt to be no longer necessary were abolished.

Policy Measures July, 1985

51. Following the coming into force of the provisions of the Banking Laws (Amendment) Act, 1986 with effect from March 29, 1985, penalties were prescribed for daily shortfall in the maintenance of the statutory liquidity ratio. The penal interest on the amount of the daily shortfall is 3 per cent above Bank rate or 5 per cent above Bank rate, depending on the duration for which the shortfall continues.

52. Credit budget discussions with major scheduled commercial banks and the monitoring of the daily maintenance of SLR in the early months of 1985-86 revealed that a number of banks had large shortfalls and were facing heavy penalties from March 30, 1985 onwards. A strict implementation of the provisions could have resulted in a sudden disruption of certain vital credit operations. With a view to giving banks some more time to rectify these shortfalls and to ensure the continued flow of credit for meeting the genuine productive needs of the economy, a comprehensive scheme of phased introduction of penalties on SLR shortfalls was devised. The key elements of the scheme were as follows:

- (i) A general waiver of penalties was granted on daily SLR shortfalls upto September 13, 1985. Effective September 14, 1985 penalties were imposed on the daily SLR shortfalls.
- (ii) From September 14, 1985, requests for waiver of penalties were favourably considered in the case of daily shortfalls upto 4 per cent of the amount of the SLR required to be maintained. Banks already maintaining SLR or having very small shortfalls were not allowed to relapse into shortfalls to take advantage of this concession. Banks were advised to undertake advance planning of their operations with the clear understanding that this band of

waiver would be gradually reduced and eventually extinguished.

- (iii) Daily shortfalls in excess of the 4 per cent band were considered as the daily defaults subject to the levy of penal interest. Furthermore, of the amount of the defaults so determined, only a stipulated portion was subject to penal interest charges. The proportion of daily defaults subject to penal interest in the phased programme which was 25 per cent effective September 14, 1985, was raised to 50 per cent effective October 26, 1985, to 75 per cent effective April 26, 1986 to 100 per cent effective June 21, 1986.

53. Upto March 29, 1985, an additional interest of 3 per cent was being charged on the portion of refinance accommodation from the Reserve Bank equivalent to the shortfall in the statutory liquidity and cash reserve ratios. Taking into account the phased introduction of penalties on the daily maintenance of SLR, the following changes were made:

- (i) The additional interest charge of 3 per cent on the portion of refinance equivalent to the average CRR shortfall was imposed only on alternate Fridays between March 30, 1985 and September 13, 1985. With effect from September 14, 1985, the additional 3 per cent interest charge was imposed on the portion of refinance equivalent to the average CRR shortfall on each day of the fortnight during which there was a CRR shortfall.
- (ii) In the case of SLR shortfalls, during the phased introduction of penalties, between March 30, 1985 and June 20, 1986, there would be no additional interest charge on refinance. With effect from June 21, 1986, the additional interest charge of 3 per cent would be imposed on each day on the portion of refinance from the Reserve Bank equivalent to the daily SLR shortfalls.

Policy Measures—Non-Resident Deposit Rates

54. In the context of a noticeable decline in interest rates abroad, particularly in the United States, interest rates on term deposits of one year and above under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme were revised downwards with effect from August 22, 1985. Prior to this date, the rates for such non-resident deposits were 2 percentage points higher than those prescribed for domestic deposits. In February 1986 these rates were further lowered taking into account the developments abroad. On a review in May 1986, these rates were once again lowered in the context of a decline in interest rates abroad particularly those on US dollar deposits. It was also specified that effective May 5, 1986, deposits under FCNR Scheme should not be accepted for maturity of above 3 years. The interest rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts, however, were kept unchanged at two percentage points above the rates for domestic deposits. The changes in the rates for FCNR and NRE deposits are set out below:

INTEREST RATES ON NON-RESIDENT DEPOSITS

(Per cent per annum)

Maturity	FCNR Rates				NRE Rates
	Effective	Effective	Effective	Effective	Effective
	April	August	February	May	April
	8, 1985	22, 1985	10, 1986	5, 1986	8, 1985
1 year and above but below 2 years	10.5	9.5	9.5	8.5	10.5
2 years and above but below 3 years	11.0	10.5	10.0	9.0	11.0
3 years and above but below 5 years	12.0	11.0	10.5	10.0*	12.0
5 years and above	13.0*	12.0*	11.00*		13.0

*FCNR deposits can be accepted at this rate only for 3 years' maturity.

**FCNR deposits can be accepted at these rates only for 5 years' maturity.

Policy Measures—October, 1985

55. Taking into account the developments during the first half of 1985-86 and an assessment of the likely credit requirements in the second half of 1985-86, which roughly corresponds with the busy season, the following measures were announced on October 25, 1985.

Release of Impounded Cash Balances

56. Schedule commercial banks were required to maintain additional cash reserves of 10 per cent of the incremental net demand and time liabilities accruing between January 14, 1977 and October 31, 1980. Except for the release of one-fifth of these balances in October-December 1984, these balances have remained impounded. Since it was expected that banks would be faced with increased credit requirements during the busy season it was decided to release one-third of these cash balances on October 26, 1985. Since the impounded cash balances amounted to Rs. 1,487 crores, an amount of approximately Rs. 495 crores was released.

SLR on NRE Accounts

57. Foreign Currency Non-Resident Accounts attracted a lower statutory liquidity ratio of 25 per cent while Non-Resident (External) Rupee Accounts were subject to the normal stipulation of statutory liquidity ratio of 37 per cent. Effective October 26, 1985, the statutory liquidity ratio for NRE accounts was reduced from 37 per cent to 25 per cent. This reduced the SLR requirements of banks by about Rs. 360 crores.

Export Refinance

58. Banks were being provided export refinance at an interest rate of 10 per cent per annum and the limits for such refinance were equivalent to 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of credit in 1983. With effect from November 22, 1985, banks were provided export refinance to the extent of 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level for 1984. The bringing forward of the base for export refinance is a normal annual feature and although banks' export refinance access is initially reduced, the experience in the past has been that access to refinance is quickly regained as banks expand export credit. A stimulus is thus provided to larger export credit.

Interest Rate on Banks Cash Balance held with the Reserve Bank

59. Effective October 26, 1985, the rate of interest payable on eligible cash balances maintained with the Reserve Bank, was raised from 10 per cent to 10.5 per cent per annum (cash balances held under the 3 per cent statutory minimum cash reserve requirement are, under law not entitled to receive interest). The increase in the rate of interest on cash balances was expected to enable banks to adequately cover the cost of funds and to increase their reserves.

Discretionary Refinance

60. Banks had been provided a little over Rs. 230 crores of discretionary refinance to enable them to tide over short term liquidity problems. With the release of a part of the impounded cash balances and the reduction of the SLR on NRE Accounts, the banks' liquidity increased by Rs. 855 crores on October 26, 1985 and the loss of export refinance limits of about Rs. 380 crores was felt only from November 22, 1985. Banks were advised to use the additional resources which became available to them to repay the entire discretionary refinance outstanding and also to make up any shortfalls in the maintenance of SLR beyond the band of 4 per cent of the amount of SLR required to be maintained.

Rationalisation of Selective-Credit Controls

61. The process of rationalisation of selective credit controls undertaken in April 1985 was carried forward and some exemptions and concessions were announced effective from October 26, 1985 in response to the commodity balances and developments in prices. The prescriptions on minimum lending rates, stipulations on levels of credit, prohibitions on grant of credit against book debts and clean credit were not altered in respect of items which continued to be subject to these controls. The details of changes are provided in Part II of this Report.

62. Banks were advised that in the case of commodities exempt from selective credit controls, normal inventory norms, prescription of margins by the banks and observance of credit norms and discipline must be enforced to ensure that credit was not utilised for speculative build-up of inventories. In cases where high margins were being somewhat moderated, the relevant items continued to be maintained within the purview of selective credit controls, and the levels of credit ceilings, where applicable, were not altered.

Monetary and Banking Outlook for 1986-87

63. A review of credit policy was undertaken in April 1986. It was noted that mainly as a result of the various policy measures adopted, there was a slowdown in the rate of expansion of overall liquidity (M3) in 1985-86. A notable achievement was the perceptible deceleration in the rate of inflation. Even though at that stage it was not possible to predict the developments for 1986-87 it was assumed that with an average monsoon and favourable industrial climate, the overall rate of growth of the economy in 1986-87 would be somewhat higher than in 1985-86 and could be around 5 per cent. Another factor to be reckoned in the formulation of credit policy for 1986-87 was that although the growth of overall liquidity in 1985-86 was lower than that in the previous year, a disconcerting development was that the growth of reserve money in 1985-86 was substantially higher than that in 1984-85 with potential impact on money supply. Furthermore, the annual average rate of growth of money supply (M3) in the past three years had been 17.4 per cent. In the interest of containing the inflationary pressures, it was considered necessary to regulate the rate of growth of M3 in 1986-87 to a level below the average for the previous three years.

64. Consistent with the desired objective of a slowdown in the overall growth of liquidity, a reasonable working estimate for deposit growth in 1986-87 for scheduled commercial banks was put at Rs. 15,000 crores (17.6 per cent). It was estimated that the growth of deposits would be approximately equal during each of the two halves of the year. With a deposit growth of Rs. 7,500 crores in the first half of 1986-87, banks were expected to have adequate resources to meet the credit requirements out of their own resources and also substantially build back their liquidity. The banks were expected to require some food refinance only to smoothen the sharp upswing in food credit in the quarter April-June, 1986.

65. The rabi 1986 output was expected to be good and with a large procurement on the anvil, banks were advised to plan for an increase in food credit of about Rs. 1,200 crores between the end of March and the end of June 1986 and thereafter for a decline of Rs. 900 crores in the quarter ending September 1986. As is the establishment practice, banks were to ensure that the credit requirements for public food procurement were fully met. It was expected that scheduled commercial banks would be able to provide for an increase in bank credit of Rs. 2,300 crores in the first half of 1986-87 (Rs. 300 crores for food and Rs. 2,000 crores for non-food). Even after providing for these credit requirements banks would be able to build adequate liquidity in the first half of 1986-87.

66. Apart from ensuring that the needs of food procurement were fully met, the objective of policy was that all productive activity contributing to increase output could be provided finance by banks and that too out of their own resources. The first half of the year would also be a period of consolidation for the banks and they were advised to rectify shortfalls, if any, in the maintenance of reserve requirements.

Effective date

Band of waiver
(Shortfall as a percentage of amount
of SLR required to be maintained)

July 19, 1986	3
August 16, 1986	2
September 13, 1986	1
October 11, 1986	0

68. The concession of not imposing the 3 percentage point additional interest charge on refinance from the Reserve Bank equivalent to the SLR shortfall was extended from June 21, 1986 to October 10, 1986. Effective October 11, 1986, the additional interest charge of 3 percentage points would be imposed on a daily basis on the portion of refinance from the Reserve Bank equivalent to the amount of the daily SLR shortfall.

69. Some banks which were defaulting in SLR beyond the 4 per cent band of waiver were advised to give unquestioned primacy to maintenance of reserve requirements.

Selective Credit Controls

70. The rationalisation of selective credit controls undertaken in April and October 1985 was carried further and a few more exemptions and relaxations were announced with effect from April 4, 1986, details of which are provided in part II.

Changes in the CAS

71. On a detailed review of the Credit Authorisation Scheme and taking into account the increase over time in the volume and size of financial transactions, certain changes were made in the scheme. The more important of them are the following:—The cut-off point for working capital limits for manufacturer and trader exporters was raised to a uniform Rs. 7 crores as against earlier differential cut-off points of Rs. 5 crores for manufacturer-exporters and Rs. 4 crores for trader-exporters. The cut-off point of CAS working capital limits for others was raised from Rs. 4 crores to Rs. 6 crores. The discretionary powers of banks were enlarged to enable sanction of additional limits temporarily for periods not exceeding 3 months upto 10 per cent of the existing working capital limit and/or 25 per cent of the existing packing credit limit subject to an overall ceiling of Rs. 2 crores as against the previous ceiling of Rs. 75 lakhs. The cut-off point for cases of working capital limits which

Policy Measures—April 1986 : Statutory Liquidity Ratio-Band of Waiver

67. The following package of measures was announced on April 3, 1986. In July 1985, when the scheme of phased introduction of penalties on SLR defaults was announced it was indicated that there would be a gradual phasing out of the SLR band of waiver and accordingly the following phased reduction of the 4 per cent band of waiver for SLR was prescribed :

banks have to report for post-sanction scrutiny was raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores. For statistical purposes, however, banks are required to continue to submit information on sanctions of Rs. 1 crore and above on a quarterly basis. Also, certain relaxations were made in the criteria for eligibility for the fast track facility the details of which are provided in Part II.

Transfer of Borrowal Accounts

72. On a review, the restraints on transfers of borrowal accounts from one bank to another were modified. The requirement that a transferee bank should seek consent of the transferor bank for the take-over of borrowal accounts has been dispensed with for borrowal accounts with limits upto Rs. 5 crores, subject to certain stipulations; the limit had been raised earlier from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore in July 1985. An important condition was that all liabilities including contingent liabilities of the borrower would have to be taken over by the transferee bank.

TRENDS IN MONEY, CREDIT AND PRICES

Money Supply

73. Monetary expansion during the financial year 1985-86 (on last Friday of March basis) decelerated rather sharply. The rate of expansion in narrow money (M_1) at 9.7 per cent was less than one-half of the rate of 19.9 per cent recorded in 1984-85. The increase by Rs. 3,827 crores in absolute terms was also appreciably smaller than the rise of Rs. 6,583 crores recorded in 1984-85. Broad money (M_2) also displayed a similar trend expanding at a lower rate of 15.7 per cent than that of 18.7 per cent in 1984-85. In absolute terms, the expansion of Rs. 16,003 crores was marginally lower than that of Rs. 16,058 crores witnessed in the previous year (Table 5). Considered in terms of averages of fortnights the growth rates showed a similar trend M_1 decelerating from 18.2 per cent in 1984-85 to 14.1 per cent and M_2 from 18.0 per cent to 17.0 per cent.

TABLE 5—VARIATION IN MONEY STOCK(M_2)

(Rs. crores)

	Variations During**							
	1984-85		1985-86		1985-86 (April-June)		1986-87 (April-June)	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. M_2 (a+b+c)	+16,058	+18.7	+16,003	+15.7	+6527	+6.4	+7606	+6.4
(a) Currency with the public	+3111	+15.9	+2452	+10.8	+1263	+5.6	+1503	+6.0

TABLE 5—VARIATIONS IN MONEY STOCK(M3)(Concl'd.)

(Rs. crores)

	1	2	3	4	5	6	7	8
(b) Aggregate Deposits with banks (i+ii)	+12,662	+19.2	+13,896	+17.7	+5382	+6.8	+6245	+6.7
(i) Demand Deposits	+3187	+24.2	+1720	+10.5	+1208	+7.4	+1250	+6.9
(ii) Time Deposits	+9475	+17.9	+12,176	+19.5	+4174	+6.7	+4995	+6.7
(c) Other Deposits with RBI	+285	+89.6	-345	-50.2	-118	-19.6	-142	-55.0
II. M ₁ (a+b(i)+c)	+6583	+19.9	+3829	+9.7	+2353	+5.9	+2611	+6.0
III. Sources of Money Stock (M ₁) (1+2+3+4+5)								
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	+8445	+20.8	+9531	+19.5	+5510	+11.3	+6794	+11.6
A. RBI's net credit to Government (i+ii)	+3149	+11.8	+9127	+30.7	+6693	+22.5	+4880	+12.5
(i) Claims on Government (a+b)	+8321	+31.0	+3881	+11.0	+1343	+3.8	+4767	+12.2
(a) Central Government	+7808	+30.5	+5639	+16.9	+2785	+8.3	+4767	+12.2
(b) State Governments	+513	+41.2	-1758	-100.0	-1442	-82.0	—	—
(ii) Government Deposits with RBI (a+b)	+5102	+2044.3	-5246	-96.7	-5350	-98.6	-113	-63.1
(a) Central Government	+5173	+2085.9	-5261	-97.0	-5361	-98.9	-109	-68.1
(b) State Governments	—1	-20.0	+15	+375.0	+11	+275.0	-4	-21.1
B. Other banks' credit to Government	+5296	+38.2	+404	+2.1	-1183	-6.2	+1914	+9.8
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	+10,809	+18.0	+10,509	+14.8	+2196	+3.1	+1688	+2.1
A. RBI's credit to commercial sector*	+389	+16.4	+301	+10.9	-32	-1.2	-17	-0.6
B. Other banks' credit to commercial sector (i+ii+iii)	+10,420	+18.1	+10,208	+15.0	+2228	+3.3	+1705	+2.2
(i) Bank Credit by commercial banks	+7660	+18.5	+6965	+14.2	+1969	+4.0	+1109	+2.0
(ii) Bank Credit by co-operative banks	+1013	+12.7	+1136	+12.6	-88	-1.0	-64	-0.6
(iii) Investments by commercial and co-operative banks in other securities	+1747	+21.0	+2107	+20.9	-347	+3.4	+660	+5.4
3. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector (A+B)	+1419	+89.8	+299	+10.0	-389	-13.0	+247	+7.5
A. RBI's net foreign exchange assets (i+ii)	+1420	+87.4	+299	+9.8	-389	-12.8	+247	+7.4
(i) Gross foreign assets	+1484	+25.9	+54	+0.7	-453	-6.3	+179	+2.5
(ii) Non-monetary foreign liabilities	+64	+1.6	-245	-5.9	-64	-1.5	-68	-1.7
B. Other bank's net foreign exchange assets	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Government's Currency Liabilities to the Public	+57	+7.9	+99	+12.7	+22	+2.8	—	—
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	+4672	+27.6	+4435	+20.6	+812	+3.8	+1123	+4.3
A. Net non-monetary liabilities of RBI	+2581	+50.6	+2984	+38.8	+497	+6.5	+692	+6.5
B. Net non-monetary liabilities of other banks	+2091	+17.7	+1451	+10.5	+315	+2.3	+431	+2.8

*Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

**Based on last Friday of March/month data.

Notes: 1. Data are provisional.

2. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

74. Of the two major components of M_3 , currency with the public expanded by Rs. 2,452 crores or by 10.8 per cent which was markedly lower than Rs. 3,111 crores or 15.9 per cent in the preceding year; as a result, the ratio of currency in incremental M_3 came down from 0.19 in 1984-85 to 0.15 in 1985-86.

75. The incremental currency— M_3 ratio which had mostly fluctuated between 0.21 and 0.23 between 1978-79 and

1983-84 has been on the decline in the subsequent period, perhaps as a corrective to earlier high rises. The average currency— M_3 ratio displayed persistent decline from 0.26 in 1978-79 to 0.21 in 1985-86. Reflecting a steep decline in the growth rate of demand deposit component of M_1 in 1985-86 the share of currency in incremental M_3 improved perceptibly to 64 per cent from 47 per cent in the previous year (Table 6).

TABLE 6—MONETARY RATIOS

Year	Average Ratios				Incremental Ratios			
	C	C	AD	TD	C	C	AD	TD
	M_1	M_3	M_3	M_3	M_1	M_3	M_3	M_3
1978-79	0.59	0.26	0.74	0.57	0.55	0.23	0.75	0.59
1979-80	0.59	0.25	0.74	0.57	0.55	0.21	0.76	0.61
1980-81	0.58	0.24	0.75	0.58	0.56	0.21	0.80	0.63
1981-82	0.59	0.23	0.77	0.60	0.64	0.15	0.88	0.77
1982-83	0.58	0.23	0.77	0.61	0.57	0.21	0.79	0.64
1983-84	0.59	0.23	0.77	0.62	0.64	0.22	0.77	0.65
1984-85	0.57	0.22	0.77	0.61	0.47	0.19	0.79	0.59
1985-86	0.58	0.21	0.78	0.63	0.64	0.15	0.87	0.76

C = Currency

AD = Aggregate Deposits

TD = Time Deposits

76. Aggregate deposits, the most important component of M_3 showed a larger increase of Rs. 13,896 crores in absolute amount, but the rate of growth came down to 17.7 per cent in 1985-86 from 19.2 per cent in the previous year. The decline in the rate of increase is attributable to demand deposits, the rise in which was of a considerably lower order of Rs. 1,720 crores than that of Rs. 3,187 crores recorded in 1984-85—an increase which was the highest witnessed during the past six years. Accretion to time deposits, on the other hand, was at an accelerated pace both in absolute and relative terms, with the growth rate moving up from 17.9 per cent in 1984-85 to 19.5 per cent in 1985-86. Consequently, incremental aggregate deposits formed about 87 per cent of the incremental M_3 in 1985-86 as against 79 per cent in 1984-85. The share of incremental time deposits alone shot up from 59 per cent to 76 per cent.

77. It is difficult to explain fully the factors that contributed to the sharp declaration in currency and demand deposits in 1985-86 at this stage. However, the decline in food credit, relative price stability, the greater attractiveness of financial assets, measures to check the growth of black money and the relatively smaller accruals to foreign exchange assets, all seem to have contributed to the decline in the holdings of currency by the public.

78. An analysis of sources of change in M_3 indicates that the lower order of expansion in bank credit to commercial sector and a sharp fall in the accrual to net foreign exchange assets were the major factors which helped to bring about a slowdown in monetary expansion. Bank credit to commercial sector expanded by Rs. 10,509 crores, lower by Rs. 300 crores than the increase in 1984-85. Of this, the increase in Reserve Bank credit to commercial sector at Rs. 301 crores was Rs. 88 crores lower than that in 1984-85. The lower order of expansion in other banks' credit is attributable to the fall in food credit to the extent of Rs. 71 crores in contrast to a rise of Rs. 1,643 crores in 1984-85. The expansion in non-food credit extended by commercial and cooperative banks at Rs. 8,172 crores during the year was

larger than the figure of Rs. 7,030 crores in 1984-85. The expansionary impact of foreign exchange assets of the banking sector was for less significant in 1985-86: the accruals were only Rs. 299 crores as against Rs. 1,419 crores in 1984-85. In respect of net bank credit to Government the expansion during 1985-86 was more pronounced at Rs. 9,531 crores; in 1984-85 it was lower at Rs. 8,445 crores. The higher expansion in RBI credit to Government amounting to Rs. 9,127 crores was entirely on account of borrowings by the Central Government as the credit to State Governments declined by Rs. 1,773 crores.

79. During the first quarter of the fiscal year 1986-87, the growth rate in M_3 remained unchanged at 6.4 per cent though, in absolute terms, it showed a larger increase. The expansion in M_1 was higher both in absolute and percentage terms. Larger increases were recorded both in currency with the public and time deposits with banks. Sourcewise, a sizeably smaller rise in bank credit to commercial sector was more than neutralised by a sharper rise in net bank credit to Government. Net foreign exchange assets of the banking sector recorded a rise, though modest, in contrast to a fall in the same period of the preceding year.

Reserve Money

80. In 1985-86, reserve money rose sizeably by Rs. 6,323 crores or 20.1 per cent on a point to point basis which was more than double the increase of Rs. 2,653 crores (9.2 per cent) in the previous year. Of its components, bankers' deposits with RBI showed a faster expansion and accounted for a major share in the incremental reserve money (Table 7). These deposits which comprise the statutory and excess reserves maintained by banks increased considerably by Rs. 4,140 crores in contrast to a decline of Rs. 891 crores last year. The faster rate of expansion in reserve money was mainly brought about by net RBI credit to Government which expanded by Rs. 9,127 crores, nearly thrice as much as the rise of Rs. 3,149 crores in 1984-85.

TABLE 7—RESERVE MONEY VARIATIONS—COMPONENTS AND SOURCES

(Rs. crores)

	Variations during							
	1984-85		1985-86		1985-86 (April-June)		1986-87 (April-June)*	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
RESERVE MONEY (1+2+3+4)	+2,653	+19.2	+6,323	+20.1	+5,641	+17.9	+3,683	+9.7
1. Currency with the public	+3,111	+15.9	+2,452	+10.8	+1,263	+5.6	+1,503	+6.0
2. Other deposits with RBI	+285	+89.6	—345	57.2	—118	—19.6	+142	—55.0
3. Cash with banks	+148	+14.0	+76	+6.3	+445	+37.0	+352	+27.5
4. Bankers' deposits with RBI	—891	—11.3	+4,140	+59.1	+4,051	+57.8	+1,970	+17.7
SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3+4+5—6)								
1. Net RBI credit to Government	+3,149	+11.8	+9,127	+30.7	+6,693	+22.5	+4,880	+12.5
2. RBI claims on commercial and co-operative banks**	+218	+8.4	—519	—18.5	—156	—5.6	—735	—32.2
3. RBI-credit to commercial sector	+389	+16.4	+301	+10.9	—32	—1.2	—17	—0.6
4. Net foreign exchange assets of RBI	+1,420	+87.4	+299	+9.8	—389	—12.8	+247	+7.4
5. Government's currency liabilities to the public	+57	+7.9	+99	+12.7	+22	+2.8	—	—
6. Net non-monetary liabilities of RBI	+2,581	+50.6	+2,984	+38.8	+497	+6.5	+692	+6.5

* Provisional

** Including NABARD.

Note : Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

81. The reason for the sizeable expansion in reserve money is partially statistical in the sense that the increase on a point-to-point basis has been over a lower base figure of March 1985, which resulted from large increase in Central Government deposits in that week. In contrast, the annual average fortnightly figures of reserve money showed a lower growth rate of 13.6 per cent during the year as against 19.3 per cent in 1984-85. Perhaps from the annual flows angle it is the average figure which is analytically more meaningful, particularly in the context of the volatility in reserve money. Such volatility in recent months has been due to involuntary excess of cash balances maintained by banks with RBI. In such an eventuality the resource base of banks on which secondary expansion of credit generally takes place itself shrinks and thereby the relationship between reserve money and monetary expansion is affected. In addition, allowance has to be made for the lags in reserve money creation and its eventual impact on monetary expansion.

82. During the first quarter of the fiscal year 1986-87 reserve money growth was lower at Rs. 3,683 crores than that of Rs. 5,641 crores in the same period of 1985-86. This was due mainly to a lower order of expansion in bankers' deposits with RBI, which at Rs. 1,970 crores was less than half the increase of Rs. 4,051 crores in the same quarter of

the previous year. The declaration in reserve money growth during the quarter was due in a large measure to the smaller expansion in net Reserve Bank credit to Government of Rs. 4,880 crores as compared with Rs. 6,693 crores.

Banking Variables

83. The year 1985-86 witnessed deceleration in rates of growth of deposits, bank credit and investments of scheduled commercial banks. The growth rate of 18.1 per cent in aggregate deposits of scheduled commercial banks was lower, as compared with 19.2 per cent in the preceding year, although in absolute terms the increase was higher at Rs. 13,044 crores than that of Rs. 11,648 crores in 1984-85 (Table 8). Although national income growth was marginally higher than that in 1984-85, the rate of inflation was appreciably lower and this explains in part the lower deposit growth in nominal terms. The expansion in bank credit at Rs. 6,963 crores or 14.2 per cent was lower both in absolute and percentage terms than that of Rs. 7,659 crores or 18.5 per cent in the previous year. While food credit registered a decline of Rs. 71 crores, in sharp contrast to an increase of Rs. 1,643 crores in 1984-85, non-food credit recorded a larger increase of Rs. 7,034 crores or 16.2 per cent compared with that of Rs. 6,016 crores or 16.1 per cent in the previous year.

TABLE 8—VARIATIONS IN IMPORTANT BANKING INDICATORS
(Scheduled Commercial Banks)

Items	(Amount outstanding as on)			Variations during the Financial Year		Quarterly variations	
	March 29, 1985	March 28, 1986*	June 27, 1986*	1984-85	1985-86	1985 (April-June)	1986 (April-June)
	1	2	3	4	5	6	7
Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI & NABARD)	81885	96828	102939	+13435	+14943	+5700	+6111
Aggregate Deposits	72244	85288	91454	+11648 (+19.2)	+13044 (+18.1)	+4831 (+6.7)	+6166 (+7.2)
Borrowings from RBI	1558	954	544	+222	—604	+305	+410
Bank Credit	48953	55916	57025	+7659 (+18.5)	+6963 (+14.2)	+1968 (+4.0)	+1109 (+2.0)
Food Credit	5665	5594	6439	+1643	—71	+1100	+845
Non-food Credit	43288	50322	50586	+6016 (+16.1)	+7034 (+16.2)	+868 (+2.0)	+264 (+0.5)
Investments (a+b)	28138	30536	33081	+6892 (+32.4)	+2398 (+8.5)	—886 (—3.1)	+2545 (+8.3)
(a) Government Securities	18697	19013	20898	+5223 (+38.8)	+316 (+1.7)	—1230 (—6.6)	+1885 (+9.9)
(b) Other approved securities	9441	11523	12183	+1669 (+21.5)	+2082 (+22.1)	+344 (+3.6)	+660 (+5.7)
Cash in hand	1044	1113	1464	+116	+69	+375	+351
Balances with RBI	6884	11053	12940	+899 (+11.6)	+4169 (+60.6)	+4002 (+58.1)	+1887 (+17.1)
Credit-Deposit Ratio (%)	67.8	65.6	62.4				
Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	59.9	59.0	55.3				

* Partially Revised.

Notes: 1. Since bills rediscounted under the Bills Rediscounting Scheme are nil, gross bank credit is the same as bank credit.

2. Figures in brackets are percentage variations.

84. Data on sectoral distribution of credit show that the rise in credit to industry was Rs. 4,436 crores in 1985-86 as against an increase of Rs. 2,483 crores in the previous year. This sharp increase has to be seen in the context of a lower growth in industrial output during 1985-86 of 6.3 per cent as compared with 6.8 per cent in the previous year and of a lower rise of 5.7 per cent in wholesale price index of a weekly average basis than that of 7.1 per cent in the previous year. Whereas non-food gross bank credit rose by 17.3 per cent in 1985-86 as compared with 16.2 per cent in the preceding year, credit to industry (small, medium and large) rose by 19.7 per cent as against 12.4 per cent in the same period of the previous year. Industry-wise distribution of credit shows that a higher proportion of incremental credit went to non-traditional industries such as engineering and chemicals. It also indicates that in respect of most industrial groups credit extended in 1985-86 was larger than in 1984-85. These data would show that credit needs of the industrial sector as a whole, appear to have been met adequately during the year.

85. The growth in banks investments at Rs. 2,398 crores or 8.5 per cent formed about one third of the expansion of Rs. 6,892 crores recorded in 1984-85. Whereas the expansion in 1984-85 was partly due to the stepping of the SLR by one percentage point, the smaller expansion in investment during the year has taken place despite a smaller increase in SLR in 1985-86. Banks, however, seem to have compensated for the lower holdings of gilt-edged securities by building up larger cash balances with the Reserve Bank which recorded a jump of Rs. 4,169 crores as against a decline of Rs. 899 crores in 1984-85. Borrowings from the Reserve Bank recorded a decline of Rs. 604 crores in contrast to an increase of Rs. 222 crores in the previous year.

86. During the first quarter of the current financial year, deposit growth at Rs. 6,166 crores (7.2 per cent) was larger

than that of Rs. 4,831 crores (6.7 per cent) in the corresponding quarter of the previous year. The expansion in bank credit at Rs. 1,109 crores (2.0 per cent) was however less than the increase of Rs. 1,968 crores (4.0 per cent) in the same period a year ago. Both food and non-food credit recorded increases of Rs. 845 crores and Rs. 264 crores which were of a perceptibly lower order than that of Rs. 1,100 crores and Rs. 868 crores, respectively, in the corresponding period of the previous year. Bank's investment increased substantially by Rs. 2,545 crores (8.3 per cent) in contrast to a decline of Rs. 886 crores (—3.1 per cent) during the same period of the previous year. To some extent, the larger increase in the first quarter of 1986-87 may reflect attempts of banks to make up for SLR deficiencies.

Sectoral Development of Credit

87. An outline of the direction of flow of credit in the financial years 1985-86 and 1984-85 is presented in Table 9 on sectoral deployment of credit. These data which relate to 50 scheduled commercial banks accounting for about 95 per cent of gross bank credit show that during 1985-86 the expansion in gross bank credit at Rs. 7,255 crores (15.1 per cent) was lower than that of Rs. 7,335 crores (18.6 per cent) during 1984-85. This deceleration was brought about by a decline of Rs. 71 crores in credit for food procurement in contrast to an increase of Rs. 1,643 crores in the preceding year. Non-food gross bank credit, however, showed a larger expansion of Rs. 7,326 crores (17.3 per cent) than that of Rs. 5,892 crores (16.2 per cent) during the previous year; the increase in 1985-86 was mainly due to larger extension of credit to medium and large industry while in the previous year the expansion was largely the result of credit extended to priority sectors.

TABLE 9—DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT BY MAJOR SECTORS*

Sector	Outstanding (As on last Friday)			Variations (Financial Years)	
	March 1984	March 1985	March 1986	1984-85	1985-86
	1	2	3	4	5
I. Gross Bank Credit (1+2)	40421	47956	55211	7535	7255
1. Public Food Procurement Credit	4022	5665	5594	1643	—71
2. Non-Food Gross Bank Credit (A+B+C+D)	36399	42291	49617	5892	7326
(A) Priority Sectors	14899	18409	21584	3510	3175
(i) Agriculture	6144	7660	9071	1516	1411
(ii) Small-scale industries	5447	6512	7808	1165	1196
(iii) Other priority sectors	3308	4137	4705	829	568
(B) Industry (medium & large)	14621	15939	19179	1318	3249
(C) Wholesale Trade (Other than food procurement)	2343	2649	3048	305	399
(i) Cotton Corporation of India	193	103	160	—90	57
(ii) Food Corporation of India for fertiliser distribution	241	166	127	—75	—39
(iii) Jute Corporation of India	49	116	141	67	25
(iv) Other Trade	1860	2264	2620	404	356
(D) Other Sectors	4536	5294	5806	753	512
II. Export Credit (including under item (2))	2041	2335	2409	294	74

*Provisional.

Notes: 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of gross bank credit. Further these gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, Exim Bank and other approved financial institution and participation certificates.

2. Figures in brackets are proportions to non-food incremental credit.

88. Bank credit to priority sectors constituted 40.9 per cent of net bank credit as at the end of March 1986 and thus exceeded the target of 40 per cent. It recorded an expansion of Rs. 3,175 crores during 1985-86 and formed 43.3 per cent of total incremental non-food gross bank credit in 1985-86. Of the rise in advances to the priority sectors, agriculture and small-scale industries accounted for Rs. 1,141 crores (44.4 per cent) and Rs. 1,196 crores (37.7 per cent) respectively, as compared with increases of Rs. 1516 crores (43.2 per cent) and Rs. 1165 crores (33.2 per cent) in the previous years. At the end of March 1986, the amount of outstanding advances to agriculture stood at Rs. 9,071 crores as compared with Rs. 7,660 crores a year ago; its proportion to total priority sector advances increased marginally by 0.4 percentage point to 42.0 per cent over the year. Advances to small-scale industries at Rs. 7,808 crores accounted for 36.2 per cent of the total advances to priority sectors as against 35.9 per cent a year ago. Advances to other priority sectors, which include weaker sections, small transport operators, self-employed persons and rural artisans, rose to Rs. 4,705 crores and formed 21.8 per cent of total priority sector

1086 GI/86—19

advances in March, 1986. Outstanding credit to medium and large industry including public sector enterprises amounted to Rs. 10,179 crores at the end of March 1986 as against Rs. 15,939 crores a year earlier. Aggregate advances to industry, i.e. small-scale, medium and large industry taken together, rose by Rs. 4,436 crores during 1985-86 and accounted for 60.6 per cent of the non-food incremental credit. This marks a notable improvement over the previous year's figures of Rs. 2,483 crores and 42.1 per cent.

89. The industry-wise (inclusive of small-scale industry) distribution of bank credit is presented in Table 10. Industries which accounted for a major part of the growth in credit during 1985-86 were the engineering group (Rs. 1,153 crores), chemicals group (Rs. 821 crores), residual industries (Rs. 1,136 crores), cotton textiles (Rs. 326 crores), petroleum (Rs. 301 crores), other textiles (Rs. 269 crores) and other metals and metal products (Rs. 139 crores). Large declines were observed in respect of iron and steel (Rs. 163 crores) and SAFAUNS (Rs. 50 crores).

TABLE 10—INDUSTRY-WISE DEPLOYMENT OF GROSS BANK CREDIT

Industry	(Rs. crores)				
	Outstanding (As on last Friday)			Variations (Financial Years)	
	March 1984	March 1985	March 1986	1984-85	1985-86
	1	2	3	4	5
Industry (Total of small-scale, medium and large scale)	20068	22551	26987	2483	4436
1. Coal	147	119	93	—28	—26
2. Iron and steel	1594	1430	1267	—164	—163
3. Other Metals and metal products	670	801	940	131	139
4. All engineering	4815	5560	6713	745	1153
5. Electricity (generation & transmission)	303	415	493	112	78
6. Cotton textiles	1644	1860	2195	225	326
7. Jute textiles	211	263	277	52	14
8. Other textiles	1192	1365	1634	173	269
9. Sugar	590	423	533	—171	110
10. Tea	247	205	321	43	26
11. Vegetable oils (including vanaspathi)	265	311	341	46	30
12. Tobacco and tobacco products	169	159	184	—10	25
13. Paper and paper products	486	596	654	110	68
14. Rubber and rubber products	390	434	456	44	22
15. Chemicals, dyes, paints, etc. Of which: Fertilisers	2088 (397)	235 (361)	3146 (700)	237 (—36)	821 (339)
16. Cement	237	282	353	45	71
17. Leather and leather products	267	323	383	56	65
18. Construction	216	265	285	49	21
19. Petroleum	374	72	373	—302	301
20. SAFAUNS**	368	376	326	8	—50
21. Residual	3786	4863	5909	1077	1136

* Provisional.

** Ships acquired from abroad under the new scheme.

90. Advances to wholesale trade (other than food procurement) recorded a larger increase of Rs. 399 crores during 1985-86 than that of Rs. 306 crores in the previous year. Credit to 'other sectors' which represent residual sectors and include advances to financial institutions, hire purchase agencies, leasing companies and personal loans registered a smaller increase of Rs. 512 crores during 1985-86 as compared with an increase of Rs. 758 crores in 1984-85.

91. The developments in utilisation of various refinance facilities are set out below :

Food Credit Refinance

92. As on the last reporting Friday of June 1985 the bank's food credit refinance limits amounted to Rs. 2,100

crores of which only Rs. 742 crores or 35.3 per cent was utilised (Table 11). Food credit refinance limits reached the peak level of Rs. 2,150 crores as on July 5, 1985. The peak outstanding amounting to Rs. 1,306 crores (64.4 per cent of the limits) was reached on July 26, 1985. The proportion of limits utilised reached a peak of 89.5 per cent on September 20, 1985. The limits came down steeply after July 1985 due to the increase in food credit refinance threshold effected in three phases from Rs. 4600 crores to Rs. 5,800 crores during August-September 1985 combined with the decline in the outstanding level of food credit. As on the last reporting Friday of June 1986, scheduled commercial banks were eligible for food credit refinance limits to the extent of Rs. 736 crores and the amount outstanding against these limits was Rs. 34 crores.

TABLE 11—RBI ACCOMMODATION TO SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(Excluding special refinance against shipping loans and duty drawback)

(Rs. crores)

As on last reporting Friday	Food Credit Refinance		Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		Total Refinance	
	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUNE 1985	2099.8	742.4	653.5	173.7	—	—	—	—	2753.3	916.1
SEPTEMBER 1985	47.4	225.4	562.5	258.4	10.0	—	50.0	50.0	659.9	553.8
DECEMBER 1985	159.7	—	208.9	127.3	30.0	—	22.3	—	420.9	127.3
MARCH 1986	—	—	339.3	252.7	50.0	40.0	393.0	336.5	787.3	629.2
JUNE 1986	736.1	33.6	510.4	63.6	—	—	45.0	1.0	1292.5	103.2

Export Credit Refinance

93. The banks export credit refinance limits reached a peak of Rs. 640 crores on July 5, 1985. The peak level outstanding during the year was Rs. 439 crores as on July 12, 1985 when 70.5 per cent of the limits were utilised. The limits came down during December 1985 and January 1986 following the change in the base year from 1983 to 1984. The limits started rising thereafter and as on the last reporting Friday of June 1986, the bank's export credit refinance limits amounted to Rs. 510 crores of which Rs. 69 crores or 13.4 per cent was utilised; the comparable position as at the end of June 1985 was limits of Rs. 654 crores and utilisation of Rs. 174 crores i.e. a utilisation rate of 26.6 per cent.

Stand-by Refinance Limits

94. The amount of stand by refinance limits sanctioned to banks as on the last reporting Friday of June 1985 and June 1986 was nil. The maximum amount of stand-by refinance limits sanctioned to banks was Rs. 50 crores as on the last reporting Friday of March 1986 and the amount outstanding against these limits was Rs. 40 crores.

Discretionary Refinance Limits

95. During 1985-86 (July—June) banks were provided substantial discretionary refinance accommodation. The limits started increasing from the end of September 1985 and reached a level of Rs. 233 crores as on October 25, 1985 when some banks were sanctioned discretionary refinance limits to enable them to adjust to increase in food credit refinance threshold. The limits were reduced substantially thereafter but reached a peak level of Rs. 430 crores as on April 11, 1986. The usual seasonal pressure on liquidity of banks at the end of March 1986 was accentuated in the current year. The peak outstanding of Rs. 337 crores was reached on March 28, 1986 when 84.5 per cent of limits were utilised. As on the last reporting Friday of June 1986, the amount of discretionary refinance limits sanctioned to banks amounted to Rs. 46 crores and the amount outstanding was Rs. 1 crore.

Overall Position

96. The total of limits available under various Reserve Bank refinance facilities to scheduled commercial banks

(excluding special refinance against shipping loans and duty drawback) which stood at Rs. 2,753 crores as on the last reporting Friday of June 1985 declined gradually during 1985-86. As on June 20, 1986 the limits amounted to Rs. 1,293 crores which was equivalent to 1.45 per cent of the aggregate deposits of scheduled commercial banks.

Credit Budgets

97. During the year under review, the credit budgets for the year 1985-86 were discussed with each of the major scheduled commercial banks. The banks were advised to plan their lending operations out of their own resources with a view to ensuring smooth adjustment to the phased increase in the threshold for food refinance. The banks were specifically advised to ensure that adequate provision was made in their credit budgets for maintenance of reserve requirements and their attention was drawn to the fact that with the coming into force of the amendments to Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, penalties would become applicable on the daily defaults in the maintenance of the statutory liquidity ratio. Banks were also advised to avoid large deviations between the projections of the key variables in the credit budget and their actual outturn. In November 1985, the banks were advised to revise their credit budgets taking into account changes in policy. A second round of discussions was held in February 1986 with a few scheduled commercial banks which were persistent defaulters in the daily maintenance of SLR.

98. After the announcement of the credit policy for the first half of 1986-87 on April 3, 1986, banks were advised to prepare their credit budgets for 1986-87 (April-March) and discussions were held in June 1986 with the major scheduled commercial banks.

Price Situation

99. There was a perceptible abatement of inflationary pressure during 1985-86. Continuing the deceleration for the third year in succession wholesale prices rose, on a point-to-point basis, by 3.8 per cent as compared with 7.6 per cent in 1984-85 and 8.9 per cent in 1983-84 (Table 12). On weekly average basis also the price index rose at a lower pace of 5.7 per cent as compared to 7.1 per cent in the previous year. A deceleration of this order was rendered possible by prudent demand and supply management.

TABLE 12—EXTENT OF PRICE RISE AND WEIGHTED CONTRIBUTION OF MAJOR COMMODITY GROUPS TO THE RISE IN WHOLESALE PRICES INDEX

(1970-71 = 100)

	Weight	Wholesale Price Indices					Variations in per cent				Weighted Contribution			
	End-March	End-March	End-March	End-June	End-June	End-June	Fiscal Year		First Quarter		Fiscal Year		First Quarter	
		1984	1985	1986	1985	1986	1984-	1985-	1985-	1986-	1984-	1985-	1985-	1986-
							85	86	86	87*	85	86	86	87
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
All commodities	1000.00	321.7	346.3	359.3	358.6	372.5	+7.6	+3.8	+3.6	+3.7	100.0	100.0	100.0	100.0
Primary Articles	416.67	308.1	321.6	330.7	335.4	343.5	+4.4	+2.8	+4.3	+3.9	+22.9	+29.0	+46.8	+40.6
Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	508.6	559.2	609.2	568.7	614.8	+9.9	+8.9	+1.7	+0.9	+17.5	+32.4	+6.5	+3.7
Manufactured Products	498.74	301.4	330.8	340.9	342.3	355.6	+9.8	+3.1	+3.5	+4.3	+59.6	+33.6	+46.7	+55.7

*Provisional.

100. In line with the seasonal pattern, three distinct phases in the price movements during 1985-86 could be clearly identified, as can be seen from the data provided in Table 13. As in the previous year, the first four months spanning April to July 1985 witnessed a continuous and

sharp increase in the general index of wholesale prices which moved up by 5.4 per cent; the rise in the corresponding period of 1984-85 was sharper at 7.2 per cent. There was a decline of 2.5 per cent during August-November 1985, followed by a small increase of 1.0 per cent in the last four months of the year.

TABLE 13—THREE PHASES OF VARIATIONS IN WHOLESALE PRICES INDEX

(In percentages)

	Weight in per cent	1985-86					1984-85				
		End-March to End-July	End-July to End-November	End-November to End-March	End-March to End-July	End-July to End-November	End-March to End-July	End-July to End-November	End-November to End-March	End-March to End-July	End-July to End-November
		to	to	to	to	to	to	to	to	to	to
		July	Novem-ber	March	July	Novem-ber	July	Novem-ber	March	July	Novem-ber
All Commodities	100	+5.4	+2.5	+1.0	+3.8	+7.2	-1.5	+1.9	+7.6		
Primary Articles	42	+6.6	-4.2	+0.7	+2.8	+9.7	-4.1	-0.8	+4.4		
Fuel, Power, Light and Lubricants	8	+1.7	+2.4	+4.6	+8.9	+1.4	+0.9	+7.4	+9.9		
Manufactured Products	50	+5.4	-2.5	+0.2	+3.1	+6.8	—	+2.7	+9.8		

101. Though the increase in the general index as also in the indices of all the three major groups has shown a welcome deceleration, an analysis of price movements of individual commodities reveals some disturbing trends; this is clear from the data in Table 14. Of the primary articles, both rice and wheat recorded steep increases as against a small decline and a marginal rise respectively in the previous year. Other commodity groups which showed sharp increases were fruits and vegetables; 21.8 per cent against 11.1 per cent, coal; 13.8 per cent against a static position last year and sugar; 23.2 per cent against 7.0 per cent. Some of the important commodities/groups which recorded lower order of increases or larger declines than in the previous year are pulses, tea, fibres, raw cotton, gur, textiles, paper and paper products and cement. The decline in the sub-group fibres (-36.9 per cent) under primary articles and textiles (-7.9 per cent) under manufactured products was

particularly sharp and it is this element which was responsible for slowing down the rate of increase in the general index. Within the fibres group, prices of raw jute, hemp and mesta with a weight of about 0.6 per cent in the general index showed a fall of 70 per cent in 1985-86. Again, in the textiles group, jute, hemp and mesta textiles having a weight of about 1.2 per cent recorded a decline of 43 per cent during the year. Assuming that the price index for this sub-group had remained unchanged between March 1985 and March 1986, the general index as at the end of March 1986 would work out to 363.6 instead of 359.3 thus giving a percentage rise of 5.0 during 1985-86 on a point-to-point basis. The corresponding percentage rise in 1984-85 works out to 6.9

TABLE 14 : VARIATIONS IN INDEX NUMBERS OF WHOLE SALE PRICES
(1970-71 = 100)

Major Groups/Groups/Sub-Groups/Commodities	Weight	Percentage variations during financial years (Point-to-point)			
		1984-85	1985-86	1985-86 (April-June)	1986-87* (April-June)
	1	2	3	4	5
All Commodities	1000.00	+ 7.6	+ 3.8	+ 3.6	+ 3.7
I. Primary Articles	416.67	+ 4.4	+ 2.8	+ 4.3	+ 3.9
Food articles	297.99	+ 5.8	+ 7.8	+ 7.7	+ 4.5
(a) Cereals	107.43	+ 0.2	+ 11.9	+ 4.0	- 1.6
(i) Rice	51.31	- 0.8	+ 4.7	+ 6.3	+ 4.6
(ii) Wheat	34.17	+ 1.6	+16.4	- 0.9	- 8.3
(b) Pulses	21.79	+14.9	+ 4.0	+ 0.3	- 9.5
(c) Fruits and vegetables	61.32	+ 11.1	+ 21.8	+ 22.3	+14.9
(d) Milk and milk products	61.50	+ 1.4	+ 2.4	+ 3.9	+ 3.6
(e) Other food articles	16.04	- 1.0	- 21.3	+ 0.3	+ 20.9
Tea	11.49	- 7.0	- 23.9	- 1.2	+22.1
Non-food articles	106.21	+ 1.9	- 9.7	- 3.5	+ 3.3
(a) Fibres	31.73	+ 14.6	- 36.9	-12.0	- 5.4
Raw cotton	22.46	- 4.6	- 25.2	- 5.2	- 7.8
(b) Oil seeds	42.01	- 5.7	- 4.1	- 3.8	+14.6
Minerals	12.47	+ 1.4	+ 0.6	+ 0.5	-
Petroleum, crude and natural gas	6.02	+ 0.7	-	-	-
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	- 9.9	+ 8.9	+ 1.7	+ 0.9
Coal	10.39	-	+13.8	-	- 3
Mineral oils	49.12	+12.8	+ 2.7	-	-
III. (Manufactured Products)	498.74	+ 9.8	+ 3.1	+ 3.5	+ 4.3
Sugar, khandasari and gur	72.41	+13.3	+ 9.9	+17.5	+13.3
(i) Sugar	21.91	+ 7.0	+23.2	+14.3	- 4.2
(ii) Gur	45.58	+14.7	+ 4.8	+18.1	+21.1
(iii) Khandasari	4.92	+21.4	+21.7	+22.0	- 1.0
Edible oils	37.16	- 2.0	- 0.3	- 7.8	+15.0
Textiles	110.26	+ 8.6	- 7.9	- 1.5	+ 1.7
Paper and paper products	8.51	+11.2	+ 3.9	-	-
Cement	7.03	+15.7	- 6.0	+ 3.3	-
Chemicals and chemical products	55.48	+ 6.7	+ 5.1	+ 1.5	+ 0.6
Iron, steel and ferro alloys	34.73	+27.7	+ 1.1	+ 0.7	+ 0.2

* Provisional

102. Considering the fact that contrary to the trend in the general index the prices of some of the essential commodities which figure prominently in the daily consumption basket have actually accelerated during the year, it would be more pertinent to analyse the trend in a 'general price index' based on a group of such commodities. If the indices of 24 commodity/sub-groups consisting of such articles commanding a total weightage of 57.5 per cent in the general index are considered separately and an adjusted 'wholesale price index' is worked out, the rise in the price index works out to 7.5 per cent as compared with 6.1 per cent in 1984-85. This trend seems to correspond with the trend in the consumer price index which recorded a rise, on a point-to-point basis, of 8.9 per cent as compared with 5.0 per cent in the previous year. On an average basis, however, the rise of 6.4 per cent in consumer price index was of the same magnitude as in 1984-85.

103. Data on weighted contribution of commodity groups as well as important commodities within each group to the increase in general price index are presented in Table 15. The major group 'fuel, power, light and lubricants', contributed to the extent of 32.4 per cent to the rise in general price level as compared with 17.5 per cent in 1984-85. The increase was mainly on account of higher contribution of electricity. The weighted contribution of primary articles at 29.0 per cent was 6.1 percentage points higher than that in 1984-85. Whereas contribution of commodities like cereals and fruits and vegetables recorded marked increase, that of fibres and other food articles turned negative in a perceptible manner. The contribution of oilseeds has been negative for the second year in succession. There was a notable fall in the share of manufactured products in price increase from about 60 per cent to 39 per cent which was mainly brought about by jute textiles, dairy products, edible oils and cotton textiles.

TABLE 15 --INDEX NUMBER OF WHOLESALE PRICES:
TRENDS IN WEIGHTED CONTRIBUTIONS OF COMMODITY GROUPS

	Weight	1984-85	1985-86
All-commodities	1000.00	100.0	100.0
I. Primary Articles	416.67	22.9	29.0
1. Cereals	107.43	0.2	24.0
2. Pulses	21.79	4.9	2.8
3. Fruits and vegetables	61.32	7.7	31.6
4. Milk and milk products	61.50	1.0	3.0
5. Eggs, fish, and meat	18.97	5.0	7.1
6. Other food articles	16.04	-0.3	-11.2
7. Oilseeds	42.01	-3.0	-3.8
8. Fibres	31.73	4.9	-26.8
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	17.5	32.4
9. Coal mining	11.47	0.1	7.4
10. Mineral oils	49.12	13.7	6.1
11. Electricity	24.00	3.6	19.1
III. Manufactured Products	498.74	59.6	38.6
12. Dairy products	3.88	1.0	Neg.
13. Grain mill products	4.64	-0.7	0.5
14. Bakery products	1.85	0.2	0.2
15. Sugar, confectionery, etc.	0.53	—	0.1
16. Sugar, khandsari and gur	72.41	11.8	18.8
17. Edible oils	37.16	-0.9	-0.3
18. Tobacco manufactured	19.49	0.6	12.5
19. Cotton textiles	81.02	4.1	-1.0
20. Jute, hemp and mesta textiles	12.14	3.4	-16.2
21. Footwear and leather products	0.90	0.1	0.5
22. Transport equipments	16.73	1.7	6.4

Note: Weighted contributions are as percentages to 'All Commodities'.

104. A series of upward revisions in administered prices were made during the year, the details of which are provided later. Taking into account only the direct effect on general price level it is estimated that the weighted contribution of changes in administered prices to the rise in wholesale price index was 35.7 per cent in 1985-86 as compared with 37.3 per cent in 1984-85.

105. Thus while it remains true that wholesale prices showed a deceleration in 1985-86, this phenomenon co-exists with the higher rate of rise in prices of some essential commodities. This disaggregated analysis has important implications for future price policy, especially if the objective of macro-economic policy is to protect the average man from inflationary forces.

106. The price increase during the first quarter of the current financial year at 3.7 per cent on a point-to-point basis was marginally higher than that of 3.6 per cent in the corresponding quarter of the previous year. The impetus for the higher increase was provided by manufactured products which rose by 4.3 per cent during the first quarter of the current financial year as compared with 3.5 per cent in the first quarter of 1985-86. Both primary articles and fuel, power, light and lubricants showed smaller increases of 3.9 per cent and 0.9 per cent respectively as compared with 4.3 per cent and 1.7 per cent. Among the commodities that triggered the price increase during the period are edible oils which rose by 15.0 per cent in contrast to a decline of 7.8 per cent and oilseeds which rose by 14.6 per cent in contrast to a fall of 3.8 per cent. As against those, there was a decline of 1.6 per cent in cereals as opposed to an increase of 4.0 per cent and a fall of 9.5 per cent in pulses as against a small increase of 0.3 per cent. The rise in the sugar sub-group at 13.3 per cent in the first quarter of the current financial year was less than that of 17.5 per cent in the corresponding quarter of the preceding year.

107. During the first quarter of the current financial year viz., April—June 1986 the consumer price index (CPI) for industrial workers rose by 3.1 per cent as against 3.4 per

cent during the corresponding period of 1985-86. On an average basis, however, the increase of 8.4 per cent was higher by 2.2 percentage points than the increase during the corresponding period of 1985-86.

Changes in Administered Prices

108. With the multiple objectives of covering up cost escalations, promoting production, reducing the magnitude of subsidies, curtailing the consumption rate of certain commodities and strengthening mobilisation of resources for financing development plans, a series of changes were made in the administered prices of various commodities during the year.

109. The minimum support prices for Kharif oilseeds for the marketing year October 1985-September 1986 were announced on September 27, 1985. These were Rs. 350 per quintal for groundnut, Rs. 250 for soyabean (black), Rs. 275 for soyabean (yellow) and Rs. 335 for sunflower seed, representing an increase of Rs. 10 a quintal over the prices fixed for the 1984-85 marketing year for each of these oilseeds. These price increases have to be seen against the basic objective of giving a boost to production of oilseeds.

110. Procurement prices of paddy and coarse grains and minimum support prices of moong, urad and tur for the marketing year 1985-86 were announced on October 8, 1985. The procurement price of paddy was raised at a uniform rate of Rs. 5 to Rs. 142, Rs. 146 and Rs. 150 a quintal for common, fine and superfine varieties, respectively. The procurement price of coarse grains was retained at the previous year's level of Rs. 130 a quintal. The minimum support prices of moong, urad and tur were fixed at Rs. 300 a quintal each representing a rise of Rs. 25 over the levels for the marketing year 1984-85. The issue prices of common, fine and superfine varieties of rice were uniformly raised by Rs. 9 to Rs. 217, Rs. 229 and Rs. 244 a quintal effective October 10, 1985 and further by Rs. 14 to Rs. 231, Rs. 243 and Rs. 258 per quintal, respectively, from February 1, 1986. In January 1986, the Union Government announced procurement prices of wheat and minimum support prices for barley, gram and rapeseed/mustard for the marketing

year 1986-87. The procurement price of wheat was raised by Rs. 5 to Rs. 162 a quintal. The minimum support price of barley was raised by Rs. 2 to Rs. 132 a quintal and that of gram by Rs. 20 to Rs. 260 a quintal. The minimum support price of rapeseed/mustard was fixed at Rs. 400 a quintal representing an increase of Rs. 15. The issue price of wheat was raised effective February 1, 1986 by Rs. 18 to Rs. 190 a quintal for both the public distribution system (PDS) and roller flour mills; in the case of the latter it was raised further to Rs. 220 a quintal from April 1, 1986.

111. The Government announced on November 11, 1985 an increase of Rs. 15 a quintal in the minimum support price for the medium and superior medium groups of cotton for the 1985-86 marketing year. Consequently, the minimum support price for F-414 and H-777 varieties of cotton was fixed at Rs. 425 a quintal; for H-4 variety (i.e. superior long staple), it was kept unchanged at the previous season's level of Rs. 535 a quintal. The statutory minimum price for W-5 grade of jute in Assam was raised by Rs. 10 to Rs. 225 a quintal for the 1986-87 marketing year.

112. Consequent on the increase in the statutory minimum price of sugarcane to Rs. 16.50 a quintal for the 1985-86 season and Rs. 17.00 a quintal for the 1986-87 season linked to the basic recovery of 8.5 per cent announced in November 1985, the issue price of levy sugar was increased by Rs. 0.40 to Rs. 4.80 a kg., effective December 1, 1985.

113. Effective November 15, 1985, the Government increased the issue price of imported edible oils for both DPS and vanaspati industry. The retail price of vanaspati also was raised. The issue price of imported edible oils to States for PDS was stepped up by Rs. 1,000 to Rs. 9,000 a tonne for bulk supplies and to Rs. 10,500 a tonne for supplies in tins. The price of imported oils supplied to the vanaspati industry was hiked by Rs. 2,000 to Rs. 11,500 a tonne. The retail price of vanaspati was raised from Rs. 318 to Rs. 345 for 20 kg. tin, from Rs. 16.70 to Rs. 18.05 for 1 kg. pouch and from Rs. 8.60 to Rs. 9.30 for a half kg. pouch reflecting the increase in the issue prices of imported edible oils to industry. In January 1986, the voluntary price agreement with the vanaspati industry was terminated.

114. On December 20, 1985, the Government announced an increase in the retention price of aluminium metal by more than Rs. 1,000 a tonne. This would push up the sale price (exclusive of excise) of the commercial grade metal from Rs. 18,405 to Rs. 19,435 a tonne and of electrical conductor grade metal from Rs. 18,505 to Rs. 19,635 a tonne or an average increase of upto 6 per cent. The statutory retail prices of fertilisers were raised from January 31, 1986. The principal fertilisers, viz., urea and diammonium phosphate would now cost Rs. 2,350 and Rs. 3,600 as against their earlier prices of Rs. 2,150 and Rs. 3,350 a tonne, respectively. Effective January 9, 1986 Government increased the average pithead price of coal by Rs. 27 to Rs. 210 a tonne in the case of Coal India and to Rs. 219 a tonne in the case of Singareni Collieries. The increase was necessitated by substantial escalation in the cost of production due to increases in the wage bill, higher depreciation and interest charges, increased cost of stores power, petroleum products and transportation and other factors. The Government announced a hike in the prices of petroleum products ranging between 6 and 23 per cent effective February 1, 1986. The basic price of motor spirit (petrol) per kilolitre was raised by Rs. 500, high speed diesel oil by Rs. 180, kerosene oil by Rs. 225 and aviation turbine fuel (for domestic airlines only) by Rs. 500; cooking gas was made costlier by Rs. 700 per tonne. The reduction per kilolitre which was effective from February 6, 1986 was Rs. 100 for petrol, Rs. 72 for high speed diesel and Rs. 90 for kerosene. For cooking gas the reduction was Rs. 280 a tonne.

115. The ex-godown prices of some of the non-ferrous metals were periodically revised taking into account the price trends in the international markets, appreciation of the dollar value and the country's overall requirements.

GOVERNMENT FINANCES

116. In the fiscal sphere, the highlights of the year 1985-86 were the announcement of a long term fiscal policy which would impart an element of stability to the whole range of fiscal measures, an unprecedented buoyancy in Central

Government revenues, and the persistence, notwithstanding this buoyancy, of the structural problem of the capital budget covering revenue deficit. In regard to States finances, a sizeable devolution of resources from the Centre and effective implementation of the scheme to prevent emergence of overdrafts by the State Governments were the major developments. These are discussed in detail in the following paragraphs.

Long Term Fiscal Policy (LTFP)

117. The Budget for 1985-86 had indicated the Government's intention to formulate a Long Term Fiscal Policy co-terminus with the Seventh Five Year Plan. The Long Term Fiscal Policy (LTFP) which was announced in December 1985, aims at creating an environment conducive to rapid growth in production and employment, so that the burden of poverty can be progressively reduced. One of the elements of LTFP is to increase the share of direct taxes in total tax revenue over time and take measure to curb evasion so that the fiscal system as a whole becomes even more progressive. It also seeks to assist in the endeavour to make the incidence of the indirect tax system progressive, both through low tax rates on essential commodities and through subsidised distribution of foodgrains, edible oils and sugar through the public distribution system. It proposes to take a hard look at the structure of taxes and assess the directions in which the country must move forward with reforms to further the basic objectives of growth and social justice while at the same time ensuring that there is no significant revenue loss. Yet another aim is to control the pace of implementation of reforms with a view to taking into account possible dislocations to the existing structure of production, which has evolved in response to past economic policies. Given the high priority of keeping inflation under firm control, non-inflationary financing of the Plan will require progressively more reliance on surpluses generated by the budget and public sector undertakings and correspondingly diminished recourse to borrowed funds. This is an essential component of the LTFP.

Union Budget 1986-87

118. At the 1985-86 rates of taxation the budgetary deficit in 1986-87 is estimated to be Rs. 4,095 crores. Taking into account the proposed tax measures and reliefs a net additional revenue of Rs. 445 crores is expected to accrue of Rs. 3,650 to the Centre leaving an uncovered deficit of Rs. 3.65 crores. This would be lower by Rs. 340 crores or 18.7 per cent than the Revised Estimate (R.E.) of deficit of Rs. 4,490 crores and more by Rs. 334 crores or 10.1 per cent than the Budget Estimate (B.E.) of Rs. 3,316 crores for 1985-86 (the last after taking into account post-budget modifications).

119. While the budget for 1985-86 contained several new features on the side of direct taxes, this year's budget initiated a process of reforms in indirect taxes through the introduction of the Modified Value Added Tax (MODVAT).

120. The income tax rates were left unchanged in accordance with the LTFP. However, for salaried persons the standard deduction was raised from 25 per cent to 30 per cent of salary income and the ceiling was fixed at Rs. 10,000 as against the earlier limit of Rs. 6,000. These concessions would benefit about 3.5 lakh tax payers.

121. The changes made in gift tax included (i) the raising of the basic exemption limit from Rs. 5,000 to Rs. 20,000, (ii) the levying of a flat rate of 30 per cent of the value of the taxable gifts, (iii) the deletion of the provisions relating to the aggregation of gifts and (iv) the withdrawal of certain exemptions like those relating to National Defence Gold Bonds, 1980, gifts to spouses, gifts of policies of insurance, gifts in the course of carrying on a business and gifts to any other person up to a maximum of Rs. 500.

122. In regard to capital gains taxation, the date of determining the cost of acquisition of assets or its fair market value was advanced from 1-1-1964 to 1-4-1974 and a uniform scale of deduction at the rate of 50 per cent was prescribed for long-term capital gains from buildings and lands and 60 per cent for others. The limit for initial deduction was increased from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. Notified bonds issued by the Industrial Development Bank of India and those issued by other notified public sector agencies were

added to the list of investment outlets qualifying for exemption from capital gains taxation under section 54 E of the Income Tax Act. The existing period of one year for purchase of a residential house in cases where the capital gain arose on the sale of an old house was increased to two years. The Government was also empowered with a pre-emptive right to purchase high valued properties which are offered for sale in the market at the price agreed to by the transferor.

123. The surcharge on companies which was largely being deposited with the IDBI would be abolished from the assessment year 1987-88 along with the introduction of the New Funding Scheme. The new scheme, which replaces the Scheme of Investment Allowance, would allow assesses' deduction to the extent of 20 per cent of their profits if it is deposited with the IDBI or utilised for the purchase of plant and machinery. The abolition of sur-tax on Corporate income from the assessment year 1987-88, envisaged in the LTTP, was postponed by one year on revenue considerations. The rationalisation of the provisions relating to depreciation, disallowance of the practice of capitalisation of interest payment after the asset is first put to use and creation of a Venture Fund to promote indigenous technology were the other features of the Budget proposals relating to the corporate sector.

124. The introduction of MODVAT was a major measure to overhaul the system of excise taxation in order to reduce the cascading effect of multi-point excise levies and help in reducing costs and prices to consumers. Liberalisation of the excise exemption scheme for small-scale industry and substantial help to domestic production of edible oils and indigenous capital goods industry are envisaged. The burden of proposals for raising revenue through increase in the excise duty on certain consumer goods was intended to fall on the affluent sections of the society. Measures were proposed for providing incentives for import substitution and export promotion. Proposals were also made to set up a new Mutual Fund as a subsidiary of the Unit Trust of India and to introduce another series of public sector bonds with tax-free return. The acceptance in principle of modifications in the concept of budgetary deficit of the Central Government and the setting up of overall monetary targets as recommended by the Chakarvarty Committee on the Working of the Monetary System elaborated elsewhere in the Report, and the raising of the rate of interest on Provident Funds were among the other major highlights of the budget.

State Budgets 1986-87

125. Of the 22 State budgets for 1986-87, 21 are final budgets passed by the legislatures. The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Act, 1986 was enacted by the Governor of the State on March 25, 1986. At 1985-86 rates of taxation the State budgets reveal a combined deficit of Rs. 587 crores in 1986-87 against a surplus of Rs. 844 crores in 1985-86. However, when allowance is made for additional resource mobilisation (net of concessions) of Rs. 380 crores and the State's share of Rs. 43 crores in the Centre's additional tax collections in 1986-87, the overall deficit gets reduced to Rs. 164 crores.

126. The Budget Estimates of States for 1985-86 had anticipated an overall deficit of Rs. 100 crores after additional resource mobilisation. However, against a deficit of Rs. 1,438 crores in 1984-85 (Accounts) the year ended with a surplus of Rs. 844 crores according to Revised Estimates, even after the exclusion from the capital account of the medium-term loans received by the States from the Centre for the clearance of overdrafts. This transformation in the financial position of the States was due to a substantial transfer of resources from the Centre to the State reflecting partly the impact of the recommendations of the Eighth Finance Commission which raised the level of such transfers. In fact, 1985-86 was the first year when these recommendations were implemented. According to budgets of the States for 1986-87, the net resources transferred to them in 1985-86 were Rs. 17,716 crores (RE) registering a growth of 21 per cent over the Budget Estimate. The States benefited from the higher tax collections of the Centre, larger amounts of loan assistance and increased grants from it.

Consolidated Position : Centre and States : 1986-87

127. Data relating to the combined financial position of the Central and State Governments are presented in Table 16. The combined budgetary deficit of the Centre and the 22 States is expected to be Rs. 3,814 crores in 1986-87 recording a rise of Rs. 168 crores or 4.6 per cent over the Revised Estimates and Rs. 398 crores or 11.6 per cent over the Budget Estimates for 1985-86. (The medium-term loan of Rs. 1,628 crores given by the Centre to the States to clear their overdrafts is excluded from the capital disbursements of the former and the capital receipts of the latter).

TABLE 16—COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS: 1984-85 to 1986-87

Items	(Rs. crores)						
	1984-85	1984-85	1985-86	1985-86		1986-87	
	(Revised Estimates)	(Accounts)	(Budget Estimates)	(Revised Estimates)		(Budget Estimates)*	
				Amount	Percentage variation over the Revised Estimates of the previous year	Amount	Percentage variation over the Budget Estimates of the previous year
	1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	66920	66471	73690	79852	+19.3	85456	+16.0
A. Revenue Receipts	45932	45296	50995	53543	+16.6	58796	+14.3
of which : Tax Receipts	35902	35808	40358	47359	+18.0	47022	+16.5
B. Capital Receipts	20988	21175	22695	26309	+25.3	27160	+19.7
II. Total Disbursements (A+B+C)	72864	71657	77106	83498	+14.6	89270	+15.8
A. Developmental Expenditure (a+b+c)	46698	46265	47525	52990	+13.5	54800	+15.3
(a) Revenue	27929	27676	29735	32632	+16.8	34320	+15.4
(b) Capital	11327	11383	11441	12934	+14.2	13395	+17.1
(c) Loans and Advances	7442	7706	6349	7424	+0.2	7085	+11.6

TABLE 16 — COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS: 1984-85 to 1986-87 (Concl'd.)

	(Rs. crores)						
	1	2	3	4	5	6	7
B. Non-Developmental Expenditure (a+b+c)	23646	23393	27913	28321	+19.8	32442	+16.2
(a) Revenue	21978	21683	25926	26149	+19.0	29851	+15.1
(b) Capital	1308	1374	1652	1750	+33.8	2161	+30.8
(c) Loans and Advances	360	336	335	422	+17.2	430	+28.4
C. Others	2520	1999	1668	2187	-13.2	2028	+21.6
III. Overall Surplus (+) or Deficit (-) (I-II)	-5944	-5186	-3416	-3646		-3814	

Notes: 1. Data in respect of States relate to 21 final budgets and the interim budget for Jammu and Kashmir. Further, the data do not cover Union Territories with legislatures. Figures for Nagaland and Jammu and Kashmir for 1984-85 (Accounts) relate to Revised Estimates.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in the figures of repayments of loans by State Governments to Central Government, given in their respective budgets. Includes effects of budget proposals. Post-budget tax changes are not taken into account.

128. Aggregate receipts of the Centre and the States are expected to reach a level of Rs. 85,456 crores in 1986-87 registering a rise of 16.0 per cent over the Budget Estimates of Rs. 73,690 crores and 7.0 per cent over the Revised Estimates of Rs. 79,852 crores for 1985-86. Their revenue receipts (Rs. 58,296 crores) and capital receipts (Rs. 27,160 crores) will go up in 1986-87 by 14.3 per cent and 19.7 per cent respectively, over the Budget Estimates of the previous year. Following the fiscal reforms initiated last year collection from major Central taxes rose by 22 per cent in 1985-86 (RE) over those in 1984-85 (Accounts) which was the highest increase in a decade. Direct taxes exceeded the Budget Estimates by about 15 per cent. Income tax collections from non-corporate tax payers went up by 36 per cent over the Budget Estimates. Both the Centre and the States benefited from this unprecedented rise in collections. The Centres share of taxes increased by 19 per cent and that of States by 30 per cent over 1984-85 (Accounts). While this buoyancy could continue in 1986-87 also, it may not be as pronounced as in 1985-86. The Central Budget assumes that at 1985-86 rates of taxation, additional gross tax receipts in 1986-87 would be 7.2 per cent higher than those in 1985-86 (RE). There is practically no additional resource mobilisation by the Centre on the direct tax side. Total receipts from direct taxes as a proportion of total tax revenues are expected to decline from 20.2 per cent in 1985-86 (RE) to 19.0 per cent in 1986-87 (BE). In the additional mobilisation of resources of Rs. 467 crores through indirect taxes proposed by the Centre a predominant share (Rs. 407 crores or 87 per cent) is from customs. As a result the net transfer of resources to the States on account of the share in the additional tax efforts is only around Rs. 40 crores.

129. Aggregate disbursements of the Centre and the States are expected to be Rs. 89,270 crores indicating a rise of

Rs. 5,772 crores or 6.9 per cent over the revised estimates and Rs. 12,164 crores or 15.8 per cent over the Budget Estimates for 1985-86. An allocation of Rs. 22,300 crores for the Central Plan for 1986-87 has been made indicating a large increase of Rs. 3,800 crores or 20.5 per cent over the Budget Estimates and Rs. 2,206 crores or 11.0 per cent over the Revised Estimates for 1985-86. In the first two years of the Seventh Plan over 40 per cent of the Seventh Plan outlay would thus be provided for in real terms (at 1984-85 prices). The total Plan outlays for States and Union Territories for 1986-87 have been fixed at Rs. 15,880 crores and Rs. 872 crores, respectively, indicating increases of 21 per cent and 36 per cent, respectively, over the corresponding Revised Estimates for 1985-86. There is a larger percentage increase in the allocations for poverty alleviation programmes in 1986-87.

Market Borrowings

130. During the fiscal year 1985-86, the Central Government entered the market eight times—twice placing an amount of Rs. 500 crores each initially favour of the Reserve Bank of India—and borrowed a gross amount of Rs. 5,764 crores. After providing for a repayment of Rs. 663 crores on loans maturing during the year (including the 3 per cent Non-Terminable Loan 1986-87 which the Government has decided to repay), the net receipts from market borrowings amounted to Rs. 5,101 crores recording a substantial increase of Rs. 1,001 crores or 24.4 per cent over those of the preceding year (Table 17). The gross market borrowing of Rs. 5,764 crores was made up of cash subscription of Rs. 5,554 crores and conversion of Rs. 210 crores. As in the previous two years, the Central Government's net market borrowings were in conformity with the budget estimates.

TABLE 17—MARKET BORROWINGS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS, LOCAL AUTHORITIES AND INSTITUTIONS SPONSORED BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS—1984-85 AND 1985-86 FISCAL YEARS

	(Rs. crores)					
	Gross Market Borrowings		Repayments (Total Maturities)		Net Market Borrowings	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
1. Central Government	4591	5764	491	663	4100	5101
2. State Governments	1301	1414	529	441	772	973
3. Total Government Borrowings (1+2)	5892	7178	1020	1104	4872	6074
4. Institutions sponsored by Central Government	1309	1644	92	177	1217	1467
5. Institutions sponsored by State Governments (Including Local Authorities)	1080	1311	398	569	682	742
6. Total Institutions' Borrowings (4+5)	2389	2955	490	746	1899	2209
7. Aggregate Market Borrowings (3+6)	8281	10133	1510	1850	6771	8283

131. Gross borrowings of the State Governments during 1985-86 amounted to Rs. 1,414 crores of which Rs. 1,189 crores was through cash subscription and the balance of Rs. 225 crores was by way of conversion. The States' net market borrowings of Rs. 973 crores after taking into account the repayment of maturing loans (Rs. 441 crores) were larger by Rs. 201 crores or 26.0 per cent than in the previous year. Gross borrowings during 1985-86 by local authorities and institutions sponsored by Central and State Governments were placed at Rs. 2,955 crores. After the repayment of maturing loans (Rs. 746 crores) their net borrowings amounted to Rs. 2,209 crores showing a rise of Rs. 310 crores or 16.3 per cent over the 1984-85 level. The total net Government borrowings (Centre and States) as a proportion of gross domestic product at current market prices formed 2.5 per cent in 1985-86 as against 2.3 per cent in 1984-85. The net receipts from total Government borrowings financed 18.8 per cent of the Plan outlay in 1985-86 as against 16.0 per cent in 1984-85.

132. Apart from market borrowings discussed above, the Centre and States borrow through other sources such as provident funds and small savings. The net additions to internal debt and other liabilities of the Centre and States in 1985-86 amounted to 10.3 per cent of GDP as against 9.0 per cent in the previous year.

133. During the Sixth Five Year Plan the annual increase in net market borrowings by the Centre was 32.7 per cent, 11.6 per cent, 30.8 per cent, 5.2 per cent and 2.4 per cent in 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 and 1984-85, respectively. As stated earlier, in 1985-86 net market borrowings amounted to Rs. 5,101 crores, a rise of 24.4 per cent over those in 1984-85 and as proportion to GDP worked out to 2.1 per cent. The Central budget for 1986-87 has assumed net market borrowings of Rs. 5,300 crores, a rise of 3.9 per cent over the previous year. On the assumption of a 10 per cent rise in GDP in 1986-87, net market borrowings would form 2.0 per cent of GDP at current market prices as against 1.6 per cent indicated in the Long Term Fiscal Policy based on Seventh Plan projections.

134. During the financial year 1986-87, the Central Government entered the market for the first time on May 12, 1986 with the issue of three loans, viz., 10 per cent Loan, 1991, 10.50 per cent Loan, 1996, and 11.50 per cent Loan, 2006 on a cash-cum-conversion basis and raised an aggregate amount of Rs. 1,320 crores. The Central Government approached the market for the second time on July 14, 1986 with two loans, viz., 10.20 per cent Loan, 1993 and 11.50 per cent Loan, 2006 (second issue) for a notified amount of Rs. 1,200 crores on a cash-cum-conversion basis. With the right to retain 10 per cent excess subscription over the notified amount, the Central Government raised a gross amount of Rs. 1,320 crores from this floatation.

The Government of India's total gross borrowings so far during 1986-87 inclusive of this floatation are Rs. 2,640 crores or 41.6 per cent of the budgeted gross amount for 1986-87.

Coupon Rates on Central Government Loans

135. The conscious policy stance to raise the coupon rates on Central Government loans observed in recent years continued in 1985-86. During 1984-85, long-dated securities with a maturity of 30 years were introduced for the first time with a coupon rate of 10.50 per cent. In 1985-86 similar securities were floated but at a higher coupon rate of 11.50 per cent. An increase of 1.00 to 1.24 percentage points was provided for in the rates on other maturities comparable with those of 1984-85 in keeping with the spirit of the recommendations of the Report of the Chakravarty Committee. In the first tranche of loans floated in 1986-87, the rates on 5 year, 10 year and 20 year loans were fixed at 10.00 per cent, 10.50 per cent and 11.50 per cent, respectively, as against 9.00 per cent, 9.50 per cent and 10.50 per cent, respectively, in 1985-86.

RBI's Support to Central Loans

136. As mentioned in the last year's Annual Report, along with the steady increase in the market borrowing programme of the Central Government, the Reserve Bank's support to the Central Government loans was also increasing over the years with serious implications for reserve money creation and money supply in the economy. Loans taken up by Reserve Bank reached a maximum of 43.1 per cent of the total in 1980-81; this proportion came down to 38.6 per cent in 1981-82 and 25.2 per cent in 1982-83. But it rose to 30.5 per cent in 1983-84 and 35.9 per cent in 1984-85. In 1985-86 however, the proportion came down to 6.4 per cent (Table 18). RBI support to dated securities in 1985-86 was low at Rs. 367.9 crores. This is on the basis of book value. However, on the basis of face value, the RBI's holdings of dated securities would show an increase of Rs. 604.0 crores. The hike in coupon rates and the introduction of a 30-year loan with the highest interest rate till then, viz., 11.5 per cent, referred to earlier, might have assisted in the raising of larger resources from the market. Of the total amount of loans floated, the proportion accounted for by those carrying the highest coupon rate, viz., 11.5 per cent, was 72.4 per cent in 1985-86 as compared with 38.2 per cent in respect of the loan carrying the highest rate of 10.5 per cent in 1984-85. It should be added that the Statutory Liquidity Ratio for banks was raised from 36.0 per cent to 37.0 per cent during 1985-86 alongside stricter enforcement of SLR maintenance on a daily basis. Though RBI support to dated securities in 1985-86 was lower in 1985-86 net RBI credit to Central Government at Rs. 6,469.2 crores in that year was higher than the amount Rs. 6,054.9 crores in 1984-85.

TABLE 18—BUDGETARY DEFICIT, MARKET LOANS AND RBI'S SUPPORT TO MARKET LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT (1983-84 to 1986-87)

Items	(Rs. crores)				
	1983-84 (Accounts)	1984-85 (Accounts)	1985-86 (Budget Estimates)	1985-86 (Revised Estimates)	1986-87(a) (Budget Estimates)
1	2	3	4	5	6
I. Revenue Account					
(a) Revenue	20492.6	24383.7	27116.5	29021.3	31400.2
(b) Expenditure	22890.2	27881.2	32717.8	34961.5	38273.8
(c) Surplus (+)/Deficit (—)	—2397.6	—3497.5	—5601.3	—5940.2	—6873.6

	(Rs. crores)					
	1	2	3	4	5	6
2. Capital Account						
(a) Receipts		15861.0	17768.3	20862.7	23610.5	24896.8
(b) Disbursements		14880.6(b)	18018.6	18577.6	22160.7(c)	21673.0
(c) Surplus (+)/Deficit (—)		+980.4(b)	—250.3	+2285.1	+1449.8(c)	+3223.8
3. Total Receipts [1(a) + 2(a)]		36353.6	42152.0	47979.2	52631.8	56297.0
4. Overall Surplus (+)/Deficit (—)		—1417.2(b)	—3747.8	—3316.2	—4490.4(c)	—3649.8
5. (4) as percent (3)		3.9	8.9	6.9	8.5	6.5
6. Gross Market Loans		4381.7	4583.7	5754.0	5763.0	5350.0
7. (a) as percent of (3)		12.1	10.9	12.0	10.9	11.3
8. RBI's holdings of dated securities (increase)*		1338.1	1644.0	367.9	367.9	
9. (8) as percent of (6)		30.5	35.9	6.4	6.4	

Notes: (a) Includes effects of budget proposals and excludes those of post-budget tax changes.

(b) Excludes Rs. 400 crores of loans given to State Governments to clear their overdrafts as on March 31, 1983.

(c) Excludes Rs. 1,528 crores of medium-term loans given to State Governments on October 1, 1985 under the overdraft regulation scheme.

* On book value basis, according to the records of the RBI.

National Rural Development Bonds (Second Issue)

137. Details of resource mobilisation through bonds, certificates and deposit schemes are given in the following paragraphs. National Rural Development Bonds (Second Issue) were put on tap from July 7, 1983 with a maturity period of 3 years and carrying an interest rate of 7.5 per cent. As in the case of the 7-Year National Rural Development Bonds introduced on July 9, 1979, these bonds were intended to provide an investment facility to persons desirous of availing exemption from capital gains tax on transfer/sale of assets. The Budget for 1986-87 has assumed a receipt of Rs. 20 crores from the sale of the 3-Year bonds. The total outstandings since inception from the sale of 3-Year bonds amounted to Rs. 89 crores, as on June 30, 1986, and of 7-Year Bonds to Rs. 183 crores.

Social Security Certificates

138. Social Security Certificates were introduced on June 1, 1982 to mobilise private savings for public use, especially from small savers. The rate of interest works out to 11.3 per cent per annum (compounded half yearly). The total subscription to Social Security Certificates amounted to Rs. 17.5 crores, as on March 31, 1986.

Capital Investment Bonds

139. Capital Investment Bonds were put on tap from June 28, 1982. These bonds have a maturity period of ten years and carry interest at the rate of 7.0 per cent per annum. The Budget for 1986-87 has taken credit for Rs. 60 crores from the sale of these bonds. The outstanding receipts from the sale of these bonds since inception were Rs. 162.4 crores as on June 30, 1986.

National Deposit Scheme

140. The National Deposit Scheme having broadly the same features of long-term time deposits with banks was introduced on July 30, 1984 for mobilising additional resources for public investment. The deposits under the scheme are for a period of four years and carry interest at 10.50 per cent per annum. These deposits carry exclusive wealth tax and income-tax benefits. Interest from these deposits is eligible for an exemption upto Rs. 2,000 in addition to the exemption upto Rs. 10,000 (inclusive of Rs. 3,000 for income from Unit Trust of India) now available under Section 80L of the Income Tax Act. Besides the consolidated exemption limit of Rs. 5 lakhs in respect of all the assets, an additional

exemption upto Rs. 25,000 from wealth tax is exclusively provided for these deposits. The Budget for 1986-87 has estimated an accrual of Rs. 200 crores from these deposits. The subscriptions to these deposits since inception were placed at Rs. 58.7 crores as on April 18, 1986, as against the target of Rs. 500 crores fixed by the Government over a period of time. The LTFP indicated the outline of a National Deposit Scheme (New Series) for public discussion. The proposal has since been referred to the Study Group on Progressive Taxation of Expenditure for further examination.

National Savings Certificates

141. The Six-Year National Savings Certificates—VI and VII Issues—which have been on tap from May 1, 1981, have become increasingly popular and attractive due to high return and liberal benefits under Income-Tax Act and Wealth Tax Act. Investment in these certificates qualifies for deduction from taxable income along with other financial assets up to a maximum of Rs. 40,000 under Section 80-C of Income Tax Act and interest on these certificates also qualifies for exemption up to Rs. 7,000 along with interest earned on other specified investments under Section 80-L of the Income Tax Act. In addition, wealth tax exemption up to a ceiling of Rs. 5 lakhs along with other specified assets has been provided. The trend of higher collections from the sale of these certificates continued during 1985-86. The total collections during 1985-86 (April—March) amounted to Rs. 3,155 crores as compared with Rs. 2,598 crores in 1984-85.

Overdrafts of State Governments

142. The persistence of overdrafts of State Governments has been commented upon in the previous Reports. With a view to bringing about financial discipline the Centre advised the States on February 4, 1985 to restrict their unauthorised overdrafts in fiscal 1984-85 to the level of Rs. 1,808.83 crores reached on January 28, 1985 by 17 States. The Statewise limits on overdrafts were also fixed at the levels outstanding as on that date. The States were further advised that in case the overdraft exceeded the level already reached on January 28, 1985 and continued for more than seven working days, the Reserve Bank would stop payments in respect of the concerned State. In fact

the Reserve Bank stopped payments of two State Governments in February and April 1985. The level of overdrafts declined to Rs. 947.66 crores on the last working day of March 1985 in respect of 11 States. It had been Rs. 257.57 crores on account of 8 States on March 31, 1984. The outstanding overdrafts which stood at Rs. 351.25 crores in respect of 7 States as on June 27, 1985 were cleared with Central assistance. However, the overdrafts reappeared in July 1985 and reached a peak, for 1985-86, of Rs. 935.74 crores on July 24, 1985 in respect of 9 States. They came down to Rs. 311.25 crores in respect of 5 States at the end of September 1985. Under the scheme evolved for the regulation of overdrafts, on October 1, 1985 the Centre extended medium-term loans of Rs. 1,628.01 crores to 17 States equal to 90 per cent of their overdrafts outstanding as on January 28, 1985. The Centre also advised the State Governments that thereafter they should not have any overdrafts with the Reserve Bank and that in case any overdraft appeared in any State Government account and remained beyond 7 continuous working days the Reserve Bank would stop payments on that account. It is indeed gratifying to record that the States have abided by the requirements of the scheme.

CAPITAL MARKET

Capital Issued and Raised

143. The capital market was quite buoyant during greater part of 1985-86 but experienced a temporary setback after presentation of the Union Budget for 1986-87. New capital issues by non-Government public and private limited companies at Rs. 1,527.9 crores in 1985-86 were higher by 14.3 per cent than the issues of Rs. 1,336.5 crores in 1984-85. Equity issues more than doubled while debenture issues declined by 22.6 per cent. Further, during the year, three public sector companies in the power and telecommunications sector issued bonds for an amount of Rs. 265 crores in terms of the guidelines issued by the Government of India in September 1985.

144. Provisional data indicate that capital raised (paid-up) by non-Government public and private limited companies exclusive of bonus shares during 1985-86 amounted to Rs. 934.5 crores. As compared with Rs. 858.3 crores in the previous year, this shows an increase of 8.9 per cent.

TABLE 19 : CAPITAL ISSUES AND CAPITAL RAISED BY NON-GOVERNMENT COMPANIES (Public and Private)

Securities	Capital Issues		Capital Raised* (Paid up)	
	1984-85 (Revised)	1985-86 (Provisional)	1984-85 (Revised)	1985-86 (Provisional)
Equity Shares	385.87	793.15	242.75	227.46
Preference Shares	4.86	2.46	1.93	2.87
Debentures	945.74	732.28	613.61	704.19
(i) Convertible	164.88	57.81	n.a.	n.a.
(ii) Non-convertible	780.86	674.47	n.a.	n.a.
Total	1,336.47	1,527.89	858.29	934.52

*Data relate to capital raised under consents/acknowledgements granted by the Controller of Capital Issues and are exclusive of bonus issues.

n.a. : not available

Note : Effective February 23, 1985 the exemption limit on seeking consents/acknowledgements for capital issues was raised from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore. Hence the data relating to 1984-85 are not strictly comparable with those for 1985-86.

Source : The Controller of Capital Issues, Ministry of Finance, Government of India.

Assistance by Financial Institutions

145. According to provisional data, assistance sanctioned and disbursed during 1985-86 (April—March), by the all-India financial institutions (viz., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) aggregated Rs. 6,349.8 crores and Rs. 4,293.2 crores, respectively. This shows a rise of 20.0 per cent in sanctions and 36.6 per cent in disbursements over the preceding year. The

steep rise in disbursements by the all-India financial institutions and in capital issues during 1985-86 points to the increased tempo of industrial investment. This tempo is likely to be maintained in 1986-87 as the consents/acknowledgement granted by the Controller of Capital Issues in 1985-86 were as much as Rs. 3,055 crores representing an increase of 80 per cent over the level of Rs. 1,699 crores in 1984-85 (Table 20).

TABLE 20 : CONSENTS/ACKNOWLEDGMENTS GRANTED BY THE CONTROLLER OF CAPITAL ISSUES TO NON-GOVERNMENT COMPANIES (Public and Private)

	(Rs. crores)		
	1983-84	1984-85	1985-86
1. Equity and Preference (a+b)	319.46	779.53	1,066.31
(a) Initial	192.09	557.27	645.48
(b) Further	127.37	222.26	420.83
2. Debentures	609.36	919.55	1,989.01
Total (1+2)	928.82	1,699.08	3,055.32

Note : Effective February 23, 1985 the exemption limit on seeking consents/acknowledgements for capital issues was raised from Rs. 50 lakhs to Rs. 1 crore. Hence the data relating to 1984-85 are not strictly comparable with those for 1985-86.

Policy Changes

146. The Union Budget for 1986-87 contained proposals designed to strengthen the capital market and improve investment environment. These included creation of a new mutual fund in the public sector as a subsidiary of the Unit Trust of India to provide an additional investment channel for small investors.

147. The long term fiscal policy announced by the Government of India has entrusted the IDBI with the responsibility of administering the Venture Capital Fund and mobilising funds for long term development purposes. With this view, certain fiscal concessions including exemption from capital gains tax under Section 54-E of the Income Tax Act have been extended to IDBI.

148. The Unit Trust of India Act, 1963 was amended to widen the scope of operations of the Trust. The amended Act enables UTI to undertake direct lending, acquisition/sale of immovable property, leasing bills, rediscounting merchant banking, etc., and also facilitates extension by UTI of investment/fund/portfolio management services to non-resident Indians.

149. The Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill, 1985 which was passed by the Lok Sabha provides for increasing IDBI's authorised capital and enlarging the scope of the definition of industrial concerns under the IDBI Act so as to extend assistance to modern industrial activities, services sector and for ancillary activities taken up by small entrepreneurs. It also envisages strengthening the institution-building role of IDBI.

150. During 1985-86, the Government took several steps to strengthen and diversify the capital market. These included introduction of the Employees Stock Option Scheme to give employees of public limited companies a share in equity capital of their companies, introduction of a new instrument named Cumulative Convertible Preference (CCP) share for raising capital for purposes of modernization, expansion and establishment of new units, and announcement of guidelines for issue of bonds by public sector undertakings.

151. The new scheme of public sector bonds is applicable to Government corporate bodies in the power and telecommunication sectors and such other sectors as may be notified by the Government of India. The bonds can be issued both by existing and new corporate undertakings. The interest rate on the bonds will be determined by the finance ministry and interest can be either non-cumulative or cumulative. The maximum interest rate is fixed at 14 per cent per annum. The face value of the bonds, which will be listed on the stock exchanges, can be Rs. 500 or Rs. 1,000. The bonds will not normally be redeemable before the expiry of 7 years nor will the redemption period exceed 10 years. These bonds will be exempt from wealth tax without any limit. There will be no deduction of tax at source from the interest which accrues to the investors in these bonds; the income by way of interest from these bonds will be entitled to exemption under Section 80L of the Income Tax Act, 1961.

As in the case of non-convertible debentures, the buy-back facility has been allowed in the case of these bonds. Further, these bonds are transferable by endorsement and delivery.

Equity Prices

152. Equities ruled buoyant on major stock exchanges during the greater part of 1985-86. Equity prices which rose sharply following presentation of the Union Budget for 1985-86, gained considerable speculative momentum in June and July and reached a new peak level towards mid-August, despite various regulatory measures taken by the Stock Exchange authorities to curb the speculative build-up. Later, on persistent unloading of shares by financial institutions like UTI, a downward trend set in which continued upto November owing mainly to market uncertainties. A firm trend re-emerged after the announcement of the long term fiscal policy in December 1985 and prices scaled a new peak in mid-February 1986. The downward trend, which was in evidence following presentation of the Union Budget for 1986-87 continued up to end of June, excepting for short spells of recovery. From the last week of March to mid-April equity prices firmed up initially following the Government's assurance to reconsider some of the budget proposals which had dampened the market sentiment and later following modifications in certain Budget proposals, especially the one to restore the provision of exempting 60 per cent of inter-corporate dividend from income tax. Reflecting these trends, the Reserve Bank's all-India Index number of ordinary share prices (1980-81=100), which stood at 164.4 in the week ended March 30, 1985 rose to 247.0 in the week ended August 10, and dipped to 211.6 in the week ended November 9. The index, after rising sharply in December 1985 and January 1986, reached a new peak of 268.1 in the week ended February 15, 1986. Thereafter the index started declining and touched 237.9 in the week ended March 22. Later the index fluctuated between 230.5 and 248.6 and stood at 240.0 in the last week of June.

DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

Balance of Payments

153. Balance of payments data for the fiscal year 1985-86 are not yet available. However, the much smaller increase in foreign exchange reserves during 1985-86 as compared with that in 1984-85 and the substantial widening of the trade deficit during 1985-86 according to the data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), indicate that India's external payments position which had shown a marked improvement in 1984-85 came under strain during 1985-86. During the fiscal year 1985-86, the foreign exchange reserves (SDRs, gold and foreign exchange) rose by Rs. 577 crores that is, by less than one half of the increase of Rs. 1,271 crores during 1984-85. Excluding the repayments of Rs. 253 crores to the IMF, reserves would show an increase of Rs. 830 crores during 1985-86, as against a rise of Rs. 1,201 crores during 1984-85 (excluding the net drawings of Rs. 70 crores from the IMF). Table 21 presents India's foreign exchange reserves and IMF drawings and repurchases, in recent years.

TABLE 21—INDIA'S FOREIGN EXCHANGE RESERVES

End of the month	Foreign Exchange Reserves					Gross Drawings from the IMF under CFF and EFF (SDR millions)	Repurchases* from the IMF (SDR millions)	Net Drawings (SDR millions) (6-7)
	SDRs (in millions)	SDR** (Rs. lakhs)	Gold (Rs. lakhs)	Foreign Exchange (Rs. lakhs)	Total (Rs. lakhs) (Col. 2+3+4)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
March 1984	216.4	248.24	225.58	5497.85	5971.67	3966.00	66.50	3899.50
June 1984	330.8	382.05	225.58	5712.18	6319.81	4166.00	99.75	4066.25
March 1985	146.5	180.50	245.78	6816.78	7243.06	4166.00	199.50	3966.50
June 1985	303.7	376.89	246.67	6679.80	7303.36	4166.00	251.50	3914.50
March 1986	115.1	161.40	274.28	7384.35	7820.03	4166.00	397.25	3768.75
June 1986	126.9	186.26	274.28	7084.91	7545.45	4166.00	466.00	3700.00

Note: Gross drawings, repurchases and net drawings are from August 1980 when the CFF drawing was made.

* Repurchases under CFF and EFF.

** At Rupee-SDR exchange rate at the end of respective months.

154. In SDR terms, India's foreign exchange reserves amounted to SDR 5,728 million at end-March 1986, and showed a decline of SDR 276 million in 1985-86, as against an increase of SDR 696 million in the previous year. Excluding capital transactions with the IMF referred to above, these reserves would show a fall of SDR 78 million in 1985-86 as compared with a rise of SDR 629 million in 1984-85.

Merchandise Trade

155. According to provisional data released by the DGCI&S the trade deficit during the fiscal year 1985-86 widened sharply to Rs. 7,951 crores from Rs. 5,188 crores during 1984-85. The decline in exports and a sharp rise in imports caused this marked deterioration in trade balance.

156. Exports at Rs. 10,420 crores recorded a decline of 7.8 per cent as against a rise of 20.2 per cent during the previous year. An important contributory factor for the decline of exports was the sharp drop in exports of crude oil from Rs. 1,563 crores during 1984-85 to Rs. 135 crores in 1985-86 reflecting the further development of domestic refining capacities.

157. The 'non-crude oil exports' showed an increase, albeit modest, at 5.7 per cent as compared with a growth rate of 17.5 per cent achieved in 1984-85. In SDR terms, non-oil exports fell by 2.4 per cent as compared with an increase of 7.7 per cent in 1984-85. The growth in India's exports has to be seen in the broader context of world trade: exports in SDR terms of the group of non-oil exporting countries from the group of developing countries in fact dropped more sharply from a rise of 17 per cent in 1984 to less than one per cent in 1985, following the slowing down in the growth of some of the major economies as well as intensification of protectionism by some developed countries.

158. Available commodity-wise information for the first three quarters of 1985-86 suggests that exports of wheat, gems and jewellery, garments, iron ore, rice, cashew and marine products showed significant increases. Among these, exports of wheat, rice, cashew and iron ore improved sizeably in volume. On the other hand, exports of some important traditional commodities like unmanufactured tobacco and oil cakes, declined significantly owing to a fall in their volume. Exports of tea and chemical also declined substantially.

159. Total imports increased by 11.4 per cent to Rs. 18,371 crores during 1985-86, much faster than the rate of growth of 7.4 per cent witnessed in 1984-85. Imports excluding oil imports equivalent of crude oil exports, shot up by 22.2 per cent during 1985-86 as against 4.8 per cent during 1984-85. Imports of crude oil and petroleum products (net of crude exports) rose steeply by 34.4 per cent while they had increased by 0.4 per cent during 1984-85. The growth rate of non-oil imports at 18.4 per cent during 1985-86 was almost three times that during 1984-85.

160. In SDR terms, total imports expanded by 2.9 per cent during 1985-86 as compared with a decline of 1.5 per cent in 1984-85. Non-oil imports increased at an even faster rate by 9.3 per cent as compared to a decline of 2.6 per cent in 1984-85.

161. Available itemised information for the first three quarters of 1985-86 indicates that the sharp rise in import volume of some bulk commodities like crude oil, iron and steel and a few industrial raw materials was mainly responsible for the marked increase in imports. Besides, the substantial rise in imports of capital goods by some Government enterprises like the Oil and Natural Gas Commission and by the private sector also contributed to the increase in the import bill.

Invisibles

162. Available partial information on invisibles account suggests some decline in the net invisibles receipts during 1985-86 due mainly to higher interest payments on steadily growing foreign borrowings by both official and private sectors, and possibly some fall in private transfers. Earnings from tourism during 1985-86 would be larger than in 1984-85, as the

number of foreign tourists arrivals was higher by 9 per cent during 1985-86 as against a decline of 11 per cent in 1984-85. Payments on account of foreign travel, transportation and miscellaneous items also would have shown an upward trend.

External Assistance and Bilateral Transactions.

163. The rising trend in gross external assistance in nominal terms noticed in recent years continued in 1985-86. During 1985-86 (April-March) it amounted to Rs. 3,165 crores and was higher by Rs. 811 crores than in 1984-85. The amortisation payments on external debt at Rs. 737 crores were also higher than those of Rs. 647 crores in 1984-85. Consequently, the net inflow of external assistance (net of repayments) during 1985-86 was Rs. 2,428 crores as against Rs. 1,707 crores in 1984-85. In terms of U.S. dollars the net inflow of foreign aid in 1985-86 was U.S.\$ 1,984 million as compared with U.S.\$ 1,436 million in 1984-85. The transactions with bilateral account countries during 1985-86 resulted in a net outflow of Rs. 166 crores as against an inflow of Rs. 195 crores in the previous year.

Accretions under NR(E) R and FCNRA Schemes

164. Inflows from non-resident Indians into deposit accounts under the Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme were lower during 1985-86 than in the previous year, but were substantially higher under the Foreign Currency Non-Resident Accounts Scheme. The accretions under the NR(E) R Scheme (excluding the estimated interest element) are estimated at Rs. 281 crores during 1985-86 as compared with Rs. 354 crores during 1984-85. The net inflows under the FCNRA Scheme during 1985-86 (April-March) were Rs. 1,151 crores as against only Rs. 275 crores in 1984-85. It is noteworthy that the dramatic rise in inflow in 1985-86 and taken place despite the lowership of interest rates on FCNRA deposits twice during the year. The large inflow of funds under the FCNRA scheme has given a measure of support to balance of payments during the year.

Foreign Currency Assets

165. Among the three components of foreign exchange reserves, foreign currency assets of the Reserve Bank of India and its gold holding increased during 1985-86 (July-June) while the SDR holdings decline. The foreign currency assets of the Reserve Bank rose by Rs. 405 crores during 1985-86 (July-June) as compared to an increase of Rs. 968 crores during the same period of 1984-85.

SDRs

166. Holdings of SDRs declined by SDR 177 million during 1985-86 (July-June) as compared with a fall of SDR 27 million during 1984-85 (July-June). The decline in the level of SDR holdings during 1985-86 (July-June) was due to the payment of charges/interest amounting to SDR 384 million to the IMF and repurchases of SDR 214 million from the IMF, partially offset by acquisition of SDRs 390 million against foreign currencies.

Gold

167. Gold holdings of the Reserve Bank increased by Rs. 28 crores during 1985-86 (July-June) to reach a level of Rs. 274 crores (valued at the statutory holding price of Rs. 84.39 per 10 grammes) at end-June 1986. During 1984-85, gold holdings of the RBI had risen by Rs. 21 crores.

International Economic Developments

168. The worst fears regarding international economic developments during 1985, expressed in the previous year's Annual Report, unfortunately proved true. The world output growth decelerated appreciably from 4.4 per cent in 1984 to below 3 per cent in 1985, and that of developing countries from 4.1 per cent to 3.2 per cent. World trade, in volume terms, expanded by just 2.9 per cent after it had soared by 8.7 per cent in the preceding year. The rise in exports of the group of non-fuel exporting developing countries at 3.4 per cent was the second lowest since 1978; in SDR terms, the increase in their exports dropped from 17 per cent in 1984 to less than one per cent in 1985. The non-oil commodity prices declined steeply by over 12 per cent, the second sharpest fall since 1978, and the declining trend in the terms of trade of non-fuel exporters, which was arrested during 1983 and 1984,

re-emerged. Despite some fall in international interest rates, the debt service ratio of capital importing countries rose further to over 24 per cent in 1985.

169. The price situation in developing countries as a group worsened during 1985, though there was some improvement in Africa and Asia. Industrial countries made further progress in reducing inflationary pressures, aided by the fall in oil and other primary commodity prices. International interest rates also softened though the order of decline was much smaller than in the previous year. The Euro-dollar deposit rate for 6 months came down from 7.88 per cent in June 1985 to 6.80 per cent in June 1986. Similarly, the Euro-yen 6 months deposit rate declined from 6.25 per cent to 4.63 per cent and Euro-DM deposit rate from 5.50 per cent to 4.56 per cent. The prime rate of U.S. banks which remained stable at 9.50 per cent for most of the year, fell to 8.50 per cent in April 1986, and continued at that level till end-June 1986.

170. The sharp fall in prices of oil provided a measure of comfort to importers of oil, both in the developing and in the industrial world, though the major beneficiaries would be the industrial countries whose oil import bill is large. The oil price situation, however, remains fluid. The net effect of the drop in oil prices on the external position of individual countries would depend on several factors including the effect of lower oil prices on oil imports, the adverse impact on exports to oil exporting countries and on remittances and aid receipts from oil exporting countries to developing countries. As a result of the massive shift in incomes, following the drop in oil prices, from oil exporting countries to industrial countries in particular, the growth prospects in industrial countries may be expected to improve and this should have a favourable effect on the external situation of some developing countries.

171. Another important development during the period was a strong depreciation of the U.S. dollar in relation particularly to the Yen and the DM, resulting in a realignment of exchange rates reflecting more closely the underlying economic realities, particularly the relative competitiveness of the economies concerned. Though this realignment did not have an immediate impact on the huge current account payments imbalances of the United States, Japan and the Federal Republic of Germany, the effects should become visible gradually. A remarkable fact about the realignment was the strong impetus it received through co-ordinated intervention by the Central banking authorities. That this was brought about without much market disruption has encouraged the large industrial countries to move towards greater surveillance of each other's economic objectives and policies with a view to maintaining sustainable growth, and orderly market conditions. Although this is a welcome development, it is desirable, from the point of view of global growth, to strive for a truly multilateral surveillance, which would also take care of the interests and concerns of developing countries.

172. Income growth of developing countries needs to be improved substantially and spread more evenly. Their efforts in this direction continue to be hampered by an unfavourable international environment which is characterized by faltering and uneven growth, deflationary tendencies and growing trade protectionism. The industrial world should ensure distinctly better economic performance, now that inflation has been brought under control. Higher economic activity in industrial countries would have beneficial effects on commodity prices which have remained depressed for a long time and other exports of developing countries. Real interest rates need to be lowered further through the pursuit of appropriate mix of monetary and fiscal policies attuned to the overall objective of world growth. Lower interest rates would also alleviate the external debt servicing problems of several countries. The drop in oil prices has shifted large incomes in favour of the industrial world. In this context, the urgency of adequate concessional flows to low income countries needs to be reiterated. The growing protectionism among industrial countries increases the burden of adjustment on developing countries and delays progress towards the resolution of the debt problem; protectionist measures, therefore need to be rolled back.

173. The systemic and other weaknesses in the functioning of the international economy have been identified by the Committees of Deputies of the Group of Twenty four

(developing countries) and the Group of Ten (industrial countries). Their reports, however, differ significantly regarding the prescriptions to improve the functioning of the system. The discussions on these reports and the international monetary reform have not progressed much beyond the usual generalities. It is to be hoped that the progress towards solutions appropriate for global growth would be more rapid in the coming year.

The Exchange Rate Movements

174. As already indicated, the long-awaited decline in the U.S. dollar rates, in relation to several major currencies, materialised during the year. The downturn in the U.S. dollar witnessed since end-February 1985 became pronounced after the September 1985 agreement among G-5 ministers to strengthen, particularly the yen and the DM, currencies of countries with large current account surpluses, in relation to the U.S. dollar, and to actively use official intervention in foreign exchange markets to attain the objective. The Tokyo summit in May 1986 emphasised the need for relative stability in exchange rates. However, important differences in the direction of the movement of exchange rates of some currencies emerged at the summit. It was, however, agreed that Finance Ministers of G-7 would meet more frequently to exercise surveillance over each other's economic objectives and policies. If this leads to timely, appropriate and co-ordinated policy changes among these countries there could be greater stability in exchange rates of major currencies.

175. The exchange markets continued to be volatile during 1985-86 (July-June) with occasional periods of subdued trading. The declining trend in the U.S. dollar witnessed during July and August 1985 was reversed in September 1985. Till June 1986 thereafter, the average monthly dollar rate in relation to major currencies and the SDR depreciated, month after month, with a few exceptions. Thus, between September 1985 and June 1986, the U.S. dollar depreciated, in terms of average monthly rates, by 29.7 per cent against the yen, 21.3 per cent against the DM, 11.7 per cent in relation to the SDR and 9.5 per cent against the pound sterling.

176. During 1985-86, the U.S. dollar depreciated against all the major world currencies and SDR, generally, the rate of its depreciation, more than offsetting its appreciation in 1984-85. Thus, in terms of the average yearly rates the U.S. dollar rate against the SDR and the pound sterling eased by 9.7 per cent and 15.2 per cent, respectively, as against the appreciation of 5.9 per cent and 18.9 per cent during 1984-85. The U.S. dollar, which had appreciated by 14.6 per cent in 1984-85 in relation to the DM eased by 19.2 per cent in 1985-86; it weakened by 20.8 per cent against the yen as compared to its appreciation of 6.5 per cent during 1984-85. The appreciation of the yen during 1985-86 against the pound sterling and the DM was by 7.0 per cent and 2.0 per cent, respectively. The pound sterling generally ruled firm during 1985-86 which could be attributed to favourable interest rate differentials, an buoyant equity markets. The sentiment was somewhat affected after August 1985 by concern over falling oil prices. During 1985-86 the pound sterling appreciated by 6.5 per cent against the SDR while it had depreciated by 10.9 per cent during the previous year. The significant strengthening of the DM against the SDR (by 11.8 per cent) and the pound sterling (by 5.0 per cent) could be attributed to optimism about the prospects of the West German economy in terms of real growth and low inflation rate, besides strong balance of payments position.

Exchange Rate of the Rupee

177. The rupee value continues to be determined in relation to a weighted basket of currencies of India's major trading partners, with the pound sterling as the intervention currency. The number of adjustments in the rupee-sterling rates aggregated 149 during 1985-86 (July-June) as against 164 during the preceding year. The rupee remained more or less stable in relation to the U.S. dollar, declining only marginally by 0.7 per cent between end-June 1985 and end-June 1986. However, reflecting the strong appreciation of the yen, Swiss franc, the DM, the pound sterling and the SDR vis-a-vis the U.S. dollar, the rupee declined against those currencies.

Rupee-Rouble Exchange Rate

178. During 1985-86 (July-June), the rupee-rouble exchange rate was changed six times, i.e., on July 13, September 9, and November 10, 1985 and January 20, February 6 and April 24, 1986. The rupee-rouble exchange rate weakened over the year by 12.5 per cent from Rs. 11.34 per rouble at end-June 1985 to Rs. 12.96 per rouble at end-June 1986.

ASSESSMENT AND PROSPECTS

179. The encouraging features of the performance of the economy in 1985-86 were the continuing deceleration in inflation, sizeable stocks of foodgrains with the public distribution system, a high level of savings and a reasonably comfortable level of foreign exchange reserves despite a massive trade deficit. However, for the second year in succession, growth in real national income has fallen below 5 per cent—a rate which the Seventh Plan aims to sustain during the period 1985-86 to 1989-90—due partly to adverse weather conditions.

180. The performance of the economy in 1986-87 could be expected to be better than in the previous two years. Reports are that unlike in the previous two years, the monsoon is likely to be good this year. This would mean that the growth rate in agricultural output in 1986-87 would be significantly higher than in the previous two years. During the year, the Government initiated several policy measures designed to accelerate investment in the industrial sector. With the various policy measures in position and continuing buoyancy in investment, the outlook for industrial growth during the year 1986-87 would largely depend on the performance of infrastructure industries, particularly electricity generation. Improvement in agricultural production should also help in achieving better industrial performance. With both agriculture and industry set to grow faster, it would seem reasonable to expect that the rate of growth in real national income in 1986-87 would at least be 5 per cent.

181. While taking a view on medium term prospects, it has to be recognized that the main support to overall growth during the Seventh Plan is expected to emanate from industrial growth. In order to achieve the target rate of growth of income, ensuring a more than 8 per cent growth in the industrial sector in the remaining years of the Plan becomes imperative. Since 1981-82 industrial growth has been hovering around 6 per cent and a breakthrough from this relatively lower level of growth has to be engineered. Perhaps the full impact of the various measures taken in the industrial sphere as also of the buoyancy in the capital market may begin to manifest itself from 1986-87, assuming a lag of two years or so. In these efforts to facilitate a breakthrough, removal of the infrastructural constraints should receive the first priority in macro economic policy.

182. The industrial strategy for the Seventh Plan lays special emphasis on improvement in productivity and upgradation of technology. The implied incremental capital-output ratio in the Seventh Plan is around 5. This, the Plan recognises is lower than the trend value of 5.5. But the Plan adds, "The lower value is expected to be realised because of the emphasis on efficiency which is a crucial part of the Seventh Plan strategy". Improved efficiency must result in larger output with lower unit cost of production. This in turn should help avoid the emergence of demand constraint.

183. In the agricultural sector the problem is of a different nature. The agricultural strategy has yielded major gains; self-sufficiency in foodgrains reflected in the sizeable stocks of foodgrains with the public distribution system is concrete evidence of the success of the strategy. At the same time, the agricultural scene is characterized by regional and crop imbalances.

184. These imbalances have manifested themselves in several ways. For instance, foodgrains stocks at the end of June 1986 are reckoned at around 28.6 million tonnes—a level which is well in excess of what is deemed necessary for operational requirements and buffer stocks even in agriculturally bad years. Such unusually large stocks pose problems in terms of both cost to the national exchequer

as also possible deterioration of quality. Subsidies for food and fertilizers have jumped from about Rs. 1,200 crores in 1980-81 to Rs. 3,700 crores in 1985-86. Similarly, production of cotton, raw jute and mesta has already exceeded the Seventh Plan targets. At the other end of the spectrum are edible oils and sugar, imports whereof are causing a severe strain on the balance of payments.

185. The agricultural production scenario as it has emerged over the past 10 years or so, shows that the output of wheat has grown at a much faster rate than other foodgrains. Wheat production has grown at a compound annual growth rate of about 6.0 per cent between 1967-68 and 1985-86. Over the same period, rice production has shown a growth rate of only 2.8 per cent, while the growth in pulses was negligible; coarse grains recorded a decline of about 0.6 per cent. It was only in 1983-84 that rice production exceeded the previous record of 53.54 million tonnes. It reached a new peak of 60 million tonnes in 1984-85. It has risen further to 63.0-63.5 million tonnes in 1985-86. In contrast, production of coarse grain and pulses has remained almost stagnant. This is because the green revolution has mainly benefited wheat, and to some extent, rice. This coupled with effective price support and procurement policies has brought about increased production of these commodities mainly from areas with assured supply of water. Agricultural productivity in rainfed and dry areas remains poor. There are disparities in growth of crops, between foodgrains and non-foodgrains on the one hand and among different foodgrains themselves on the other. The net result is that relatively large production of wheat, cotton and raw jute co-exists with shortages of oilseeds, sugar, pulses and coarse cereals.

186. Agricultural policy in the coming years must emphasize improvement in yields in the dry/rain-fed areas, and a more integrated agricultural price and procurement policies with a view to correcting present imbalances in the production of various crops. Production of crops on dry land has so far received much less attention in terms of investment and technology and hence no significant breakthrough in dry land/rain-fed farming has been achieved. Dry land farming accounts for 70 per cent of the gross cropped area and contributes to about 50 per cent of the total agricultural production. The main crops grown in these areas are pulses, coarse grains, oil seeds and cotton; these are produced with low farm investment and poor technology. Sustained and strenuous efforts would be necessary to overcome such deficiencies and raise productivity in these areas.

187. In the context of the need to accelerate agricultural production and correct crop imbalances, the case for evolving an integrated agricultural price policy has become urgent. The Government of India have already announced that such a policy is in the process of formulation. A national agricultural price policy evolved in co-ordination with the State Governments could contain the following elements. First, relative prices among agricultural commodities could be adjusted to correct imbalances as they emerge in the crop pattern. Second, even in relation to a single crop there may be a need to evolve a price policy designed to produce the appropriate mix of varieties. Third, agricultural prices have direct implications for policies relating to wages and subsidies and the latter will have to be subsumed in the national agricultural price policy. Finally to effectively implement the agricultural price policy so formulated it would be necessary to back it up by an appropriate procurement and distribution in apparatus.

188. In the process of accelerating growth of the economy with stability and social justice, the financial system will, of course, continue to play a very important part. Its role in mobilizing resources and in deploying them in desired channels will depend on its strength and on the quality of service it can offer. In this context it is of paramount importance to consolidate and improve on the gains which the banking system has achieved.

189. Steps toward consolidation aimed at improving the financial viability of banks are already under way. The new branch licensing policy while concentrating on filling spatial gaps in rural areas envisages opening of urban and metropolitan bank branches only on the basis of demonstrated need and potential financial viability. The capital base of national-

used banks is being strengthened. Returns on investments in Government securities as well as on cash reserves of banks have been raised. After a considerable time lag, banks have revised their service charges. All of these measures should go to strengthen the viability of the banking system.

190. Each bank has drawn up a comprehensive two-year plan for improving its overall operations. The plans include measures (a) to strengthen the internal structure to ensure better supervision and control, (b) to expand training facilities where warranted, (c) to improve credit appraisal and quality of loan assets, (d) to introduce new work technology on a selective basis and (e) to improve recovery of bank dues, control costs and raise profitability. In effect, the fulfilment of these plans should lead to better customer service and improved financial viability. The emphasis on improved customer service has already begun to show results.

191. An area of concern is the inadequate recovery of claims which impairs the ability of banks to recycle funds and prevents optimum use of resources. The overall recovery of agricultural dues has ranged between 50 per cent and 55 per cent of demand in recent years. There are wide inter-regional and inter-bank variations.

192. Among the factors responsible for this state of affairs are wilful defaults especially by large borrowers, misutilisation of loans, natural calamities, defective appraisal of loan applications and inadequate financing, deficient monitoring of credit utilisation and weaknesses in recovery procedures. Since commercial banks are now committing 40 per cent of their lending to priority sectors, mainly in rural areas, they must improve the quality as well as recovery of such loans. Rural branch managers need to develop greater contacts with their clients through regular field visits so that identification of beneficiaries and appraisal of loan applications improve, post-sanction monitoring of credit utilisation is strengthened and recovery of loans is pursued regularly and effectively. At the same time, it is necessary that under-financing is avoided, repayment schedules are pragmatically drawn up and when natural calamities occur, short-term loans are quickly converted into medium-term loans according to prescribed procedures. The importance of maintaining an environment conducive to recovery of dues cannot be overemphasised. Here, the role of State Governments is crucial.

193. Poor recovery performance is not confined to agricultural advances alone. It covers other sectors as well. Of particular concern is the growing sickness in industries—large, medium and small. The seriousness of the problem is evident from the fact that about 8 per cent of total bank credit is frozen in these sick units. A business like approach appears to be warranted with the objective of reviving potentially viable units and taking hard decisions on those that are not. The Board for Industrial and Financial Reconstruction would, it is hoped, promote this approach. Early detection of incipient sickness in industry, regular reviews of industrial accounts and quicker adoption of remedial measures could be very helpful.

194. Innovations in banking and financial services have become the order of the day the world over and the next phase of banking in India will also have to acquire an increased degree of sophistication. Apart from the selective introduction of modern technology to speed up operations, there will be changes in the composition of bank business reflecting the changes occurring in industry and trade. Non-fund business may assume greater importance. Merchant banking services will grow in response to the development and maturation of the capital market. Already, leasing is catching on and other services such as trust functions could also become important. With greater exposure to external banking and capital markets, there will be increased opportunities for involvement in areas like foreign collaboration arrangements, external commercial borrowing and non-resident investments. Banks will, however, have to contend with increasing competition in the area of mobilisation of savings from other institutions as a wider spectrum of investment avenues becomes available to savers. They need to prepare themselves for these challenges and opportunities.

195. In recent years, the magnitudes of credit flows from the various financial institutions have been increasing. To further the objective of higher mobilisation of financial savings and channelisation of resources in accordance with national priorities, the need was felt of a forum at which coordinated views on the financial flows in the economy can be formulated. Accordingly, the Reserve Bank has set up a National Finance and Credit Council which, besides taking an overall view of the flow of finance and credit, both short-term and long-term, for industry, agriculture and trade, will consider developments in capital and money markets with a view to improving their financial efficiency.

196. On the external front, there is need to take a fresh look at the balance of payments scenario for the Seventh Plan in the wake of the large trade deficit witnessed during the first year of the Plan. The balance of trade situation worsened considerably in 1985-86 and this is reflected in the marked rise in the ratio of external resources inflow to NNP from 1.3 per cent in 1984-85 to 2.0 per cent in the following year. The growth in Indian exports, in terms of volume, continued to be weak and formed less than one-half of the annual increase of 6.8 per cent targeted for the Plan period. In contrast, imports, both oil (net of exports) and non-oil, rose sharply. Consequently, the annual trade deficit, which hovered around Rs. 5,500 crores during the Sixth Plan period, reached a new record during the year of about Rs. 8,000 crores. Net invisible receipts also were lower because of growing interest payments and perhaps some fall in private transfers. However, the buoyancy in FCNRA deposits and a moderate increase in external aid limited the dependence on foreign commercial borrowings and helped to strengthen modestly the reserves position. Despite this, the signs of deterioration in the balance of payments observed in 1985-86 call for urgent measures to reduce the current account deficit, mainly through the contraction of trade deficit. The critical importance of exports is well recognised and policies for increasing exports need to be implemented vigorously. In particular, large industry should make a greater contribution to exports. No significant improvement is expected in the international trade environment in the immediate future though the prospects of world trade growth are considered somewhat better on the assumption that the level of oil prices continues to remain around present levels. Still, there should be considerable scope for larger exports from India, particularly to industrial countries most of which will be major beneficiaries of the decline in oil prices.

197. Sustained efforts are required to improve the competitiveness of Indian exports, in the face of the strategy that might be adopted by our competitors in the world markets. Fuller utilisation of installed capacities in infrastructure industries as also greater cost consciousness in establishment and operation of enterprises need to receive much greater attention. It is necessary to ensure that required exportable surpluses are generated as quickly as possible in respect of commodities with high export potential. Larger industrial units have to contribute substantially towards export growth.

198. On the imports side, net oil imports in value terms, are expected to be significantly lower during 1986-87, and the remaining years of the Plan as compared to the Plan projections due to the present and projected softness in oil prices. We should naturally secure the maximum advantage from these developments. However, the oil price outlook will continue to be characterised by uncertainties and could change substantially. There is, therefore, no room for complacency, especially because the demand for oil products has been rising rather fast. From the medium to the long term stand point, therefore, the emphasis on exploration and conservation of energy should continue.

199. Non-oil imports increased sharply during 1985-86. The details of commodity-wise imports for the full year are not available but data for the first nine months of the year point to a substantial increase in imports of capital goods, fertilisers, iron and steel and 'other' imports. The fall in oil prices would no doubt soften fertiliser prices in 1986-87. Imports of capital goods and iron and steel may, however, continue to increase in view of the investment programme under the Plan. There is, however, scope to minimise the rise in such imports through redoubled efforts at efficient

import substitution. The 1986-87 budget has provided incentives for higher production of edible oils. It is important to reduce dependence on edible oil and sugar imports, which have been sizeable in recent years. Similarly, import substitution of bulk items such as crude oil, steel and fertilisers needs to be pursued vigorously. This would call for better utilisation of installed capacity in power, steel, fertiliser, cement and paper industries and improved agricultural production, with particular emphasis on commodities which could promote exports or save imports.

200. The private transfer receipts are an important element of net invisible receipts. Their buoyancy during the last decade was partly due to a rise in such transfers from the Middle East countries. With the drop in oil prices, remittances from this area are likely to decline. Improvement in tourist arrivals witnessed during 1985-86 needs to be sustained. Though the international interest rates are sliding down, as the proportion of our external debt at variable interest rates is relatively small, the saving on interest payments because of falling international interest rates would be less than such interest payments last year. In fact, net interest payments during 1986-87 would be higher because of increased external borrowing both at concessional and commercial rates. On the whole, net invisible receipts may decline moderately during 1986-87.

201. On the capital account, while the net external assistance is expected to be higher, the scheduled repayments to the IMF will be substantially larger during 1986-87. Given the current policy regarding commercial borrowing, the trend in exchange reserves would largely be determined by the size of the trade deficit. The level of reserves is comfortable at present and no major difficulty is envisaged in the management of external payments situation during 1986-87.

202. Even so, the balance of payments outturn during the year 1986-87 and beyond will be critical for the successful implementation of the Seventh Plan. This would seem to underline the need to strengthen our efforts considerably to increase exports, in view of the none-too-bright prospects for concessional aid, the diminished prospects of remittances from abroad, and the likelihood of a rise in imports of non-bulk items.

203. On the fiscal scene, a welcome development has been the buoyancy in tax revenues. As indicated earlier, collection from major central taxes rose by 22 per cent over the previous year according to the Revised Estimates for 1985-86. Income-tax collections rose dramatically by 36 per cent over even the Budget Estimates. Nevertheless, a disconcerting aspect is the continuance of large deficits on revenue account which are financed by the surpluses of the capital budget. The Budget Estimates for 1986-87 envisage a revenue deficit of Rs. 6,874 crores registering a rise of Rs. 934 crores or 15.7 per cent over the Revised Estimate for 1985-86. The three major items in revenue expenditure, viz., defence, interest and subsidies, are expected to use up 67.8 per cent of revenue receipts in 1986-87 as against 66.3 per cent in 1985-86. The revenue deficit has widened partly due to the larger devolution of resources consequent on the implementation of the recommendations of the Eighth Finance Commission. The surplus on capital account would be Rs. 3,224 crores which is much larger than the surplus of Rs. 1,450 crores (R.E.) last year. This surplus would finance 46.9 per cent of the revenue deficit as against 24.4 per cent last year. It is necessary to reiterate that the continuation of this disturbing trend would imply increasing pre-emption of resources for current expenditure including interest payments, away from spending on development. A rise in public debt which becomes necessary for generating surplus on capital account implies rising interest burden. A medium term strategy therefore needs to be evolved to correct the structural deficiency of the capital budget supporting the revenue budget. Also, in the light of the resources constraint that is being faced, a thorough review of expenditure policies and procedures needs to be undertaken with a view to containing the deficit within reasonable limits.

204. The sustained deceleration in the inflation rate during the last three years has been a welcome development. There has been a significant slowdown in the rate of expansion of broad money (M1) from 17.9 per cent in 1983-84 and 18.7 per cent in 1984-85 to 15.7 per cent in 1985-86. Against the

background of this deceleration, what should be the stance of monetary policy in the coming years, particularly in 1986-87? In answering this question, it has to be remembered that the deceleration in wholesale prices in 1985-86 co-existed with an uptrend in consumer prices; consumer prices recorded, on a point-to-point basis, a rise of 8.9 per cent in 1985-86 against 5 per cent in 1984-85. On an average basis also, the rise in 1985-86 at 6.4 per cent was of the same order as during the previous year. This underlines the need for continued vigilance over the price situation. Assuming that the growth in real national income in 1986-87 would be around 5 per cent, that is, higher than that during the previous two years, it would be necessary to regulate the expansion in M₃ in 1986-87 so that it remains well below the triennial average increase of 17.5 per cent. That is why the stance of credit policy in 1986-87 would have to be one of caution while at the same time, ensuring adequate flow of credit for meeting the genuine requirements of various sectors of the economy.

205. From the medium term point of view, the acceptance in principle by the Government of India of the Chakravarty Committee recommendation that the definition of the budget deficit should be widened to include RBI support to dated securities can be regarded as an important development. Another recommendation of the Chakravarty Committee which has been accepted by the Government relates to the setting of overall monetary targets which can be monitored. The acceptance of the wider concept of budget deficit and the introduction of monetary targets should help in promoting greater co-ordination between monetary and fiscal policies.

PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

206. The overall economic situation in 1985-86 and the monetary and credit policy measures taken during the year were reviewed in Part I of this Report. This part of the Report deals with other important developments in the various spheres of the Reserve Bank's operations. The balance sheet and accounts of the Bank for 1985-86 are presented at the end.

The Highlights

207. The highlights of the developments during the year are :

- (a) The new branch licensing policy covering the period of the Seventh Five Year Plan came into effect in April 1985.
- (b) Larger discretionary powers were given to banks in respect of their loan operations under the Credit Authorisation Scheme.
- (c) A beginning was made for strengthening the capital base of public sector banks in a phased manner.
- (d) Selective credit control measures were further rationalised.
- (e) The scope and coverage of forward cover facilities were enlarged to take into account changes in the external payment scenario and the emergence of new lines of activities.

DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKING

Branch Expansion Policy and Progress

208. A reference was made in the previous year's Report to the successful implementation of the three-year branch expansion plan covering the period April 1982 to March 1985. During this period, 12,366 new offices were opened taking the total number of bank offices to 50,980 at the end of March 1985. Of the new offices, as many as 10,876 were opened in rural/semi-urban centres. Consequently, the average population coverage in these areas improved to 15,500 per office as against the target of 17,000.

209. The new branch licensing policy covering the period April 1985 to March 1990 was formulated in consultation with the Government of India. It is to be co-terminous with the Seventh Five Year Plan and has been formulated keeping in view the level and spread of banking services already achieved and the gaps which still remain as well as the need for banks to concentrate on consolidation of

their position by improving, among others, customer services, resource base, lending operations, house keeping, supervision and control systems and financial viability. The main objective of the policy is to ensure efficient banking service and to provide banking facilities in deficient rural areas, especially where identifiable spatial gaps exist. The policy aims at covering a population of 17,000 (as per the 1981 census) in the rural and semi-urban areas of each block. Special attention will be paid to hilly tracts, sparsely populated regions and tribal areas. A rural banked centre is envisaged to cover an average of about 200 sq. kms and a rural branch is to be normally available within 10 kms. Expansion in urban and metropolitan/port towns, where the coverage of banking services is already quite intensive, will continue to be restrictive and new branches will be allowed in these areas on a highly selective basis taking into account their need and financial viability. The expansion programmes would be implemented in two phases—phase one covering the period April 1985 to March 1988 and phase two from April 1988 to March 1990.

210. As at the end of June 1986, there were 81 scheduled commercial banks as against 83 a year ago. Mention was made in the previous year's Report about the orders of moratorium issued in respect of three private sector banks in view of their unsatisfactory financial position and methods of operation. The Miraj State Bank Ltd. with 26 branches was amalgamated with the Union Bank of India on July 30, 1985, Laxmi Commercial Bank Ltd. with 231 branches with Canara Bank on August 24, 1985 and Bank of Cochin Ltd. with 108 branches with State Bank of India on August 26, 1985. Consequent on these amalgamations the total number of scheduled commercial banks was reduced to 80, but increased to 81 with the inclusion in the second schedule to the Reserve Bank of India Act of the Oman International Bank, SAO which opened a branch in Bombay.

211. During 1985-86 (April-March) commercial banks including RRBs opened 1,566 branches raising the total number of branches to 52,936. Around 77 per cent of the new offices were opened in rural areas, and 73 per cent at un-banked centres. Rural offices constituted 56 per cent of all offices at the end of March 1986 as compared with 22 per cent in June 1969. Of the 1,566 new bank offices opened, 191 belonged to State Bank of India and its associate banks, 583 to nationalised banks, 747 to regional rural banks and the remaining offices to private sector banks.

212. During the year ending June 1986, no new branches were opened by Indian banks abroad. On the other hand, seven overseas branches were closed. These included two branches of State Bank of India viz, the Anuradhapura branch in Sri Lanka and Bristol branch in U.K., two branches of Bank of Baroda at Bolton and Coventry in U.K., two branches of UCO Bank at Mongkok and North Point in Hongkong and one branch of Indian Overseas Bank at Kwaichung in Hongkong. Consequently, the total number of overseas branches of thirteen Indian bank stood at 134 at the end of June 1986. During the year the representative office of State Bank of India at Manila (Philippines) was closed down thereby reducing the number of representative offices of 4 Indian banks to 11 in 9 countries. The number of subsidiaries, foreign bank affiliates and exchange companies managed by Indian banks remained unchanged at 7, 4 and 11 respectively.

213. During the year, Oman International Bank, SAO and Bank of Bahrain and Kuwait, ESC opened a branch each in Bombay and Royal Bank of Canada opened a representative office in New Delhi. Consequently, the number of branches and representative offices of foreign banks stood at 136 (of 21 banks) and 14 (of 14 banks), respectively, at the end of June 1986.

Regional Rural Banks

214. Since April 1985, eleven new regional rural banks (RRBs) were established taking the total number of RRBs to 194 at the end of June 1986. They cover 342 districts in the country. The deposits and advances of 190 reporting RRBs at the end of June 1986 amounted to Rs. 1,364 crores and Rs. 1,510 crores, respectively.

Public Sector Banks' Assistance to Priority Sectors and other Special Schemes

215. Public sector banks which had already crossed, by March 1985, the overall target of 40 per cent of net bank credit in respect of priority sector advances, made further headway. Their advances to priority sectors at Rs. 20,544 crores at the end of December 1985, formed 42.7 per cent of their net credit. According to provisional data available, such advances had gone up to Rs. 20,853 crores by the end of March 1986. Direct advances to agriculture which was to form 15 per cent of net bank credit by March 1985, constituted 15.3 per cent at the end of December 1985. Advances to weaker sections within the priority sector at 10.2 per cent on the same date also exceeded the target of 10 per cent which was to be attained by March 1985.

216. Public sector banks' assistance to beneficiaries under the 20 Point Programme at the end of March 1986 amounted to Rs. 7,107 crores spread over 140.13 lakh accounts (according to preliminary data) as against Rs. 5,531 crores covering 114.83 lakh accounts a year earlier. Credit flow from these banks to scheduled castes/scheduled tribes (SC/ST) beneficiaries gathered momentum during the year. The outstanding advances to these categories recorded an increase of Rs. 296 crores during the year to Rs. 1,394 crores at the end of March 1986 and covered 58.30 lakh borrowal accounts (provisional data).

DRI Scheme

217. During the year ended December 1985, the number of loan accounts under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme rose by 2.79 lakhs to 45.51 lakhs and the amount of loans outstanding by Rs. 44.7 crores to Rs. 486.08 crores. The average amount of loan per account increased from Rs. 1,033 to Rs. 1,068 during the same period. Such advances at the end of December 1985 formed 1.15 per cent of banks' total advances at the end of the previous year. Preliminary data for March 1986 place DRI advances at Rs. 505.5 crores in about 45.70 lakh accounts.

Self Employment Scheme

218. Under the Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth introduced in September 1983, an overall target of 2.50 lakh beneficiaries was fixed for the fiscal year 1985-86. The proportion of industrial ventures to be sanctioned during the year out of the total target set for each State was to be not less than 50 per cent and that of business ventures not more than 30 per cent. However, the relaxation made in the previous year in respect of hilly areas of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura was continued during 1985-86 also. In these areas the minimum proportion of industrial ventures was 30 per cent instead of 50 per cent and there was no upper limit for percentage of business ventures. According to provisional figures for 1985-86, banks sanctioned loans amounting to Rs. 415 crores to 2.18 lakh beneficiaries against the target of 2.50 lakh beneficiaries.

Banks and the IRDP

219. Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) 28.23 lakh beneficiaries were assisted during 1985-86 and term credit of Rs. 606.27 crores was granted by the banks (including RRBs and co-operatives). During the Sixth Plan period, 16.56 million families were assisted under the programme against the target of 15 million families and term credit to the tune of Rs. 3,102 crores was disbursed.

220. Since evaluation reports on implementation of IRDP by various agencies indicated that 60 per cent of the assisted families could not cross the poverty line for no fault of theirs, a scheme of providing supplementary assistance to certain eligible categories of borrowers assisted during Sixth Plan period, was initiated in 1985-86 besides covering new beneficiaries. The supplementary assistance was to help those borrowers who were not defaulters and had maintained the previously financed assets in good condition or had lost them due to reasons beyond their control. The physical target for supplementary assistance during the Seventh Plan placed at 10 million families to be covered

in the first three years. The target in respect of new beneficiaries is also placed at 10 million families for the Seventh Plan period. The Central sector outlay for the programme is Rs. 1,186.79 crores.

221. The Government of India has issued a set of new guidelines for implementation of IRDP programmes during the Seventh Five Year Plan. The poverty line which was fixed at an annual family income level of Rs. 3,500 has been raised to Rs. 4,400. However, for identification of the families a lower cut-off point has been fixed at annual income level of Rs. 4,800. Further, in view of the inter-State variation and disparities in the incidence of poverty, it has been decided that the allocation of funds under IRDP would be in relation to incidence of poverty in each State. A separate target of 30 per cent for coverage of women beneficiaries under the programme has also been fixed.

222. A Study Group was set up by the Reserve Bank in November 1985 under the chairmanship of a Deputy Governor with the objective of streamlining the arrangements for flow of credit and supply of inputs and assets to the IRDP beneficiaries so that they would draw the full benefit of the anti-poverty programme. Based on the recommendations of the Study Group contained in its interim report, banks were advised to implement, on an experimental basis, a system of cash disbursement of IRDP assistance for specified purposes in 22 selected blocks all over the country with effect from April 1, 1986.

Lead Bank Scheme

223. Pending finalisation of the guidelines for the fourth round of district credit plans, the lead banks were advised in September 1985, to prepare only annual action plans (AAPs) for 1986, broadly on the lines of the guidelines issued by the Reserve Bank for preparation of AAPs 1985, subject to a few changes which were considered necessary in the light of the experience gained. Accordingly, AAPs 1986 were prepared and launched for implementation in all the districts of the country except three districts in Nagaland.

224. The lead bank responsibility in respect of the new district created viz. Nalbari (Assam), Anna (Tamil Nadu) and North 24 Parganas (West Bengal) has been entrusted to UCO Bank, Canara Bank and Allahabad Bank respectively.

Credit Authorisation Scheme

225. A detailed review of the Credit Authorisation Scheme was made during the year and, after taking into account the increase over time in the volume and size of financial transactions, some changes were made mostly with a view to vesting banks with larger discretionary powers. The more important of these changes were covered in Part-I.

226. With a view to enabling greater flexibility in the use of the 'fast track' without dilution of financial discipline some changes were introduced. Borrowers who managed in the past with inventory and receivable levels lower than the standard norms, would qualify for the 'fast track' facility even if the estimated inventory/receivables levels for the current and following year are higher than in the past, provided these do not exceed the standard norms. Borrowers, who in the past, adhered to standard norms but found it necessary for good and valid reasons to deviate from the norms in the estimates/projections for the current/following year would be eligible for the 'fast track' facility, provided the deviation is not more than 15 per cent of the standard norms and the levels are expected to be brought down so as to conform to the norms within one year. This facility would also be available to borrowers who were holding inventory levels higher than the norms which were accepted by the Reserve Bank in the past assessments, provided the deviation from the norms for the current year did not go beyond 15 per cent. The Bank might, however, disallow the deviation if, on subsequent scrutiny of the CAS proposal, it was found to be not justified. The requirement of timely submission of the quarterly operating statement for the previous two quarters was modified to cover the performance for the previous four quarters. It was also provided that, if a borrower delayed submission of the returns in one of the previous two quarters, he would still qualify for the 'fast track' if he was punctual during the earlier two quarters.

227. The number of parties covered under CAS increased

by 25 to 843 during the period July 1985 to March 1986. The total limits in force relating to parties covered under the scheme amounted to Rs. 21,671 crores as at the end of March 1986; of these, 63.0 per cent related to public sector undertakings. Industry claimed 54.4 per cent of total working capital limits and trading, mainly public sector, another 43.3 per cent.

228. During the year July 1985—June 1986, 113 proposals from 19 urban banks involving an aggregate amount of Rs. 56.3 crores were received for authorisation, of which 85 proposals for an amount of Rs. 37.4 crores were approved.

Other Credit Norms

229. Guidelines relating to share of banks in term loans to industries extended in participation with term lending institutions were revised in July 1985; the more important of them are the following: Banks may finance projects in participation with State level institutions upto Rs. 3 crores (earlier limit was Rs. 1.50 crores). Banks are not expected to provide financial assistance to project costs ranging between Rs. 3 crores and Rs. 7.50 crores (earlier range between Rs. 1.50 crores and Rs. 5 crores) as they would be taken care of by financial institutions. In respect of projects costing more than Rs. 7.50 crores, banks may participate to the extent of 25 to 30 per cent of the term loan requirement including deferred payment guarantee. Term loans and deferred payment guarantees sanctioned for projects on a pari passu basis with other financial institutions or under the relinance scheme of IDBI/NABARD, where the share of the banking system is not more than Rs. 25 crores, do not require Reserve Bank's prior authorisation. For projects upto Rs. 3 crores (where financial institutions do not normally participate) banks should observe the guidelines of IDBI in respect of debt-equity ratio and financing pattern, and doubtful cases should continue to be referred to IDBI for prior clearance.

230. Since the conditions in the capital market gave scope for speculative activity, banks were advised in August 1985 to exercise greater caution and restraint in lending against shares and corporate securities to all parties including financial and investment companies. The need to strictly comply with the various instructions issued by the Reserve Bank, while making advances against corporate securities of every description, was reiterated in June 1986.

Credit for Specific Industries/Commodities

231. Taking into account the bumper crop of raw jute and the consequent fall in prices, the Jute Corporation of India was authorised a credit limit of Rs. 100 crores under consortium arrangement for procurement of raw jute under its price support operations; the limit was raised to Rs. 110 crores in April 1986. For its commercial operations, the Corporation was also authorised a limit of Rs. 34 crores in October 1985.

232. The Cotton Corporation of India was authorised a peak level credit limit of Rs. 210 crores under consortium arrangement for procurement of cotton under the price support operations, besides a limit of Rs. 40 crores for its commercial operations during the 1985-86 season.

233. The National Agricultural Co-operative Marketing Federation (NAFED) which is the Central nodal agency for undertaking price support operations in oilseeds was authorised a total credit limit of Rs. 60 crores during 1985-86 for undertaking procurement of different oilseeds at prices fixed by the Government. The NAFED was also authorised a credit limit of Rs. 20 crores for undertaking market intervention operations in copra as approved by the Government of India.

234. In respect of sugar industry, banks were advised to sanction for the 1985-86 season, subject to estimates of sugar production of individual sugar mills, need-based credit limits upto 100 per cent of the maximum amount availed of during 1984-85 season. Sanction of additional credit limits to individual units covered by the CAS Scheme was subject to Reserve Bank's prior authorisation.

Sick Industrial Undertakings

235. Several important changes were made in the policy relating to sick units during the year. Emphasis was placed on selection or only such units for revival, as were viable on purely commercial considerations. There was a shift in policy emphasis from ad hoc nursing of sick units to making available assistance under well integrated packages involving removal of the causes of sickness in addition to laying stress on the various reliefs and concessions to be given not only by banks and term lending institutions but also by the promoters, Government and labour. Recognising that prevention of sickness would be less expensive and more productive in the long run, than undertaking remedial measures after sickness has set in, fresh guidelines were issued to banks in October 1985 for identification of sickness in a unit at the earliest. Details of the symptoms to be watched and the common causes of sickness were listed and the concept of accountability at the branch level for timely reporting & initiation of corrective action was introduced to minimise the loss of time between the detection of the symptoms and the response thereto. Through a fresh set of guidelines issued in November 1985, banks were asked to ensure a co-ordinated approach between themselves and term lending institutions in assessing the viability of the sick units and in framing suitable rehabilitation package within the broad framework of detailed parameters evolved for the purpose. In addition, special legislation on the lines recommended by the Tiwari Committee on sick industrial undertakings has been enacted in order to handle industrial sickness effectively.

236. According to the latest data available, there were 597 large sick industrial units, with aggregate outstanding bank credit of Rs. 2,655 crores as at the end of June 1985 as compared with 545 units with outstanding amount of Rs. 2,330 crores at the end of December 1984. Of these, viability studies in respect of 503 units were completed. Of the 357 units considered viable, 264 units were put under nursing programmes by banks. As at the end of June 1985, there were 97,890 sick small-scale industrial units involving bank finance of Rs. 954.65 crores as compared with 91,450 involving bank finance of Rs. 879.69 crores at the end of December 1984. Of the 97,890 sick units, 6505 units were considered by banks as potentially viable and 2,079 among them had been brought under nursing programme. Efforts are under way to ensure that appropriate remedial steps are taken in all cases where potential viability of sick units has been established.

Selective Credit Controls

237. A reference was made in Part I of this Report to the measures taken to nationalise selective credit controls. The main changes are indicated below: Effective October 26, 1985, advances upto an aggregate limit of Rs. 50,000 per borrower in respect of all commodities were exempted from all provisions of selective credit controls, provided a borrower deals with only one bank; the limit till then was Rs. 25,000. The limit was further raised to Rs. 100,000 with effect from April 4, 1986. For commodities where there was a stipulation on the level of credit based on the three year period 1980-81 to 1982-83, the base was brought forward by one year viz., 1981-82 to 1983-84 from the same date. In the light of the distinct improvement in the supply position of wheat and the large public sector stocks, advances against wheat were exempted from all provisions of selective credit controls effective October 26, 1985. Likewise, in the context of the comfortable supply position of raw cotton and the new textile policy, advances to mills against raw cotton and kapas were also exempted from all provisions of selective credit regulations. Banks were, however, required to ensure that for those commodities inventory norms were observed and normal margins fixed on a case-by-case basis.

238. With effect from October 25, 1985, the minimum margins were reduced in the case of all advances against paddy/rice and advances to parties other than mills against cotton and kapas, by 15 percentage points. In the light of further improvement in the supply position and adequacy of stocks, all advances against stocks of paddy/rice and cotton/kapas were exempted from the provisions of selective credit controls with effect from April 4, 1986.

239. The multiple prescriptions of margins for oilseeds was rationalised with downward adjustments. The minimum margin against stocks of vegetable oils with processing units/mills was also reduced. The minimum margins on oilseeds and vegetable oils were further reduced across-the-board by 15 percentage points effective April 4, 1986. Bank advances against stocks of cottonseed and its oil were completely exempted from selective credit controls. Also, as in the case of high yielding and hybrid seeds used for growing foodgrains, advances against such seeds used for growing oilseeds were similarly exempted. The revised structure of minimum margins consequent to these changes is set out in the Table.

MINIMUM MARGINS ON BANK ADVANCES

(In percentages)

Commodities	Effective October 26, 1985			Effective April 4, 1986		
	Against Stocks		Against warehouse receipts	Against Stocks		Against warehouse receipts
	Processing units/mills	Others		Processing units/mills	Others	
Paddy/Rice	30	45	30	x	x	x
Wheat	x	x	x	x	x	x
Other foodgrains	45	60	45	45	60	45
Pulses	45	60	45	45	60	45
Oilseeds*	45	60	45	30	45	30
Vegetable oils*	45**	75	60	30**	60	45
Cotton and Kapas	x	45	30	x	x	x
Sugar —						
(a) Buffer stocks	0	—	—	0	—	—
(b) Unreleased stocks	17.5	—	—	17.5	—	—
(c) Released stocks	75	75	60	75	75	60
Gur and Khandsari	45	75	60	45	75	60

x These items were completely exempted from all stipulations of selective credit controls.

* Other than cottonseed and cottonseed oil which are completely exempt from April 4, 1986.

** Applicable to registered oil mills and vanaspathi manufacturers.

240. Banks were advised that in the case of commodities exempted from selective credit controls, inventory norms, prescription of margins by the banks and observance of credit norms and discipline must be enforced to ensure that credit was not utilised for speculative build-up of inventories. All these measures were a response to the then prevailing and anticipated development in respect of individual sensitive commodities.

Leasing

241. Consequent on the Issue of the necessary notification under the Banking Regulation Act by the Government in August 1984, commercial banks can now undertake the business of equipment leasing as one of their activities. A bank is allowed to set up a subsidiary with not less than 51 per cent of shareholding for transacting equipment leasing business, or to invest in shares within specified limits. The subsidiary promoted is, however, prohibited from transacting hire purchase business and financing of other companies or concerns engaged in equipment leasing. Banks are, besides prohibited from undertaking departmentally the business of equipment leasing as also acting as promoters of companies (other than their subsidiaries) in which they make portfolio investment. The aggregate investment of a bank in a subsidiary and/or in shares of other leasing companies should not exceed 10 per cent of the paid-up capital and reserves of the bank. Till the end of April 1986, the Reserve Bank approved proposals from six banks to make portfolio investment in equipment leasing companies and one proposal to set up a fully owned subsidiary to undertake merchant banking and equipment leasing business.

RBI Assistance to Financial Institutions

242. The Reserve Bank continued to provide financial assistance to term lending institutions by way of long-term loans and medium and short-term credit facilities. During 1985-86 (July-June) the Bank sanctioned and disbursed long-term loans amounting to Rs. 300 crores to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-term Operations) [NIC(LTO)] Fund as against Rs. 260 crores sanctioned and disbursed in the previous year. The IDBI repaid an amount of Rs. 30.90 crores during the year ended June 30, 1986. Its outstanding borrowings from the fund as on that date amounted to Rs. 2,590 crores. A short-term credit limit of Rs. 200 crores was also sanctioned in April 1986 to IDBI against the security of eligible usance bills rediscounted by it. The facility has not been utilised and the limit expired on June 30, 1986. A credit limit of Rs. 200 crores had been sanctioned during 1983-84 for enlarging assistance to State Electricity Boards and State Road Transport Corporations through IDBI's bill rediscounting scheme, which was to be repaid in 16 quarterly instalments, commencing from December 1984; of these, seven instalments were received upto the quarter ended June 1986. An amount of Rs. 112.5 crores was outstanding against the limit as on June 30, 1986.

243. The Export-Import Bank of India (Exim Bank) was sanctioned and disbursed a credit limit of Rs. 80 crores of the NIC (LTO) Fund during 1985-86, as against Rs. 55 crores sanctioned and disbursed during the previous year. The Exim Bank utilised the entire limit raising the total amount of loans outstanding from the Fund as on June 30, 1986 to Rs. 260 crores.

244. The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), which commenced its operations from March 20, 1985 is also eligible for assistance from the NIC (LTO) Fund. A credit limit of Rs. 10 crores was sanctioned to IRBI out of the fund during 1985-86. The limit was fully utilised in December 1985 and remains outstanding.

245. A credit limit of Rs. 15 crores was sanctioned to Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for the calendar year 1986, as in the previous year. The limit is to be used as a cash credit facility. The IFCI had not availed of the facility till June 30, 1986.

246. A credit limit of Rs. 15 crores was sanctioned to Industrial Credit and Investment Corporation of India for the calendar year 1986 and the Corporation availed of loans on several occasions for short periods. An amount of Rs. 13.10 crores was outstanding as on June 30, 1986.

247. The Reserve Bank sanctioned fresh ad-hoc borrowing limits aggregating Rs. 38.65 crores to 15 State Financial Corporations (SFCs) against ad-hoc bonds guaranteed by the respective State Governments. These limits were valid upto June 25, 1986. No amount was outstanding against these limits as on June 30, 1986.

248. The National Bank for Agriculture and Rural Development was sanctioned a credit limit of Rs. 1,300 crores for 1985-86 for providing short-term loans and advances by way of relinance to State Co-operative Banks and RRBs. The interest rate for this accommodation which was 4.50 per cent below the Bank rate during 1984-85 was raised to 4.25 per cent below the Bank rate from July, 1 1985. The maximum level of outstandings reached against this credit limit was Rs. 1,288 crores on April 1, 1986.

Inspection of Banks

249. During the year ended June 1986, the annual financial review of 51 public sector banks and financial inspection of 7 public sector banks, 25 private sector banks and 9 foreign banks were completed. Further, portfolio inspections of international banking divisions of seven public sector banks having overseas branches, were undertaken during the period. In addition, a number of scrutinies regarding various complaints/frauds/allegations against banks/their employees were also carried out.

Customer Service

250. Apart from monitoring the implementation by banks of the recommendations of the Working Group on Customer Service, a number of steps were taken to improve the quality of customer service rendered by banks. An impressionistic survey was carried out during July/August 1985 to assess the quality of customer service in public sector banks. On the basis of the findings, public sector banks were advised to take measures to remove the deficiencies and were requested to submit quarterly reports, indicating the follow-up action taken by them in this regard. Banks were also asked to consider constituting special squads in areas of frequent complaints, to hold on-the-spot enquiries into such complaints and to include customer service in their training programmes. Another survey was conducted in May/June 1986 at the instance of Government of India, at selected public sector banks' branches of representative character across the country to ascertain the position regarding the quality of implementation of the various measures initiated by the Government and the Reserve Bank, identifying certain key areas. The findings of the survey have been apprised to the Government.

251. Public sector banks were further advised to take steps to avoid complaints regarding collection of outstation cheques. These included the grant of immediate credit to outstation cheques for amounts upto Rs. 2,500 of individual constituents, payment of interest at rates applicable for saving bank account on delayed collection, beyond 14 days in case of instruments drawn on branches of the same bank and 21 days in the case of cheques drawn on other banks and increased use of courier service for despatch of instruments. Banks were also instructed to issue demand drafts to all customers without insisting on their having an account with them, to ensure that teller counters were kept open throughout the banking hours, and to ensure the implementation of nomination facilities to deposit holders in all their branches.

252. Government of India has advised bank officials at all levels to meet customers on specified dates each month so that they can gain an insight into the problems of the Customers. Besides customer service centres have been/are being opened at all State capitals for redressal of complaints.

Frauds in Banks

253. In view of several complaints of fraudulent withdrawals from savings bank accounts made recently, banks were advised to instruct their branches to follow strictly all the rules and procedures regarding opening of accounts,

withdrawals, maintenance of passbooks etc. The procedure for reporting instances of fraud from banks to the regional offices of the Reserve Bank and from the latter to the Bank's Central Office was clarified. Instructions were also issued to report cases of frauds committed by unscrupulous borrowers. Bank's attention was particularly drawn to certain aspects of advances against merchandise/bills which were highly fraud-prone. During the year ended June 1986, investigations of 22 frauds/complaints at 114 offices of banks were carried out and the findings communicated to the banks concerned for corrective action. The outcome of such investigations was also brought to the notice of the Government, wherever necessary.

Moratorium on Bank

254. In view of the unsatisfactory financial position and method of operation of the Hindustan Commercial Bank Ltd., the Government of India, on the recommendation of the Reserve Bank, issued an order for moratorium on it from the close of business on May 24, 1986. Steps for amalgamating it with the Punjab National Bank are under way.

Capital Base of Banks

255. During the year, the authorised capital of the State Bank of India was raised from Rs. 20 crores to Rs. 200 crores. Its subscribed and paid-up capital was raised from Rs. 5.625 crores to Rs. 50 crores by an additional issue of 44,37,500 shares. During 1985, the authorised capital of the associates of the State Bank of India was increased to Rs. 10 crores each. The total issued and paid-up capital of all these associate banks put together was increased from Rs. 5 crores to Rs. 22.45 crores. As a first step towards augmenting the capital of nationalised banks an amount of Rs. 400 crores was provided by the Government of India in 1985-86. The contribution made by the Government towards the share capital of these banks stands simultaneously invested in non-negotiable special securities floated by the Government bearing interest at 7.75 per cent.

Banking Laws Amendment Act, 1985

256. The Banking Laws (Amendment) Act, 1985 amending various statutes, mainly the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980 and the Reserve Bank of India Act, 1934 was enacted in December, 1985. Some of the provisions of the Act were brought into force with effect from December 30, 1985 and the others with effect from May 1, 1986. The more important amendments are the following: The limit in respect of borrowing powers of the State Financial Corporations was raised from 90 per cent of the paid-up share capital to twice the paid-up capital. The ceiling on the paid-up capital and reserves of nationalised banks was raised from Rs. 15 crores to Rs. 100 crores so as to improve their debt-equity ratio and profitability. The name of United Commercial Bank was changed to UCO Bank so as to avoid confusion in the international operations of the bank in view of the existence of a bank with the same name in Bangladesh.

National Clearing of Cheques

257. As part of the project to introduce national clearing of cheques and adoption of Magnetic Ink Character Recognition (MICR) technology for mechanised cheque processing, the majority of banks in Bombay, Madras and New Delhi commenced issuing MICR cheques to customers. In Calcutta, about 50 per cent of the banks have issued MICR cheques. Banks are also in the process of getting their requirements of draft forms printed in the revised format. Inter-city clearing in respect of cheques presented in Bombay and drawn on banks/branches of banks in New Delhi and Madras under the MICR national clearing project has commenced with effect from July 8, 1986. Similar facility in New Delhi and Madras for cheques presented at these centres will be extended shortly. Computerised local clearing of cheques at Bombay, New Delhi and Madras by using

MICR technology of cheque processing is also expected to commence in the next three months.

Working Groups Committees

258. A reference was made in Part I of the Report to the setting up by the Reserve Bank of a National Finance and Credit Council. The objectives of the Council are: (1) to take an overall view of the flow of finance and credit both short-term and long-term, for industry, agriculture and trade; (2) to co-ordinate policies relating to the flow of short-term and long-term credit; and (3) to consider developments in capital and money markets with a view to enhancing their role and efficiency.

259. A committee to review co-ordinate, monitor and guide the training arrangement in banks on an ongoing basis was set up by the Reserve Bank in March 1986 with the Deputy Governor in charge of training as its chairman. The functions of the committee are to: (i) co-ordinate among industry level training institutions inter se as also with the training establishments of banks, (ii) assess the emerging training needs and gaps, if any, in the existing arrangements and suggest appropriate action by banks, (iii) review the training infrastructure and assess the adequacy of arrangements regarding manning and training of faculty, procedures for selection of candidates for training and their post-training placements and generally evaluate the effectiveness of the training systems, (iv) authorise special studies/research work for furthering the cause of training in banking, and (v) provide appropriate guidance to banks for evolving and implementing a comprehensive system of training to all categories of bank staff.

260. The Reserve Bank has appointed a standing advisory committee under the chairmanship of a Deputy Governor, to review the flow of institutional credit to small-scale industries sector and other related matters. The main terms of reference of the committee are: (i) to review the flow of institutional credit for small-scale industries (SSI) sector, identify operational deficiencies, if any, and suggest remedial measures; (ii) to examine the support available from State Government agencies, in particular district industries centres to financial institutions for ensuring adequate and smooth flow of credit to small-scale industries and suggest measures for improvement where necessary; (iii) to look into the arrangements available for upgradation of entrepreneurial skills and modern technology in respect of SSI units and make suitable recommendations and (iv) to review the problem of sickness in SSI units in relation to the role of various agencies concerned and recommend suitable remedial action.

261. In February 1986, the Bank appointed a committee under the chairmanship of an Executive Director to consider problems of identification and rehabilitation of sick SSI units. The committee was asked to examine and make recommendations on: (i) Definition of a sick SSI unit; (ii) identification of incipient sickness in SSI units; (iii) establishment of a suitable machinery for identification of sickness, preparation of rehabilitation packages in the case of potentially viable units, and follow-up and monitoring of implementation; and (iv) formulation of parameters for provision of reliefs/concessions by commercial banks, State Financial Corporations, State Governments and other agencies under rehabilitation packages evolved for sick SSI units considered as potentially viable. The report has been finalised and will be submitted shortly.

DEVELOPMENTS RELATING TO CO-OPERATIVE BANKING

Progress of PCBs

262. As on June 30, 1986 there were 1,346 primary co-operative banks in the country comprising 1,247 urban co-operative banks (UCBs) and 99 salary earners' societies. During the year (July 1985—June 1986), 33 banks (new as well as existing) were issued licence to commence/carry on banking business taking the total number of licensed banks to 461. The total number of offices of primary co-operative banks (including head offices) increased to 2,995

as on March 31, 1986 from 2,897 at the end of June 1985. There was no addition to the number of licensed State and central co-operative banks which remained at 8 and 35 respectively.

Refinance Facilities

263. During the fiscal year 1985-86, short-term credit limits aggregating Rs. 24.61 crores were sanctioned to 5 State co-operative banks in respect of 43 urban co-operative banks for financing cottage and small scale industrial units at concessional rate of interest. Applications for sanction of loans aggregating Rs. 23.77 lakhs for contribution to the share capital of 16 UCBs were received during the year from the State Government of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Manipur. Out of this, amounts aggregating Rs. 14.77 lakhs for contribution to the share capital of 9 UCBs were recommended to NABARD for sanction. This arrangement with NABARD for sanctioning of loans to State Governments for contribution to the share of UCBs expired on April 1, 1986.

Working Capital Limits for Co-operative Sugar Factories

264. For the 1985-86 crushing season, the State co-operative banks were allowed to sanction without prior authorisation from NABARD, pledge limits to co-operative sugar factories against sugar stocks, to the extent of 100 per cent of the maximum amount availed of during the previous season keeping in view the need-based requirements of individual sugar factories for funds in relation to their production programmes. For additional pledge limits, if required by sugar factories, the State co-operative banks had to obtain prior authorisation from NABARD. Further, the central co-operative banks were to continue to obtain prior authorisation from NABARD for sanction of working capital limits in excess of the limit of Rs. 150 lakhs in individual cases.

UCBs' Lending to Priority Sectors

265. Urban co-operative banks had been exhorted to ensure that not less than 60 per cent of their loans and advances went to priority sectors by the end of June 1985, of which 25 per cent was to go to the weaker sections of society. Banks whose levels of advances to priority sector were less than 40 per cent as on June 30, 1983 had been advised to step up their lending to these sectors by 10 per cent every year. Available information indicates that while smaller urban banks operating in urban and semi-urban areas made significant strides in lending to priority sectors, the performance of bigger banks was not very satisfactory. This matter was reviewed by the Standing Advisory Committee and it was agreed to extend the target date up to end-June, 1986.

Permission to Accept NRE Accounts

266. In response to requests from urban co-operative banks it was decided to allow selected banks to open and maintain Non-Resident (External) Rupee accounts. During the year seven UCBs were issued authorisation to open and maintain such accounts.

Standing Advisory Committee for UCBs

267. The Standing Advisory Committee for UCBs discussed various issues such as revision in the viability norms for urban co-operative banks, representation of urban banks on the boards of management of State and central co-operative banks and the need for streamlining the procedure for appointment of chief executives of urban banks. It also reviewed the policies relating to refinance facilities for small-scale industries, licensing of existing banks and the performance of urban co-operative banks in lending to priority sectors.

Studies and Working Groups Relating to Rural Development

268. As part of the World Bank aided NABARD-I credit project, a wide ranging review of the agricultural credit system in India is to be undertaken. The review is to consist of five studies viz. (a) role and operations of the agricultural credit system, (b) role and effectiveness of individual

lending institution, (c) scope of supervisory and regulatory functions of the apex level institutions in agricultural credit, (d) costs of lending and margin and (e) effectiveness of NABARD's operations. These studies will be conducted under the guidance and superintendence of a senior level expert group which will evaluate the major problems and issues currently affecting the agricultural credit system and make recommendations for a programme to strengthen the sector.

269. The Working Group appointed in June 1984 to study operational problems of State Handloom Development Corporations in relation to bank credit completed field studies in Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal, Uttar Pradesh and the north eastern region. The field visits helped the Working Group in understanding the various operational problems such as supply and distribution of yarn to weavers, marketing of handloom products and raising finance for production and marketing in the context of local conditions. A preliminary draft report of the Working Group has been prepared.

270. The Reserve Bank set up a high level standing committee under the chairmanship of a Deputy Governor to review the flow of institutional credit to the rural sector and other related matters. The Committee will suggest measures for improving the credit delivery system for the greater benefit of the weaker sections. The terms of reference of the Committee are : (i) to review and assess the requirements and availability of institutional credit for agricultural and rural development; (ii) to identify operational shortcomings which inhibit effective delivery of institutional credit to intended beneficiaries and suggest remedial measures; (iii) to examine the progress made in correcting regional imbalances in the matter of agricultural credit and related facilities and to recommend appropriate steps for improvement; (iv) to suggest measures so that the co-operative and land development banks at State and district levels become effective agencies to facilitate flow of rural credit; (v) to review the progress of flow of credit and complementary inputs to weaker sections of society and recommend measures for improvement; (vi) to recommend measures for improving the effectiveness of co-ordination between credit institutions and various State Government agencies at or below the district level; (vii) to suggest improvements in needed infrastructural support and packages of complementary inputs including technological support to make rural credit more effective; (viii) to identify factors which adversely affect the timely recovery of rural credit and suggest ways and means of improving recycling of funds of credit institutions; and (ix) to promote co-ordination at the national and State levels, among credit institutions and other agencies concerned with institutional credit for agricultural and rural development.

271. This Committee constituted a Working Group to consider (i) the problems relating to non-availability of credit to new and non-defaulting members of co-operative credit institutions and to suggest measures to ensure smooth flow of credit to these borrowers and (ii) to recommend measures that could be taken to assist the co-operative credit structure in areas susceptible to repeated natural calamities and their impact on recovery of loans.

DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL AND OTHER MATTERS

Forward Exchange Cover

272. In view of the changing external trade and payments scenario and the emergence of new lines of activities on a larger scale, a review of the regulations relating to forward sale and purchase contracts for foreign currencies undertaken by authorised dealers was made. It was found necessary to enlarge the scope and coverage of some of the existing facilities and introduce forward cover facilities in respect of some newly emerging business activities. Accordingly the Reserve Bank introduced a number of changes in the package of forward cover facilities with effect from December 28, 1985. The new areas where forward cover facilities were introduced for the first time are (i) roll-over forward cover for repayment of foreign currency loans, (ii) cross-currency forward cover for payments towards imports financ-

ed out of foreign currency loans where the goods are invoiced for payment in a currency/currencies other than the currency of the loan, (iii) cross-currency forward cover in respect of repayment of instalments of a loan obtained in one foreign currency by an Indian Airline or a shipping company for acquisition of aircraft/ships from out of revenue earnings in other foreign currencies, (iv) forward cover for charter hire payments by Indian airline and shipping companies/shippers, (v) forward cover for remittance of technical know-how fees, (vi) forward cover for remittance of erection and commissioning charges and (vii) forward cover for retransfer abroad of funds temporarily brought into India by Indian companies/firms executing turnkey/civil construction/service contracts abroad.

Relaxation in Exchange Control Procedure

273. According to the recommendations of the Expert Committee on Exports and Imports, the period prescribed for realisation of proceeds of India's exports to Pakistan and Afghanistan was raised from 3 months to 6 months from the date of shipment with effect from October 1, 1985.

The RIFEE Scheme

274. Under the Returning Indians Foreign Exchange Entitlement—(RIFEE) scheme, prior to December 26, 1985, eligible non-residents of Indian nationality or origin returning to India for permanent settlement were entitled to avail of foreign exchange upto 25 per cent of the total amount repatriated to India and balances held in their Non-resident (External) Accounts or Foreign Currency Non-resident Accounts at the time of transfer of residence. The limit for foreign exchange entitlement under the scheme was raised from 25 to 50 per cent with effect from December 26, 1985.

Foreign Travel Under Special Travel Scheme

275. Under the Foreign Travel Scheme (FTS) Indian residents were eligible to undertake visits to any country (other than Nepal and Bhutan) once in two calendar years and were entitled to draw foreign exchange upto the equivalent of U.S. \$ 500 per capita. Similarly, under the Neighbourhood Travel Scheme (NTS) Indian residents were eligible to visit any country in the group of eight neighbouring countries (viz., Bangladesh, Burma, Malaya, Maldives Islands, Mauritius, Pakistan, Seychelles Islands and Sri Lanka) once in two calendar years and to draw foreign exchange upto the equivalent of U.S. \$ 250 per capita. According to changes made with effect from April 7, 1986, foreign travel under these schemes can be undertaken only once in three calendar years instead of two years. Further, combination of FTS and NTS for the purpose of drawing exchange is not permissible.

Import-Export Pass Book Scheme

276. The Government of India has introduced an 'Import-Export pass book Scheme' for manufacturer-exporters to provide duty-free access to imported inputs for export production. This scheme, which is broader in its coverage than the advance licensing scheme is intended to help the regular registered manufacturer-exporters to obtain their requirements of imported articles such as raw materials duty free to suit their production/export time schedules. The validity of the pass book for the purpose of import is 18 months and for the purpose of export 27 months from the date of issue. No letter of credit can be allowed to be opened against the licence incorporated in the pass book in favour of any person other than the licensee nor is any letter of authority permissible against such a licence.

Asian Clearing Union

277. With effect from August 1, 1985, the Reserve Bank has arranged to announce on a daily basis its rates for purchase and sale of the Asian Clearing Union (ACU) currencies. This is in response to the decision taken by the ACU to the effect that exchange rates for ACU currencies against domestic currencies of the participating countries should be quoted by the respective central banks on a daily basis to overcome the problem of divergence between the rates fixed for the accounting period and the actual daily rates.

1086 GI/86—22

Standing Consultative Committee on Exchange Control

278. As recommended by the Committee on Export and Imports, the Reserve Bank has constituted a Standing Consultative Committee to advise on matters relating to administration of exchange control on an ongoing basis. The Committee comprises representatives of the Foreign Exchange Dealers Association of India, Exim Bank, Export Credit Guarantee Corporation of India, Trade Development Authority, a few of the associations of commerce, industry and travel and airline representatives in India besides officials from Government of India and the Reserve Bank.

Indianisation of Foreign Companies.

279. During the year ending June 1986, 3 more companies complied with the directive for dilution of non-resident interest to the required level taking the total number of such companies to 359 out of 382 companies against which final orders under section 29(2) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 had been passed for Indianisation and/or dilution of foreign equity.

Working Group on Exchange Control

280. The Working Group on Exchange Control constituted by the Reserve Bank to which a reference was made in the previous year's Report submitted its report in January 1986. Several recommendations made by the Working Group for simplification and selective liberalisation of exchange control policies in the interest of better customer service have been accepted and already implemented by the Bank. These relate inter alia to foreign travel under the special travel schemes, remittance facilities available to non-residents of Indian nationality or origin, remittance of dividend by non-FERA companies and agency commission on exports.

Committee on Non-resident Indians investment

281. The Committee set up to review the exchange control procedures followed by the Reserve Bank and commercial banks in respect of investment schemes for non-resident Indians and to suggest measures for simplifying and improving these procedures submitted its report in October 1985. A number of recommendations of the Committee have since been accepted by Government of India and implemented by the Reserve Bank.

Indian Joint Ventures Abroad

282. At the end of December 1985, there were 208 Indian joint ventures abroad of which 156 were in operation and 52 at different stages of implementation. The value of share capital of Indian entrepreneurs in the joint ventures in operation was around Rs. 93.84 crores and in the projects under implementation Rs. 23.48 crores. These overseas projects have generated additional exports from India to the tune of Rs. 147.91 crores.

Other Developments

283. During the year ended June 1986, 52 overseas companies were granted permission to open new liaison/representative offices in India. Further, a few Indian companies were permitted to open 20 trading and 32 non-trading offices and to post 24 representatives at various foreign centres. Permission was also granted for opening one showroom at a foreign centre and 16 project offices for execution of specific contracts.

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

284. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation made notable progress during the year in fulfilling its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended by eligible credit institutions to certain categories of small borrowers, particularly those belonging to the weaker and hitherto neglected sections of the society. For this purpose, the Corporation is operating five credit guarantee schemes including the small loans (co-operative banks) guarantee scheme 1984, introduced with effect from July 1, 1984.

285. The number of insured banks increased by 30 to 1,851 during the year ended June 1986 and comprised 83 commercial banks, 193 regional rural banks and 1,575 co-operative

banks. The deposit insurance scheme now covers 14 States and 3 Union territories. The number of fully protected accounts increased from 2,000 lakhs at the end of June 1984 to 2,145 lakhs by the end of June 1985 and constituted 95.8 per cent of the total number of accounts. The insured deposits increased from Rs. 46,340 crores to Rs. 56,211 crores during the same period and constituted 73.5 per cent of total assessable deposits as at the end of June 1985.

286. During 1985-86 (July-June) the number of credit institutions participating in the small loans guarantee scheme, 1971 increased by 19 to 251 and comprised 71 commercial banks and 180 RRBs. Those participating in the service co-operative societies guarantee scheme, 1971 increased by 4 to 173 comprising 58 commercial banks, 78 RRBs and 37 co-operative banks. The number of financial corporations (including State industrial development corporations) participating in the small loans (financial corporations) guarantee scheme, 1971, also increased by 1 to 20. At the end of June 1986, 44 primary (urban) co-operative banks were participating in the small loans (co-operative banks) guarantee scheme, 1984. The total guaranteed advances to small borrowers under the above four schemes aggregated Rs. 8,923 crores at the end of June 1985, recording a rise of 25.6 per cent over the previous year.

287. The number of institutions participating in the Corporation's small loans (SSI) guarantee scheme, 1981, rose to 462 by the end of June, 1986 comprising 69 commercial banks, 143 RRBs, 14 State financial corporations, 8 other State development agencies and 228 co-operative banks. The guaranteed advances to the small-scale industrial sector increased from Rs. 4,891 crores to Rs. 5,844 crores over the year ending June 1985 or by 19.5 per cent.

288. During the year ended June, 1986, the Corporation received 4,86,577 claims for Rs. 114.23 crores in respect of its guarantee schemes relating to small borrowers and 24,858 claims for Rs. 84.05 crores in respect of the scheme for small-scale industries. Total disposal in respect of the latter during the same period was 6,16,449 claims for Rs. 151.42 crores and in respect of the latter 26,815 claims for Rs. 52.83 crores.

Non-Banking Companies : Chit Fund Act, 1982

289. During the year the provisions of the Chit Fund Act, 1982 and rules framed thereunder were brought into force in Orissa and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Goa, Daman and Diu. With this, the Act has been brought into force

in 6 States and five Union territories. The States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Meghalaya, Manipur, Rajasthan and Madhya Pradesh and Union territories of Delhi and Pondicherry have finalised their rules and further action by them is awaited. The remaining States/Union territories are yet to finalise their draft rules.

Acceptance of Deposits by Non-Banking Companies

290. The provisions of Chapter III C incorporated in the Reserve Bank of India Act, 1934 which relate to prohibition of acceptance of deposits by unincorporated bodies, except to a limited extent, had come into force in February 1984. Accordingly, the State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Gujarat, Karnataka, Nagaland, Kerala and Tamil Nadu have created necessary machinery for the enforcement of the Act. In February 1986 the Reserve Bank initiated action against several private financial concerns under the provisions of Chapter III C in the States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Several writ petitions were filed in law courts challenging the constitutional validity of the provisions of Chapter III C of the Act but were dismissed. Appeals against these decisions filed in the Supreme Court are pending.

Trend of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

291. Aggregate deposits held by 7,508 reporting financial and non-financial companies and miscellaneous non-banking companies stood at Rs. 16,140 crores as on March 31, 1985 as against Rs. 11,124 crores, held by 6,798 reporting companies a year ago. The number of deposit accounts rose from 88.97 lakhs to 124.14 lakhs during the same period. Regulated deposits rose by Rs. 431 crores and exempted deposits by Rs. 4,536 crores during 1984-85 (April-March). Regulated deposits held by non-financial companies worked out to 15.8 per cent of their aggregate net owned funds which is well below the statutory ceiling of 35 per cent upto which deposits can be accepted by these companies. In the miscellaneous non-banking companies category also, excepting the chit fund companies, regulated deposits remained within the respective ceilings prescribed under the directive. The aggregate deposits of Rs. 16,140 crores in the non-banking corporate sector as on March 31, 1985, constituted 22.2 per cent of total deposits held by all scheduled commercial banks as against 18.3 per cent in March 1984. Regulated deposits with non-banking companies recorded a growth rate of 20.6 per cent during 1984-85 as against 19.5 per cent in respect of bank deposits.

292. Details of deposits held by different categories of companies as at the end of March 1985 and 1984 are given below :

	(Amount in Rupees crores)			
	1983-84		1984-85	
	No. of reporting companies	Amount	No. of reporting companies	Amount
Aggregate deposits	6798	11124	7508	16140
of which :				
Regulated deposits		2334		2815
Exempted deposits		8790		13325
Deposits held by :				
(i) Government companies	48 (0.7)	5744 (51.6)	55 (0.7)	8923 (55.3)
(ii) Public limited companies	2346 (34.5)	4580 (41.2)	2516 (33.5)	5617 (34.8)
(iii) Private limited companies	4404 (64.8)	800 (7.2)	4937 (65.8)	1600 (9.9)
(a) Financial companies	3599 (53.0)	2770 (25.0)	4134 (55.1)	3914 (24.3)
(b) Non-financial companies	2558 (37.6)	7963 (71.6)	2510 (33.4)	11784 (73.0)
(c) Miscellaneous non-banking companies	641 (9.4)	382 (3.4)	864 (11.5)	442 (2.7)

Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies/aggregate deposits as the case may be.

Surveys

293. An analytical report based on the findings of the All-India Debt and Investment Survey, 1981-82 relating to assets and liabilities of the households at the beginning of the reference period viz., July 1, 1981, was prepared for publication. A similar report giving details of the capital expenditure, borrowings and repayments during the reference period and the outstanding debt at the end of the year is under preparation.

894. The field work for the survey of beneficiaries and non-beneficiaries, 1983-84 conducted to study the impact of IRDP schemes in selected districts spread over the country was completed. A brief analytical report of the findings of the Survey is under preparation. The processing of data relating to the survey of small-scale industrial units, private corporate units and artisans and craftsmen, 1983-84 is also in progress.

Currency Chests

295. The total number of currency chests in the country at the end of March 1986 was 3,506 (excluding 487 repositories). Of these 17 currency chests continued to be maintained with the Reserve Bank, 2,610 were with the State Bank of India group, 502 with nationalised banks, 372 with treasuries/sub-treasuries and 5 with Jammu & Kashmir Bank, Limited.

ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

Mechanisation/Computerisation

296. During the year, a few additional areas were covered under the programme of mechanisation/computerisation in the Bank using the mini-computer/micro processor systems installed in Bombay. Following the successful experiment at Byculla Office, similar mini-computers were installed at Ahmedabad, Nagpur and New Delhi for resource and accounting operations of issue Department. Installation of mini-computers to cover clearing house operations at Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur has been completed. Work on development of dedicated telecommunication network for the Bank has commenced and the same will be completed in segments in the next two years.

Bankers Training College, Bombay

297. The bank imparts training to its officers/staff and officers of commercial, co-operative and regional rural banks, Central and State Governments as also foreign trainees through its training establishments comprising three colleges and four zonal training centres. The Bankers Training College continued to conduct general broad spectrum programmes with a view to providing specialised functional and managerial training to the officers of the commercial banks, financial institutions, the Reserve Bank and certain cadres of Government of India. These programmes in general concentrate on perspective building, emphasising conceptual skills in functional areas such as credit management and appraisal, foreign exchange, inspection and specialised programmes like personnel management. Besides the regular programme, the College conducted a few new programmes, such as faculty development (computer); computerisation (systems analysis); computer orientation programme; mechanisation in banks; auditing the dealing room; currency/coin management; legal officers' programme; portfolio and funds management; public relations in banks; international economic relations; non-resident investments and financing of priority sectors (Hindi medium). During the year, the College conducted 81 programmes and trained 2,030 officers. In all, 30,827 participants attended the programmes since the inception of the College in 1954.

298. The College also provided faculty assistance to colleges of other banks in response to their requests. At the request of Bank Markazi, Iran, a team of faculty members conducted a programme on foreign exchange in Iran during September-October 1985. Programmes on foreign exchange business and credit appraisal were also conducted in Mauritius in March 1986.

1086 GI/86—23

299. Besides the BTC Bulletins, the College also brought out during the year a publication titled 'Guidelines for Internal Bank Inspection' to cater to the needs of bankers.

Reserve Bank Staff College, Madras

300. The Reserve Bank Staff College at Madras continued to cater to the training needs of staff officers grade A to C in different departments of the Bank with the objective of using training as an integral part of human resources development. The College conducted training programmes on annual financial review, planning and budgetary control, executive health, time management and communication workshop for the benefit of senior officers of the Bank. The College also imparted training to the newly promoted staff officers in Grade A through specially designed programmes in the officers development programme series. Outstation programmes at Trivandrum, Ahmedabad, and Hyderabad were conducted for the benefit of officers of urban co-operative banks of respective States. Officers from public sector banks in the country as also from central banks/other institutions of Kenya, Bhutan, Zambia, Tanzania, and Botswana attended some of the programmes conducted by the College. The new programmes introduced during the year included the following: supervision and control over banks; officers development programmes; workshop on planning and budgetary control; inspection officers' programme (advanced); systems analysis and computer programming and refresher/crash programmes for officers.

301. With the introduction of the 5th channel of training in January 1986, the College now has a capacity to train about 2,500 officers each year. During the year the College conducted 92 training programmes and trained 2,037 officers. In all 18,421 officers attended various programmes since the inception of the College.

College of Agricultural Banking, Pune

302. The College of Agricultural Banking continued to conduct various broad spectrum and specialised programmes on agricultural finance and allied subjects for personnel attached to commercial/co-operative banks, NABARD and the Reserve Bank. The new programmes conducted during the period under review included: regional course on rural finance for trainers sponsored by the Economic Development Institute; programme on financing of forestry with focus on tribal development; programme on formulation and implementation of dry land projects; rural development projects course for trainers; programme on rural credit management; and joint training course on fisheries. Besides, the College also conducted 84 regular programmes, 2 outstation programmes, one each at Nagpur and Bangalore, one international programme sponsored by the World Bank jointly with the College and two seminars. A total of 2,379 officers attended these programmes, thus raising the total number of participants trained since the inception of the College to 28,379.

Zonal Training Centres

303. The Zonal Training Centres of the Bank at Byculla (Bombay), Calcutta, Madras and New Delhi cater to the training needs of the Bank's staff at the clerical and non-clerical levels. They also conduct special courses for clerks gr. II at the entry point, special programme for teller/coin-note examiners gr. I, courses for stenographers/typists as also for Class IV staff. During the year, 2,146 Class III members of clerical and non-clerical staff and 501 members of Class IV staff received training at the four centres raising the total number of staff trained to 29,940 and 1,092 respectively, since the establishment of these training centres.

Training in Commercial Banks

304. With a view to exposing the officers of the Bank to various aspects of working of commercial banks the Bank has evolved three schemes of training in commercial banks. The first scheme envisage training of officers of grades A, B and C in rural and urban branches of public sector banks for a period of two years. Under the second scheme, officers in grades D and E will be deputed to controlling/head offices of banks for a period of six months for an in-depth exposure in key departments including internal inspection/audit departments. The third scheme envisages an exchange of senior

officers between the Bank and selected public sector banks with the objective of widening their perspective and enriching their experience. The first phase will cover 40, 4 and 6 officers, respectively under the three schemes. It is expected that within the period of next five years, the Bank will have a pool of officers with in-depth exposure to commercial banks who can be placed appropriately in various departments of the Bank.

Deputation of Staff for Training in India and Abroad

305. The Bank deputed 188 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management institutes of repute in India and continued to make extensive use of training facilities offered by various foreign training institutions. In all, 27 officers of the Bank were deputed for training and study visits to banking and financial institutions abroad including USA, England, Switzerland, West Germany and Japan.

Training Facilities extended to officers of Foreign Banks

306. The Bank continued to extend training and study facilities to participants from foreign central and commercial banks in response to specific requests received from them, including those sponsored under schemes of international co-operation. Of the 77 foreign officials who were afforded training/study facilities, 15 were from Sri Lanka, 10 from Tanzania, 9 from Nepal, 6 from Ethiopia, 5 from Botswana, 4 each from Sudan, Nigeria, Bhutan, Kenya and Burma, 2 each from Vietnam and Gambia and one each from Uganda, Iran, Ghana, Zambia, Bangkok, Seychelles, Indonesia and Korea.

Employer-employee Relations

307. The pay revision for the officers was finalised and announced on September 27, 1985. The revised pay-scales were made effective from February 1, 1984. Negotiations on pending issues were also held with the recognised Class III and Class IV unions and satisfactory solutions to certain

problems concerning the workmen employees were arrived at. During the conference of managers held in March 1986, important issues as review of industrial relations scenario in the bank, staff motivation, enforcement of discipline and punctuality, use of computerisation and mechanisation, improvement of customer service, issues relating to currency and coinage and the branch manager's role were discussed.

308. Certain provisions of the Bank's scheme of promotion to staff officer grade A had been struck down by the Nagpur Bench of the Bombay High Court in March 1981. The Bank had thereafter gone in appeal to the Supreme Court. A division bench of the Supreme Court in its judgement dated April 30, 1986, set aside the High Court's judgement. The scheme of promotion as modified by the Bank has been affirmed by the Supreme Court as valid as the scheme provides for a happy blend of two important constituents of service—one which brings fresh clerical employees and the other matured experience. In allowing the Bank's appeal the court also observed that in matters of service conditions it is difficult to evolve an ideal set of norms governing various conditions of service and in the grey area where service rules operated, if more than one view is possible, without sacrificing either reason or commonsense, the ultimate choice has necessarily to be conditioned by several considerations that would ensure justice to as many as possible and injustice to as few.

Representation of SCs/STs

309. The total strength of scheduled castes and scheduled tribes employees in the Bank in Class IV as on January 1, 1986 was 2,317 comprising 1,829 of the former and 488 of the latter. In Class III, of the 3,034 SC/ST employees, 2,065 were SCs and 969 STs. In Class I, of the 386 employees in SC/ST, 320 were SCs and 66 STs. Particulars of direct recruitment in various classes of service in the Bank during the calendar year 1985 and the representation of SCs/STs in the total recruitment are given in the Table.

Category	Total No. of candidates recruited	Of which		Percentage of	
		SCs	STs	SCs	STs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Class I	21	5	14	23.8	66.7
Class III	110	17	6	15.5	5.5
Class IV					
(i) Other than sweepers	86	23	12	26.7	14.0
(ii) Sweepers	6	4	1	66.7	16.7

3.10 Arrangements were made to impart pre-examination training to SC/ST candidates applying for the post of Staff Officer gr. A (direct recruit) in response to the Bank's advertisement issued in February 1986.

Employment of Ex-servicemen

311. Reservation at the rate 14-1/2 per cent and 24-1/2 per cent for Class III and IV posts, respectively, is provided by the Bank for ex-servicemen. During 1985, out of 110 vacancies filled in Class III and 112 in Class IV, 16 and 27 vacancies were required to be reserved for ex-servicemen at the prescribed rates of reservation. As against this, 9 vacancies in Class III and 11 vacancies in Class IV were actually filled in. The total strength of ex-servicemen as on December 31, 1985 was 569 in Class III and 877 in Class IV.

Promotion of Hindi

312. Promoting the use of Hindi in various offices/departments of the Bank continued to receive special attention. Annual time-bound programmes for 1985-86 regarding use of Hindi were circulated to various offices/departments for implementation. Hindi cells were opened in five main Central Office departments for increasing the use of Hindi in their day-to-day working. Circulars, office orders and other general orders, were issued bilingually and Bank's publications

reports also continued to be brought out both in Hindi and English. Employees were imparted training in Hindi noting, drafting and correspondence through Hindi workshops, and Hindi classes continued to be conducted for the benefit of the staff under the compulsory/voluntary Hindi teaching scheme.

313. With a view to overseeing the progress made by the departments/offices of the Bank, the Official Language Implementation Committee in Central Office continued to hold its quarterly meetings and the decisions taken therein were conveyed to the departments/offices for implementation. Apart from the 'Rajbhasha Shield' competitions, departmental shield scheme is also being introduced in each department in the Central Office and region 'C' offices to encourage the use of Hindi in their working. Elocution competitions, poets' gatherings, essay competitions, competitions in noting and drafting in Hindi and Hindi samarohs were also organised during the year. The Bank continued to bring out help literature for facilitating use of Hindi in day-to-day work.

Office Premises and Residential Quarters

314. During the year, a sum of Rs. 28.03 crores was spent on construction/acquisition of office buildings and residential quarters, additions/alterations to the existing premises and purchase of land. The total expenditure in the first 3 years

of the 5 year plan for construction of office buildings and residential quarters would thus work out to Rs. 71.31 crores against a total outlay of Rs. 161.15 crores over the 5 year plan period.

315. During the year under review the additional office building at Nagpur and the expansion scheme at the Bankers' Training College in Bombay were completed. The construction of additional floors in the existing office building at Bangalore is likely to be completed by September 1986. Work is in progress for construction of office buildings at Chandigarh, Cochin, Bandra-Kurla Complex in Bombay and at Kanpur. The proposed office buildings at Bhopal, Cochin, Jammu and New Bombay are at planning stage and work is likely to start during 1986-87. The general building work of the proposed Indira Gandhi Institute of Development Research at Bombay being established as part of the Bank's golden jubilee celebration has commenced and is progressing fast.

316. Progress was made in the provision of various facilities required for the proposed computer installation for national clearing cells at Bombay, New Delhi and Madras. These include air-conditioning, uninterrupted power supply, system, raised flooring, false ceiling and diesel generator sets. The work for the Bombay centre is expected to be completed by August and at New Delhi and Madras by September 1986.

The total cost for all three centres is approximately Rs. 180 lakhs.

317. During the year, construction of 734 flats and 8 single rooms were completed comprising 136 flats and 8 single rooms for officers, 196 flats for Class III staff and 402 flats for Class IV staff in different centres. Including the 251 flats in Hyderabad which were targetted to be built in 1984-85 but were actually completed only in 1985-86, a total of 2,560 flats and 36 self-contained single rooms have been completed in the first three years of the Plan for various categories of staff; the cadre-wise break-up is: 589 flats and 36 single rooms for officers, 987 flats for Class III staff and 984 flats for Class IV staff. At 12 centres, 1,202 flats and 984 flats 1,565 flats for Class III staff and 320 flats for Class IV staff are under construction. A number of projects for residential quarters for staff are at different stages of planning at various centres.

Housing Loans

318. During the year ending June 1986, housing loans aggregating Rs. 5.69 crores were sanctioned, details of which are given in the Table.

	No. of Societies	No. of employees	Amount sanctioned (Rs. lakhs)
A. Co-operative Housing Societies			
Fresh loans	12	208	139.31
Additional loans	27	185	37.55
TOTAL	39	393	176.86
B. Individual loans			
Fresh loans		218	141.00
Additional loans		6	1.04
Loans sanctioned by Regional Officers*		626	250.51
TOTAL		850	392.55

*Up to end-March, 1986.

Central Board

319. Prof. M.L. Dantwala relinquished charge as director of the central board on December 20, 1985. The board placed on record its high appreciation of the valuable services rendered by him and of his contributions to the deliberations at its meetings. Shri S. S. Marathe was appointed in place of Prof. Dantwala on January 16, 1986. Shri M.S. Patwardhan was appointed as a director on the same date in one of the existing vacancies.

Local Boards

320. The appointment of Shri S.S. Marathe on the central board was made following his nomination as a member of the western area local board in place of Prof. M.L. Dantwala with effect from January 16, 1986.

321. The board regrets to report the sad demise on March 26, 1986 of Shri G.R. Ramaswamy, a member of the local board (southern area) of the Bank and places on record its appreciation of the valuable services rendered by him.

Accounts

322. During the accounting year ended on June 30, 1986, the Bank's income after making adjustments for various provisions amounted to Rs. 1,381.40 crores as against Rs. 1,246.98 crores for the previous year.

323. The contributions to the National Rural Credit (Long-Term Operations) Fund, National Rural Credit (Stabilisation) Fund and National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund during 1985-86 were Rs. 350 crores, Rs. 10 crores and Rs. 400 crores as against Rs. 300 crores, Rs. 25 crores and Rs. 350 crores, respectively, during 1984-85.

324. Out of the balance of income amounting to Rs. 621.40 crores, after allowing for the total expenditure of Rs. 411.40 crores during the year (as against the balance on income of Rs. 571.98 crores and expenditure of Rs. 361.98 crores in 1984-85), the surplus profit set aside for payment to the Central Government was Rs. 210 crores (same as on the previous year).

325. The rise of Rs. 134.42 crores in the income of the Bank from the previous year's level of Rs. 1,246.98 crores to Rs. 1,381.40 crores during the year was due chiefly to higher discount earned on Rupee treasury bills and higher interest earned on loans and advances to banks, partly offset by decline in the interest earned on ways and means advances to State Governments and increase in the amount of interest paid to schedule commercial banks on their additional cash reserves kept with the Bank. The rise of Rs. 49.42 crores in expenditure was mainly due to increase in the cost of security printing and turnover commission payable to the agency banks for handling Government transactions.

Auditors

326. The accounts of the Bank have been audited by Messrs. K.C. Khanna & Co., New Delhi Messrs. Ved Co., Ghaziabad, Messrs. Dass Gupta & Co., New Delhi, Messrs. C.C. Chokshi and Co., Bombay, Messrs S.R. Batliboi and Co., Calcutta and Messrs. Brahmayya & Co., Madras. All the auditors were re-appointed by the Government of India. This year also, all the offices of the Bank were audited by the statutory auditors. For the purpose of audit, all the offices of the Bank were divided into six zones and the audit fees paid per zones per auditor were Rs. 75,000. An additional fee of Rs. 5,000 was paid to central office auditors for consolidation of branch accounts.

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 30th JUNE 1986

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES				ASSETS			
	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
Notes held in the Banking Department	15,38,14,668.00				Gold Coin and Bullion:		
Notes in circulation	27376,84,16,312.50				(a) Held in India	274,27,76,380.65	
					(b) Held outside India	..	
					Foreign Securities	1564,05,75,253.50	
Total Notes issued			27392,22,30,980.50		Total		1838,33,51,634.15
					Rupee Coin		22,51,68,831.20
					Government of India		
					Rupee Securities		25531,37,10,515.15
					Internal Bills of		
					Exchange and other		
					Commercial Paper		..
Total Liabilities			27392,22,30,980.50		Total Assets		27392,22,30,980.50

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES				ASSETS			
	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
Capital Paid up	5,00,00,000.00				Notes	15,38,14,668.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00				Rupee Coin	8,11,044.00	
National Industrial Credit (LTO) Fund	3295,00,00,000.00				Small Coin	2,45,531.52	
Deposits:					Bills Purchased and Discounted :		
(a) Government					(a) Internal	..	
(i) Central Government	57,09,03,373.31				(b) External	..	
(ii) State Governments	14,01,33,635.35				(c) Government Treasury Bills	15834,61,56,415.79	
(b) Banks					Balances held abroad	3760,23,20,272.63	
(i) Scheduled commercial banks	12616,58,36,433.76				Investments ¹	5554,25,29,142.84	
(ii) Scheduled State co-operative banks	171,70,80,711.49				Loans and Advances to:		
(iii) Non-scheduled State co-operative banks	5,93,85,498.77				(i) Central Government	..	
(iv) Other banks	25,51,30,796.64				(ii) State Governments ²	18,06,00,000.00	
(c) NABARD Deposit					Loans and Advances to:		
(i) NRC (Long Term Operations) Fund	..				(i) Scheduled commercial banks	474,54,19,484.23	
(ii) NRC (Stabilisation) Fund	266,87,20,915.61				(ii) State co-operative banks	19,73,42,000.00	
(d) Others	5901,50,25,855.62				(iii) NABARD	860,90,24,000.00	
Bills Payable	129,16,08,519.88				(iv) Others	135,60,00,000.00	
Other Liabilities	8627,95,57,694.61				Loans, Advances & Investments from		
					National Industrial Credit (LTO) Fund:		
					(a) Loans & Advances to:		
					(i) Industrial Development Bank of India	2589,87,90,500.00	
					(ii) Export Import Bank of India	260,00,00,000.00	
					(b) Investments in bonds debentures issued by :		
					(i) Industrial Development Bank of India	..	
					(ii) Export Import Bank of India	..	
					Other Assets ³	1743,03,30,376.03	
Total Liabilities			31266,33,83,435.04		Total Assets		31266,33,83,435.04

¹ Includes Rs. 1760,62,12,768.79 held abroad in foreign currencies.

² Includes Ways & Means Advances.

³ Includes amounts advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

K. G. PATKAR
Chief Accountant

Dated 14th August 1986.

R. N. MALHOTRA Governor
A. GHOSH Deputy Governor
C. RANGARAJAN Deputy Governor
R. K. KAUL Deputy Governor
P. D. OJHA Deputy Governor

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1986

	Rs.	P.
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.	621,40,12,853.38	
Total	621,40,12,853.38	
EXPENDITURE		
Establishment	128,12,08,682.12	
Directors' & Local Board Members' Fees & Expenses	3,37,965.01	
Auditors' Fees	7,08,633.50	
Rent Taxes, Insurance, Lighting, etc.	6,37,88,291.34	
Law Charges	34,53,597.76	
Postage and Telegraph Charges	1,46,17,550.44	
Remittance of Treasure	4,08,34,355.50	
Stationery, etc.	1,47,79,459.38	
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	100,07,82,422.27	
Depreciation, and Repairs to Bank Property	6,64,16,997.37	
Agency Charges	150,01,19,357.24	
Contribution to Staff Gratuity and Superannuation Funds	2,15,00,000.00	
Miscellaneous Expenses	10,54,64,541.40	
Total	411,40,11,853.33	
Net available balance	210,00,01,000.05	
Total	621,40,12,853.38	
Surplus payable to the Central Government	210,00,01,000.05	

*After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of Reserve Bank of India Act, 1934.

RESERVE FUND ACCOUNT

	Rs.	P.
Balance on 30th June 1985	150,00,00,000.00	
Transfer from Profit and Loss Account		
Total	150,00,00,000.00	

K.G. PATKAR
Chief Accountant

Dated the 14th August 1986.

R.N. MALHOTRA Governor
A. GHOSH Deputy Governor
C. RANGARAJAN Deputy Governor
R. K. KAUL Deputy Governor
P.D. OJHA Deputy Governor

REPORT OF THE AUDITORS**TO THE PRESIDENT OF INDIA**

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Banks as at 30th June, 1986.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of all Offices of the Bank and report that where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Dated the 14th August 1986

M/s. BRAHMAYYA & Co.
M/s. C.C. CHOKSHI & CO.
M/s. S.R. BATLIBOI & CO. Auditors
M/s. DASS GUPTA & CO.
M/s. VED & CO.
M/s. K.C. KHANNA & CO.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET

Particulars	For the year ended			
	June 30, 1984		June 30, 1985	
	Rs.	P.	Rs.	P.
ISSUE DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Notes held in the Banking Department	5,63,23,572.00		39,68,97,530.00	
Notes in circulation	21776,91,60,554.50		24755,60,11,721.50	
Total notes issued [¶]		21782,54,84,126.50		24795,29,09,251.50
Total Liabilities		21782,54,84,126.50		24795,29,09,251.50
ASSETS				
Gold Coin and Bullion				
(a) Held in India	225,58,28,485.81		246,66,66,362.28	
(b) Held outside India	—		—	
Foreign Securities	1564,05,75,253.50		1564,05,75,253.50	
Rupee Coin	16,10,91,167.06		15,00,32,662.85	
Government of India Rupee Securities	19976,79,89,220.13		22969,56,34,972.87	
Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—		—	
Total Assets		21782,54,84,126.50		24795,29,09,251.50
BANKING DEPARTMENT				
LIABILITIES				
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00		150,00,00,000.00	
National Industrial Credit (LTO) Fund	2545,00,00,000.00		2895,00,00,000.00	
Deposits				
(a) Government				
(i) Central	2919,08,02,336.88		59,86,10,234.95	
(ii) States	13,07,55,456.28		14,87,27,256.98	
(b) Banks				
(i) Scheduled commercial banks	8104,86,78,299.28		10886,01,46,502.08	
(ii) Scheduled state co-op. banks	141,34,14,266.56		142,83,62,962.37	
(iii) Non-scheduled State co-op. banks	4,71,21,135.00		4,57,75,099.57	
(iv) Other banks	16,25,80,279.50		25,18,33,462.00	
(c) NABARD Deposit				
(i) NRC (LTO) Fund	249,58,65,242.03		117,58,65,242.03	
(ii) NRC (Stabilisation) Fund	281,28,55,673.58		281,28,55,673.58	
(d) Others	6423,01,90,647.87		6461,81,25,057.68	
Bills Payable	86,30,48,132.88		22,28,24,900.36	
Other Liabilities	4498,73,43,967.16		6074,47,42,058.44	
Total Liabilities		25438,26,55,437.02		27140,78,68,450.04

Note: June 30, 1984—Contingent liability on partly paid shares Rs. 7,57,495.42 equivalent of £ 50,000.

June 30, 1985—Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,04,997.42 equivalent of £ 50,000.

STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET (Concld.)

Particulars	For the year ended			
	June 30, 1984		June 30, 1985	
	Rs.	P.	Rs.	P.
BANKING DEPARTMENT				
ASSETS				
Notes	5,63,23,572.00		39,68,97,530.00	
Rupee Coin	3,30,353.00		7,20,074.00	
Small Coin	1,63,897.40		2,19,447.75	
Bills purchased and discounted				
(a) Internal				
(b) External				
(c) Government Treasury Bills	9374,62,39,191.70		8394,06,37,831.32	
Balances held abroad	3277,95,38,519.45		3732,00,89,774.67	
Investments	4369,15,45,657.57(b)		6952,77,49,528.59(c)	
Loans and Advances to				
(i) Central Government				
(ii) State Governments (a)	460,47,00,000.00		315,58,00,000.00	
(iii) Scheduled Commercial Banks	1768,66,06,105.87		1863,00,79,190.68	
(iv) State Co-operative Banks	44,88,60,000.00		21,66,25,000.00	
(v) NABARD	1039,05,76,000.00		761,83,41,000.00	
(vi) Others	166,00,00,000.00		182,05,00,000.00	
Loans, Advances and Investments from				
NIC (LTO) Fund:				
(a) Loans and Advances to				
(i) Industrial Development Bank of India	2084,78,11,075.00		2320,78,30,730.00	
(ii) Export Import bank of India	125,00,00,000.00		180,00,00,000.00	
(b) Investment in Bonds/Debentures issued by :				
IDBI/EXIM Bank				
Other Assets (d)	2721,99,61,065.03		2377,23,78,323.03	
Total Assets	25438,26,55,437.02		27140,78,68,450.04	

(a) Includes ways and means advances.

(b) Includes Rs. 870,16,68,177.87 held abroad in foreign currencies.

(c) Includes Rs. 1383,73,65,508.44 held abroad in foreign currencies.

(d) Includes amounts advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1984 AND 1985

	1984 Rs. P.	1985 Rs. P.
INCOME		
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.*	459,68,22,728.03	571,97,87,340.98
TOTAL	459,68,22,728.03	571,97,87,340.98
EXPENDITURE		
Establishment	93,33,56,846.98	142,25,62,666.01
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses	2,22,702.85	2,64,677.99
Auditors' Fees	8,43,227.00	6,68,795.90
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	4,83,44,920.97	4,77,58,619.79
Law Charges	6,05,114.98	8,56,772.09
Postage and Telegraph Charges	1,29,43,134.35	1,30,13,462.74
Remittance of Treasure	1,97,86,226.57	2,27,86,300.80
Stationery, etc.	1,40,17,921.72	1,50,83,724.29
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	43,41,68,205.58	58,28,05,498.05
Depreciation and Repairs to Bank Property	4,23,54,739.96	6,63,11,894.66
Agency Charges	93,92,73,197.30	132,84,76,907.52
Contributions to Staff Gratuity and Superannuation Funds	1,60,00,000.00	1,70,00,000.00
Miscellaneous Expenses	3,49,06,250.00	10,21,97,196.67
Net Available Balance	210,00,00,239.77	210,00,00,824.47
TOTAL	459,68,22,728.03	571,97,87,340.98
Surplus payable to Central Government	210,00,00,239.77	210,00,00,824.47

*After making statutory contributions, and the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00
By Transfer from Profit and Loss Account	Nil	
TOTAL	150,00,00,000.00	150,00,00,000.00